सबसे बड़ा स्वास्थ्य अभियान

प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के धार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आठवें राष्ट्रीय पोषण माह के साथ 'स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार' अभियान (एसएनएसपी) (17 सितंबर-दो अक्तूबर) का शुभारंभ कर महिलाओं और बच्चों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का शानदार उदाहरण पेश किया है. एक पखवाड़े तक चलने वाले इस अभियान में, जिसे अब तक का सबसे बड़ा स्वास्थ्य अभियान बताया जा रहा है, देशभर के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी), जिला अस्पतालों और अन्य सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में करीब एक लाख स्वास्थ्य शिविर लगाये जायेंगे, जिनमें किशोरियों, महिलाओं और बच्चों को स्वास्थ्य और पोषण संबंधी सुविधाएं दी जायेंगी. जिन बच्चों का टीकाकरण अधूरा रह गया है, उसे इन शिविरों में पूरा किया जायेगा, किशोरियों में खून की कमी की जांच के साथ इलाज होगा, साथ ही, उनकी मानसिक समस्याओं का भी समाधान होगा. इससे आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक महिलाओं की पहुंच सुनिश्चित होगी. इस अभियान का नेतृत्व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय संयुक्त रूप से कर रहे हैं. दोनों मंत्रालय मिलकर एनीमिया की रोकथाम, संतुलित आहार और मासिक धर्म स्वच्छता पर जागरूकता अभियान भी चलायेंगे, ताकि महिलाओं और किशोरियों की स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी जरूरतें पूरी करना सुनिश्चित हो सके. इस अभियान का उद्देश्य स्वास्थ्य, पोषण, तंदरुस्ती और 2047 तक प्रधानमंत्री के विकसित भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना है. यह अभियान गैर संचारी रोगों, तपेदिक, सिकल सेल रोग की जांच, शीघ्र पहचान और उपचार की कड़ी को मजबूती प्रदान करेगा, टीकाकरण, स्वच्छता, जीवनशैली और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता की गतिविधियों को बढ़ावा देगा, साथ ही मोटापे की रोकथाम और स्वैच्छिक रक्तदान पर विशेष जोर देते हुए लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करेगा. इस अभियान का एक उद्देश्य देश में मां और बच्चे की मृत्यु दर को कम करना भी है. हालांकि हाल ही में आयी सैंपल रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट, 2023 के अनुसार, बाल मृत्यु दर प्रति 1,000 में 40 से घटकर अब 25 रह गयी है. इस अभियान की सफलता के लिए सशक्त पोर्टल के माध्यम से वास्तविक समय पर निगरानी भी की जायेगी. प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देशवासियों को संबोधित करते हुए देश को विकसित बनाने के चार स्तंभों- नारी, युवा शक्ति, किसान और गरीब- को रेखांकित किया, जिसमें नारी शक्ति को राष्ट्र की प्रगति का मुख्य आधार बताया.

अपने जन्मदिन पर प्रधानमंत्री ने स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ कर महिलाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का ही उदाहरण पेश किया. यह अभियान विकसित भारत के प्रति उनके नजरिये का द्योतक है.

मोटापे और कुपोषण से निपटने की रणनीति

अन्नपूर्णा देवी
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री
delhi@prabhatkhabar.in

वर्ष 2018 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत के पोषण परिदृश्य को रूपांतरित करने के लिए एक प्रमुख योजना के रूप में पोषण अभियान शुरू किया गया था. महिलाओं और बच्चों के पोषण व कल्याण पर केंद्रित यह मिशन कुपोषण के विरुद्ध लड़ाई में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ है. यह केवल एक योजना नहीं, बल्कि विकासशील भारत के निर्माण हेतु प्रतिबद्धता है- एक ऐसा भारत, जो स्वस्थ, सशक्त और समावेशी हो. 'विकसित भारत@2047' की यात्रा में पोषण अभियान एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभरा है. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संकल्पित है- एक ऐसा भारत, जहां हर बच्चा सुपोषित हो, हर मां सशक्त हो, और हर नागरिक को आगे बढ़ने का अवसर मिले.

जब एक बच्चा सही पोषण पाता है, अच्छी तरह सीखता है और मजबूती से आगे बढ़ता है, तब हम केवल एक जीवन नहीं, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र की दिशा बदलते हैं. बच्चों को पर्याप्त पोषण, शिक्षा और सामुदायिक देखभाल प्रदान कर हम एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य में निवेश कर रहे हैं- विकसित भारत के भावी नेतृत्व को आकार दे रहे हैं. मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के माध्यम से मंत्रालय बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं के पोषण परिणामों को बेहतर बनाने हेतु एक समन्वित तंत्र विकसित कर रहा है. इस अभियान का केंद्र है देशभर में फैले 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों का विशाल नेटवर्क, जो लगभग 10 करोड़ लाभार्थियों को सेवा प्रदान कर रहा है. यद्यपि इसमें एक करोड़ से अधिक महिलाएं और 23 लाख से अधिक किशोरियां शामिल हैं, लेकिन लाभार्थियों में से अधिकांश छह महीने से छह वर्ष की आयु के बच्चे हैं. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 'एक समय पर एक भोजन' के सिद्धांत पर कार्य करते हुए आठ करोड़ से अधिक बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के जरिये भविष्य को पोषित कर रहा है. इस प्रयास का मूल है- पूरक पोषण कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन और सभी लाभार्थियों को पौष्टिक टेक होम राशन प्रदान किया जाता है, जिसका उद्देश्य अनुशंसित आहार भत्ता (आरडीए) और औसत दैनिक सेवन (एडीआइ) के बीच के महत्वपूर्ण अंतर को पाटना है. हम विविध आहार को अपनाते हुए स्थानीय, मौसमी और पारंपरिक खाद्य पदार्थों जैसे, ज्वार, बाजरा, रागी, कुट्टू आदि को बढ़ावा देकर यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक बच्चे को सीखने, बढ़ने और फलने-फूलने के लिए आवश्यक ऊर्जा मिले. जहां हमने बच्चों में स्टंटिंग और वेस्टिंग की समस्याओं से निपटने में प्रगति की है, वहीं अब हम एक अन्य महत्वपूर्ण पोषण संकेतक- अधिक वजन और मोटापे की समस्या को दूर करने की दिशा में भी अग्रसर हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, बचपन में मोटापा बच्चों के वयस्क होने पर उनके लिए गंभीर परिणाम उत्पन्न कर सकता है, जिससे टाइप 2 मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी गैर संचारी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले और मैकगिल के सहयोग से किये गये एक अध्ययन में यह पाया गया कि जिन बच्चों को शुरुआती 1,000 दिनों के दौरान चीनी सेवन पर नियंत्रण लगाया गया, उनमें वयस्क होने पर टाइप 2 मधुमेह होने का जोखिम 35 प्रतिशत तक कम और उच्च रक्तचाप होने का जोखिम 20 फीसदी तक कम हो गया. यह दर्शाता है कि गर्भवती मां का चीनी सेवन बच्चों के दीर्घकालिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है.

इस समस्या के समाधान और पूरक पोषण की समग्र गुणवत्ता में सुधार के लिए मंत्रालय ने हाल ही में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को पूरक पोषण की संरचना के संबंध में एक परामर्श जारी किया है, जो डब्ल्यूएचओ (विश्व स्वास्थ्य संगठन) और एनआइएन (राष्ट्रीय पोषण संस्थान) की सिफारिशों के अनुरूप है. डब्ल्यूएचओ के दिशानिर्देशों के अनुसार, वयस्कों और बच्चों के लिए चीनी का सेवन कुल दैनिक ऊर्जा सेवन के 10 फीसदी तक कम किया जाना चाहिए. एनआइएन की 2024 के आहार दिशानिर्देशों के अनुसार, दो साल से कम उम्र के बच्चों को अतिरिक्त चीनी नहीं दी जानी चाहिए और गर्भवती महिलाओं सहित सभी आयु और जेंडर समूहों के लिए चीनी का सेवन पांच फीसदी से कम होना चाहिए. चीनी सेवन को सीमित करने से बच्चों में दांतों की सड़न और क्षय को कम किया जा सकता है.

हमारे मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को परामर्श दिया है कि परिष्कृत चीनी का उपयोग सीमित किया जाये और आवश्यकता पड़ने पर गुड़ या अन्य प्राकृतिक मिठास का इस्तेमाल करें. हमने अनुरोध किया है कि पूरक पोषण में नमक का इस्तेमाल कम किया जाये. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से नाश्ते और स्वास्थ्यवर्धक आहार में मिठास वाले व्यंजनों की संख्या घटाने का आग्रह किया गया है. साथ ही, सभी आयु समूहों में वसा, नमक और चीनी की अधिकता वाले खाद्य पदार्थों के उपयोग को भी हतोत्साहित किया गया है. राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से आग्रह किया गया है कि सामग्री को खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम, 2011 का और शिशु आहार खाद्य सुरक्षा और मानक (शिशु पोषण हेतु खाद्य) विनियम, 2020 का पालन करना चाहिए.

जहां पारंपरिक खाद्य पदार्थ बाजार में लोकप्रिय हो रहे हैं, वहीं मंत्रालय पहले से ही 'पुष्टाहार'- स्थानीय, मौसमी सामग्री और अनाज जैसे रागी, बाजरा, टुकड़ा गेहूं, चना और फोर्टिफाइड चावल से बने पौष्टिक प्रीमिक्स प्रदान कर रहा है. ये मिश्रण स्वाद और पोषण में समृद्ध हैं, जिन्हें स्थानीय स्वादानुसार मीठे या नमकीन रूप में तैयार किया जा सकता है. पुष्टाहार दुकानों से खरीदे जाने वाले मिश्रणों का एक स्वास्थ्यवर्धक और अधिक बहुमुखी विकल्प है, जो स्थानीय, मौसमी स्वाद और संपूर्ण पोषण प्रदान करता है. जब हम अपने नागरिकों को पर्याप्त कैलोरी प्रदान करके सुपोषित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, तब हमारे बच्चों और महिलाओं को जो भोजन दिया जा रहा है, उसकी गुणवत्ता पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है. हम अपने बच्चों को जो भोजन प्रदान करते हैं, वह उनके समग्र विकास और स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त होना चाहिए. माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, 'अपने खान-पान की आदतों में छोटे-छोटे बदलाव करके हम अपने भविष्य को अधिक मजबूत, स्वस्थ और रोग मुक्त बना सकते हैं.' इस अमृत काल में हमारे बच्चों को पौष्टिक भोजन और पर्याप्त कैलोरी उपलब्ध होनी चाहिए. इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके लिए भोजन न केवल पर्याप्त होना चाहिए, बल्कि पौष्टिक भी होना चाहिए, जो उनके समग्र विकास और वृद्धि में योगदान दे.

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के माध्यम से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं के पोषण परिणामों को बेहतर बनाने हेतु एक समन्वित तंत्र विकसित कर रहा है. इस अभियान का केंद्र है देशभर में फैले 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों का विशाल नेटवर्क, जो लगभग 10 करोड़ लाभार्थियों को सेवा प्रदान कर रहा है. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 'एक समय पर एक भोजन' के सिद्धांत पर कार्य करते हुए आठ करोड़ से अधिक बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के जरिये भविष्य को पोषित कर रहा है.

नेपाल का स्थिरता की ओर लौटना भारत के लिए सुखद

एसडी मुनि
पूर्व प्रोफेसर और अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ
delhi@prabhatkhabar.in

सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाये जाने के बाद नेपाल स्थिरता की ओर जाता दिख रहा है. चूंकि वे पूर्व प्रधानमंत्रियों, सेना तथा जेनरशन जी की सहमति से अंतरिम प्रधानमंत्री चुनी गयी हैं, ऐसे में, निकट भविष्य में असहमति या विवाद की आशंका नहीं है. लेकिन दो चुनौतियां जरूर हैं. एक तो राजनीतिक पार्टियों ने संसद को भंग किये जाने का विरोध किया, क्योंकि इससे फौरी तौर पर उनका महत्व खत्म हो जायेगा. वास्तविकता यह है कि नेपाल की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने संसद को भंग करने के राष्ट्रपति के फैसले की कड़ी आलोचना की है.

नेपाल की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी नेपाल कांग्रेस ने इसे संविधान का उल्लंघन बताया है और कहा है कि यह फैसला देश की लोकतांत्रिक उपलब्धियों को कमजोर करता है. जबकि वास्तविकता यह है कि नेपाल का मौजूदा राजनीतिक संकट राजनीतिक पार्टियों के भ्रष्टाचार के कारण ही यहां तक पहुंचा है. युवा आंदोलनकारियों ने तमाम राजनीतिक दलों के प्रति सार्वजनिक तौर पर अपनी गहरी नाराजगी व्यक्त की. लेकिन इतनी बेइज्जती के बाद भी वे नेपाल की राजनीति में प्रासंगिक बने रहना चाहते हैं. हालांकि संसद को भंग कर देने से उनकी राजनीतिक प्रासंगिकता फिलहाल कम हो गयी है. ऐसे में, खुद को प्रासंगिक बनाये रखने के लिए वे अंतरिम सरकार को अस्थिर करने का काम करते रह सकते हैं. जबकि आंदोनकारियों ने नेपाल की राजनीतिक पार्टियों को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है. इसके बावजूद ये नेतागण चुप बैठने वाले नहीं हैं. सुशीला कार्की की अंतरिम सरकार को सबसे बड़ी चुनौती इन राजनीतिक दलों से ही है.

दूसरी चुनौती राजशाही की ओर से है. दरअसल जेन जी के आंदोलन के बाद नेपाल में राजशाही की वापसी के कयास भी लगाये जाने लगे थे. कहा यह भी जा रहा था कि छात्र आंदोलन को राजशाही का समर्थन है. चूंकि इस आंदोलन से पहले नेपाल में राजशाही के पक्ष में जुलूस निकलते देखा गया था. इसलिए भी इस संभावना को बल मिला था. ऐसे में, जब सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया है, तब राजशाही से जुड़े लोग स्वाभाविक ही इसे सहजता से नहीं लेंगे. इसलिए अगर आने वाले दिनों में राजशाही की तरफ से अंतरिम सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए. इस बीच अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने भी अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय दिया है. पहली बात उन्होंने यह कही है कि अंतरिम सरकार छह महीने के लिए ही है. उन्होंने साफ जताया है कि वह सत्ता से चिपकी रहने वाली नहीं हैं. दूसरे, उन्होंने नेपाल में हुई हिंसा की जांच कराने की बात कही है. इससे स्पष्ट है कि वह जेनरेशन जी को खुश करके सत्ता में नहीं रहने वालीं. युवा आंदोलनकारियों ने अंतरिम प्रधानमंत्री द्वारा चुने गये तीन मंत्रियों में से गृह मंत्री की नियुक्ति पर जिस तरह आपत्ति जतायी है, उससे लगता है कि जेनरेशन जी शायद उनके फैसलों से बहुत सहज न हो. लेकिन लगता नहीं कि इससे सरकार की स्थिरता पर कोई फर्क पड़ेगा.

जहां तक भारत की बात है, तो नेपाल में अस्थिरता भारत के लिए चिंताजनक होती है. ऐसे में, वहां की मौजूदा स्थिति भारत के लिए सकारात्मक है. वैसे यह जानने की जरूरत है कि नेपाल में जब हिंसा हो रही थी, तो उसकी जानकारी भारत को दी जा रही थी. यह जानकारी दो स्तर पर दी जा रही थी. एक तो सैन्य स्तर पर, और दूसरे राजशाही के स्तर पर. आपको पता होगा कि भारत और नेपाल के सैन्य रिश्ते बहुत पुराने हैं. इसलिए नेपाल की सेना अपने यहां के घटनाक्रमों की जानकारी भारतीय सेना को दे रही थी. नेपाल में राजशाही से जुड़ा जो तंत्र मौजूद है, उसकी तरफ से भी घटनाक्रम की निरंतर जानकारी भारत को दी जा रही थी. नेपाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी प्रभावी उपस्थिति है, और उसके नेटवर्क से भी भारत को सारी जानकारी मिल रही थी. सिर्फ आंदोलनकारी जेनरेशन जी से ही नयी दिल्ली का उस तरह का संपर्क नहीं था.

फिर वहां अब जो अंतरिम सरकार है, वह भी भारत के लिहाज से सकारात्मक है. जिन सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया है, उनका भारत से रिश्ता रहा है. उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है. उनके पति दुर्गा प्रसाद सुबेदी नेपाली कांग्रेस के युवा नेता थे और जून, 1973 में नेपाल के विराटनगर से काठमांडू जा रहे रॉयल नेपाल एयरलाइंस के विमान अपहरण कांड से चर्चा में आये थे. उस मामले में चालक दल के साथ झड़प के बाद अपहर्ताओं ने विमान को फारबिसगंज में उतारने के लिए मजबूर कर दिया था. सुबेदी और अन्य को इस मामले में दो साल की सजा हुई थी और 1975 में आपातकाल के दौरान उन्हें रिहा कर दिया था. मेरा मानना यह है कि नेपाल की सेना और वहां की नौकरशाही अगर अंतरिम सरकार को पूरी तरह अपना समर्थन दें, तो अगले छह महीने तक यह सरकार आराम से चल सकती है. आगामी पांच मार्च को होने वाले चुनाव में जिस राजनीतिक पार्टी को जीत मिलेगी, उस पर नेपाल में नयी शुरुआत करने की जिम्मेदारी होगी. **(ये लेखक के निजी विचार हैं.)**

अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला कार्की दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय दे रही हैं. नेपाल की सेना और वहां की नौकरशाही अगर अंतरिम सरकार को अपना समर्थन दें, तो अगले छह महीने तक यह सरकार आराम से चल सकती है. उसके बाद देश को शांति और स्थिरता की ओर ले जाने की जिम्मेदारी नयी सरकार की होगी.

देश दुनिया

राजनीतिक दलों को देश में आये बदलाव को स्वीकार करना होगा

बीते सप्ताह की अशांति के बाद नेपाल में जनजीवन धीरे-धीरे सामान्य हो रहा है. इस बीच, प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने तीन मंत्रियों का चयन कर लिया है, परंतु अभी तक उन्होंने अपने मंत्रिमंडल को पूरी तरह से आकार नहीं दिया है. उन पर जेन जी की भावना के अनुरूप आगे बढ़ने का दायित्व है, जिसने उन्हें देश के कार्यकारी प्रमुख के पद तक पहुंचाया है. आंदोलन के दौरान युवा प्रदर्शनकारियों द्वारा की गयी सबसे महत्वपूर्ण मांगें थीं : भ्रष्टाचार समाप्त करना, सुशासन सुनिश्चित करना और पर्याप्त संख्या में स्थानीय नौकरियों का सृजन करना. वे मौजूदा प्रमुख राजनीतिक शक्तियों के नेतृत्व और ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन चाहते हैं. अंतरिम सरकार को मार्च 2026 की शुरुआत में संसदीय चुनाव कराने होंगे और एक निर्वाचित सरकार को सत्ता सौंपनी होगी. देश की राजनीति को सही रास्ते पर लाने और हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए, उन्हें यह कार्य छह महीने के भीतर पूरा करना होगा. इसके लिए कार्की को न केवल उभरती शक्तियों, बल्कि पारंपरिक राजनीतिक दलों के समर्थन की भी आवश्यकता है. दुर्भाग्यवश, तीन प्रमुख दलों- नेपाली कांग्रेस, सीपीएन-यूएमएल और सीपीएन (माओवादी सेंटर)- के नेताओं के कुछ हालिया बयान उत्साहजनक नहीं कहे जा सकते. इन दलों के वफादारों की टिप्पणियों से यह पता चलता है वे अभी भी जेनरेशन जी की क्रांति से आये रातोंरात बदलाव को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं. यहां समझने की जरूरत है कि युवाओं की मांगें दरअसल देशभर के आम लोगों की मांगें हैं. बात बस इतनी-सी है कि जेन जी के आंदोलन ने इन्हें कहीं अधिक स्पष्टता से व्यक्त किया है. यही कारण है कि यह आंदोलन तेजी से एक जन विद्रोह में बदल गया, और देश की सरकार को गिराने में जरा भी देर नहीं लगायी. पुरानी पार्टियों ने पिछले एक दशक में जनता को पूरी तरह निराश किया है. उनके द्वारा समय को पीछे मोड़ने का कोई भी प्रयास न केवल व्यर्थ, बल्कि आत्मघाती भी साबित होगा.

THE KATHMANDU POST
WITHOUT FEAR OR FAVOUR

जयंती विशेष

आत्मजयी व मानवतावादी कवि थे कुंवर नारायण

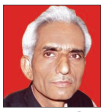

कृष्ण प्रताप सिंह
वरिष्ठ पत्रकार
kp_faizabad@yahoo.com

'एक अजीब-सी मुश्किल में हूं इन दिनों/मेरी भरपूर नफरत कर सकने की ताकत/दिनोंदिन क्षीण पड़ती जा रही/...हर समय/पागलों की तरह भटकता रहता/कि कहीं कोई ऐसा मिल जाये/जिससे भरपूर नफरत करके/अपना जी हल्का कर लूं/पर होता है इसका ठीक उल्टा/कोई-न-कोई, कहीं-न-कहीं, कभी-न-कभी/ऐसा मिल जाता/जिससे प्यार किये बिना रह ही नहीं पाता!'

मिथकीय चेतना से संपन्न और 'आत्मजयी' कहलाने वाले हिंदी के जाने-माने मानवतावादी कवि कुंवर नारायण (जिन्हें समन्वय व विद्रोह का कवि भी कहा जाता है) ने आठ वर्ष पहले 15 नवंबर, 2017 को इस संसार को अलविदा कहा, तो उनकी 'एक अजीब-सी मुश्किल' शीर्षक रचना को उनकी प्रतिनिधि कविताओं में शुमार किया जाने लगा था. स्वाभाविक ही उनकी स्मृतियों के साथ इसकी ऊपर उल्लिखित पंक्तियों को सबसे ज्यादा याद किया गया. यूं तो पांच दशकों से भी अधिक समय की उनकी साहित्य सेवा में इतने आयाम रहे हैं कि आलोचकों द्वारा उनके बारे में कहा जाता है कि अपने निधन के बाद अनुपस्थित रहकर भी वे हमारे बीच ज्यादा उपस्थित रहेंगे. बहरहाल, 19 सितंबर, 1927 को फैजाबाद (अब अयोध्या) में पिता विष्णु नारायण अग्रवाल के दूसरे बेटे के रूप में जब उनका जन्म हुआ, तो देश अंग्रेजों से मुक्ति की लड़ाई लड़ रहा था और फैजाबाद की सामाजिक चेतना उरूज पर थी. फैजाबाद शहर का उनका घर कांग्रेस के समाजवादियों की गतिविधियों व जमावड़ों का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था. आचार्य जेबी कृपलानी, सुचेता कृपलानी, आचार्य नरेंद्र देव और डॉ राममनोहर लोहिया जैसे अनेक समाजवादी नेता वहां आते, कई-कई दिनों तक ठहरते और परस्पर लंबा विचार-विमर्श किया करते थे.

कुंवर नारायण
(19 सितंबर, 1927–15 नवंबर, 2017)

यूं तो विष्णु नारायण महाजन थे और जरूरतमंदों को सूद पर रुपये दिया करते थे, परंतु देश और समाज के सरोकारों से अपने जुड़ाव के चलते उन्होंने सुचेता कृपलानी के नाम पर अपने घर का नाम 'सुचेता सदन' रख छोड़ा था. घर के इस वातावरण में कुंवर नारायण को किशोरावस्था से ही कांग्रेसी-समाजवादी नेताओं का भरपूर सान्निध्य मिलने लगा था, जिसका प्रभाव उनकी साहित्य सर्जना पर भी पड़ा. वे इस प्रभाव को ईमानदारी पूर्वक स्वीकार भी किया करते थे. परंतु उनकी इस जन्मभूमि ने उनके निधन के आठ वर्षों में ही उनके प्रति ऐसा अजीबोगरीब बेगानापन ओढ़ लिया है कि उसमें उनकी बहुत कम स्मृतियां बची हैं. यह देखकर उनके सहृदय पाठकों का हृदय बिंधकर रह जाता है. तब से अब तक उनके घर की कम से कम दो बार खरीद-बिक्री हो चुकी है. इसलिए वहां उनकी स्मृतियों से जुड़ा कुछ होने या दिखने का तो प्रश्न ही समाप्त हो गया है. इससे भी बड़ी विडंबना यह कि उनके रहते बेहद गर्व व दर्प से उन्हें अपना अभिभावक बताने वाले उनके अनेक प्रियजनों को अन्य किसी रूप में भी उनकी स्मृतियों की रक्षा की चिंता नहीं सताती. ऐसे में कई लोगों को अवध में प्रचलित यह पुरानी कहावत याद आती है कि घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध. वे कहते हैं कि अपनी जन्मभूमि में कुंवर नारायण की यह बेकद्री इसलिए है कि उनको 'घर का जोगी' मान लिया गया है. यह बात इस कारण कुछ ज्यादा ही कही जाती है क्योंकि एक समय यह सपना देखा जाता था कि जैसे अयोध्या के बगल का बस्ती जिला 'कुंआनो के कवि' सर्वेश्वरदयाल सक्सेना को अपनी माटी की उपज के रूप में निरंतर याद रखता है, वैसे ही कुंवर नारायण को भी 'सरयू के कवि' अथवा 'अयोध्या के कवि' के रूप में याद किया जायेगा.

बावजूद इसके कि छुटपन में एक के बाद एक त्रासदियों के चलते अपने अयोध्यावासी परिजनों से उनके तार उनके इस संसार में रहते ही टूटकर रह गये थे. छुटपन में उन दिनों तक पूरी तरह लाइलाज क्षय रोग से असमय ही पहले मां, फिर चाचा और फिर बहन को खोकर उन्होंने अयोध्या छोड़ा, तो अरसे तक वहां वापस लौटने का कोई कारण ही नहीं तलाश सके थे. अनंतर, उनके परिवार ने अयोध्या स्थित अपनी ज्यादातर परिसंपत्तियां बेच डालीं और लखनऊ में नया व्यवसाय आरंभ कर लिया. कुंवर नारायण ने वहीं विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद साहित्य में अपनी गहन अभिरुचि के कारण आगे का रास्ता बदल लिया और 1951 में लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया. अलबत्ता, अपने निधन से कुछ वर्ष पूर्व तक वे अयोध्या के विमला देवी फाउंडेशन के, जिसके वे संस्थापक सदस्य थे, वार्षिक समारोहों में शिरकत करने आया करते थे. उनकी जन्मभूमि में उनके पिता विष्णु नारायण के नाम की तो एक गली है भी, पर उनसे जुड़ा कुछ नहीं है.

प्रसंगवश, उनकी काव्य यात्रा 'चक्रव्यूह' नामक कविता संग्रह से शुरू हुई थी. उसके बाद से इस यात्रा में वे अपने पाठकों में लगातार एक नयी तरह की समझ पैदा करते रहे थे. कहते हैं कि उनके रचनात्मक जीवन की शुरुआत में लखनऊ शहर का विशेष योगदान रहा, परंतु 2017 में जब उन्होंने दिल्ली के सीआर पार्क स्थित अपने घर में अंतिम सांस ली, तो पत्नी भारती गोयनका और बेटा अपूर्व ही उनके साथ थे.

आपके पत्र

बुजुर्गों का सम्मान करें हम

आज अनेक बुजुर्ग अकेलेपन और उपेक्षा का शिकार हैं. पारिवारिक ढांचे में आया बदलाव, संयुक्त परिवारों का विघटन, आर्थिक स्वतंत्रता की चाह और उपभोक्तावादी सोच ने बुजुर्गों को हाशिये पर ला दिया है. शारीरिक हिंसा, मानसिक प्रताड़ना, आर्थिक शोषण के साथ ही समाज में उनके मान-सम्मान में भी कमी आयी है. यह स्थिति तब है जब सरकार की ओर से बुजुर्गों के लिए पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, वृद्धाश्रम और स्वास्थ्य सहायता केंद्र बनाये गये हैं. बुजुर्ग पथ प्रदर्शक होते हैं, उनका सम्मान होना ही चाहिए.

हिमांशु शेखर, गयाजी

एंटीबायोटिक का अंधाधुंध उपयोग

भारत में एंटीबायोटिक का अंधाधुंध उपयोग गंभीर संकट बन चुका है. हालत यह है कि बिना डॉक्टरी परामर्श के भी लोग इन्हें लेने लगे हैं. वहीं दूसरी ओर कई प्राइवेट डॉक्टर भी मरीजों को बिना जरूरत इसे लिख रहे हैं. अध्ययन बताता है कि निजी क्षेत्र में हर वर्ष आधे अरब से अधिक एंटीबायोटिक दवाएं लिखी जाती हैं, जिनमें से अधिकांश अनावश्यक होती हैं. यह प्रवृत्ति रोगाणुरोधी प्रतिरोध को बढ़ा रही है, जो वैश्विक स्तर पर हर वर्ष लगभग 50 लाख और भारत में लाखों मौतों का कारण है.

अमृतलाल मारू, इंदौर

पोस्ट करें : प्रभात खबर, 15 पी, इंडस्ट्रियल एरिया, कोकर, रांची 834001 ■ **फैक्स करें :** 0651-2544006 ■ **मेल करें :** eletter@prabhatkhabar.in पर ■ ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है.

https://t.me/AllNewsPaperPaid

अभिव्यक्ति

प्रेरणा

अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। - अब्दुल कलाम

संपादकीय

विश्व स्तर के शोधार्थियों को हमें बढ़ावा देना होगा

ट्रम्प ने नासा और नेशनल साइंस फाउंडेशन जैसे शोध-विकास संस्थानों के बजट में 50% से ज्यादा की कटौती की है, जिससे स्टेम (साइंस, टेक्नोलोजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स) विषय के रिसर्चर्स के उच्च गुणवत्ता वाले शोध प्रयासों में भारी गिरावट आने लगी है। इसे देखते हुए यूरोप ने चूज यूरोप फॉर साइंस थीम पर विगत मई में एक बैठक कर दुनिया के शोधार्थियों के लिए अपने दरवाजे खोलने शुरू किए हैं। फ्रांस ने बजट बढ़ा दिया है। उधर चीन ने शोध-विकास के लिए युवाओं को बेहतर करियर विकल्प देना शुरू किया है। स्कूल स्तर पर ही छात्रों की पहचान कर उन्हें शोध की दिशा में उन्मुख किया जाता है। आज चीन सेमी-कंडक्टर, प्रॉपल्शन (प्रक्षेपण-शक्ति), सिंथेटिक बायोलॉजी और क्वांटम कम्युनिकेशन/कंप्यूटिंग के कोर क्षेत्रों में काफी आगे निकल चुका है। भारत ने भी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाकर एक लाख करोड़ रु. के फंड से शोध को नया आयाम देने की मंशा बनाई है। सरकार ने विगत जून में प्रेस वार्ता में बताया कि ईज ऑफ साइंस की नई नीति के तहत संस्थानों को शोध में सहूलियत के लिए अधिक वित्तीय आजादी दी जाएगी। भारत के शोधकर्ताओं का प्रतिशत दुनिया के 2% सबसे बेहतरीन और चर्चित शोध-पत्रों में मात्र 2.4% है। लेकिन हम खुश हो सकते हैं कि दुनिया के 29 टेक-देशों में भारत प्रथम 5 में है।

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता
humarehanuman@gmail.com

अच्छे श्रोता और मृदु वक्ता बनने का प्रयास करिए

सबसे अधिक भाषाएं बोलने वाले देशों में भारत का क्रमांक चौथा है। हमारे यहां सैकड़ों भाषाएं हैं। लेकिन धर्म और अध्यात्म में भाषा का प्रयोग भारत ने अद्भुत रूप से किया है। संस्कृत का तो कोई जोड़ ही नहीं है। भाषा जन-व्यवहार के लिए बनी है। मनुष्य आपस में जितने भी व्यवहार करते हैं, उसका सशक्त माध्यम भाषा है। अध्यात्म कहता है अच्छे श्रोता और मृदु वक्ता बनें। हमारे यहां सत्य और आत्मा के लिए कोई भाषा नहीं बनी। कोई इन्हें जानना चाहे तो भाषा से नहीं पा सकता। इसके लिए मौन और विनम्रता ही लगेगी। यदि हम अच्छे श्रोता बन जाएं तो बनेंगे विनम्रता के कारण, और प्राप्त होगी आत्मा। यदि मौन साधें तो मृदु वक्ता होंगे, और मिलेगा सत्य। यह भी तय है कि जिन्हें सत्य और आत्मा की अनुभूति हुई है, उनके जीवन से शब्द चले गए। ये आचरण में ही प्रकट होते हैं। इनकी परिभाषाएं की जा सकती हैं, लेकिन अनुभूति के लिए तो भाषा भी छूट जाती है। इसलिए सामान्य रूप से अच्छे श्रोता और मृदु वक्ता बनने का प्रयास कीजिए।

• Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

स्पीक-अप • उपलब्धियों सहित चुनौतियों की भी बात हो

75 वर्ष के पीएम मोदी के सामने हैं ये 8 बड़ी चुनौतियां

आकलन

मिन्हाज मर्चेंट
लेखक, प्रकाशक और सम्पादक
mmleditorial@gmail.com

नरेंद्र मोदी 63 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बने थे और अब वे 75 वर्ष के हैं। उनके जन्मदिन पर उनके 11 वर्षों से अधिक के कार्यकाल की उपलब्धियों का तो व्यापक विश्लेषण हो चुका है। लेकिन उनके तीसरे कार्यकाल के शेष 44 महीनों में उनके सामने प्रमुख 8 चुनौतियां कौन-सी हैं? आइए, इन्हें समझें।

1. रोजगार और महंगाई पर विशेष ध्यान होना चाहिए। इंडिया टुडे के एक ताजा राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में मतदाताओं के बीच यही दो सबसे बड़ी चिंताएं सामने आई थीं। हालांकि महंगाई दर 3% से नीचे आ गई है और खाने-पीने की चीजों की कीमतें भी कम हुई हैं, लेकिन वेतनमानों में आई अवरुद्धता ने इन लाभों को कम कर दिया है। अच्छी तनख्वाह वाले रोजगारों की किल्लत है। तिस पर, अब एआई भी प्राथमिक स्तर की कोडिंग नौकरियों पर कुठाराघात कर रहा है। आईटी कंपनियां छंटनी कर रही हैं या नई नौकरियां चाहने वालों का वेतन कम कर रही हैं। अमेरिकी टैरिफ ने कपड़ा श्रमिकों, रत्न व आभूषण उद्योग और चमड़ा उद्योग जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों को प्रभावित किया है। भारत-अमेरिका ट्रेड वार्ता फिर शुरू होने से सम्भव है हाई टैरिफ ज्यादा दिन न रहें, लेकिन दीर्घकालिक समाधान तो हमारी वर्कफोर्स की उत्पादकता में सुधार से ही होगा।

2. भ्रष्टाचार महामारी के स्तर पर पहुंच गया है। खासकर, राज्य और नगरपालिकाओं के स्तर पर। पीएम की भ्रष्टाचार-मुक्त छवि तो बरकरार है। लेकिन उन्हें नगरीय निकायों में भ्रष्टाचार कम करने के लिए सख्ती दिखानी होगी, जिस कारण देश में आए दिन पुल ढह रहे हैं, सड़कों में गड्ढे हैं, साफ-सफाई खस्ताहाल है। तीसरे कार्यकाल में यह उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए।

3. अमेरिका और चीन के साथ मोदी की संतुलित रणनीति ने भारत को एक परिवर्तनशील ताकत के रूप में स्थापित किया है। भारत में नए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर की नियुक्ति संबंधी कार्यक्रम में विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि भारत आज अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण रिश्तों में से एक है। 21वीं सदी की कहानी हिंद-प्रशांत क्षेत्र में लिखी जाएगी और भारत इसके केंद्र में है। ट्रम्प के करीबी गोर ने यह भी कहा कि हम टैरिफ को लेकर समझौते से बहुत दूर नहीं हैं। उधर चीन भी भारत के प्रति गर्मजोशी दिखा रहा है। लेकिन वह अवसरवादी दोस्त है। अमेरिका और चीन के साथ सुनियोजित भू-राजनीतिक रणनीति अपनानी पड़ेगी।

4. पाकिस्तान दीर्घकालीन समस्या है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के सैन्य हवाई ठिकाने और आतंकवादी शिविर बर्बाद हो गए थे। अब उसने क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के कट्टर सैन्य प्रमुख असीम मुनीर एक अप्रत्याशित फैक्टर बने हुए हैं। मोदी के लिए यह अनिवार्य है कि वे पाकिस्तान पर लगातार सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक दबाव बनाए रखें।

5. मोदी की मणिपुर यात्रा भले ही विलंब से हुई, लेकिन अब ना सिर्फ उस राज्य को विकास के लिए पैसा मुहैया कराना होगा, बल्कि मैतेई और कुकी समुदायों के बीच शांति का स्थायी हल भी निकालना होगा। अगले छह महीनों में चार प्रमुख राज्यों में चुनाव होने हैं। नवंबर में बिहार और अगले साल अप्रैल में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। मोदी को राहुल गांधी द्वारा शुरू किए गए 'वोट चोरी' अभियान को भी बेअसर करना पड़ेगा। तमिलनाडु और बंगाल के परिणामों का देशव्यापी असर होगा। दोनों राज्यों में सत्ताविरोधी लहर है, लेकिन मजबूत क्षेत्रीय वोट बैंक भी हैं।

रोजगार और महंगाई पर प्रधानमंत्री का विशेष ध्यान होना चाहिए। भ्रष्टाचार कम करने के लिए सख्ती दिखानी भी जरूरी है। विदेश नीति के मोर्चे पर संतुलित रणनीति की दरकार है। हमारे लिए दुनिया के सामने अपना नैरेटिव स्पष्ट करना भी जरूरी है।

6. अत्यधिक नियम थोपना मोदी कार्यकाल की एक कमी रही है। आरबीआई से सेबी तक, नौकरशाही ही हर प्रमुख संस्थान को चला रही है। ईज ऑफ डुइंग बिजनेस के बजाय नियम-कायदों की अधिकता जटिलताओं को बढ़ाती है। मोदी को जल्द ही लालफीताशाही को खत्म करने के कदम उठाने होंगे।

7. मोदी सरकार के तीनों कार्यकालों में धीमा और अप्रभावी संवाद एक बड़ी कमी रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और उसके बाद यह स्पष्ट तौर पर दिखा था। इससे विरोधियों को फायदा मिलता है। प्रधानमंत्री कार्यालय को एक बेहतर मीडिया निदेशक चाहिए, जो महत्वपूर्ण नीतियों और घटनाओं पर तत्काल मीडिया ब्रीफिंग की हैसियत रखता हो। पुष्ट सूचनाओं के अभाव में दुष्प्रचार हावी हो जाता है।

8. 2029 के लोकसभा चुनाव में एनडीए का नेतृत्व करते वक्त मोदी 79 वर्ष के होंगे। यदि वे जीते तो संभावित चौथे कार्यकाल के अंत तक 84 के होंगे। मोदी भारत के सबसे फिट प्रधानमंत्रियों में से एक हैं। लेकिन हर नेता को अपने उत्तराधिकार की रूपरेखा पर भी विचार करना चाहिए।

(ये लेखक के अपने विचार हैं।)

दूरदृष्टि • केवल बातें करने का समय अब जा चुका...

अब जलवायु-आपातकाल के दौर में आ चुके हैं हम

क्लाइमेट

सुनीता नारायण
पर्यावरणविद्
sunita@cseindia.org

उत्तर भारत में इस बारिश के मौसम में हुई तबाही को व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। विशाल क्षेत्र जलमग्न हो गए। घर, स्कूल और अस्पताल तहस-नहस हो गए। सड़कें तबाह हो गई और खेत जलमग्न हो गए। एक के बाद एक बादल फटने की घटनाओं से बड़े-बड़े पहाड़ ढह गए। हालात को देख कर जान-माल के नुकसान का अंदाजा ही लगाया जा सकता है।

इस क्षेत्र में बारिश की यह तीव्रता सामान्य नहीं है। अगस्त के महीने में पंजाब में 31 में से 24 दिन भारी और अत्यंत भारी बारिश हुई। मौसम विभाग 112 मिमी से अधिक बारिश को 'भारी' और 204 मिमी से अधिक बारिश को 'अत्यंत भारी' के तौर पर वर्गीकृत करता है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में भी ऐसे ही हालात थे। हिमाचल प्रदेश ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए, क्योंकि पिछले तीन महीनों में 90% से अधिक दिनों तक वहां भारी और अत्यंत भारी बारिश हुई।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार बादल फटने से बाढ़ आने की 13 घटनाएं हुईं, जबकि 10 अन्य घटनाएं मीडिया द्वारा रिपोर्ट की गईं। जून और अगस्त के महीनों में पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में सामान्य से लगभग 50% अधिक बारिश हुई। अगर इसे साप्ताहिक औसत के रूप में देखें तो तबाही का पैमाना और स्पष्ट हो जाता है। मसलन, पंजाब में अगस्त के अंतिम पखवाड़े में सामान्य से 400% अधिक बारिश हुई। हिमाचल में 28 अगस्त से 3 सितंबर के बीच राज्य में साप्ताहिक औसत से 300% अधिक बारिश हुई। इसी कारण हम इतने पैमाने पर तबाही देख रहे हैं।

आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? निःसंदेह यह एक जलवायु-आपातकाल है। किसी भी कीमत पर विकास चाहने की लापरवाही इस विनाश में नजर आ रही है। जबकि आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन को बढ़ाने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए संघर्ष कर रही है। आगे ये प्रभाव और घातक होते जाएंगे। लेकिन अगर हम समझ पाएं कि सुधार का समय आ गया है तो निर्माण अलग तरीके से किया जा सकता है, ताकि अगली बार बाढ़ या बादल फटने से नुकसान कम हो।

जलवायु कैसे बदल रही है। इसका बड़ा कारण मौसम प्रणाली में बदलाव है। हम जानते हैं गर्मी जितनी होगी, बारिश भी उतनी होगी और अपेक्षाकृत कम दिनों में होगी। पिछले मौसम में हमने यही देखा कि पूरे मौसम की बारिश महज चंद घंटों में ही बरस गई। लेकिन मौसम के इस पैटर्न में और भी बहुत कुछ चल रहा है।

पश्चिमी विक्षोभ प्राकृतिक घटनाएं हैं, जहां भूमध्यसागरीय क्षेत्र से पैदा हुई हवाएं चक्रवात और बारिश लाती हैं। लेकिन इस बार तो मानो पश्चिमी विक्षोभ को बुखार-सा चढ़ गया। आमतौर पर दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान एक या दो विक्षोभ आते हैं, लेकिन इस साल सितंबर के पहले सप्ताह तक 19 विक्षोभ आए। ये हवाएं वास्तव में मानसून की हवाओं से टकरा रही हैं और इसी कारण उत्तरी भारत और पाकिस्तान में विनाशकारी बारिश देखी गई। इसका और कोई कारण स्पष्ट नहीं, सिवाय इसके कि पश्चिमी विक्षोभ आर्कटिक से आने वाली जेट स्ट्रीम हवाओं से जुड़े हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण जैसे-जैसे आर्कटिक वायु तंत्र कमजोर हो रहा है, यह अन्य संबंधित वैश्विक वायु तंत्रों को प्रभावित कर रहा है।

इस साल अरब सागर से पैदा होने वाले वायु तंत्रों में भी कुछ अलग घट रहा है, जो बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून हवाओं को धकेल रहा है। यह कई सारे फैक्टर्स का मिला-जुला परिणाम है- जैसे समुद्र से लेकर आर्कटिक क्षेत्र तक बढ़ती गर्मी और भूमध्य रेखा एवं उत्तरी ध्रुव के बीच तापमान का कम होता अंतर। यह अस्थिरता अब बाढ़ के रूप में हमें प्रभावित कर रही है। लगता है कि प्रकृति हमसे बदला ले रही है।

हम संतुष्ट होकर नहीं बैठ सकते, ना ही जलवायु परिवर्तन को दोष देकर यह बहाना बना सकते कि हम इंसान इसमें क्या कर सकते हैं? यह विनाश ईश्वर का काम नहीं। यह हमारी अपनी करतूत है, और अब यह हमारी दहलीज पर है।

जलवायु परिवर्तन हमारी आर्थिक वृद्धि और लालच के लिए वायुमंडल में छोड़े उत्सर्जन का ही परिणाम है। विकास की होड़ का जो हमारा तरीका है, उससे हम इस समस्या को और जटिल बना रहे हैं। हम बाढ़ संभावित क्षेत्रों में इमारतें बना रहे हैं। जरूरत के अनुसार जल निकासी योजना नहीं बना रहे। पहाड़ी क्षेत्रों में अतिक्रमण कर वहां घर, सड़क, बांध बना रहे हैं। यह सोच ही नहीं रहे कि ये क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से एक्टिव हैं। मैं और भी अधिक कह सकती हूं। लेकिन उम्मीद करती हूं कि जब मैं यह कह रही हूं कि अब बहुत हो चुका तो आप मेरी पीड़ा समझ रहे होंगे। अनुकूलन और विविध तरीके अपनाने की बातें करने का समय गुजर गया। अब हम जलवायु परिवर्तन के युग में जी रहे हैं।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

ब्रांड से सबक | PEPSICO | अमेरिकी फूड एंड बेवरेज कंपनी

दो बार दिवालिया हुई, कई बार बिकी पेप्सी, अब दुनिया की दूसरी बड़ी फूड एंड बेवरेज कंपनी

1917-18 का समय, प्रथम विश्व युद्ध लगभग खात्मे की ओर था। चार साल से अधिक समय तक चले इस युद्ध ने दुनियाभर में खानपान की चीजों की कीमतों पर भारी असर डाला। उन्हीं में से एक थी चीनी। चीनी के दामों में हुई भारी बढ़ोतरी ने एक मशहूर कंपनी को दिवालिया कर दिया। यह कंपनी थी, पेप्सिको (तब इसे पेप्सी-कोला कहा जाता था)। दरअसल कंपनी के मालिक कैलब ब्रैडहम ने चीनी के दाम बढ़ने पर भारी मात्रा में इसका स्टॉक कर लिया, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद उसके दाम तेजी से घटे, जिससे कंपनी को लागत निकालना मुश्किल हो गया। और 1923 में कंपनी दिवालिया हो गई। उस समय कंपनी की वैल्यू करीब 35 हजार डॉलर बची थी। करीब 6 साल बाद ऐसा ही एक और दौर आया जब महामंदी ने कंपनी को फिर से दिवालिया कर दिया। कंपनी बिकी, लेकिन इस बार कंपनी के नए मालिक ने पेप्सी को मजबूती से खड़ा किया। उन्होंने मुख्य प्रतिद्वंद्वी कोकाकोला के बराबर दाम में ही दोगुनी पेप्सी देने जैसे गेमचेंजर कदम उठाकर उसे फिर से बुलंदियों पर पहुंचा दिया। आज यह दुनिया की दूसरी बड़ी फूड एवं बेवरेज कंपनी है। भारत के वेस्टर्न स्नैक्स जैसे पोटेटो चिप्स आदि के बाजार में इसकी हिस्सेदारी करीब 24% है। ब्रांड से सबक में आज पढ़िए कहानी पेप्सिको कंपनी की।

वर्तमान स्थिति

17 लाख करोड़ रु. वैल्यू, 200 देशों में व्यापार

वर्तमान में कंपनी का मूल्य करीब 17 लाख करोड़ रु. है। इस समय यह 200 से अधिक देशों में व्यापार कर रही है। दुनिया भर में हर रोज पेप्सिको के प्रोडक्ट 100 करोड़ से ज्यादा बार खाए/पिए या इस्तेमाल किए जाते हैं। भारत में पेप्सिको का 80% रेवेन्यू स्नैक्स से आता है। केवल 20 फीसदी रेवेन्यू ही पेय पदार्थ यानी इसकी ड्रिंक से आता है। भारत में कंपनी लेज, कुरकुरे, डोरिटोज जैसे स्नैक्स बनाती है। पेप्सिको ने जुलाई 2025 में प्री-बायोटिक कोला लॉन्च किया है। इसमें प्रीबायोटिक फाइबर होगा।

सबक क्यों- 1923 में कंपनी की वैल्यू करीब 35 हजार डॉलर रह गई थी। आज यह 19,100 करोड़ डॉलर से अधिक की कंपनी है।

24% हिस्सेदारी है पेप्सिको की भारत के वेस्टर्न स्नैक्स जैसे पोटेटो चिप्स आदि के बाजार में।

100 करोड़ से ज्यादा बार खाए/पिए या इस्तेमाल किए जाते हैं पेप्सिको के प्रोडक्ट दुनियाभर में रोज।

फार्मेसी की दुकान की यह तस्वीर पेप्सी की शुरुआत करने वाले कैलब ब्रैडहम की है। ब्रैडहम ने डाइजेशन से जुड़े एक पेय के रूप में पेप्सी की शुरुआत की थी।

ऐसे डूबी थी पेप्सिको

1. **मंदी का शिकंजा-** 1929 की भारी मंदी ने उपभोक्ताओं की खरीदने की क्षमता घटा दी, ऐसे में पेय पदार्थ जैसी लग्जरी चीजें बेचना मुश्किल हो गया। इस दौरान पेप्सिको की बिक्री लगभग 90 प्रतिशत तक गिर गई थी।
2. **कमजोर वित्तीय प्रबंधन-** कंपनी के शुरुआती दौर में निवेश कम था, नगदी का प्रवाह कमजोर था। बड़ा झटका आने पर कंपनी संभल नहीं पाई और कर्ज में डूबती चली गई।
3. **कच्चे माल की बढ़ती लागत-** 1920 के दशक में वनीला और चीनी की कीमतें बढ़ीं, जिससे उत्पादन लागत करीब 50% बढ़ गई। कैलेब ने सस्ता फॉर्मूला बनाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे।
4. **मैनेजमेंट की गलतियां-** कैलब ने बिना किसी ठोस प्लानिंग के विस्तार पर फोकस किया, जिससे कंपनी पर कर्ज बढ़ा।

इस तरह की वापसी

1. **चार्ल्स गुथ का अधिग्रहण--** पेप्सी के दोबारा दिवालिया होने पर पहले रॉय सी. मेगार्गल नाम के निवेशक ने 1931 में इसे खरीदा, लेकिन संभाल नहीं सके। फिर लॉफ्ट कैंडी कंपनी के मालिक चार्ल्स गुथ ने पेप्सी को अधिग्रहित कर लिया।
2. **5 सेंट में कोक से दोगुनी पेप्सी-** कोकाकोला जहां 5 सेंट में 6 औंस की बोतल देता था, वहीं गुथ ने उसी दाम पर12 औंस और बाद में 18 औंस की पेप्सी बोतल लॉन्च कर दी। इससे मांग जबर्दस्त बढ़ी।
3. **फ्रीटो-ले के साथ मर्जर-** 1965 में पेप्सी-कोला ने तब की सबसे बड़ी स्नैक्स कंपनी फ्रीटो-ले के साथ मर्जर कर लिया, और पेप्सिको बनी। अब यह एक फूड एवं बेवरेज कंपनी बन गई।
4. **मार्केटिंग इनोवेशन-** पेप्सिको ने माइकल जैक्सन जैसे स्टार को जोड़ा। टीवी, स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप से युवाओं में पहुंच बढ़ाई।

डाइजेशन से जुड़े पेय के रूप में बनी थी पेप्सिको

शुरुआत : एक फार्मासिस्ट ने रखी थी कंपनी की नींव

1893 में कैलब ब्रैडहम नाम के फार्मासिस्ट ने अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में एक पेय बनाया, जिसका नाम रखा ब्रैड्स ड्रिंक। यह एक तरह की डाइजेस्टिव सॉफ्ट ड्रिंक थी, जो लोगों को पसंद आई। 1898 में उन्होंने इसका नाम बदलकर पेप्सी-कोला रख दिया। शुरुआत में इसकी छवि दवा जैसी थी, लेकिन बाद में यह ताजगी देने वाला पेय बन गया।

गिरावट : प्रथम विश्व युद्ध में बढ़ी चीनी की कीमतों ने डुबाई थी कंपनी

पेप्सी में पहली गिरावट 1920-21 में पहले विश्व युद्ध के दौरान आई जब चीनी की कीमतें अचानक बढ़ीं। ब्रैडहम ने बड़ी मात्रा में महंगे दामों में चीनी स्टॉक कर ली, लेकिन जब कीमतें गिरने लगीं तो बड़ा घाटा हुआ और कंपनी 1923 में दिवालिया हो गई। ऐसे ही 1929 में आई भारी मंदी ने मांग कमजोर की। बार-बार मालिक बदले और 1931 में फिर दिवालिया हुई।

ऐसे पड़ा नाम : पेप्सी शब्द पेप्सिन और डायसपेप्सिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पाचन के लिए फायदेमंद। कोला शब्द, कोला नट्स से लिया गया है।

सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी : इसके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वियों में कोका-कोला, डॉ. पेपर, नेस्ले और रेडबुल जैसी कंपनियां और उनके उत्पाद हैं।

पीपुल भास्कर | जस्टिस बीआर गवई | भारत के मुख्य न्यायाधीश

पिता के सपने को पूरा करने के लिए वकील बने, आर्किटेक्ट बनना चाहते थे सीजेआई गवई

1 दिसंबर 2014, गुजरात के सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले की सुनवाई कर रहे सीबीआई जज बीएच लोया नागपुर में एक शादी समारोह में गए थे। यहां हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद एक मैगजीन ने इस पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें संदिग्धता के पहलुओं को बताया गया। इस रिपोर्ट के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट में जज रहते हुए जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सुनील शुकरे ने पूरे मामले को लेकर एक प्रेस बयान जारी किया, जिसमें जस्टिस गवई ने कहा कि वे शादी समारोह में जस्टिस लोया के साथ थे। उनकी मृत्यु के समय अस्पताल भी गए। इस मामले में कोई संदिग्धता नहीं थी। उनकी मृत्यु प्राकृतिक थी। जस्टिस गवई का यह बयान उनके स्पष्ट दृष्टिकोण और न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) गवई का बचपन काफी कठिनाई भरा रहा। उनकी शुरुआती पढ़ाई ऐसे स्कूलों में हुई जहां बच्चों के बैठने के लिए बेंच तक नहीं होती थीं, उन्हें फर्श में बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती थी।

एक साक्षात्कार में उनकी मां कमलताई बताती हैं, उनके पति यानी जस्टिस बीआर गवई के पिता, समाजसेवी थे और अक्सर घर से बाहर रहते थे, जिससे घर के कामों में जस्टिस गवई मां की पूरी मदद करते। जून 2025 में नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जस्टिस गवई ने बताया कि बचपन में उनका सपना आर्किटेक्ट बनने का था, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि वे वकालत करें। क्योंकि उनके पिता भी जज बनना चाहते थे, लेकिन बन नहीं पाए।

चर्चा में क्यों- भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति को दोबारा स्थापित करने की याचिका पर की गई उनकी टिप्पणी से विवाद शुरू हो गया है।

पत्नी और बेटे के साथ स्वर्ण मंदिर के दर्शन के दौरान सीजेआई गवई

सीजेआई गवई मानते हैं न्यायाधीशों द्वारा रिटायरमेंट के बाद सरकारी पद ले लेना या चुनाव लड़ना, जनता के न्यायपालिका में विश्वास को कमजोर करता है

जन्म : 24 नवंबर 1960 अमरावती, महाराष्ट्र
शिक्षा : नागपुर यूनिवर्सिटी से बी.ए, एल.एल.बी
परिवार : पत्नी- तेजस्विनी गवई, एक बेटा।

शुरुआत
आंबेडकर आंदोलन के प्रमुख नेता थे पिता

सीजेआई बीआर गवई का जन्म अमरावती जिले के फ्रेजरपुर इलाके में आरएस गवई और कमलताई गवई के घर हुआ था। पिता आंबेडकर आंदोलन के प्रमुख नेता थे, जो बाद में बिहार, सिक्किम और केरल के राज्यपाल रहे। मां, स्कूल शिक्षिका थीं। जस्टिस गवई तीन भाई-बहन हैं। उनके छोटे भाई राजेंद्र गवई राजनीति में सक्रिय हैं जबकि बहन शिक्षा के क्षेत्र में।

जीवनसाथी
तेजस्विनी गवई से किया है विवाह

जस्टिस बीआर गवई का विवाह तेजस्विनी गवई के साथ हुआ है। सार्वजनिक जीवन से दूरी रखने वाली तेजस्विनी गवई ने वर्षों तक उनके न्यायिक करियर के दबाव और चुनौतियों में मजबूती से उनका साथ दिया। जस्टिस गवई ने कई बार स्वीकार किया है कि उनके न्यायिक दायित्व इतने व्यापक रहे कि परिवार को पर्याप्त समय नहीं दे पाए।

करियर
सरकारी वकील से सीजेआई के पद तक

कानूनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वे 1985 में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच से वकालत के पेशे से जुड़े। हालांकि उनके करियर में असली मोड़ 2000 में आया जब उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया। इसके बाद 2003 में वे स्थायी न्यायाधीश बने। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और 2025 में मुख्य न्यायाधीश बने।

रोचक : 300 से ज्यादा फैसले लिखे, 700 बेंचों में शामिल रह चुके हैं सीजेआई गवई

खास : मातृभाषा में पढ़ाई करने के समर्थक हैं

- पहले बुद्धिस्ट और दलित समुदाय के दूसरे व्यक्ति हैं जो सीजेआई के पद तक पहुंचे हैं।
- मातृभाषा में शिक्षा के समर्थक हैं। उन्होंने कहा अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करने से मूल अवधारणाओं की समझ बेहतर होती है।
- उन्होंने अभी तक 300 से अधिक निर्णय लिखे हैं करीब 700 बेंचों में भाग लिया है।

चर्चित फैसले : नोटबंदी को बताया सही, बुलडोजर कार्रवाई रोकी

- **नोटबंदी को वैध बताया** : 2023 में जस्टिस गवई ने 2016 की नोटबंदी योजना को 4:1 के बहुमत से वैध ठहराते हुए कहा कि यह निर्णय केंद्र सरकार और आरबीआई के बीच परामर्श के बाद लिया गया था। यह अनुपातिकता की कसौटी पर खरा उतरता है।
- **बुलडोजर कार्रवाई पर रोक** : 2024 में जस्टिस गवई व जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि केवल आरोपी या दोषी होने के आधार पर संपत्ति ध्वस्त करना असंवैधानिक है।
- **राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की रिहाई** 2022 में जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने 30 साल से जेल में बंद छह दोषियों की रिहाई का आदेश यह मानते हुए दिया कि तमिलनाडु सरकार की सिफारिश पर राज्यपाल ने कोई कार्रवाई नहीं की थी।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

संपादकीय

अमृतवर्षा संपादकीय

सुप्रीम कोर्ट की खरी-खरी

भारत के लोकतन्त्र को सर्वदा लोकोन्मुखी बनाये रखने के लिए ही हमारे संविधान निमार्ताओं ने चुनाव आयोग का गठन किया था और इसे सरकार का अंग न बनाकर स्वतन्त्र सत्ता सौंपी। इसका मन्तव्य यही था कि भारत की चुनी हुई सरकार हर हालत में आम लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करे। यह इच्छा न केवल बहुमत के शासन के रूप में प्रतिष्ठापित होनी चाहिए, बल्कि अल्पमत में रहने वाले राजनीतिक दलों की भी इसमें पूरी भागीदारी हो। इसके लिए हमारे संविधान निमार्ताओं ने संसदीय प्रणाली को अपनाया जिसमें सरकारें अल्पमत की बराबर की भागीदारी के साथ ही चलती हैं। संसद में जब किसी सरकारी विधेयक पर बहस या चर्चा कराई जाती है तो उसका आशय यही होता है कि उस पर विपक्ष में बैठे लोगों की राय व सुझाव भी आ सके जिससे हर विधेयक जनहित की दृष्टि से सम्पूर्णता पा सके। चुनाव आयोग लोकतन्त्र की यही आधारभूमि बनाकर सौंपता है और तय करता है कि भारत के प्रत्येक वयस्क मतदाता की इसमें शिरकत उसे मिले एक वोट के अधिकार के माध्यम से हो। भारत के लोकतन्त्र में इस एक वोट के अधिकार की बहुत बड़ी कीमत होती है, बल्कि यह अमूल्य होती है क्योंकि इसी की मार्फत भारत का सामान्य नागरिक लोकतान्त्रिक व्यवस्था का मालिक बनता है। इस अधिकार की रक्षा करने का दायित्व चुनाव आयोग को सौंपा गया अतः 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने वाले हर भारतीय नागरिक को मतदाता बनाने का अधिकार चुनाव आयोग के पास होता है परन्तु यह अधिकार समावेशी नजरिये के साथ इस प्रकार लागू होना चाहिए कि भारत का कोई भी वैध नागरिक इस अधिकार से वंचित न रहे। वर्तमान में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में कराई जा रही मतदाता गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया का मामला सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) में चल रहा है और इस बारे में सभी संवैधानिक पक्षों का क्रमवार खुलासा हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि चुनाव आयोग हर भारतीय वयस्क नागरिक को मतदाता का दर्जा दे और इससे कोई भी व्यक्ति बाहर न होने पाये साथ ही अवैध लोग मतदाता सूची में शामिल न हो पायें। यह कार्य जरा भी दुष्कर नहीं है। 1952 के स्वतन्त्र भारत के पहले आम चुनावों से आयोग यह कार्य करता आ रहा है। इसके काम में कुछ खामियां भी रही होंगी मगर आमतौर पर भारत के नागरिक उसके कामकाज से सन्तुष्ट रहे। मतदाता सूची बनाने का काम चुनाव आयोग लोकमित्र बन कर ही करता है और लोगों को प्रेरणा देता है कि वे अपने इस अधिकार के अधिकारी बन कर भारत के लोकतन्त्र को मजबूत करें और अधिक से अधिक संख्या में मतदान में हिस्सा लें। मतदाता सूचियों को पारदर्शी बनाने की गरज से ही चुनाव आयोग ने 90 के दशक में प्रत्येक मतदाता को वोटर पहचान पत्र जारी करने की परंपरा शुरू की जो बहुत सफल रही क्योंकि इसमें मतदाता की फोटो लगी होती है और उसका पूरा नाम-पता होता है। मगर इसके बावजूद मतदाता सूची में दोहरीकरण की समस्या भी विद्यमान रही। साथ ही यह संसार छोड़ कर जाने वाले मतदाताओं के नाम काटने में गफलत पाई गई। चुनाव आयोग इसी त्रुटि को दूर करने के लिए मतदता सूची का गहन पुनरीक्षण कर रहा है। मगर इसमें इसने शुरू में जो शर्तें लगाई उन्हें लेकर पूरे भारत में भारी विवाद पैदा हुआ और मामला सर्वोच्च न्यायालय तक आ पहुंचा। सर्वोच्च न्यायालय इस बारे में पूरी तरह तथ्य परक रुख अख्तियार कर रहा है और चुनाव आयोग को समझा रहा है कि वह अपने मूल कार्य मतदाता सूची बनाने से ताल्लुक रखे न कि मतदाताओं की नागरिकता की जांच करे क्योंकि संविधानतः यह कार्य गृह मन्त्रालय का होता है। इसी वजह से सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि जिस वयस्क नागरिक के पास भी आधार कार्ड है उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज किया जाये। वह भारत का नागरिक हो इसकी गारंटी गृह मन्त्रालय देगा। जाहिर है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, मतदाता नहीं बन सकता है परन्तु मतदाता की नागरिकता को चुनौती देने का काम राज्य का है। अब बिहार की मतदाता सूची को लेकर गहन पुनरीक्षण का काम इस महीने सितम्बर में पूरा हो जायेगा और आगामी 1 अक्तूबर को चुनाव आयोग बिहार की पुनरीक्षित मतदाता सूची प्रकाशित कर देगा। अभी फिलहाल जो चुनाव आयोग ने फौरी मतदाता सूची बनाई है उसमें राज्य के 65 लाख मतदाताओं के नाम काट दिये गये हैं। इसकी वजह कुछ लाख मतदाताओं का संसार छोड़ कर चला जाना बताया गया है और कुछ लाख का दूसरे राज्यों में पलायन करके बसना तथा कुछ का मतदाता सूची में दोहरीकरण लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में ही चुनाव आयोग के इन आंकड़ों को सप्रमाण चुनौती दी गई और कहा गया कि चुनाव आयोग जिन मतदाताओं को मृत बता रहा है उनमें से बहुत से जीवित हैं। विपक्ष चुनाव आयोग पर यह खुलमखुल्ला आरोप लगा रहा है कि गहन पुनरीक्षण के नाम पर समाज के गरीब, अल्पसंख्यक व पिछड़े समुदाय के मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से उड़ाने का षड्यन्त्र रचा जा रहा है। यह आरोप निश्चित रूप से बहुत गंभीर है क्योंकि हमारे संविधान निमार्ताओं ने भारत के हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के एक वोट का अधिकार दिया है। भारत में टाटा या बिड़ला के वोट की भी कीमत वही है जो किसी छप्पर में रहने वाले मजदूर के वोट की। इसीलिए तो यह वोट अमूल्य कहा जाता है। अतः सर्वोच्च न्यायालय ने विगत दिन इस मामले की सुनवाई करते हुए खरी-खरी सुनाई और कहा कि यदि गहन पुनरीक्षित सूची में भी किसी प्रकार की विसंगति पाई गई तो वह इस पूरी प्रक्रिया को ही राष्ट्रीय स्तर पर रद्द कर देगा।

संस्थापक संपादकः स्व. पारसनाथ तिवारी
स्वत्वाधिकारी एवं प्रकाशक रीता तिवारी,मुद्रक कुंज बिहारी के द्वारा आर डी प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स प्रा. लि., प्लॉट नं- सी 16-17 पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया, पटना-800013 से मुद्रित व B-14 जगत भवानी अपार्टमेंट, एसपी सिन्हा लेन, बोरिंग कैनाल रोड, पटना-1 से प्रकाशित
संपादक-बन बिहारी
दूरभाष - 9905463571, 8757425017, धनबाद कार्यालयः मास्टर पाड़ा जे.सी. मल्लिक रोड, हीरापुर, धनबाद दूरभाष - 2204991, दिल्ली कार्यालयः बी-49, जैन मंदिर गली, शकरपुर मेन मार्केट, दिल्ली-110092, फोन नं.- 011-22055208, आर.एन.आई नं. 44420/87
ईमेलः amritvarshanews2015@gmail.com

आधुनिक, सशक्त व शक्तिशाली नए भारत के शिल्पकार प्रधानमंत्री 'नरेन्द्र मोदी'

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नया भारत अब अगली पीढ़ी के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण करने में दिन-रात जुटा हुआ है। जो कार्य स्थिरता और दीर्घकालिक सोच से प्रेरित है। नरेन्द्र मोदी का यह प्रयास आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव तैयार करने का कार्य बखूबी कर रहा है।

दीपक कुमार त्यागी

भारत में लंबे समय तक लगातार सत्ता में रहते हुए सेवा करने वाले राजनेता, राष्ट्रहित और जनहित को हमेशा सर्वोपरि रखने वाले, मां भारती के सच्चे-सपूत, नए आधुनिक सशक्त शक्तिशाली भारत के शिल्पकार और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का 17 सितंबर को जन्मदिन है। मैं उन्हें जन्मदिन की बहुत-बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप दीघार्यु हों और सदैव स्वस्थ एवं प्रसन्न रहें और देश का नाम रोशन करते रहें और हम भारतवासियों का मार्गदर्शन करते रहें। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने कार्यों के दम पर अब आधुनिक, सशक्त, शक्तिशाली नए भारत के शिल्पकार बन चुकें हैं, यह तथ्य अब किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। कोई भी व्यक्ति राजनीतिक लाभ लेने के चलते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भारत के नव निर्माण के लिए दिये गये योगदान को कमतर आंकने का कार्य कर सकता है। लेकिन धरातल पर सच्चाई यह है कि नरेन्द्र मोदी ने देश में आजादी के दशकों बाद दूरदराज के दुर्गम इलाकों तक में भी हम भारतीयों के लिए विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का कार्य किया है, जो काबिले-तारीफ व अचंभित करने वाला है। नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में आज बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव हो रहा है। रेलवे, हाईवे, एक्सप्रेस-वे, बंदरगाह और हवाई अड्डों जैसे क्षेत्रों में बेहतरीन विश्व स्तरीय ढांचा तैयार किया जा रहा है। अभी तक के तैयार ढांचे ने ही देशवासियों के जीवन को बेहद सरल बनाते हुए देश के विकास को तेजी गति देते हुए धरातल पर समृद्धि को बढ़ावा देने का कार्य कर दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नया भारत अब अगली पीढ़ी के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण करने में दिन-रात जुटा हुआ है। जो कार्य स्थिरता और दीर्घकालिक सोच से प्रेरित है। नरेन्द्र मोदी का यह प्रयास आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव तैयार करने का कार्य बखूबी कर रहा है। देश में आधुनिक रेलवे स्टेशन, बंदरगाह, सड़क व रोपवे आदि जगह-जगह बन रहे हैं। पूरे देश में सड़क, हवाई, रेल व जल मार्ग से यात्रा व माल ढुलाई आदि की सुविधा को बेहतर किया जा रहा है। वैसे भी नरेन्द्र मोदी कहते हैं कि - स्मार्ट शहर, सुरक्षित सड़कें और आसान यात्रा झ्र यही है नए भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर वादा। जिस वादे को नरेन्द्र मोदी धरातल पर साकार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण को वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम मानते हैं। देश की सीमाओं की रक्षा की बात करें तो नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज देश के वीर योद्धाओं के हाथ दुश्मन पर कार्रवाई के लिए पूरी आजादी के साथ खुले हुए हैं, जिसकी बानगी देश व दुनिया के लोग सर्जिकल स्ट्राइक व अभी हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर में देख चुके हैं। वहीं आम-जनमानस के हित के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें मुख्य रूप से जन धन योजना, कौशल भारत मिशन, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, सांसद आदर्श ग्राम योजना, श्रमेव जयते योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हृदय योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, उजाला योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री ज्योति ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, स्मार्ट सिटी योजना, अमृत योजना, डिजिटल इंडिया मिशन, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना, उदय, स्टार्ट- अप इंडिया, सेतु भारतम योजना, स्टैंड अप इंडिया, ग्रामोदय से भारत उदय, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, नमामि गंगे योजना, पीएम सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना, प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान भारत योजना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना आदि योजनाएं हम भारतवासियों के जीवन स्तर में सुधार करते हुए उसे बेहतर बनाने कार्य कर रही हैं। वैसे कोई नेता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी में लाख कमियां निकाले लेकिन जनता की अदालत की सच्चाई यह है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जन-जन की आशा और राष्ट्र की आकांक्षा के प्रतीक बन चुकें हैं। देश व दुनिया के लोग देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ओजस्वी नेतृत्व में भारत का बहुत तेजी से सर्वांगीण विकास हो रहा है। नया भारत अब आत्मनिर्भरता, विकास और वैश्विक सम्मान की नई ऊंचाइयों को छूने का कार्य कर रहा है। मोदी के संकल्पित नेतृत्व में ही विकसित भारत की दिशा में राष्ट्र तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी के साथ मजबूत होती जा रही है, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के ताकतवर देशों को पीछे छोड़ रही है। देश में बहुत ही तेजी से विश्व स्तरीय सड़कों व एक्सप्रेस-वे का जाल बिछा कर के विकास पथ का निर्माण करते हुए विकास को तेज गति दी जा रही है, आज हमारा प्यारा देश भारत दुनिया के निवेशकों की पसंदीदा जगह बनता जा रहा है, भारत में अब तेजी से विदेशी कंपनियों के बड़े-बड़े कल-कारखाने खुलने लगें हैं। आर्थिक स्तर के मोर्चे के साथ-साथ सामरिक स्तर पर भी अब तो दुनिया भारत का लोहा मानने लगी है, दुनिया सर्जिकल स्ट्राइक व ऑपरेशन सिंदूर में देश के वीर जांबाजों का दमखम देख चुकी है। वैसे भी देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी कार्यशैली के बलबूते देश की राजनीति को अपने इर्दगिर्द केन्द्रित रखते हुए आम जनमानस के दिलोदिमाग पर छा जाने का कार्य बेहद ही सफलता के साथ किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दुनिया की उन शख्सियतों में शुमार हैं, जिन्होंने अपनी कार्यशैली, मेहनत, वाकपटुता, मंत्रमुग्ध कर देने वाली करिश्माई भाषण शैली, राष्ट्रहित व जनहित के कार्यों के बलबूते लोगों के दिलों में जगह बनाने का कार्य किया है। जिसके चलते ही नरेन्द्र मोदी राजनीति के जबरदस्त प्रतिस्पर्धा वाले क्षेत्र में भी पिछले कई दशकों से लगातार महत्वपूर्ण पदों पर विराजमान हैं। वैसे तो नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल में ही काम के दम पर एक बहुत लंबी रेखा खींचने का कार्य किया था, लेकिन वर्ष 2014 में जब नरेन्द्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री पद का दायित्व सम्हालने का कार्य किया था, उसके बाद तो उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर ही नहीं देखा है। जिसके बाद से ही नरेन्द्र मोदी की लोकप्रियता में दिन-प्रतिदिन तेजी से इजाफा हुआ है और वह भारत के साथ-साथ दुनिया भर में लोगों की पसंदीदा ताकतवर राजनीतिक शख्सियत बनकर के उभरे हैं, इसकी एक बानगी अभी हाल ही में दुनिया ने अमेरिका से टैरिफ विवाद के समय और चीन दौरे के समय देखी है, विवाद के बाद नरेन्द्र मोदी को अपने से दूर होता देखकर अब तो दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प तक भी नरेन्द्र मोदी को अपना दोस्त बता रहे हैं और महान बता रहे हैं।

नेपाल का घटनाक्रम और भारत

हमारे पड़ोस में एक के बाद एक ऐसे बुत तोड़े जा रहे हैं। 2022 में गम्भीर आर्थिक संकट के बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़ भाग गए थे। एक और पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंघे और 5 पूर्व मंत्रियों को जेल की सजा सुनाई गई थी। कई नेताओं के घर जला दिए गए। लगभग एक साल पहले बांग्लादेश में ऐसा ही विद्रोह हुआ था जब ढाका में हिंसक प्रदर्शनों के बीच शेख हसीना को भागना पड़ा था और भारत ने उन्हें शरण दी थी। उनका भी घर जला दिया गया था। वहां 90 दिनों में चुनाव होने थे, पर बिना चुनाव लड़े मोहम्मद यूनुस सत्ता सम्भाले हुए हैं जिससे फिर असंतोष उभर रहा है। पाकिस्तान, मालदीव, म्यांमार और अफगानिस्तान की हालत पहले ही अस्थिर है और अब नेपाल में लगभग क्रान्ति होकर हटी है। कुछ सामान्यता लौट आई है और सुशीला कार्की सेना के हस्तक्षेप से प्रधानमंत्री बन गई है। संसद को भंगकर दिया गया है और 6 महीने में चुनाव करवाने का वायदा किया गया है, पर नेपाल का घटनाक्रम, हमारे पूर्व राजदूत रणजीत राय के अनुसार बांग्लादेश से भी अधिक खतरनाक है। प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। 70 के करीब लोग सेना या पुलिस की फायरिंग में मारे गए हैं। काठमांडौ विश्वविद्यालय के दिनेश काफले ने इसे ओली की अश्लील क्रूरता कहा है। इन मौतों के बाद कई मंत्रियों के घर जला दिए गए। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर दोउबा और उनकी पत्नी की सार्वजनिक पिटाई हो चुकी है। एक और पूर्व प्रधानमंत्री झलानाथ खनाल की भी पिटाई की गई और उनकी पत्नी को आग लगा दी गई। उनके घर को भी आग लगा दी गई। ओली समेत कई मंत्रियों और पूर्व मंत्रियों को सेना ने हैलीकाप्टरों द्वारा बचाया है और भी गम्भीर है कि संसद भवन, प्रधानमंत्री निवास, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति भवन को आग लगा दी गई। पाकिस्तान में ऐसा हो चुका है जब इमरान खान के समर्थकों ने सेना के संस्थानों पर हमले कर दिए थे। पाकिस्तान में एक बड़ा वर्ग सेना को देश के दुर्भाग्य के लिए ज़िम्मेवार ठहराता है। नेपाल के युवा जिन्हें जेन जैड (18 से 25 वर्ष की पीढ़ी) कहा जा रहा है, समझता है कि सारा राजनीतिक वर्ग ही भ्रष्ट है और उनके दुर्भाग्य के लिए ज़िम्मेवार है। संसद भवन और सुप्रीम कोर्ट को जलाने के प्रयास बताते हैं कि युवाओं का लोकतांत्रिक व्यवस्था से भरोसा उठ गया है। सिर्फ. ओली सरकार को ही नहीं राजनीतिक और प्रशासनिक सत्ता के प्रतीकों को ही विध्वस्त कर दिया गया। वह समझते हैं कि वोट के द्वारा वही बदनाम नेता बार-बार सत्ता में आ रहे हैं। बदलाव कुछ नहीं होता, इसलिए सोशल मीडिया पर लगाई पाबंदी के बाद भड़क गए और नियंत्रण से बाहर हो गए।

पंजाब में प्रवासी मजदूरों के खिलाफ घृणा अभियान जोरों पर

राकेश सैन

पंजाब में दूसरे राज्यों से आए मजदूरों का उड़ाया जाने वाला उपहास अब उनके विरोध यहां तक कि उन्हें पंजाब से बाहर करने की मांग तक पहुंच गया है। इन मजदूरों से खैनी-गुटका खाने से लेकर हर छोटे-मोटे अपराधों से इनका नाम जोड़ कर और बाहरी राज्यों से आए अपराधी किस्म के लोगों द्वारा किए गए घिनौने कृत्यों की आड़ में प्रदेश में घृणा अभियान चलाया जा रहा है। गत दिनों 13 सितम्बर को होशियारपुर में दूसरे राज्य से आए एक व्यक्ति ने 5 वर्षीय हरवीर के साथ दानवों जैसा व्यवहार किया और बाद में उसकी नृशंस हत्या कर दी। पुलिस ने इसके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है परन्तु इस घटना से उपजे आक्रोश की आड़ में कट्टरपंथी शक्तियों ने अपना घिनौना खेल खेलना शुरू कर दिया है। अब राज्य में कई स्थानों पर पंचायतें दूसरे राज्यों से आने वाले श्रमिकों के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर रही हैं। केवल होशियारपुर में ही 25 पंचायतें इस तरह का प्रस्ताव पारित कर चुकी हैं जिसमें बाहर से आए श्रमिकों को काम न देने, रहने को मकान न देने, उनके आधार कार्ड व राशन कार्ड न बना कर देने की बात कही गई है। बठिंडा में भी गहरी देवी नगर की पंचायत ने इस तरह का प्रस्ताव पारित किया है। पंजाब में इन दिनों सोशल मीडिया पर बाहरी राज्यों से आए इन मजदूरों के खिलाफ घृणा अभियान चलाया जा रहा है, जिनमें मेहनती मजदूरों की छवि को अपराधिक बना कर पेश किया जा रहा है। इन मजदूरों के खिलाफ विषवमन करने वालों में कनाडा, अमेरिका, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया में बैठे अलगाववादी लोग सबसे आगे हैं। इसी के चलते पंजाब में प्रवासी मजदूरों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार की समस्या गंभीर रूप ले चुकी है। उत्तर प्रदेश और बिहार से आए प्रवासी मजदूरों को गाँवों में काम करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने विधानसभा चुनाव प्रचार अभिचान में उत्तर प्रदेश और बिहार से आने वाले प्रवासी मजदूरों को अपमानजनक अर्थ में ह्यभैयाह्न कहा था। दुखद बात यह है कि उस समय मंच पर मौजूद पार्टी की नेता प्रियंका गांधी ने चन्नी के इस शर्मनाक ब्यान पर तालियां बजाई थीं। ऐसा ही एक मामला आया है मोहाली से, जहाँ एक गाँव से प्रवासी मजदूरों को भगाया गया। मोहाली जिले के जंडपुर गाँव में प्रवासी मजदूरों को घर किराए पर लेने की अनुमति नहीं है। गाँव में उनके लिए 11 तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिनमें रात 9 बजे के बाद बाहर जाने पर प्रतिबंध, धूम्रपान और तम्बाकू चबाने पर पाबंदी, और उनके कपड़ों को लेकर सख्त नियम शामिल हैं। गाँव के गुरुद्वारा कमेटी ने यह फैसला लिया कि प्रवासी मजदूर अब गाँवों में नहीं रह सकते। इसी साल अगस्त में मुंडो संगतियां गाँव से प्रवासी मजदूरों को निकालने का सिलसिला शुरू हुआ। जब मजदूरों को काम से निकाल कर गाँव से बाहर कर दिया गया, तो यह मामला पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय तक पहुँचा। वैभव वत्स नामक एक व्यक्ति ने प्रवासी मजदूरों को अवैध रूप से निकालने के खिलाफ याचिका दायर की, जिससे यह मामला कानूनी चर्चा में आया। दूसरी तरफ, प्रवासी मजदूरों का दर्द है कि वे अपनी मेहनत से पैसे कमाते हैं, लेकिन उन्हें यहां सम्मान नहीं मिलता। मजदूरों को भैया कहकर अपमानित किया जाता है और उनके सांवले रंग के कारण उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता है। लुधियाना, जालन्धर, अमृतसर जैसे उद्योगिक नगरों में अपराधी तत्व आटो चालकों, रेहड़ी-फड़ी वालों, फेरी वालों को अकेला देख कर लूट लेते हैं। वेतन वाले दिन यह श्रमिक इन अपराधी तत्वों का विशेष लक्ष्य होते हैं और फैक्ट्री से घर जाते समय इनको रास्ते में लूट लिया जाता है। पुलिस प्रशासन इनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं देता और कई बार तो प्राथमिकी भी दर्ज नहीं की जाती। बहुत सी श्रमिक बस्तियां सडक, बिजली, पानी, सीवरेज जैसे मौलिक सुविधाओं से वंचित हैं और इन श्रमिकों को नारकीय जीवन जीना पड़ रहा है। राजनीतिक दल बहला फुसला कर इनसे वोटें तो हासिल कर लेते हैं परंतु असंगठित होने के कारण इनकी मांगों पर गौर तक नहीं किया जाता। समय की मांग है कि आपराधिक कृत्यों पर सख्त कार्रवाई करते हुए श्रमिक वर्ग के खिलाफ अभियान चलाने वाली शक्तियों के खिलाफ सख्ती से पेश आया जाए और पंजाब में निवास कर रहे बाहरी राज्यों के श्रमिकों को पूरी सुरक्षा व नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। प्रदेश में चले इस अभियान को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि प्रदेश पिछले कई दशकों से अलगाववाद की आग में जल रहा है। बिखराव की इस आंच में अलाव डालने का काम देश-विदेश में बैठी समाज विरोधी शक्तियां कर रही हैं। सोशल मीडिया पर चल रहे इस अभियान के एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम हैण्डलरों के थ्रेड ही चेक कर लिए जाएं तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि इसके पीछे कौन हैं।

राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी खत्म नहीं हो पाया गहलोत बनाम पायलट का मामला

राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा सचिन पायलट सहित सभी आरोपियों को क्लीन चिट दिए जाने के बाद अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट की लड़ाई का अंत हो जाएगा। वैसे भी अब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार नहीं है तो कुर्सी के लिए लड़ाई का कोई मतलब नहीं है।

संतोष कुमार पाठक

वर्ष 2020 में राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी ही सरकार के उपमुख्यमंत्री एवं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट पर भाजपा के साथ मिलकर सरकार गिराने और विधायकों की खरीद फरोख्त करने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। मामला एसओजी और एसीबी तक पहुंचा। लेकिन उस समय के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा दर्ज करवाए गए मामले में जांच करने के बाद एसीबी ने अदालत के सामने एफआर लगाते हुए यह कह दिया कि उन्हें कोई सबूत नहीं मिला है और यह पूरा मामला फर्जी है। जांच एजेंसी की रिपोर्ट के बाद राजस्थान हाई कोर्ट ने मामले को खारिज करते हुए सभी आरोपियों को क्लीन चिट दे दी है। यह माना जा रहा था कि राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा सचिन पायलट सहित सभी आरोपियों को क्लीन चिट दिए जाने के बाद अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट की लड़ाई का अंत हो जाएगा। वैसे भी अब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार नहीं है तो कुर्सी के लिए लड़ाई का कोई मतलब नहीं है। अदालत का फैसला आने के बाद सचिन पायलट ने सधे हुए अंदाज में संतुलित प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, न्यायपालिका में सभी का भरोसा है। न्यायपालिका में कभी-कभी देरी हो जाती है, लेकिन उन्हें लगता है देश की न्याय पालिका सुदृढ है, मजबूत है। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें नहीं लगता कि जब अदालत का निर्णय आ गया है, तो अब कुछ बचा है कहने को। न्यायपालिका में सबका भरोसा है। अदालत द्वारा क्लीन चिट मिलने के बाद यह माना जा रहा था कि सचिन पायलट को जल्द ही कांग्रेस संगठन में नई और बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। खबरें तो यहां तक आ रही है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, दोनों नेताओं ने सचिन पायलट से उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय संगठन महासचिव बनाने का वादा कर रखा है। आपको बता दें कि, कांग्रेस संगठन में राष्ट्रीय संगठन महासचिव का पद राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद दूसरा सबसे ताकतवर पद माना जाता है। इसी पद को छोड़कर वर्ष 2018 में अशोक गहलोत राजस्थान का मुख्यमंत्री बनकर जयपुर चले गए थे और वर्तमान में इस पद पर केसी वेणुगोपाल बैठे हुए हैं। लेकिन अदालत का फैसला आने के बाद अशोक गहलोत ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर लिखा, " राजस्थान में 2020 में कांग्रेस सरकार गिराने की साज़िश करने वाले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एसीबी द्वारा एक मुकदमे में एफआर लगाने पर बड़ी-बड़ी बातें कह रहे हैं। वो यह बताएं कि यदि इतने ही ईमानदार हैं तो विधायकों से खरीद-फरोख्त की बात करने वाले ऑडियो की जांच के लिए आज तक वॉइस सैंपल क्यों नहीं दिया? संजय जैन वाले मुकदमे में वो बार-बार अदालत में वॉइस सैंपल देने का विरोध क्यों करते हैं? यदि वो ईमानदार हैं तो एक बार वॉइस सैंपल देकर अपनी ईमानदारी साबित करें। सरकार बदलने के बाद पहले संजीवनी केस और अब दूसरे मामलों में जांच एजेंसियों पर दबाव डालकर तथ्य तोड़े-मरोड़कर एफआर लगाई जा रही है जिससे कोर्ट के सामने कोई और चारा नहीं बचता है। जुलाई-अगस्त 2020 में सरकार गिराने के लिए 30 विधायकों के समर्थन वापसी के दावे, 20 विधायकों को मानेसर ले जाना, अमित शाह, धर्मेन्द्र प्रधान और जफर इस्लाम से मुलाकात, कांग्रेस नेताओं पर ईडी, आईटी और सीबीआई के छापे, विधायकों को रिश्वत के मामले, बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों के ऊपर अचानक मुकदमे समेत सभी यादें प्रदेशवासियों के मन में ताजा हैं। सांसद हनुमान बेनीवाल ने ही कुछ दिन पूर्व ही सरकार गिराने के संदर्भ में बयान दिया था कि उस समय वो भाजपा का सहयोग कर रहे थे।तब महीनेभर पहले मध्य प्रदेश में जैसे सरकार गिराई गई थी वही प्रयास राजस्थान में हुए इसमें किसी को शक नहीं है। कांग्रेस आलाकमान और जनता के आशीर्वाद से वह प्रयास असफल हुआ था और हमारी सरकार 5 साल चली। इससे गजेन्द्र सिंह शेखावत समेत सभी लोग मन मसोस कर रह गए। इस प्रकार गजेन्द्र सिंह शेखावत चुनी हुई सरकार को गिराने के प्रयास के इस पाप से कभी मुक्त नहीं हो सकते। अपने इस पोस्ट में अशोक गहलोत ने अमित शाह, गजेंद्र सिंह शेखावत और बीजेपी के अन्य नेताओं के नाम लेकर यह साबित करने की कोशिश की है कि वर्ष 2020 में उनकी सरकार गिराने की साजिश हुई थी और इस बात पर वो आज भी कायम है। इतना ही नहीं 20 विधायकों को मानेसर ले जाने की याद दिलाकर उन्होंने बिना नाम लिए एक बार फिर से सचिन पायलट पर निशाना साधा है क्योंकि यह सब जानते हैं कि अपने समर्थक विधायकों के साथ पायलट ही मानेसर गए थे। यानी अदालत के फैसले के बाद भी अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट की लड़ाई का अंत फिलहाल तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको याद दिला दें कि, वर्ष 2018 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी के करीबी सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनने के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। लेकिन अशोक गहलोत ने सबको चौंकाते हुए सोनिया गांधी और उनके आसपास के बुजुर्ग नेताओं को साध लिया। पायलट को मजबूरी में अशोक गहलोत की सरकार में उपमुख्यमंत्री का पद स्वीकार करना पड़ा। वर्ष 2020 में मध्य प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे बुजुर्ग नेताओं से परेशान राहुल गांधी के एक और करीबी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने समर्थक विधायकों के साथ पाला बदलकर कांग्रेस की सरकार गिरवा दी थी। जिसका जिक्र गहलोत ने भी अपनी पोस्ट में किया है। राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष एवं उपमुख्यमंत्री होने के बावजूद लगातार उपेक्षा का दंश झेल रहे सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ मानेसर चले गए। उसके बाद क्या हुआ,यह सबको मालूम है। पायलट वापस आए, गहलोत सरकार बच गई लेकिन उनके अड़ जाने के कारण सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री, दोनों पदों से हटना पड़ा।

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

संपादकीय

“ मतदान लोकतंत्र का आधार स्तंभ है।
- मार्टिन लूथर किंग, जूनियर

ऐतिहासिक कदम

कोलकाता में तीनों सेनाओं के संयुक्त कमांडर सम्मेलन में देश में पहली बार लिया गया तीन साझा सैन्य स्टेशन बनाने का फैसला सशस्त्र सेनाओं के बीच अभूतपूर्व एकीकरण और समन्वय के लिहाज से निस्संदेह ऐतिहासिक है, इसके साथ ही यह भविष्य की सामरिक चुनौतियों से निपटने की देश की तैयारियों की एक झलक भी पेश करता है। दरअसल, तीनों ही सेनाएं पिछले कुछ वर्षों से आपस में बेहतर एकीकरण के लिए क्रॉस-पोस्टिंग, लॉजिस्टिक्स की संयुक्त व्यवस्था और खरीद, प्रशिक्षण व स्टाफिंग की संयुक्त योजना इत्यादि को अपना रही हैं। तीन साझा स्टेशनों का निर्णय इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। दरअसल, इन्हें बदलते वैश्विक माहौल की जटिल चुनौतियों से निपटने के लिए थिएटराइजेशन सुधार लागू करने की प्रक्रिया का अंग माना जा सकता है। गौरतलब है कि रक्षा मंत्रालय तीनों सेनाओं के एकीकरण के लिए पहले ही अंतर-सेवा कानून बना चुका है, जो किसी सेना अधिकारी को दूसरी सेनाओं के ऊपर कार्रवाई एवं कमान का अधिकार देता है। थिएटराइजेशन का उद्देश्य सेना की तीनों सेवाओं और उनके संसाधनों को एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में एकीकृत कमान संरचना के तहत परिचालन तैनाती के लिए विशिष्ट 'थिएटर' कमानों में समन्वित करना है। हालांकि, तीनों सेनाएं अब तक थिएटर कमान पर एकमत नहीं हुई हैं। वायुसेना ने थिएटर कमान को लेकर इस बात पर आपत्ति जताई है कि इससे उसकी सीमित लड़ाकू परिसंपत्तियों का और अधिक विभाजन हो जाएगा। बहरहाल, तीन संयुक्त सैन्य स्टेशन बनाने से संसाधनों के बेहतर उपयोग से आर्थिक बचत तो होगी ही, आधुनिक युद्ध और आपदा राहत जैसे साझा अभियानों को पूरा करने में भी भारतीय सेना की क्षमता बढ़ेगी और सीमाओं की बेहतर ढंग से सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। इसके अलावा, सम्मेलन में तीनों सेनाओं की शिक्षा शाखा के विलय की भी घोषणा की गई है, जिससे प्रशिक्षण की गुणवत्ता तो बढ़ेगी ही, सभी सेनाओं के अधिकारियों व जवानों के बीच एक साझा रणनीतिक दृष्टिकोण और मूल्यों को स्थापित करने में भी मदद मिलेगी। हालांकि, विभिन्न सेनाओं की पृथक परंपराओं, कार्यप्रणालियों और संस्कृति के चलते उनमें समन्वय आसान नहीं होगा, लेकिन आधुनिक युद्ध की बदलती प्रकृति और क्षेत्रीय सुरक्षा की चुनौतियों के बीच संयुक्त सैन्य स्टेशनों और त्रि-सेवा शिक्षा कोर की स्थापना देश को यकीनन एक अधिक समन्वित और शक्तिशाली रक्षा शक्ति के रूप में स्थापित करेगी।

तमिलनाडु में किसकी लहर

राज्य में अगले साल अप्रैल में चुनाव होने हैं, लेकिन विपक्षी और सत्ताधारी दल आपसी कलह में उलझे हुए हैं। अब तक कोई भी पार्टी मजबूत गठबंधन नहीं बना सकी है। राज्य के छह करोड़ मतदाताओं को समझना होगा कि यदि स्थायी सरकार नहीं बनी, तो यह राज्य की प्रगति के साथ ही देश की सुरक्षा के लिए भी जोखिम भरा होगा।

आर राजगोपालन
वरिष्ठ पत्रकार

तमिलनाडु की राजनीति गरमा रही है। अगले साल अप्रैल में संभावित विधानसभा चुनाव राजनीतिक पार्टियों को डरा रहे हैं। चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक गर्मी तो दिखने लगी है, लेकिन न तो सत्ता पक्ष और न ही विपक्ष के पक्ष में कोई तेज लहर दिख रही है। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (अन्नाद्रमुक) और अन्य छोटी विपक्षी पार्टियां अब तक मजबूत विपक्षी गठबंधन नहीं बना सकी हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने निश्चित ही अन्नाद्रमुक के साथ गठबंधन कर अपनी कुछ पैठ बनाई है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि को बढ़ावा मिलने की वजह से सत्ताधारी दल द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्रमुक) में आपसी कलह मची हुई है। राज्य के विवादास्पद मुद्दों में बिगड़ी कानून व्यवस्था, नशीले पदार्थों का खतरा, शराब घोटाला और रेत माफिया का बोलबाला प्रमुख हैं। संक्षेप में, विपक्ष या सत्ताधारी दल की ओर से अब तक कोई चुनावी माहौल नहीं बनाया गया है।

राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में अभिनेता से नेता बने तमिल वेत्री कड़गम के विजय जोसेफ जैसे नए खिलाड़ी हैं, तो पट्टाली मक्कल काची में फूट पड़ी है। तमिल राष्ट्रवाद की राजनीति करने वाली पार्टियों, जैसे विजयकांत की द्रविड़ मुर्पोक्कू मुनेत्र कड़गम और सीमान के नेतृत्व वाली नाम तमिलार काची, टीटीवी दिनाकरन की अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम (एएमएमके), इनमें से किसी ने भी अब तक कोई ठोस गठबंधन नहीं किया है। हालांकि, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसी साल अप्रैल में अन्नाद्रमुक के साथ भाजपा के गठबंधन की घोषणा कर दी थी। आगामी चुनाव में कई कारक असर डालेंगे।

प्रमुख मुद्दे : राज्य में आर्थिक, राजकोषीय, औद्योगिक और कृषि जैसे कारक महत्वपूर्ण हैं। राज्य के पास धन का अभाव है। वित्तीय व्यवस्था बाहरी कर्जे पर निर्भर है। बैंकों का ओवरड्राफ्ट बढ़ गया है। नीति निर्माण के उच्च स्तर पर कटौती और कमीशनखोरी की वजह से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) बहुत न्यूनतम स्तर पर है।

राहुल गांधी फैक्टर : कांग्रेस के पास अपना खुद का अच्छा-खासा वोट बैंक था, लेकिन राहुल गांधी पूरी तरह द्रमुक पर निर्भर थे। नतीजतन, कांग्रेस युवाओं को अपने साथ नहीं जोड़ पाई। कांग्रेस के जनाधार को बरकरार रखने में पार्टी का राज्य नेतृत्व विफल रहा। पी चिदंबरम जैसे कद्दावर नेताओं के बावजूद द्रमुक ने बड़ी ही चतुरता से कांग्रेस को अपने प्रभाव के नीचे रखा।

राज्य की अन्य पार्टियां : अगले साल तमिलनाडु में छह करोड़ से अधिक मतदाता 234 विधानसभा सदस्यों को चुनेंगे। राज्य में 12 लोकप्रिय पार्टियां हैं, जो चुनाव में अपना भाग्य आजमाएंगी। कुछ नए दल भी बन रहे हैं। ऐसे में द्रविड़ विचारधारा का परीक्षण लाजिमी है। कहने की जरूरत नहीं है कि अध्यात्मवाद के चलते एक सौम्य हिंदुत्व की भावना पहले से ही राज्य में विद्यमान थी, जो अब उभरकर सामने आ रही है। इसके अलावा, तमिलनाडु के चुनाव में जातियां भी अहम भूमिका निभाती रही हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने वाली भाजपा ने तमिल के युवाओं में राष्ट्रवाद की भावना भर दी है। जबकि राज्य के राजनीतिक दलों में अंदरूनी कलह जारी है। इनके नेता वरिष्ठ-कनिष्ठ, निष्कासन, दल-बदल, साझा न्यूनतम मसौदा तैयार करने में उलझे हुए हैं।

अन्नाद्रमुक में बगावत : मुख्य विपक्षी दल अन्नाद्रमुक में बगावत और गुटबंदी गठबंधन के विस्तार के लिए अहम समस्या है। एडापडी के पलानीस्वामी (ईपीएस) ने कानूनी लड़ाई के जरिये नीति निर्माण के लिए संगठन के महासचिव का पद, और सबसे बड़ी बात, पार्टी का दो पत्ती का चुनाव चिह्न अपने पास रखा है।

दो वरिष्ठ नेताओं का टकराव : अन्नाद्रमुक के असंतुष्ट नेता सेंगोट्टायन, जो एमजीआर-जयललिता के कट्टर समर्थक माने जाते रहे हैं, बीते कुछ दिनों से सुर्खियां बटोर रहे हैं। उन्होंने पार्टी से अलग हुए धड़ों को मिलाने को लेकर अन्नाद्रमुक के शीर्ष नेता ईपीएस को दस दिन का अल्टीमेटम दे दिया। ईपीएस ने इसे मानने के बजाय अनुशासनहीनता बताते हुए सेंगोट्टायन को तत्काल पार्टी के सभी दायित्वों से मुक्त कर दिया। इस कठोर कार्रवाई ने निश्चित रूप से एमजीआर और जयललिता के अनुयायियों को विचलित किया होगा। ईपीएस द्वारा सेंगोट्टायन पर की गई कार्रवाई का अन्नाद्रमुक के पूर्व संयोजक ओ पन्नीरसेल्वम (ओपीएस), एएमएमके के महासचिव टीटीवी दिनाकरन और दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता की सहयोगी रहीं वीके शशिकला ने निंदा कर उन्हें सांत्वना दी है। सेंगोट्टायन की बर्खास्तगी को 'तानाशाही की पराकाष्ठा' बताते हुए ओपीएस ने कहा, 'वह पार्टी के सबसे वरिष्ठ पदाधिकारियों में से एक हैं। उनका मकसद सिर्फ पार्टी को एकजुट करना है। उन्हें इतनी बड़ी सजा इसलिए दी गई, क्योंकि उन्होंने एकता की आवाज को बुलंद किया।' टीटीवी दिनाकरन ने सेंगोट्टायन के एकता के आह्वान का समर्थन किया और चेतावनी दी कि सभी पार्टी नेताओं को एकजुट करने में विफलता अन्नाद्रमुक की हार का कारण बनेगी।

पार्टियों के तूफानी दौरे : द्रमुक एवं अन्नाद्रमुक के नेताओं ने रोड शो करने शुरू कर दिए हैं। एमके स्टालिन का ध्यान द्रमुक सरकार की समाज कल्याण योजनाओं पर है। विपक्षी अन्नाद्रमुक नेता एडापडी पलानीस्वामी 125 विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो कर चुके हैं और शेष बचे 109 क्षेत्रों में आने वाले महीनों में रोड शो करेंगे।

स्टालिन की विदेश यात्रा : मुख्यमंत्री के रूप में अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) हासिल करने के लिए एमके स्टालिन विदेश दौरे पर गए थे। विपक्ष के कई नेताओं ने इसे ढकोसला बताते हुए आलोचना की कि बीते चार साल तक एफडीआई के सिर्फ झूठे दावे किए गए थे। अब भी सिर्फ दिखावे के लिए मुख्यमंत्री विदेश दौरों पर जा रहे हैं, जिसका उन्हें कोई लाभ नहीं मिलने वाला।

तमिलनाडु का भविष्य और जोखिम : आप चाहे इसे जिस तरह से देखें, तमिलनाडु का भविष्य सकारात्मक और नकारात्मक भावनाओं से भरा है। यदि मतदाता स्थायी सरकार नहीं चुनते हैं, तो राज्य की प्रगति नहीं होगी। अगले छह माह में राज्य के छह करोड़ मतदाताओं को इसे लेकर अपना मन बना लेना चाहिए कि श्रीलंका और मालदीव से सटे तटवर्ती राज्य तमिलनाडु को गठबंधन की सरकार नहीं चाहिए। यह देश की सुरक्षा के लिए भी जोखिम भरा होगा।

तकनीक

खतरा, जो वॉशिंगटन और बीजिंग को जोड़ेगा

एआई सब कुछ बदलने वाला है। अगर मानवता की खातिर दो एआई महाशक्तियां नजदीक नहीं आईं, तो नतीजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा।

चीन और अमेरिका को अभी यह एहसास तक नहीं है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) उन्हें दूर करने के बजाय नजदीक लाने जा रही है। एआई का उदय दोनों देशों के बीच प्रभुत्व के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा का, तो इसके साथ ही इतनी ही ऊर्जा और गहराई से परस्पर सहयोग का अभूतपूर्व दबाव भी बनाएगा। दरअसल, एआई पिछली तकनीकों से बिल्कुल अलग है। यह आपकी घड़ी, टोस्टर, कार, चश्मे, कंप्यूटर और पेसमेकर इत्यादि सभी में मौजूद होगा और खुद में सुधार के लिए लगातार डाटा एकत्रित करता रहेगा। जाहिर है कि ऐसा होने पर यह सबकुछ बदल देगा, जिसमें दुनिया की दो एआई महाशक्तियों के बीच भू-राजनीति और व्यापार शामिल है। हर बीतते महीने दोनों देशों के बीच सहयोग की जरूरत अधिक तीव्रता से महसूस की जाएगी।

उदाहरण के लिए, अगर आपका कूल्हा टूट जाता है, और आपको पता चलता है कि दुनिया में सबसे स्मार्ट प्रत्यर्पण योग्य कूल्हा चीन द्वारा तैयार एआई से जुड़ा है, तो क्या आप इसे अपने शरीर में लगवाएंगे? नहीं, मैं ऐसा तब तक नहीं करूंगा, जब तक दोनों देशों के बीच सामान्य नैतिक आधारों पर इससे संबंधित कोई समझौता न हो गया हो, क्योंकि इससे यह सुनिश्चित होगा कि एआई का उपयोग हर स्थिति में मानवता के हित में होगा। अगर ऐसा नहीं हो सका, तो घोटालेबाजों, ड्रग डीलरों और आतंकियों के हाथों एआई क्रांति के दुरुपयोग का डर पैदा होगा। यह स्थिति दोनों ही महाशक्तियों को अस्थिर करेगी।

थॉमस फ्रीडमैन

हेनरी किसिंजर और एरिक श्मिट के साथ एआई पर आधारित *जेनेसिस* नामक पुस्तक लिखने वाले तकनीकी विशेषज्ञ क्रेग मुंडी, जो कि 20 वर्षों से मेरे दोस्त हैं, के साथ हुए संवाद के आधार पर वाशिंगटन में बैठे चीन विरोधी और बीजिंग में अमेरिका विरोधी कट्टरपंथियों तक संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि आप लोग भ्रम में हैं कि एआई की दोनों महाशक्तियां आपस में लड़ने का जोखिम उठाएंगी। एआई इतना अलग, इतना महत्वपूर्ण और इतना प्रभावी है कि-दोनों एआई महाशक्तियां अलग-अलग रास्ते पर चलने का साहस शायद ही जुटाएं। इसी वजह से मेरा मानना है कि अमेरिका और चीन एआई को लेकर मानवीय हितों को देखते हुए प्रतिस्पर्धा के बीच सहयोगी रवैया बनाए रख सकते हैं। साथ ही ऐसे देशों तक एआई की पहुंच सीमित कर सकते हैं, जो नियमों का पालन करने को तैयार नहीं हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, तो दुनिया ऐसी खंडित डिजिटल स्वायत्तता की ओर बढ़ जाएगी, जहां हर देश अपना अलग एआई पारिस्थितिकी तंत्र बनाएगा, जिसकी सुरक्षा असंगत मानकों और आपसी संदेह से होगी।

2000 के दशक को याद करें, जब मार्क जुकरबर्ग ने कहा था कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल नेटवर्क लोगों को नुकसान पहुंचाने के बजाय उनके सहयोगी होंगे। आज इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक तरह से जहर परोसा जा रहा है। ऐसे ही एआई को लेकर यदि चीन और अमेरिका जैसी महाशक्तियां नहीं चेतीं, तो मानवीय विनाश के लिए तैयार रहें, क्योंकि एआई को कोई सरकार, उनका रक्षा मंत्रालय या प्रवर्तन एजेंसियां संचालित नहीं कर रही हैं, इनका संचालन पूरी तरह निजी कंपनियों के हाथ में है। धीरे यह हर जगह अपनी पहुंच बना लेगा, तब इसको नियंत्रित करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। कुल मिलाकर, बात यह है कि यदि वाशिंगटन और बीजिंग इस चुनौती का सामना करने में विफल होते हैं, तो शेष दुनिया के पास बचाव का कोई मौका नहीं होगा। पहले ही काफी देर हो चुकी है।

बुजुर्गियत के साथ सबसे अच्छी बात है कि यह हमें अपना सबसे परिवर्धित संस्करण बनने का अवसर देती है। *-मैरी बुचान*

जिन खोजा, तिन पाइयां

अगर दूरदर्शिता और आत्मबोध को आप शारीरिक सुखों के ऊपर रखते हैं, तो वृद्धावस्था में भी अवसर मिलेंगे। जहां नदी की गति कम होती है, वहीं वह सबसे अधिक गहरी होती है। वृद्धावस्था में जब जीवन की गति कुछ धीमी हो जाती है, तभी उसमें गहरे अर्थ आते हैं।

रेब जालमान

मुड़-मुड़ के देख

जब आप बुजुर्ग होने लगते हैं, तो भविष्य की चिंता सबसे पहले होने लगती है। अगर जीवन के मूल्य केवल शरीर और इंद्रियों के सुख हैं, तो हमें यह मान लेना चाहिए कि युवावस्था के बाद जीवन ढलान की ओर जाता है। अगर सांसारिक सफलता और शक्ति का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ है, तो मध्य आयु, यानी गृहस्थ जीवन, जिंदगी का शिखर होगी। लेकिन यदि दूरदर्शिता और आत्मबोध इनसे भी अधिक महत्वपूर्ण माने जाएं, तो वृद्धावस्था के अपने अवसर होते हैं। ध्यान रहे, जहां नदी की गति कम होती है, वहीं वह सबसे अधिक गहरी होती है। इसी तरह वृद्धावस्था में जब जीवन की गति कुछ धीमी हो जाती है, तभी उसमें गहरे अर्थ आते हैं। लेकिन इसके लिए अज्ञानता का पर्दा हटना जरूरी है। अगर वास्तविकता एक नीरस और उदास मरुस्थल है, और आत्मा केवल जटिल यांत्रिक प्रणाली है, तो आत्मज्ञान और दृष्टि के पुरस्कार इंद्रियों के सुख या सामाजिक सफलता की तृप्ति से मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं माना जाता। उपनिषद कहते हैं, सब छोड़कर उसका अनुसरण करो! उसकी अनिर्वचनीय समृद्धि का आनंद लो। हिंदू धर्म में जीवन के तीसरे चरण की बात की जाती है, जो संन्यास या सेवानिवृत्ति का चरण है। जब पहला पौत्र या पौत्री जन्म लेती है, तब व्यक्ति समाज के दायित्वों से मुक्त हो सकता है, जिन्हें उसने अब तक इच्छा के साथ निभाया। बीस-तीस साल तक समाज के लिए काम किया, अब राहत का समय है, ताकि जीवन का अंत होने से पहले उसे समझा जा सके। अब समय है सच्ची शिक्षा शुरू करने का, यह जानने का कि मैं कौन हूं और जीवन का अर्थ क्या है। उस 'मैं' का रहस्य क्या है, जिसके साथ हम इतने करीब रहे, जिसमें अजीब विचित्रताएं, समझ से परे समस्याएं और तर्कहीन आवेग हैं? हम जन्म क्यों लेते हैं, मेहनत और संघर्ष क्यों करते हैं, सुख-दुख का हिस्सा लेकर, और अंत में मृत्यु के किनारे पर टूटकर, गुमनाम मृत्यु के समुदाय में विलीन क्यों हो जाते हैं? अस्तित्व के रहस्य में अर्थ खोजना जीवन की अंतिम और आकर्षक चुनौती है।

दूसरी पारी

फिर से बच्चे बन जाएं

आजकल किडल्टिंग खूब प्रचलित हो रहा है यानी बुढ़ापे में बच्चा बनना। वरिष्ठ पत्रकार क्षमा शर्मा बता रही हैं इसके फायदे...

95 साल के हो चुके मशहूर उद्योगपति वारेन बफे अब भी छह साल के बच्चों जैसी अपनी दिनचर्या जीते हैं। हम बुजुर्ग भी जीवन के जो वर्ष बचे हैं, उन्हें फिर से जी लें। उनका आनंद मनाएं, क्योंकि जीवन भर जिम्मेदारियों के पीछे ही तो भागते रहे हैं।

किडल्टिंग, दो शब्दों से मिलकर बना है। किड यानी कि बच्चा और एडल्ट माने वयस्क। यह जीवनशैली आजकल वयस्कों में बहुत लोकप्रिय होती जा रही है। इस बात का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि जब बच्चे होते हैं, तो सब जल्दी से जल्दी बड़े बनना चाहते हैं। और अब बड़े बच्चे बनना चाहते हैं। अपने यहां कहा भी जाता है कि जब आप उम्रदराज हो जाते हैं, तो बच्चों जैसे हो जाते हैं। फिर से बच्चे बन जाएं, यह बड़ों का एक सुंदर सपना होता है। यही सपना देखा जा रहा है। न केवल देखा जा रहा है, बल्कि उसे भरपूर जीने की कोशिश की जा रही है। अतीत में लौटने की हर कोशिश खुशी-खुशी हो रही है।

इन दिनों किडल्टिंग में लोग उन खिलौनों को खरीद रहे हैं, उनसे खेल रहे हैं, जिनसे बच्चे खेलते हैं। लंबे समय तक कार्टून देख रहे हैं। वैसे ही कपड़े पहनना चाहते हैं। उन आदतों और शौक की तरफ वापस जा रहे हैं, जो बचपन में थीं। कहा जा रहा है कि यह बीते दिनों में वापस जाने और उन्हें फिर से जीने का एक तरीका है। किडल्टिंग से वयस्कों के तरह-तरह के तनाव दूर हो रहे हैं। तनाव से दूर हटकर वे आनंद की तरफ लौट रहे हैं। बचपन से दोबारा जुड़ रहे हैं। बहुत से लोग जो ऐसा करते हैं, उनका कहना है कि इस तरह वे आज की दुनिया में पड़ने वाले अनेक प्रकार के दबाव और चिंताओं से वैसे ही मुक्त हो रहे हैं, जैसे बच्चे होते हैं।

अतीत में लौटने और बच्चा बन जाने की चाह सिर्फ पश्चिमी देशों में ही नहीं, अपने यहां भी दिखाई दे रही है। अपने समाज में जिस तरह से बुजुर्ग विवाह की पच्चीसवीं, पचासवीं वर्षगांठ धूमधाम से मना रहे हैं, इन पार्टियों का आयोजन वैसे ही हो रहा है, जैसे कि तब हुआ होगा। बुजुर्गों के डेस्टिनेशन वेडिंग भी किए जा रहे हैं। इनमें भाग लेने वाले कई बुजुर्गों ने कहा कि वे इन आयोजनों में, वह सब कुछ करना चाहते हैं, जो उस समय नहीं कर पाए। वे फिर से हनीमून पर जा रहे हैं। बहुत से लोग दुनिया घूम रहे हैं। क्लबों में जा रहे हैं। अपनी पसंद के खेलों की टीमें बनाई जा रही हैं। उनके बाकायदा मैच हो रहे हैं। नाच-गा रहे हैं। बहुत से अपने जन्मदिन किशोरावस्था की तरह मना रहे हैं। पुराने दोस्तों को ढूंढकर आमंत्रण भेजे जा रहे हैं। बुजुर्गों में बच्चों की तरह ही रंग-बिरंगे कपड़ों का चलन बढ़ रहा है। यह किडल्टिंग का ही एक उदाहरण है। इसका एक कारण यह भी है कि जीवन भर जिन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए दौड़ते रहे, अब वे लगभग पूरी हो चुकी हैं। इसलिए जीवन के जो वर्ष बचे हैं, उन्हें फिर से जी लिया जाए। आनंद मना लिया जाए। बच्चा बन जाने का सुख फिर से प्राप्त किया जाए। जो तब नहीं कर पाए, वह अब कर लें।

*जिंदगी की **दूसरी पारी** बहुत महत्वपूर्ण होती है। हर शुक्रवार इस पर आपको नया पढ़ने को मिलेगा। विशेषज्ञों की मदद से हम कोशिश करेंगे कि संवाद का पुल बन सके।*

जब छह साल के बच्चे बन जाते हैं वारेन बफे

हाल ही में 95 वर्षीय मशहूर उद्योगपति वारेन बफे ने कहा कि वह अपने खाने में कैलोरी काउंट नहीं करते हैं। वह वैसे ही खाते हैं, जैसे कि छह साल के बच्चे खाते हैं। वह मानते हैं कि छह साल में बच्चे कैलोरी काउंट के बोझ से मुक्त होते हैं। उन्हें आइसक्रीम और शीतल पेय बहुत पसंद हैं। बाजार में मिलने वाले हर तरह के हेल्थ पेयों और खाद्य पदार्थों से दूर रहते हैं। उनका कहना है कि स्वस्थ रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि छह साल के बच्चे की तरह जो मन हो, वह खाओ। वारेन ने एक बार एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि मैंने सही आंकड़ों पर गौर किया है। इनसे पता चला कि छह साल के बच्चों में मृत्यु दर सबसे कम है। इसीलिए मैं वही करता हूं, जो इस उम्र के बच्चे करते हैं। बफे का कहना है कि बढ़ती उम्र के साथ लोग अपने अंदर के बच्चे को मार देते हैं, लेकिन हमारे अंदर के बच्चे को हमेशा जीवित रहना चाहिए। वह बच्चों की तरह ही लंबी नींद लेते हैं। रात के आठ बजते ही सोने चले जाते हैं। उनका कहना है कि यदि दिल और दिमाग को मजबूती देनी है, तो लंबी नींद आवश्यक है। दुनिया के डॉक्टर भी यह मानते हैं। बफे की जीवनशैली किडल्टिंग का सबसे अच्छा उदाहरण है। वह अरबपति हैं और आज भी बहुत काम करते हैं। उम्र ने उनकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं की है।

वरिष्ठ नागरिकों के काम के संगठन

अकेलेपन का सहारा

डिग्निटी फाउंडेशन बुजुर्गों को मनोवैज्ञानिक-सामाजिक चुनौतियों, 'अकेलेपन और असुरक्षाओं' से निपटने में मदद करता है। इसका मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान और सुरक्षा के साथ जीवन जीने में सक्षम बनाना तथा पूर्ण और आनंदपूर्ण तरीके से जीवन का आनंद लेने में सक्षम बनाना है। फाउंडेशन की आधिकारिक वेबसाइट www.dignityfoundation.com पर जाएं या आप सीधे सहायता और जानकारी के लिए उनकी सामान्य हेल्पलाइन 1800 267 8780 पर संपर्क कर इसका लाभ ले सकते हैं।

बुजुर्गों के मुद्दे उठाने वाला संगठन

ऑल इंडिया सीनियर सिटिजन्स कॉन्फेडरेशन देश के 25 से अधिक राज्यों के विभिन्न वरिष्ठ नागरिक संगठनों की मदद से बुजुर्गों के मुद्दों को सरकार और समाज के सामने रखता है। इसका उद्देश्य बुजुर्गों को स्वतंत्र, सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन प्रदान करना है। इसकी आधिकारिक वेबसाइट : www.aisccon.org पर उपलब्ध जानकारियों के आधार पर आप लाभ ले सकते हैं।

Special arrangements by Amar Ujala

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेन्ट्स प्रा.लि. के लिए मुद्रक, प्रकाशक समीर माहेश्वरी द्वारा नवभारत प्रेस, नवभारत भवन, प्रेस कॉम्प्लेक्स, जी.ई.रोड, रायपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित. प्रधान संपादक : समीर माहेश्वरी, संपादक : राजेश आर. जोशी* (पी.आर.बी. कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिये जिम्मेदार)
■ रायपुर फोन : 0771-4343434, 2535555-66-77, ■ भुवनेश्वर : 0674-2380511/2380518 ■ बिलासपुर : 07752-230591, 407748, 224563 ■ वर्ष 66 ■ अंक 116 (रजि.नं. 13045/59 आरएनआई), पो. रजिस्टर्ड नं. छ.ग./रायपुर संभाग/61/2025-27 ■ भिलाई फोन : (0788) 2294181, 4030655

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। –वाल्तेयर

राजस्थान पत्रिका
संस्थापक
कर्पूर चन्द्र कुलिश

डिजिटल संसार में निजता का हनन चिंताजनक

डिजिटल संसार के तमाम फायदों के बावजूद खतरे भी हजारों है। लंबे समय से तकनीक के दुरुपयोग को रोकने की मांग उठती रही है। लेकिन हालत दिनों-दिन डरावनी और चिंताजनक होती जा रही है। इसमें संदेह नहीं कि स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक हर क्षेत्र में तकनीक के जरिए क्रांति लाने की बातें हो रही है। लेकिन जब निजता पर हनन जैसे मामले सामने आते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) को लेकर चिंता और बढ़ जाती है। यह भी एक तथ्य है कि निजता का हनन करने वाले कई खतरे तो खुद तकनीक के यूजर ही मोल लेने लगे हैं। एआइ के फोटो एडिटिंग टूल के एआइ साड़ी ट्रेंड से उजागर हुआ एक इंस्टाग्राम यूजर युवती का ताजा मामला इस ओर संकेत करने को काफी है। इतना ही नहीं, एआइ तकनीक लोगों को ठगने का काम भी कर रही है। यह एक तरह से समाज को खतरनाक निर्भरता के दलदल में धकेलने जैसा है।

गूगल के जेमिनी एआइ से विंटेज साड़ी ट्रेंड के लिए फोटो अपलोड करने वाली युवती ने खुद बताया है कि वे अपलोड की गई फोटो में फुल-स्लीव ग्रीन सूट में थीं, लेकिन एआइ-जनरेटेड इमेज में उनके बांई बांह पर वह तिल साफ दिख रहा था जो वास्तव में है भी। ऐसा और कितनों के साथ हुआ होगा और आगे भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। सवाल यह है एआइ तकनीक आखिर किसी की भी बॉडी के गहरे राज का कैसे पता लगा लेती है? यह कोई संयोग नहीं, बल्कि एआइ की जासूसी का रूप कहा जा सकता है जिसमें वह हर फोटो को स्कैन कर, डेटाबेस से जोड़ते हुए हमारी निजी डिटेल्स उजागर कर देता है। दूसरा ताजा घटनाक्रम ख्यात धर्मगुरु के डीपफेक व एआइ जनरेटेड वीडियो का है जिसमें बेंगलूरु की एक महिला को ठगी का शिकार होना पड़ा। सवाल इस तरह की ठगी और निजता के हनन का ही नहीं है। पिछले सालों में ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जिनमें यह भरोसा करना मुश्किल हो गया है कि सोशल मीडिया पर परोसी गई कोई जानकारी असली है या फर्जी। निजी जिंदगी में दखल की यह तो शुरुआत ही है। इससे भी बड़ा खतरा यह भी है कि एआइ तकनीक मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरा बन रही है। चैटबॉट्स से पूछे गए निजी सवालों के जवाब कई बार बहुत घातक होते हैं। अमरीका में एक किशोर का उदाहरण है जिसमें उसने चैटजीपीटी से सुसाइड के विचार शेयर किए तो बॉट ने उसे कोच की तरह तरीके बताते हुए इतना भ्रमित किया कि किशोर ने सच में आत्महत्या कर ली।

भारत में भी तकनीक को लेकर खतरा कम नहीं है। युवा अकेलेपन में एआइ को दोस्त बना रहे लेकिन रिश्तों को कत्ल करने पर उतारू कंटेंट का सामना भी कर रहे हैं। इसकी बड़ी वजह कानूनी सख्ती की कमी ही है। हमारे यहां डीपफेक लॉ कमजोर है। सख्त कानून, एआइ रेगुलेशन और इसके साथ ही जागरूकता और सतर्कता की जरूरत ज्यादा है।

विडंबना: 'स्थानीय बनाम प्रवासी' का मोर्चा खोलने की राजनीति यूरोप समेत दूसरे देशों में भी रंग दिखाने लगी है

'वैश्विक गांव' में लगातार उभरती विभाजक रेखाएं

राज कुमार सिंह
वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक
@patrika.com

अब अचानक इन देशों को प्रवासी अपने मूल निवासियों और अंततः राष्ट्रीय हितों के लिए खतरा नजर आने लगे हैं। स्थानीयता और राष्ट्रवाद के नाम पर नागरिकों की भावनाएं भड़काने की राजनीति जांची-परखी है।

कहावत है कि एक समय ब्रिटिश सत्ता में सूरज कभी नहीं डूबता था, अब उसी ब्रिटेन के लाखों मूल निवासी पिछले दिनों 'यूनाइट द किंगडम' के नारों के साथ प्रवासियों के विरुद्ध रैली निकालते नजर आए तो संदेश साफ है कि विश्व को एक गांव के रूप में देखने-दिखाने के सपने बिखरने लगे हैं। पिछली शताब्दी के अंतिम दशक में आर्थिक उदारीकरण के नाम पर वैश्विक गांव का नारा दिया गया था। भारत समेत तमाम देशों ने अर्थव्यवस्था ही नहीं, सोच और समझ की दृष्टि से भी अपने खिड़की-दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोल दिये। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों के दबाव में आर्थिक उदारीकरण को गति मिली, लेकिन सभी जानते हैं कि उसके मूल में अपने उत्पादों के लिए दुनिया भर के बाजार हासिल करने की अमरीकी रणनीति काम कर रही थी। इसलिए भी, अमरीका के वैचारिक विरोधियों ने अर्थव्यवस्था के उस उदारीकरण और वैश्वीकरण का विरोध किया। कुछ परंपरागत क्षेत्रों पर नकारात्मक असर के अलावा उससे लाभ भी मिला, लेकिन साढ़े तीन दशक बाद अब विश्व व्यवस्था फिर वापस अपने-अपने दायरे में लौटने को बेताब दिख रही है।

विडंबना यह कि इसकी शुरुआत भी अमरीका से ही हुई। अमरीका को फिर महान बनाने और अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने के नारे के साथ, चार साल के अंतराल के बाद, दूसरी बार राष्ट्रपति बनने में सफल रहे डॉनल्ड ट्रंप की नीतियों का भले ही अब अमरीका में भी विरोध होने लगा हो, लेकिन 'स्थानीय बनाम प्रवासी' का मोर्चा खोलने की राजनीति यूरोप समेत दूसरे देशों में भी रंग दिखाने लगी है। ये पश्चिमी देश हर तरह के उदारीकरण के लिए जाने जाते रहे हैं। इसीलिए प्रवासियों की पसंद की सूची में ऊपर रहे हैं। प्रवासियों को वहां बेहतर जीवन स्तर मिलता है तो वे भी उनके सर्वांगीण विकास में अपना योगदान देते हैं। अब अचानक इन देशों को प्रवासी अपने मूल निवासियों और अंततः राष्ट्रीय हितों के लिए खतरा नजर आने लगे हैं। स्थानीयता और राष्ट्रवाद के नाम पर नागरिकों की भावनाएं भड़काने की राजनीति जांची-परखी है। इसलिए इसे आधार बना कर सत्ता-राजनीति की बिसात भी बिछायी जाने लगी है।

अगर अमरीका सरीखे विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र और मजबूत अर्थव्यवस्था वाले उदार समाज में राष्ट्रवाद डॉनल्ड ट्रंप को दूसरी बार राष्ट्रपति बनवाने वाला 'ट्रंप कार्ड' बन सकता है तो फिर ब्रिटेन, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया समेत अन्य देशों के राजनेता उसे क्यों नहीं आजमाना चाहेंगे? ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में चुनाव भी होने वाले हैं। बेशक फ्रांस से लेकर ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया तक जनता के सड़कों पर उतरने के मूल में वहां की सरकारों की, जन आकांक्षाओं पर खरा उतरने में नाकामी तथा महंगाई, बेरोजगारी एवं खराब कानून व्यवस्था के चलते बढ़ती जीवन की मुश्किलें ही हैं, लेकिन ट्रंप के 'ट्रंप कार्ड' के बाद तमाम समस्याओं को स्थानीय बनाम प्रवासी का मुद्दा बना कर पेश करने की राजनीति जोर पकड़ रही है।

पिछले दिनों लंदन में प्रवासी विरोधी रैली का हिंसक हो जाना बताता है कि ये भावनाएं लगातार गहरा रही हैं। बेशक आर्थिक विकास की दौड़ में किसी देश के पिछड़ जाने या आगे निकल जाने का कोई एक कारण नहीं होता- और यह अचानक भी नहीं होता, पर महंगाई- बेरोजगारी के साथ-साथ अपराधों में भी वृद्धि की तपिश झेल रहे अंग्रेजों को यह समझा पाना मुश्किल नहीं कि कभी दुनिया पर राज करने वाले ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था लगातार पिछड़ने के मूल में उस पर बढ़ता प्रवासियों का दबाव भी है।

आश्चर्य नहीं कि नोजली, लॉटन और केंट के कुछ क्षेत्रों में प्रवासी विरोधी गुट सक्रिय और मुखर हो रहे हैं। कुछ दशक पहले यह कल्पना भी मुश्किल थी कि ब्रिटेन के मूल निवासी अपने ही देश में खुद को असुरक्षित महसूस करने लगेंगे, लेकिन अब राजधानी लंदन में ही कुछ 'नो-गो जोन' बन गए हैं, जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में गैर मुस्लिम जाना असुरक्षित समझते हैं। ब्रिटेन की ही बात करें तो लगातार बढ़ती मुस्लिम आबादी फिलहाल प्रवासी विरोध की बड़ी वजह है। अनुमान है कि 2035 तक ब्रिटेन की कुल आबादी में मुस्लिम आबादी 25 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी। किसी भी देश और समाज में जब आबादी का स्वरूप और संतुलन बदलता है, तो कई तरह की चुनौतियां पैदा होना स्वाभाविक है।

बेहतर जीवन की चाह में विदेश जाने वाले प्रवासी भी अपनी संस्कृति को आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेजे रखना चाहते हैं। इस प्रक्रिया में वे संगठित भी होते हैं, लेकिन राष्ट्रवाद के जरिये स्थानीयता की राजनीति करने वाले उनकी सक्रियता और मुखरता को देश की मूल संस्कृति और निवासियों के लिए खतरे के रूप में पेश करते हैं। इस्लामी संस्कृति से लेकर गाजा पर एकजुटता के प्रदर्शन तक मुस्लिम संगठनों की सक्रियता और मुखरता अंग्रेजी समाज में भविष्य के खतरे के रूप में भी रेखांकित की जा रही है।

ऐसा लग सकता है कि ब्रिटेन में प्रवासी विरोध के निशाने पर मुस्लिम ही हैं, पर वास्तव में अवैध प्रवासी हर देश में समस्या बनते जा रहे हैं। अमरीका की तरह अन्य पश्चिमी देशों में भी अवैध प्रवासियों से सख्ती से निपटने के लिए जनता का दबाव बढ़ रहा है। एक अनुमान के मुताबिक इसी साल लगभग 28 हजार अवैध प्रवासी छोटी नावों से इंगलिश चैनल पार कर ब्रिटेन में प्रवेश कर चुके हैं। खुद को अवैध प्रवासियों के लिए धर्मशाला नहीं बनने देना किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं माना जा सकता। बेशक जिन देशों से ये अवैध प्रवासी आते हैं, वे भी उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई का तर्कसम्मत विरोध नहीं कर सकते।

प्रसंगवश

बिजली चोरी के मामले चिंताजनक, हार्डकोर बदमाशों पर हो सख्ती

ऐसी कार्रवाई को राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर रखा जाना ज्यादा जरूरी है

अपराधों पर लगाम लगाने के प्रयासों के दौरान जब यह जानकारी मिले कि हार्डकोर बदमाश आम जनता में दहशत फैलाने के साथ सरकारी खजाने को चपत भी लगा रहे हैं तो जिम्मेदारों की भूमिका पर सवाल उठना स्वाभाविक है। राजस्थान के झालावाड़ में पुलिस के ऑपरेशन ऊर्जा प्रहार- अपराधियों की बत्ती गुल अभियान के नतीजे चौंकाने वाले हैं। हिस्ट्रीशीटर बदमाशों के घरों पर पुलिस एवं जयपुर विद्युत वितरण निगम की संयुक्त कार्रवाई में पता लगा कि बड़ी संख्या में इनकी घरों में बिजली चोरी हो रही है। विद्युत पोल पर सीधे तार डालकर बिजली चोरी हो रही थी। प्रदेशभर में हिस्ट्रीशीटरों, हार्डकोर एवं सक्रिय अपराधियों की संख्या को देखते हुए अभी काफी कुछ करने की दरकार है।

देखा जाए तो प्रदेश में बिजली चोरी गंभीर समस्या है। इसे केवल हिस्ट्रीशीटर या बड़े बदमाश ही नहीं, बल्कि कई स्तरों पर लोग भी करते हैं। कई लोग सीधे तार डालकर या मीटर में छेड़छाड़ कर बिजली चोरी करते हैं। दुकानदार, होटल, ढाबे, वर्कशॉप और छोटी फैक्ट्रियां अतिरिक्त कनेक्शन लिए बिना मीटर से छेड़छाड़ कर या डायरेक्ट लाइन खींचकर बिजली का दुरुपयोग करते हैं। कुछ बड़े कारखाने भी चोरी-छिपे मीटर की गति धीमी करने, चुंबक लगाने या तकनीकी छेड़छाड़ से बिजली की खपत छिपाते हैं। कई जगह अधिक हॉर्सपावर के पंप चलाने के लिए अनधिकृत लाइनें जोड़ लेते हैं या कनेक्शन की क्षमता से अधिक बिजली खींचते हैं। देखा यह भी गया है कि बिजली चोरी या अनैतिक कामों में पुलिस या प्रशासन को जनता का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाता है। इसकी प्रमुख वजह सुरक्षा की गारंटी न होना, पुलिस और न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा न होना और सामाजिक दबाव भी है। जब तक लोगों को यह भरोसा नहीं होगा कि सिस्टम उनका साथ देगा, तब तक अपराधियों के खिलाफ आवाज उठाना कठिन ही रहेगा। बिजली चोरी की गहरी जड़ें को देखते हुए संबंधित विभागों को तालमेल बैठाकर सख्ती करनी होगी। जरूरत इस बात की भी है कि ऐसी कार्रवाई को राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर रखा जाए। - महेन्द्र सिंह शेखावत

mahendra.shekhawat@in.patrika.com

बुक इनसाइट

द स्टोरी ऑफ स्पिनल टैप

मशहूर फिल्म निर्माता रॉब रेनर के साथ क्रिस्टोफर गेस्ट, माइकल मैककियन और हैरी शीयर द्वारा लिखी गई 'द स्टोरी ऑफ स्पिनल टैप' किताब डॉक्यूमेंट्री फिल्म 'दिस इज स्पिनल टैप' की कहानी को विस्तार से प्रस्तुत करती है। यह एक काल्पनिक रॉक बैंड स्पिनल टैप के चढ़ाव-उतारों को हास्य के साथ दर्शाती है। किताब में स्पिनल टैप के किरदारों की मस्ती भरी यात्रा को बखूबी पिरोया गया है। किताब में संगीत की दुनिया में व्यंग्य और हास्य का मिश्रण कर एक अनोखा अनुभव दिया गया है। इसमें बैंड के सदस्यों की मूर्खतापूर्ण लेकिन मनोरंजक हरकतें और उनके कथित 'सफल' संगीत करियर की कहानी को सरल भाषा में पेश किया गया है। रंगीन चित्र और मजेदार संवाद इसे और आकर्षक बनाते हैं। इसमें कई मजेदार किस्से और संवाद शामिल हैं, जो बैंड की सोच और उनकी क्रिएटिविटी को उजागर करते हैं। किताब में सिर्फ बैंड के संगीत सफर को ही नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपी दोस्ती, उतार-चढ़ाव और प्रयोगधर्मी सोच को भी अच्छी तरह चित्रित किया है।

फैक्ट फ्रंट

ओशन सनफिश : वजनी मछली

ओशन सनफिश, जिसे मोला मोला भी कहा जाता है, दुनिया की सबसे भारी हड्डी वाली मछली है। इसका वजन 2000 किलोग्राम तक हो सकता है, जो इसे समुद्र का एक अनोखा प्राणी बनाता है। इसका शरीर चपटा और गोल होता है, जो देखने में किसी बड़े पत्थर की तरह लगता है। हालांकि यह तैरने में कमजोर दिखाई देती है, फिर भी यह महासागरों में लंबी दूरी तय करने में सक्षम है। यह मछली ठंडे और गर्म दोनों तरह के समुद्री जल में पाई जाती है, जिससे इसकी अनुकूलन क्षमता का पता चलता है। ओशन सनफिश की एक खास आदत है पानी की सतह पर तैरते हुए 'धूप सेंकना'। इसीलिए इसे सनफिश का नाम मिला। यह धूप सेंकने से अपने शरीर का तापमान नियंत्रित करती है और परजीवियों से छुटकारा पाती है क्योंकि पक्षी इसकी त्वचा पर मौजूद परजीवियों को खा लेते हैं। इसकी त्वचा मोटी और चमड़े जैसी होती है, जो इसे शिकारियों से बचाने में मदद करती है।

चिंता मानवता के लिए अभिशाप न बने तकनीक

आशाओं व आशंकाओं के बीच एआइ पर निर्भरता कितनी सही

अतुल कनक
स्वतंत्र लेखक एवं स्तंभकार
@patrika.com

आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआइ) ने मानव जीवन में संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं। वैज्ञानिक और चिकित्सकीय शोधों में ही नहीं, कला, ज्योतिष, लेखन और मौसम विज्ञान संबंधी क्षेत्रों में भी एआइ के उपयोग की दिशा ने नई संभावनाओं की उम्मीद जगाई है। लेकिन एआइ भी एक तकनीक ही है और मानव सभ्यता का इतिहास बताता है कि तकनीक पर आवश्यकता से अधिक निर्भरता और गलत मनोवृत्ति वाले लोगों का तकनीक में दक्ष हो जाना समाज को अप्रीतिकर परिस्थितियों में झोंक देता है।

कुछ सालों पहले रोबोट नामक एक दक्षिण भारतीय फिल्म का हिंदी रूपांतरण बहुत लोकप्रिय हुआ था। इसमें ऐश्वर्या राय नायिका और रजनीकांत नायक की भूमिका में थे। नायक ने चिंकी नामक एक रोबोट विकसित किया था जो उसके कहे हुए सारे काम करता था। हालांकि रोबोट के दिल नहीं होता लेकिन चिंकी नामक इस रोबोट की प्रोग्रामिंग में मानवीय संवेदनाओं का स्पर्श भी था। चिंकी को अचानक नायिका से प्रेम हो जाता है और नायिका को अपना बनाने के लिए वो अपने निर्माता के सम्मुख भी एक चुनौती बन जाता है। इस फिल्म का कथानक भले ही काल्पनिक था लेकिन वैज्ञानिक और विशेषज्ञों ने इस बात पर चिंता जताई है कि यदि एआइ मशीनों ने अपनी कोई कूट भाषा विकसित कर ली तो फिर इंसान उन्हें समझ नहीं सकेगा और ऐसे में मशीनों द्वारा तकनीक का मनमाना इस्तेमाल संभव है। यह चिंता इस अध्ययन के बाद जताई गई, जिसमें पाया गया कि कुछ रोबोट परस्पर एक विशेष कूट शैली में कमांड्स का आदान-प्रदान कर रहे थे। कमांड्स यानी वो निर्देश जिनके आधार पर उन्हें संचालित होना था। यदि रोबोट अपने लिए स्वयं निर्देशों की रचना करने लगे तो मनुष्य के हाथ में क्या रह जाएगा?

यह चिंता इसलिए भी बलवती हुई है कि क्योंकि ऐसे कई 'टूल' हैं जो किसी भी लड़की के फोटो को आपत्तिजनक बना देते हैं। एआइ की भाषा में इसे बोट कहते हैं। अलग-अलग बोट शुल्क लेकर अपने ग्राहकों को यह सुविधा दे रहे हैं कि वो कोई भी फोटो साइट पर डालें और मनचाहा वीडियो या फोटो बदले में प्राप्त करें। जानकारों के अनुसार दुनिया में यह धंधा करोड़ों रुपए का हो गया है। अश्लील सामग्री का बाजार पहले भी मानव सभ्यता में गुलजार रहा है लेकिन एआइ ने जिस तरह इसे सहज और सर्वसुलभ कर दिया है, वैसा शायद पहले नहीं हुआ था। पहले तैयार अश्लील फिल्मों का बाजार होता था, अब तो लोग अपनी कुत्सित मानसिकता के साथ किसी को भी इस सामग्री का पात्र बना सकते हैं। प्रत्येक आविष्कार के अच्छे बुरे दोनों पहलू होते हैं। एआइ मानवता के लिए वरदान भी हो सकती है और अभिशाप भी। हमें एआइ के इस खतरे के प्रति आगाह रहना होगा कि कुप्रवृत्तियां इस तकनीक को मानवता के लिए अभिशाप न बनने दें।

होंडुरास का पुल और बदली नदी की राह

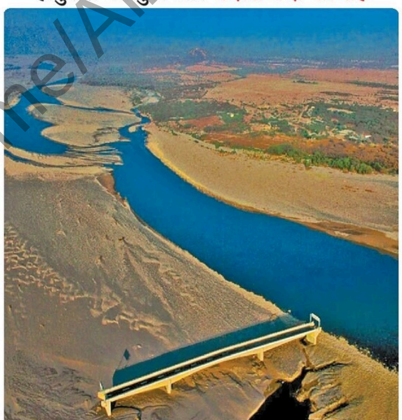

वर्ष 1998 में होंडुरास ने चोलुटेका नदी पर एक विशाल और आधुनिक पुल का निर्माण किया। इस पुल को इंजीनियरिंग की मिसाल माना गया था। लेकिन उसी वर्ष आए भयंकर तूफान 'मिच' ने सबकुछ बदल डाला। तूफान से नदी की धारा ही पूरी तरह बदल गई और चोलुटेका अब उस पुल के नीचे से नहीं बहती। परिणामस्वरूप यह शानदार पुल मजबूती से खड़ा होने के बावजूद उपयोग से बाहर हो गया। यह घटना केवल प्रकृति की ताकत का नहीं, बल्कि योजना और दूरदृष्टि के महत्त्व का प्रतीक बन गई कि कभी-कभी सबसे ठोस निर्माण भी प्रकृति की अप्रत्याशित चालों के सामने बेकार हो जाते हैं।

योजना जल संधि की बहाली की संभावना नहीं

सिंधु नदी से सूखाग्रस्त क्षेत्रों को पानी मिलने की उम्मीद

गुलाब बत्रा
वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार
@patrika.com

लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत-पाकिस्तान के मध्य संचालित सिंधु नदी जल संधि को निलंबित रखने की घोषणा दोहराने से राजस्थान सहित अन्य राज्यों को नदी जल उपलब्ध कराने की आशा बलवती हुई है। केंद्र शासित लद्दाख क्षेत्र में सिंधु नदी के तट पर बसे लेह से नदी की दिशा मोड़ने तथा नदियों के प्रमुख जलस्रोत ग्लेशियरों के संरक्षण-संवर्द्धन के अंतर्गत 'स्नो चैक डेम' योजना के क्रियान्वयन से इस लक्ष्य को जल्दी पूरा करने में सहायता मिलेगी। इसके साथ-साथ सिंधु नदी बेसिन से पाकिस्तान जा रहे पानी को भारत में उपयोग की दृष्टि से तात्कालिक मध्यम और दूरगामी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लानी होगी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक साक्षात्कार में पाकिस्तान की हरकतों के चलते निलंबित जल संधि की बहाली की संभावना को खारिज करते हुए यह भरोसा दिलाया है कि पाकिस्तान जाने वाले पानी को अब राजस्थान लाने की पहल की जाएगी। इसके लिए लगभग 200 किमी लंबी नहरों तथा एक दर्जन सुरंगों के निर्माण की योजना को क्रियान्वित किया जाएगा। विशेषज्ञों का यह मानना है कि समुद्र तल से लगभग 3500 मीटर ऊंचाई पर स्थित लेह से सिंधु नदी का पानी ग्रेविटी से राजस्थान सहित अन्य राज्यों में नहरों के निर्माण से लाया जा सकता है। गत 22 अप्रैल को पहलगाम मे बर्बर आतंकी हमले के कड़े प्रतिरोध में सिंधु नदी जल संधि निलंबित करने की अप्रत्याशित घोषणा से भारत सरकार ने पाकिस्तान को जोरदार झटका दिया। कैलाश पर्वत में मानसरोवर झील के निकट सेंगेवबब के स्रोतों से तिब्बत के पठार की चौड़ी घाटी से लेकर दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई सिंधु नदी भारत से पाकिस्तान में कराची के दक्षिण में अरब सागर में गिरती है।

भारत सरकार ने सिंधु जल समझौता निलंबित करते हुए पश्चिमी नदियों का पानी राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है। इससे श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी, नागौर, सिरोही, बालोतरा, डीडवाना, कुचामन को पानी उपलब्ध होगा। इस योजना के अंतर्गत 113 से 200 किमी लंबाई में नहरों तथा 12 सुरंगों का निर्माण किया जाएगा। चिनाब नदी के पानी को रावी व्यास और सतलुज नदियों से जोड़कर हरिके बैराज तक लाया जाएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तंत्र को और अधिक विकसित कर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में नदी जल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। एशिया की दस प्रमुख नदियों के जल भंडारक ग्लेशियरों से सिंधु, गंगा ब्रह्मपुत्र जैसी तीन प्रमुख नदियां विभाजित हुई हैं।

पश्चिमी नदियों, सिंधु झेलम चिनाब नदियों का अस्तित्व इन ग्लेशियरों के जीवन पर टिका है। इसलिए तेजी से पिघलते ग्लेशियरों को बचाने की मुहिम में तेजी आई है।

आपकी बात

सार्वजनिक परिवहन साधन बढ़ें

सार्वजनिक परिवहन के साधनों की संख्या और उनकी गुणवत्ता बढ़ाई जाए ताकि लोग निजी वाहनों की बजाय उनका उपयोग करें। कार पूलिंग तथा राइड-शेयरिंग ऐप्स को प्रोत्साहन दिया जाए। अवैध पार्किंग पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। - **मनीष अनंत**, जगदलपुर, छत्तीसगढ़

patrika.com पर पढ़ें

पाठकों की अन्य प्रतिक्रियाएं

पत्रिकायन का सवाल था, 'सड़कों पर बढ़ते वाहनों और जाम की समस्या से निजात पाने के लिए क्या विशेष उपाय किए जाने चाहिए?' ऑनलाइन देखें।

इसे स्कैन करें https://shorturl.at/J921o

समसामयिक विषयों पर पाठकों के विचार आमंत्रित हैं। चुनिंदा विचार प्रकाशित किए जाएंगे।
ईमेल करें: edit@epatrika.com

एडीआर की रिपोर्ट हत्या, बलात्कार, अवैध कब्जे, अपहरण जैसे गंभीर केस दर्ज हैं अधिकतर के खिलाफ

हमारे मंत्रियों-नेताओं के 'दामन' पर गुनाहों के बढ़ते 'दाग'

डॉ. रमेश ठाकुर
स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार
@patrika.com

साफ-सुथरी सियासी व्यवस्था की परिकल्पनाओं के बीच सफेदपोशों पर पूर्व में लगे गंभीर आपराधिक मामलों में इजाफा दिखा है। इन नेताओं-मंत्रियों पर बलात्कार, हत्या, ब्लैकमेलिंग जैसे गंभीर केस दर्ज हैं। चुनाव सुधार क्षेत्र में काम करने वाली देश की अग्रणी संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने अपनी ताजा रिपोर्ट में बिंदुवार जिक्र किया है कि किस दल के कौन-कौन नेता आपराधिक मुकदमों में फंसे हैं। कोई ऐसा दल नहीं है जिनके मंत्रियों या नेताओं पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज न हों?

रिपोर्ट में बताया है कि देशभर के 302 मंत्रियों में 174 पर गंभीर मामले इस वक्त कोर्ट में जारी हैं। मामले भी कोई छोटे-मोटे नहीं, एक से बढ़कर एक गंभीर। हत्या, बलात्कार, अवैध कब्जा, अपहरण जैसे कृत्य शामिल हैं। हिंदुस्तान में कुछ वर्षों से चुनाव सुधार और साफ-सुधरी छवि वाली राजनीतिक व्यवस्था को लेकर जो कागजी शोर मच रहा था, उसकी पोल एडीआर की ताजा रिपोर्ट ने खोल दी है।

चाहे संसद हो या राज्यों की विधानसभाएं, दागियों की संख्या में 47 फीसदी की वृद्धि बताई गई है। यानी मोटे तौर पर जनप्रतिनिधियों की आधी संख्या दागियों से भर गई है। माननीयों पर दाग वाली नई सूचना निश्चित रूप से सोचने पर विवश करती है। 27 राज्यों, तीन यूटी प्रदेश और केंद्रीय मंत्रिमंडल के कुल 643 मंत्रियों के चुनाव के वक्त दिए शपथ पत्रों की एडीआर ने छानबीन की है। उसके बाद यह सच्चाई निकल कर सामने आई। आंकड़ों में 174 दागी मंत्रियों में जो शामिल हैं उनमें भाजपा का प्रतिशत 40 और कांग्रेस का 47 फीसदी है। सर्वाधिक केस तमिलनाडु के सत्ताधारी दल द्रमुक के नेताओं पर बताए गए हैं।

> **174** *मंत्रियों पर गंभीर मामले इस वक्त कोर्ट में चल रहे हैं, देशभर के 302 मंत्रियों में से।*
>
> **47%** *की वृद्धि दागियों की संख्या में।*
>
> *(एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार)*

रिकॉर्ड 87 प्रतिशत मंत्री विभिन्न आपराधिक मामलों में लिप्त हैं। वहीं, केंद्र सरकार के 72 मंत्रियों में से 29 मंत्रियों ने अपने ऊपर आपराधिक केस होना स्वीकारा है। भाजपा के 336 मंत्रियों में से 136 पर आपराधिक केस हैं जिनमें 88 पर बहुत ही गंभीर आरोप हैं। सियासी लोग दागियों के संबंध में बातें सिर्फ जनता में करते हैं। जनता को उम्मीदें बंधाई जाती हैं कि दागी नेताओं को दल प्रमुख बाहर का रास्ता दिखाएंगे, लेकिन ऐसा कोई नहीं करता। चुनावी भाषणों में इस मसले को लेकर सिर्फ गाल बजाए जाते हैं। एडीआर की मौजूदा रिपोर्ट में कांग्रेस के 61 मंत्रियों में 45 पर, डीएमके के 31 में से 27, टीएमसी के 40 में से 13, तेलुगु देशम पार्टी के 23 में से 22, आम आदमी पार्टी के 16 में से 11 मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगे बताए हैं। क्या इन पार्टियों के प्रमुखों या संस्थापकों में इतनी नैतिकता है कि ऐसे दागियों को पार्टी से निकाल सकें। शायद नहीं।

ताज्जुब यह भी है कि इन दागियों में लगभग सभी अरबपति हैं। सभी के पास अकूत संपत्ति हैं। यानी जितने आपराधिक मामलों में वृद्धि हुई, उतनी ही दागियों की इनकम में भी इजाफा भी हुआ। एकाध राज्यों को छोड़कर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और पुडुचेरी ऐसे राज्य हैं जहां के नेताओं पर सर्वाधिक मुकदमे दर्ज हैं। हालांकि सुखद यह है कि हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, नागालैंड और उत्तराखंड के मंत्रियों पर इस समय किसी भी किस्म का कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हैं। बावजूद इसके राजनीति में सुधार और समानता की उम्मीद नहीं की जा सकती। कितने ही कानून बना लें, सख्तियां बढ़ाई जाएं, संसद या विधानसभाओं में नए कानून पारित हो जाएं, दागियों की संख्या कम नहीं होगी। ये तस्वीर भविष्य के लिए बेहद चिंतनीय और खतरनाक है। सियासी व्यवस्थाएं ऐसी बन चुकी हैं कि बिना धन या बाहुबल के कोई राजनीति में प्रवेश ही नहीं कर पाता। बगैर पैसे के चुनाव लड़ना तो संभव ही नहीं। एडीआर रिपोर्ट से यह भी पुष्टि हुई है कि बीते पांच वर्षों में कानूनों का सबसे ज्यादा दुरुपयोग माननीयों ने ही किया है।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 18 अंक 183

फेड का फैसला

अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (एफओएमसी) की बैठक पर पूरी दुनिया के वित्तीय बाजारों की नजरें टिकी रहती हैं। मगर इस बार उनकी दिलचस्पी कुछ ज्यादा ही थी। फेडरल रिजर्व ने बुधवार को नीतिगत ब्याज दर 25 आधार अंक घटाकर 4.0-4.25 फीसदी के दायरे में कर दी है। पहले यह 4.25 से 4.50 फीसदी के दायरे में थी।

वित्तीय बाजार ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद लगाए बैठा था। मगर एफओएमसी ने नीतिगत दर घटाने के निर्णय पर जिस तरह मतदान किया और भविष्य के लिए जो इशारे किए उनमें सभी की काफी दिलचस्पी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस में आर्थिक सलाहकार स्टीफन मिरान भी मंगलवार को शुरू हुई एफओएमसी की बैठक में शामिल थे। सोमवार रात अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट में मिरान को फेडरल रिजर्व बोर्ड में भेजने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई थी। मिरान फिलहाल व्हाइट हाउस से अवकाश पर हैं और केंद्रीय बैंक में कार्यकाल खत्म होने पर दोबारा अपने पुराने पद पर लौट सकते हैं। जैसा कि अनुमान जताए जा रहे थे, मिरान ने एफओएमसी बैठक में बहुमत का साथ नहीं दिया क्योंकि वह नीतिगत दर में 50 आधार अंक की कटौती के पक्ष में थे।

जो भी हो, मिरान की उपस्थिति फिलहाल फेडरल रिजर्व के लिए एकमात्र असमान्य बात नहीं है। वास्तव में फेडरल रिजर्व में उन्हें भेजा जाना एक बड़ी योजना का हिस्सा है। ब्याज दरें तेजी से नहीं घटाने के लिए फेडरल रिजर्व और इसके अध्यक्ष जेरोम पॉवेल लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के निशाने पर रहे हैं। ट्रंप ने केंद्रीय बैंक की एक गवर्नर लिसा कुक को भी हटाने की कोशिश की थी मगर न्यायालय ने उन्हें अपने पद पर बने रहने और एफओएमसी की बैठक में शामिल होने की अनुमति दे दी। ट्रंप फेडरल रिजर्व की कार्य प्रणाली पर अधिक से अधिक नियंत्रण रखना चाहते हैं। बाजार में मध्यम अवधि में काफी कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि ट्रंप की यह योजना क्या रंग दिखाती है।

एक स्वतंत्र केंद्रीय बैंक लंबे समय से अमेरिकी वित्तीय प्रणाली का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा रहा है। अमेरिकी वित्तीय तंत्र का वैश्विक वित्तीय बाजारों एवं पूंजीगत प्रवाह पर दूरगामी असर होता है। फेडरल रिजर्व या अमेरिकी बाजारों पर विश्वास डिगने से पूरी दुनिया के वित्तीय बाजारों में उथल-पुथल मच सकती है और इसके दीर्घकालिक परिणाम हो सकते हैं। निकट अवधि में होने वाली संभावित बातों का जिक्र करें तो फेडरल रिजर्व द्वारा जारी अनुमानों के अनुसार वह इस साल होने वाली दो और बैठकों में ब्याज दर में 25-25 आधार अंक की कमी कर सकता है। इसके बाद अगले वर्ष ब्याज दर में एक और कटौती हो सकती है। अमेरिकी श्रम बाजारों में दिख रही कमजोरी नीतिगत दर में कमी की एक बड़ी वजह रही है। मुद्रास्फीति को लेकर अनुमानों की जहां तक बात है तो जून की तुलना में 2026 के लिए इसे 20 आधार अंक बढ़ाकर 2.6 फीसदी कर दिया गया है। यह फेडरल रिजर्व के मध्यम अवधि के 2 फीसदी लक्ष्य से काफी अधिक है।

फिलहाल यह देखना बाकी है कि विभिन्न देशों से आयात पर शुल्क लगाने का अमेरिका में मुद्रास्फीति पर क्या असर दिखता है। मुद्रास्फीति ऊंचे स्तरों पर बनी रही तो आने वाली तिमाहियों में यह फेडरल रिजर्व के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। हालांकि, फिलहाल वित्तीय हालात आसान रहने चाहिए। उदाहरण के लिए इस महीने 10 वर्ष की अवधि के अमेरिकी सरकारी बॉन्ड पर यील्ड में 20 आधार से ज्यादा कमी आ गई है। वैश्विक स्तर पर वित्तीय हालात तुलनात्मक रूप से सहज रहने से भारत में निवेश बढ़ना चाहिए मगर आने वाली तिमाहियों में पूंजी की आमद भारत और अमेरिका के बीच व्यापार पर चल रही वार्ता पर भी काफी हद तक निर्भर रहेगी। दोनों देशों के बीच व्यापार पर जारी मौजूदा बातचीत के अनुकूल परिणाम निकलने और अमेरिकी में ब्याज दरें कम रहने से भारतीय अर्थव्यवस्था और बाजार के लिए निकट अवधि में अनिश्चितता निश्चित रूप से काफी कम हो जाएगी।

जलवायु सहयोग की दिशा में ठोस कदम

जलवायु संबंधी प्रभावी कदम उठाने के लिए आवश्यक है कि प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दरों के आधार पर साझा जिम्मेदारी तय की जाए। बता रहे हैं नितिन देसाई

पिछले माह अपने स्तंभ में मैंने जलवायु परिवर्तन की बढ़ती चुनौती और 2015 के पेरिस समझौते के अंतर्गत जताई गई प्रतिबद्धता में गंभीर कमी जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया था। मैंने कहा था कि पेरिस समझौते पर अमल में तेजी लानी होगी। खासतौर पर विकसित देशों को इसमें बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। मैं इस स्तंभ में विस्तार से यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस नवंबर में ब्राजील में होने वाली 30वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज (कॉप30) उन सिद्धांतों पर सहमति के लिए क्या कर सकती है, जो वैश्विक सहयोग और देशों के स्तर पर कार्रवाई को बढ़ावा देंगे।

मेरी नजर में सबसे महत्त्वपूर्ण सिद्धांत जिस पर जोर दिया जाना चाहिए, वह है साझा किंतु विभाजित जिम्मेदारी की भावना यानी सीबीडीआर। इस पर 1990 के दशक के आरंभ में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) में सहमति बनी थी और यह 1995 में प्रवर्तन में आया। उस समय प्रतिबद्धताओं का विभाजन एनेक्स 1 देशों और गैर-एनेक्स1 देशों में किया गया था जिनमें क्रमशः आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) तथा पूर्वी और मध्य यूरोप की इकनॉमीज इन ट्रांजिशन (ईआईटी) देश और अन्य देश आते थे। उस समय इन दोनों को विकसित और विकासशील देश माना जाता था और क्योटो प्रोटोकॉल के तहत उत्सर्जन में कमी की प्रतिबद्धता एनेक्स 1 देशों पर लागू की गई थी।

गैर एनेक्स-1 देशों के समूह को अब पूरी तरह विकासशील देशों का समूह नहीं माना जा सकता है, क्योंकि ऐसे 20 देश अब विश्व बैंक की उच्च आय वाले देशों की सूची में शामिल हो गए हैं। बहरहाल, सीबीडीआर के विरुद्ध तर्क में चीन में उत्सर्जन वृद्धि पर अधिक ध्यान दिया गया है। वहां उत्सर्जन 1995 के प्रति व्यक्ति 2.9 टन कार्बन डाइऑक्साइड से बढ़कर 2023 मे 8.4 टन प्रति व्यक्ति हो गया है। इसके चलते विकसित और विकासशील देशों के बीच साझा किंतु बंटी हुई जिम्मेदारी लगभग समाप्त हो गई है।

जलवायु परिवर्तन प्रस्तुतियों में देशों की सार्वजनिक रैंकिंग वर्तमान उत्सर्जन की मात्रा के आधार पर की जाती है, जबकि संचयी उत्सर्जन में अंतर की अनदेखी कर दी जाती है जो वास्तव में जिम्मेदारी तय करने का सही आधार है। विभिन्न देशों के आकार और उनकी नागरिक संख्या में भी भारी अंतर होता है।

यही वजह है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन करते समय हर देश के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन का आकलन करना चाहिए न कि कुल मात्रा का। भारत से यह कहना कि वह अपने उत्सर्जन की कटौती की गति बढ़ाए क्योंकि वर्ष 2023 में उसका कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन वैश्विक उत्सर्जन का लगभग 8 फीसदी था, इस तथ्य की अनदेखी करता है कि भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन वैश्विक औसत से आधे से भी कम था। कुल वार्षिक उत्सर्जन को आधार बनाकर न केवल यूरोपीय सरकारों द्वारा, बल्कि पश्चिमी देशों के कई गैर-सरकारी संगठनों द्वारा भी चिंता जताई जाती है। यह दृष्टिकोण गलत है। किसी भी देश द्वारा उत्सर्जन में कमी की वास्तविक ताकत का मूल्यांकन कुल उत्सर्जन नहीं, बल्कि प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के आधार पर किया जाना चाहिए।

आंकड़े बताते हैं कि विकसित एनेक्स1 देशों के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन में कमी आई है जबकि अधिकांश गैर एनेक्स 1 विकासशील देशों में उत्सजर्न बढ़ा है। परंतु दोनों समूहों के बीच बुनियादी भारी अंतर बरकरार रहा। वर्ष2023 में 100 गैर एनेक्स 1 देशों का प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 3 टन से कम था। एनेक्स 1 देशों में से कोई इस श्रेणी में नहीं आया। इसके अलावा एनेक्स 1 की 41 फीसदी आबादी वाले देशों का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक था जबकि गैर एनेक्स1 आबादी में केवल 2 फीसदी आबादी ऐसी थी।

सीबीडीआर की आवश्यकता आज भी बनी हुई है। यह केवल एनेक्स 1 और गैर एनेक्स 1 देशों के बीच मूल मांगों के अंतर पर केंद्रित नहीं रह सकती, क्योंकि अब गैर एनेक्स 1 समूह में ऐसे 20 देश शामिल हैं जो विश्व बैंक की उच्च-आय श्रेणी में आते हैं। इसलिए, देशों के बीच अंतर को प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। प्रति व्यक्ति उत्सर्जन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता इस रणनीति पर आधारित है, जिसका उद्देश्य भविष्य के उत्सर्जन को सीमित करना है ताकि औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1.5-2.0 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखा जा सके।

आईपीसीसी ने 2021 में अपनी छठी आकलन रिपोर्ट में 2020 से 2050 तक के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का अनुमान पेश किया जो तापमान में परिवर्तन के लक्ष्य को सीमित रखने के साथ सुसंगत होगा। हर वर्ष की जनसंख्या के योग से विभाजित करने पर वार्षिक औसत उत्सर्जन मिलता है जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य के लिए 1.1 टनकार्बन डाइऑक्साइड का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन और 2 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य के लिए 3.3 टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रति व्यक्ति उत्सर्जन। इस आधार पर, सभी देशों के लिए वार्षिक उत्सर्जन लक्ष्य को प्रति व्यक्ति औसतन 3 टन कार्बन डाइऑक्साइड तक निर्धारित किया जा सकता है जो उनके घोषित विशुद्ध शून्य लक्ष्य वर्ष तक लागू रहेगा। हालांकि यह लक्ष्य 1.5 डिग्री सेल्सियस के लिए पर्याप्त नहीं है, जो वर्तमान में असाध्य प्रतीत होता है। लेकिन यदि 2050 तक का वैश्विक प्रति व्यक्ति औसत तुरंत स्वीकार कर लिया जाए और प्रभावी रूप से लागू किया जाए, तो 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य को पुनर्जीवित करने की संभावना बन सकती है और साथ ही स्वीकृत वैश्विक प्रति व्यक्ति उत्सर्जन लक्ष्य को क्रमशः घटाया जा सकता है।

पेरिस समझौते के आधार पर अपेक्षित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) में घोषित विशुद्ध शून्य लक्षित वर्ष तक पहुंचने की योजना शामिल होनी चाहिए। इसमें ऐसे उपाय होने चाहिए जिनसे अगले दशकों में औसत उत्सर्जन 3 टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रति व्यक्ति हो। इस बात पर जोर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि कुछ ही देशों ने विशुद्ध शून्य लक्ष्य तक पहुंचने के लिए समयसीमा निर्धारित की है।

वर्तमान समय में अमेरिका जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक प्रयासों में सहयोग नहीं कर रहा है। वह पेरिस समझौते से अलग हट गया है। इसे ध्यान में रखते हुए अब नेट जीरो लक्ष्यों पर कोई भी समझौता पेरिस समझौते को लागू करने की प्रतिबद्धता के साथ किया जाना चाहिए। इससे वार्ताओं में अमेरिका हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा।

संक्षेप में, लक्ष्य इस प्रकार होने चाहिए:

1. उच्च उत्सर्जन दर वाले देशों द्वारा जलवायु शमन कार्रवाई के लिए तत्काल अधिक जिम्मेदारी लेने के लिए सीबीडीआर के सिद्धांत का दृढ़ता से पालन किया जाना चाहिए।
2. पहले की तरह एनेक्स I और गैर-एनेक्स I देशों के बीच के अंतर के समान ही दो समूहों के बीच का अंतर वार्षिक प्रति व्यक्ति उत्सर्जन पर आधारित होना चाहिए।
3. देशों को दो समूहों में विभाजित करने का मानक 3 टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष होना चाहिए।
4. सभी देशों को नेट जीरो उत्सर्जन तक पहुंचने के लिए लक्ष्य वर्ष निर्धारित करना होगा और इसके लिए समयसीमा के हिसाब नीति बनानी होगी, जिसका उद्देश्य विशुद्ध शून्य लक्ष्य तक पहुंचने वाले वर्षों में 3 टन कार्बन डाइऑक्साइड का औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति उत्सर्जन करना हो।

मुझे उम्मीद है कि वर्तमान में प्रति व्यक्ति 2.1 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन वाले भारत और 2.3 टन वाला ब्राजील इस एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए मिल कर काम करेंगे।

निजी बैंकों के मुकाबले सरकारी बैंकों का प्रदर्शन फिर बेहतर

बैंकिंग साख

तमाल बंद्योपाध्याय

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अपने समकक्ष निजी बैंकों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करना जारी रखा है। मार्च तिमाही में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद, इन बैंकों ने मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में फिर से अपनी चमक बिखेरी है।

पंजाब नैशनल बैंक को छोड़कर, जून तिमाही में सार्वजनिक क्षेत्र के हर बैंक ने सालाना आधार पर शुद्ध लाभ में बढ़ोतरी दर्ज की है और यह बढ़ोतरी 75.57 फीसदी (इंडियन ओवरसीज बैंक) से 1.87 फीसदी (बैंक ऑफ बड़ौदा) के बीच देखी गई।

इसके विपरीत, कम से कम 8 निजी बैंकों का शुद्ध लाभ घट गया है। बड़े निजी बैंकों में, ऐक्सिस बैंक का शुद्ध लाभ 3.79 फीसदी कम हुआ जबकि इंडसइंड बैंक ने शुद्ध लाभ में 68.21 फीसदी की गिरावट दर्ज की। निजी बैंकों के कुल शुद्ध लाभ में लगभग 3 फीसदी की कमी आई जबकि सरकारी बैंकों का शुद्ध लाभ 10.62 फीसदी तक बढ़ा।

पूर्ण आंकड़ों के संदर्भ में देखें तो भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) 19,160 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ के साथ आगे रहा। इसके बाद एचडीएफसी बैंक (18,155 करोड़ रुपये) और आईसीआईसीआई बैंक (12,768 करोड़ रुपये) का स्थान रहा। 5,000 करोड़ रुपये से अधिक का शुद्ध लाभ दर्ज करने वाला एकमात्र अन्य बैंक ऐक्सिस बैंक (6,035 करोड़ रुपये) है। वहीं, दूसरी ओर केवल एक सरकारी बैंक (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया) के परिचालन लाभ में कमी आई।

निजी बैंकों के समूह का शुद्ध लाभ जून तिमाही में कम हो गया, हालांकि उनके परिचालन लाभ में शानदार बढ़ोतरी देखी गई और यह सरकारी बैंक की तुलना में अधिक था। एचडीएफसी बैंक, 35,734 करोड़ रुपये के परिचालन लाभ के साथ सबसे आगे रहा। उसके बाद एसबीआई (30,544 करोड़ रुपये) का स्थान था। दो अन्य निजी बैंकों ने 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का परिचालन लाभ दर्ज किया जिनमें आईसीआईसीआई बैंक (18,746 करोड़ रुपये) और ऐक्सिस बैंक (11,515 करोड़ रुपये) शामिल हैं।

सरकारी बैंकों की तुलना में अधिक परिचालन लाभ दर्ज करने के बावजूद, निजी बैंक शुद्ध लाभ के मामले में पीछे रह गए क्योंकि उन्होंने सरकारी बैंकों की तुलना में कहीं अधिक प्रावधान किए हैं। जून तिमाही में निजी बैंकों का कुल प्रावधान 9,844 करोड़ रुपये से बढ़कर 27,661 करोड़ रुपये हो गया। इसके उलट, सरकारी बैंकों का प्रावधान 17,004 करोड़ रुपये से घटकर 15,918 करोड़ रुपये रह गया।

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, जम्मू ऐंड कश्मीर बैंक लिमिटेड, करूर वैश्य बैंक लिमिटेड और तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड को छोड़कर, बाकी सभी निजी बैंकों ने ऋण संपत्तियों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जून तिमाही में अपने प्रावधान बढ़ाए। इसके विपरीत, सात सरकारी बैंकों ने अपने प्रावधानों में कटौती की।

सबसे अधिक प्रावधान एचडीएफसी बैंक द्वारा किया गया (14,442 करोड़ रुपये) जो सभी निजी बैंकों के प्रावधान का लगभग आधा और पूरे उद्योग के प्रावधान का लगभग एक-तिहाई है। यह पिछले साल की तिमाही में किए गए 2,602 करोड़ रुपये और पिछली तिमाही में 3,193 करोड़ रुपये के प्रावधान के मुकाबले काफी ज्यादा है।

भले ही कुल ऋणों के प्रतिशत के रूप में एचडीएफसी बैंक की शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए या फंसे कर्ज) 1 फीसदी से कम रहीं लेकिन वे जून 2024 के 0.43 फीसदी से बढ़कर जून 2025 में 0.47 फीसदी हो गईं।

छह बैंकों को छोड़कर, जून तिमाही में सभी सूचीबद्ध बैंकों के शुद्ध एनपीए 1 फीसदी से कम रहे हैं जिनमें सभी सरकारी बैंक भी शामिल हैं और अधिकांश बैंकों ने इसमें गिरावट का रुझान दिखाया है।

एचडीएफसी बैंक के अलावा, इस सूची में आईसीआईसीआई बैंक, ऐक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, येस बैंक लिमिटेड, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड और अन्य शामिल हैं। करीब एक फीसदी से अधिक शुद्ध एनपीए वाले निजी बैंकों में इंडसइंड बैंक और बंधन बैंक लिमिटेड शामिल हैं। आईडीबीआई बैंक का शुद्ध एनपीए सबसे कम (0.21 फीसदी) है। वहीं सरकारी बैंकों में, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन बैंक का एनपीए सबसे कम (0.18 फीसदी) है।

बंधन बैंक का सकल एनपीए सबसे अधिक (4.96 फीसदी) है और इसके बाद इंडसइंड बैंक (3.64 फीसदी) का स्थान है। आठ अन्य बैंकों के सकल एनपीए, कम से कम 3 फीसदी हैं जिनमें पांच सरकारी बैंक और तीन निजी बैंक शामिल हैं। करूर वैश्य बैंक लिमिटेड एकमात्र ऐसा बैंक है जिसका सकल एनपीए 1 फीसदी से कम (0.66 फीसदी) है।

अब हम बैंकिंग उद्योग की सेहत का आकलन करने के लिए कुछ अन्य मापदंडों का जायजा लेते हैं। सूचीबद्ध सार्वभौमिक बैंकों की औसत जमा वृद्धि लगभग 11 फीसदी है और यह ऋण वृद्धि 10 फीसदी से थोड़ी अधिक है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जमाओं में 26.4 फीसदी वृद्धि और ऋण में 21 फीसदी वृद्धि के साथ सबसे आगे है। सीएसबी बैंक लिमिटेड ने अपनी जमा राशि को 20 फीसदी से थोड़ा अधिक और ऋण को 31.3 फीसदी बढ़ाया है लेकिन इसका आधार बहुत कम था।

बड़े बैंकों में, एसबीआई की जमा राशि सालाना आधार पर 11.7 फीसदी बढ़ी है, लेकिन तिमाही आधार पर वृद्धि सिर्फ 1.7 फीसदी रही है। वहीं एचडीएफसी बैंक ने सालाना आधार पर ऋण में 6.7 फीसदी की वृद्धि दिखाई है।

कई बैंकों ने जून 2024 की तुलना में जून 2025 तिमाही में ऋण में दो अंकों की वृद्धि दर्ज की है वहीं, कम से कम 9 बैंकों ने अपने ऋण खाते में तिमाही आधार पर 5 फीसदी से 1 फीसदी के बीच कमी देखी है।

आखिरकार हम इस बात का जायजा लेते हैं कि बैंकों ने शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) और चालू एवं बचत खाता (कासा) जैसे दो अहम मापदंडों के लिहाज से कैसा प्रदर्शन किया। कुछ अपवादों को छोड़कर, जून की तिमाही में सालाना और तिमाही आधार पर अधिकांश बैंकों के एनआईएम और कासा दोनों में कमी आई। यह रुझान कुछ तिमाहियों से बरकरार है।

एसबीआई का कासा सालाना आधार पर 40.7 फीसदी से घटकर 39.36 फीसदी हो गया। इस अवधि के दौरान, इसका एनआईएम 3.22 फीसदी से कम होकर 2.9 फीसदी हो गया। वहीं एचडीएफसी बैंक का कासा 36 फीसदी से घटकर 34 फीसदी हो गया और एनआईएम 3.47 फीसदी से घटकर 3.35 फीसदी हो गया।

निश्चित रूप से एनआईएम पूरी कहानी को बयां नहीं करता है। असुरक्षित ऋणों पर ब्याज दरें अधिक होती हैं और इसके कारण एनआईएम अधिक होता है लेकिन अगर ये फंसे ऋण में तब्दील हो जाते हैं तो इनकी रिकवरी बैंकों के लिए मुश्किल हो जाती है।

अंत में यह कहा जा सकता है कि बैंकिंग क्षेत्र का बेहतर प्रदर्शन जारी है लेकिन इसमें परिसंपत्ति और देनदारी के मोर्चे पर चुनौतियां भी हैं। जमाओं के लिए प्रतिस्पर्द्धा बढ़ रही है जबकि ऋण के मांग में सुस्ती है। हालांकि अच्छी बात यह है कि बैंक मौजूदा चुनौतियों के हिसाब से ही अपनी राह तय कर रहे हैं।

(लेखक जन स्मॉल फाइनैंस बैंक के वरिष्ठ सलाहकार हैं)

आपका पक्ष

भारत-अमेरिका का गतिरोध समाप्त हो रहा

भारत-अमेरिकी व्यापार वार्ता पर प्रगति संबंधी लेख दोनों देशों के बीच टैरिफ को लेकर गतिरोध के बावजूद दोनों देशों में आपसी व्यापार सहमति और संबंधों को सुधारने के प्रयासों के फलीभूत होने को पुष्ट करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने संभवतः भारत के साथ अपने विचित्र व्यवहार से वैश्विक समीकरणों को बदलने के दुष्परिणामों के अनुमान और अमेरिका पर उसके दीर्घकालिक प्रभाव को देखते हुए भारत के साथ व्यापार और राजनयिक संबंधों को सामान्य करने का प्रयास किया है जो प्रशंसनीय है। अमेरिका को यह भी समझ आ जाना चाहिए कि भारत के साथ व्यापार में अमेरिका को कोई घाटा नहीं है, बल्कि फायदा ही है। हमारे विद्यार्थियों की फीस, वीजा, एमेजॉन जैसी कंपनियों के लाभ का अमेरिका को ट्रांसफर, विशालकाय इन्वेस्टमेंट कंपनियों के लाभ का आकलन करें तो कुल मिलाकर

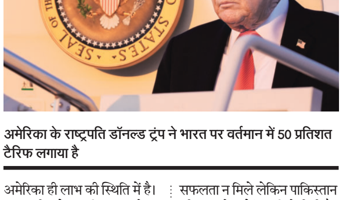

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने भारत पर वर्तमान में 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है

अमेरिका ही लाभ की स्थिति में है। भारत की अपेक्षा पाकिस्तान को तरजीह देना, अमेरिका के लिए घातक है क्योंकि पाकिस्तान तो नाटो जैसा इस्लामिक संगठित करने का प्रयास कर रहा है, भले ही इसमें सफलता न मिले लेकिन पाकिस्तान की मंशा तो अमेरिका विरोधी ही है। वास्तव में अमेरिका को तो पाकिस्तान का त्याग ही कर देना चाहिए क्योंकि जिस सामरिक लाभ के लिए अमेरिका और अन्य सुपर पावर पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अपना केंद्र बनाना चाहते हैं उनको समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान तो अफगानिस्तान से बुरी स्थिति में आ चुका है और सामरिक दृष्टि से किसी के लिए लाभप्रद नहीं है। पाकिस्तान को तो इस्लामिक देश भी कोई महत्त्व नहीं देते। चीन भी पाकिस्तान में अपने निवेश डुबो चुका है। भारत और अमेरिका के संबंध विश्व में संतुलन स्थापित कर सकते हैं परंतु अमेरिका भारत और रूस के संबंधों पर कोई विपरीत रुख न अपनाए।

विनोद जौहरी, दिल्ली

पराली जलाने वालों के लिए कठोर दंड का हो प्रावधान

पिछले दिनों उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली-एनसीआर में शीतकाल के समय वायु प्रदूषण के कारक पराली जलाने वाले किसानों को जेल भेजने की चेतावनी दी और कहा कि इससे सही संदेश जाएगा। ठंड के मौसम में दिल्ली के आसपास के राज्यों में पराली जलाने के कारण वायु प्रदूषण स्तर जानलेवा हो जाता है। अदालत ने यह भी कहा कि सरकार सभी पक्षों के साथ इस मुद्दे का हल नहीं निकाल पाती तो वह परमादेश जारी कर सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि एक अधिकारी कई गांवों की निगरानी नहीं रख सकते हैं। दिल्ली में दीवाली के आसपास प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में पराली जलने से वह धुआं दिल्ली के वातावरण को ढक देता है। इस वजह से दिल्ली में पिछले साल प्रदूषण का स्तर 900 से 1,000 तक पहुंच गया था। पिछले कई वर्षों से इस समस्या का हल निकालने की कोशिश की गई लेकिन अभी तक इसका स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। अगर अदालत द्वारा कठोर कार्रवाई की जाए तो शायद कुछ राहत मिले।

मोहित कुमार, नई दिल्ली

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

उत्तराखंड के चमोली जिले के नंदानगर के पास गुरुवार तड़के चार स्थानों पर बादल फटने, बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में 14 लोग लापता हो गए और 20 घायल हो गए। इस आपदा से 200 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। प्रभावित लोगों को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

CCI NG 3.7 Product: NBTMumbaiBS PubDate: 19-09-2025 Zone: Mumbai Edition: 1 Page: NBTMTEN User: cci Time: 09-18-2025 22:32 Color:

नवभारत टाइम्स • विचार

नवभारत टाइम्स । मुंबई । शुक्रवार, 19 सितंबर 2025

दोस्ती की नींव ईमानदारी और विश्वास होने चाहिए। दोस्ती सोच-समझकर निभानी चाहिए न कि आंख मूंदकर।
–चाणक्य

चिंता की बात

पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच स्ट्रैटिजिक म्युचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है। इसके मुताबिक, किसी एक के प्रति दिखाई गई आक्रामकता दूसरे के खिलाफ भी मानी जाएगी, कुछ वैसा ही समझौता जैसा नैटो के सदस्य देशों के बीच है। भले कहा जा रहा हो कि यह समझौता पाकिस्तान और सऊदी अरब के लंबे ऐतिहासिक रिश्तों का परिणाम है, लेकिन भारत के लिए यह डिवेलपमेंट चिंता बढ़ाने वाला है।

पाक-सऊदी समझौता

बढ़ता सहयोग । सऊदी अरब खाड़ी में भारत के करीबी सहयोगियों में से एक है। व्यापार, निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा सहयोग समेत कई क्षेत्रों में दोनों के बीच पिछले दो दशकों में संबंध गहरे हुए हैं- खासकर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के दौर में नई तरह की गर्मजोशी देखने को मिली है। पीएम नरेंद्र मोदी इस साल अप्रैल में ही अपने तीसरे सऊदी दौरे पर गए थे, जहां दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति बनी थी।

सबसे बड़ी आशंका । केवल सऊदी ही नहीं, क्षेत्र के दूसरे देशों के साथ भी भारत का सहयोग बढ़ रहा है। UAE के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और ओमान व कतर के साथ बात चल रही है। लेकिन, सऊदी अरब-पाकिस्तान समझौते से इस क्षेत्र में भारत की कोशिशों को झटका लग सकता है। चार महीने पहले ही भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़ा संघर्ष हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बॉर्डर पर अब भी तनाव है। ऐसे में यह आशंका दरकिनार नहीं की जा सकती कि भारत और पाकिस्तान के तनाव में इस समझौते की वजह से सऊदी अरब भी पार्टी बन जाए।

इस्राइल का असर । समझौते का एक और अहम एंगल है, हाल में इस्राइल ने कतर की राजधानी दोहा पर एयर स्ट्राइक कर हमास के नेताओं को निशाना बनाने का प्रयास किया था। इसे लेकर मुस्लिम वर्ल्ड में काफी गुस्सा है। इस हमले के बाद दोहा में इस्लामिक देशों का आपातकालीन शिखर सम्मेलन बुलाया गया था, जहां यह चर्चा भी उछली कि क्या नैटो जैसा कोई संयुक्त सुरक्षा बल बनाया जा सकता है। अब दूसरे मुस्लिम देश भी इस तरह के समझौते की संभावना टटोल सकते हैं।

सऊदी से बात । इस रक्षा समझौते से पूरे क्षेत्र में असंतुलन पैदा हो सकता है। भारत ने कहा है कि वह इसके असर को देखेगा। सरकार को अपनी चिंताओं को लेकर सऊदी अरब से खुलकर बात करनी चाहिए। ध्यान रखना होगा कि यह समझौता किसी भी तरह से नई दिल्ली-रियाद संबंधों के आड़े न आए।

ये क्या बात हुई

Gen Z की ग़लती

हर गली नुक्कड़ पर आजकल एक नया शगल शुरू हो गया है - जेनरेशन Z का मज़ाक उड़ाना। जैसे ही कोई बच्चा या टीनेजर फोन हाथ में ले, बड़े-बुजुर्गों की आंखें घूमकर उसे ऐसे घूरती हैं जैसे वो च्युइंग गम नहीं, चंद्रयान-3 निगल गया हो। सवाल भी वही घिसा-पिटा - इतने छोटे से बच्चे के हाथ में भी फोन किसने पकड़ा दिया? जनाब, उसी ने पकड़ा दिया जिसने आपको टीवी पर 'हम लोग' और 'चित्रहार' की लत लगवाई थी, जिसके लिए आप कृषि दर्शन से पहले इंद्रधनुषी रंगीन पट्टियों तक को मज़े से घूरते थे। फर्क बस इतना है कि आपके पास तब 14-इंच का बक्सा था, इनके पास 6-इंच का। ग़लती बेचारे Gen Z की बस इतनी है कि उनके ज़माने में स्मार्टफोन हुआ। अगर यही फोन आपके हाथों में जवानी के दिनों में आता तो गली-कूचों में क्रिकेट और कंचे खेलने की बजाय सब Snake खेल रहे होते और फोन पर 'आवारा हूं' रिंगटोन सेट करने की होड़ लगी होती। सच मानिए, आज जो लोग Gen Z को 'नशेड़ी' कहकर फोन छुड़वाने की कोशिश करते हैं, वही लोग मेट्रो, मीटिंग और मंदिर सब जगह वॉट्सऐप फॉरवर्ड ठोकते मिलते हैं और अगर इनके गुड मॉर्निंग मेसेज का रिप्लाई न करो तो फिर बच्चों से नाराज़ भी हो जाते हैं। एक और आरोप, Gen Z अपने मां-बाप की इज़्ज़त नहीं करती, गुस्सैल है, मुंहफट है। लेकिन थोड़ा इतिहास खंगालिए। हर पीढ़ी अपने समय के बड़ों से टकराती रही है। अगर ऐसा न होता तो अमिताभ बच्चन का 'एंग्री यंग मैन' इतना सुपरहिट कैसे होता? उस दौर के नौजवानों की तल्खी और बग़ावत ही तो उस किरदार में झलकती थी। फर्क बस इतना है कि उस वक़्त उन्हें 'एंग्री यंग मैन' कहकर इज़्ज़त दी गई और आज Gen Z को हर वक्त 'बदतमीज़' का टैग चिपकाया जाता है। अगर जेन Z आज आपके क्रेडिट कार्ड को स्वाइप कर रहा है तो आप भी पापा की पॉकेट से, घर के गुल्लक से नोट उड़ा ही लिया करते थे। प्रॉब्लम बस ये है कि Gen Z का हर शरारती पल, सैयारा जैसी मूवी में रोना धोना, सब कुछ रील बनकर सबको दिख जाता है।

नमिता जोशी

एकदा

संकलन : रिंकल शर्मा

टॉल्सटॉय की भेंट

रूसी साहित्यकार लियो टॉल्स्टॉय (1828–1910) महान लेखक ही नहीं, गहरे चिंतक, सुधारक और मानवता के सच्चे उपासक भी थे। एक दिन वह अपने गांव में खेतों के पास टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि एक गरीब किसान नंगे पांव तपती धरती पर हल चला रहा है। खेत की मिट्टी गरम थी, जिससे उसके पैर छिल चुके थे और खून रिस रहा था। टॉल्स्टॉय ने पास जाकर पूछा, 'भाई, तुम नंगे पैर क्यों हो? जूते क्यों नहीं पहन लेते?' किसान ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, 'साहब, जूते खरीदने लायक पैसे कहां से लाऊं? जैसे-तैसे परिवार के लिए अन्न जुटा पाता हूं।' किसान की यह स्थिति देखकर टॉल्स्टॉय बेचैन हो उठे। वह उस समय कुछ बोले नहीं, लेकिन अगले ही दिन जूते लेकर उसी किसान के खेत पर गए। जब किसान को टॉल्स्टॉय ने जूते भेंट किए, तो उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, 'साहब, आपने मुझे जूते नहीं दिए, बल्कि जीवन की राह आसान कर दी। अब मैं और ज्यादा काम कर पाऊंगा।' किसान की बात सुनकर टॉल्स्टॉय मुस्कुरा दिए। उनका मानना था कि महान का मतलब दूसरों के दुख बांटना है।

Subrata Dhar
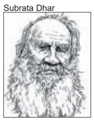

इस्राइल से क़रीबी बढ़ी, लेकिन इंडिया 'टू स्टेट सॉल्यूशन' का पैरोकार

भारत ने पकड़ा पुराना रास्ता

26 नवंबर 1938 को महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका में लिखा था, 'फलस्तीन अरबों के लिए वैसा ही है, जैसा इंग्लैंड अंग्रेजों के लिए और फ्रांस फ्रेंच लोगों के लिए।' आजादी के बाद पंडित नेहरू की ओर से संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) में फलस्तीन के बंटवारे के विरोध से लेकर इस साल जून में गाजा में सीजफायर के UN प्रस्ताव से गैरहाजिर रहने तक, भारत की विदेश नीति ने कई पड़ाव देखे हैं। लेकिन बीते 5 दिनों में हुए घटनाक्रम ने फलस्तीन-इस्राइल संकट पर विदेश नीति को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है।

अल्पयू सिंह

बैलेंस शिफ्ट । संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में भारत ने फलस्तीन को अलग राज्य का दर्जा दिए जाने से जुड़े न्यूयॉर्क घोषणा के पक्ष में वोट किया। दोहा पर इस्राइली हमले का भी कड़े शब्दों में विरोध किया। इसके बाद कहा जा रहा है कि फलस्तीन को समर्थन देने की अपनी पुरानी विदेश नीति पर हम लौटते दिख रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से 12 जून 2025 तक भारत की नीति में कथित 'डिप्लोमैटिक बैलेंस शिफ्ट' की चर्चा हुई। कहा गया कि इस दौरान हमारा झुकाव इस्राइल की ओर साफ तौर पर दिखा।

टू स्टेट सॉल्यूशन । बीते दो वर्षों में विपक्ष ने भी इस मसले पर कई बार कहा कि भारत ने फलस्तीन को लेकर नीति में बदलाव किया है। इसके बाद सरकार की ओर से विदेश मंत्री को बीते साल दिसंबर में संसद में कहना पड़ा कि सरकार 'टू स्टेट सॉल्यूशन' को मानती आ रही है। हालांकि इस स्पष्टीकरण के बाद भी यह सवाल विपक्ष से लेकर आम लोगों तक सबके ज़हन में बना हुआ है कि क्या भारत सरकार ने बीते दो साल में मध्य पूर्व की अपनी विदेश नीति की दिशा में बदलाव किया है?

संतुलन साधने की कोशिश
- इस्राइल से कई क्षेत्रों में बढ़ा सहयोग
- UN में कई मौकों पर वोटिंग से अलग रहा भारत
- मगर UN के हालिया प्रस्ताव को दिया समर्थन

सवाल क्यों उठे । 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इस्राइल में किए गए हमले को भारत ने तत्काल आतंकवादी हमला करार दिया था। हमले के बाद शुरुआती 3 दिनों में पीएम मोदी की ओर से जारी बयानों में कहा गया कि भारत आतंक के खिलाफ इस्राइल के साथ मजबूती से खड़ा है। इन बयानों में फलस्तीन का कहीं जिक्र नहीं था। 27 अक्टूबर को UNGA ने आपातकालीन सत्र बुलाकर इस्राइल और हमास के बीच मानवीय आधार पर तुरंत सीजफायर करने का प्रस्ताव पारित किया। भारत ने इस प्रस्ताव से एब्सटेन किया।

3 साल में चार एब्सटेन । UN में भारत के इस तरह के रुख को उसकी वोटिंग पॉलिसी में शिफ्ट की तरह देखा गया। खास तौर पर इसलिए भी कि मानवीय आधार पर ऐसे मामलों में भारत हमेशा स्पष्ट रुख लेता रहा है। गाजा में सीजफायर से जुड़े प्रस्तावों को लेकर भारत ने बीते 3 वर्षों में 4 बार एब्सटेन किया। हाल ही में 12 जून को सीजफायर के ऐसे ही प्रस्ताव से पीछे हटने को लेकर भी सरकार विपक्ष के निशाने पर आई।

इस्राइल से करीबी । हाल के सालों में, ख़ासकर पीएम मोदी के आने के बाद भारत की विदेश नीति में इस्राइल और फलस्तीन के साथ रिश्तों को लेकर थोड़ा बदलाव देखने को मिला है। इस्राइल के साथ रिश्ते गहरे हुए हैं। वह भारत का प्रमुख रक्षा साझेदार है। पीएम मोदी की 2017 में इस्राइल यात्रा के बाद से दोनों देशों के बीच कृषि, जल प्रबंधन, तकनीक और रक्षा मामले में सहयोग बढ़ा है। इसके 1 साल बाद पीएम मोदी फलस्तीन गए थे, वहां उन्होंने स्वतंत्र और संप्रभु फलस्तीन का जिक्र तो किया, लेकिन अखंड शब्द से परहेज किया। लंबे समय से भारत फलस्तीन के लिए स्वतंत्र, संप्रभु और अखंड शब्द का इस्तेमाल करता रहा है। 2012 में डॉ. मनमोहन सिंह और 2015 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी इसी शब्दावली का प्रयोग किया था।

गाजा में भुखमरी । बीते कुछ महीने से गाज़ा में इस्राइल की कार्रवाई से पैदा हुए हालात ने गंभीर मानवीय संकट खड़ा कर दिया है। UN के स्वतंत्र जांच आयोग ने इसे इस्राइल की ओर से नरसंहार करार दिया है। फ्रांस समेत कई दूसरे देश फलस्तीन को मान्यता देने की बात कह चुके हैं। जाहिर है, बीते दिनों इस मसले पर पश्चिम के ताक़तवर देशों की ख़ामोशी को तोड़ने के मद्देनजर एक वैचारिक ज़मीन तैयार हुई है। इसके पीछे गाजा से आई भुखमरी की वह तस्वीर है, जिसने दुनिया भर के लोगों में गुस्सा पैदा किया है।

पुराने रुख पर वापसी । इसकी वजह से कई देश इस्राइल के खिलाफ रुख लेने पर मजबूर हुए हैं। जानकारों के मुताबिक, भारत को भी समझते हुए फलस्तीन पर अपनी पहले की नैतिक-वैचारिक नीति के ट्रैक पर लौटना ही होगा। UN के सीजफायर प्रस्ताव का समर्थन उसी दिशा में एक कदम है।

मोदी सरकार में छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ा

दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत आकार में बड़ा और विविधता से भरा है, ऐसे देश में बदलाव करना शासन के जरिए आसान नहीं होता। इसके बावजूद एक दशक के भीतर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सूरत बदलने वाले महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल किए गए हैं।

विष्णु देव साय

राज्य का 25वां साल । हमने 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस मनाया। हमारे लिए यह मौका छत्तीसगढ़ की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के जश्न का भी है। इस वर्ष होने वाले राज्योत्सव को लेकर छत्तीसगढ़ के लोगों में इस बात की बेहद खुशी है कि 25 वर्ष की इस विकास यात्रा को सबसे ज्यादा ताकत देने वाले शख्सियत रहे प्रधानमंत्री मोदी जी भी भागीदारी करेंगे।

चांद पर तिरंगा । मेरा बचपन जशपुर में बीता। हमारे गांवों तक जाने के लिए सड़कें तो दूर पगडंडी भी नहीं होती थी। आज हम भारतमाला की चमचमाती सड़कों पर व्यस्त ट्रैफिक और बढ़ते कारोबार को हर दिन महसूस करते हैं। पीएम मोदी ने भारत में भी बुलेट ट्रेन चलाने का निश्चय किया है। उनके नेतृत्व में देश ने चांद पर तिरंगा लहराया है और अब हम स्पेस मिशन की तैयारी कर रहे हैं।

खाद्य सुरक्षा की पहल । जब पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया था तो न ही धान खरीदी की पुख्ता व्यवस्था थी और न ही खाद्य सुरक्षा। यह BJP सरकार ही थी, जिसने धान खरीदी का मॉडल बनाया और खाद्य सुरक्षा का मॉडल भी। पीएम मोदी ने केंद्र के पूल से धान खरीदी का कोटा बढ़ाकर देश के खाद्य सुरक्षा मॉडल को मजबूत किया है।

कॉमनरूम

शून्य बिजली बिल । आज आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं तो पूरी सूरत बदली नजर आती है। खपरैल वाले घरों की जगह पक्के प्रधानमंत्री आवासों ने ले ली है। पनघट पर जाती हुई महिलाएं भी नजर नहीं आती क्योंकि जल जीवन मिशन से शुद्ध स्वच्छ जल घर पहुंच रहा है। शौच के लिए खुले में जाने की पीड़ा से भी महिलाएं मुक्त हुई हैं। छत्तीसगढ़ में हमने लोगों को सोलर पैनल में केंद्र तथा राज्य सरकार की अनुदान राशि का लाभ देकर शून्य बिजली बिल के लक्ष्य की ओर बढ़ाया है।

तेज ग्रोथ की राह पर देश । जब दुनिया का हर देश अस्थिरता का सामना कर रहा है और बदहाल आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है भारत की अर्थव्यवस्था की 7.8 प्रतिशत की दर से तरक्की कर रही है। यह पीएम मोदी की दूरगामी नीतियों की वजह से संभव हुआ। बस्तर में हमने 450 से ऊपर माओवादियों को न्यूट्रलाइज किया है। मार्च 2026 तक हम माओवाद को देश से उन्मूलन के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी की योजनाएं तेजी से आर्थिक विकास के साथ नए अवसरों का सृजन करती हैं। पहले कहा जाता था कि मोदी हैं तो मुमकिन है अब सब यह कहते हैं कि मोदी है तो निश्चित है।

(लेखक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं)

कांटे की बात

98 साल की उम्र में ट्रोलर्स के सामने खड़ी 'मां'

सप्ताह की शख्सियत

मलयालम साहित्य की जानी-मानी रचनाकार एम. लीलावती को केरल में 'मां की आवाज' कहा जाता है। पढ़ने वाले उन्हें स्नेह से 'टीचर' भी कहते हैं। लेकिन, अपने 98वें जन्मदिवस पर जब उन्होंने गाजा में भूख से तड़प रहे बच्चों का समर्थन किया, तो उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा।
– शैलेंद्र पांडेय

सोशल मीडिया पर होने वाली बदतमीजी किसी को भी तोड़ सकती है, पर लीलावती टूटने वालों में नहीं हैं। उनका हौसला बुलंद है। उन्हें न किसी का डर है और न किसी के प्रति कड़वाहट – ट्रोलर्स के प्रति भी नहीं।

एम. लीलावती

शीर्ष से शुरुआत । लीलावती का लेखन शुरू हुआ था 1940 के दशक में। उन्होंने पहली बार लिखा भी, तो कुट्टिकृष्ण मारार पर, जो मलयालम साहित्य के शीर्ष आलोचक और निबंधकार माने जाते हैं।

आज भी टीचर । लीलावती अध्यापन से भी जुड़ी रहीं। 1952 में उन्होंने पलक्कड़ के गवर्नमेंट विक्टोरिया कॉलेज को बतौर लेक्चरर जॉइन किया था। रिटायर होने के बाद भी टीचर की पहचान है।

नई सोच डाली। उन्होंने मलयालम साहित्य में महिलाओं को नई जगह दी है। 2008 में पद्मश्री से सम्मानित, तमाम दूसरे पुरस्कार भी मिले हैं। पिछले साल आत्मकथा 'ध्वनि प्राणायाम' प्रकाशित हुई।

विशुद्ध राजनीति
पॉलिटॉक

फिर वही दुख लाया हूं

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में पिछले दिनों कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री असोसिएशन का 11वां सम्मेलन हुआ। इसमें तमाम राज्यों के विधानसभा के स्पीकर भी शामिल हुए। सम्मेलन में कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का मुख्यमंत्री नहीं बन पाने का दर्द एक बार फिर झलक उठा। उन्होंने सीएम सिद्धारमैया के सामने मंच से चुटकी ली। बोले, 'कई विधानसभा के स्पीकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं। आप सब भी सभापति हैं, हो सकता है कल सीएम बन जाएं।'। कर्नाटक में सीएम पद को लेकर लगातार खींचतान चल रही है। जब कांग्रेस चुनाव जीती, तब डीके शिवकुमार प्रदेश अध्यक्ष थे। पिछले दिनों चर्चा उठी थी कि आधा कार्यकाल बीतने पर कांग्रेस सिद्धारमैया को पद छोड़ने के लिए कह सकती है, पर उन्होंने मना कर दिया। डीके को उम्मीद है कि पार्टी अगले चुनाव में उन्हें सीएम फेस घोषित करेगी।

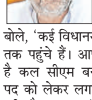

अंदर की राजनीति के शिकार नेताजी

नेताजी सांसद रह चुके हैं, कभी नीतीश कुमार के करीबी भी थे और फिर से JDU में जाने की ख्वाहिश थी। उन्होंने पार्टी के एक नेता से बात की, सब चीजें फाइनल हो गईं। पटना में उन्हें JDU में शामिल कराने के लिए कार्यक्रम की तारीख भी घोषित कर दी गई। फिर कहानी में आ गया ट्विस्ट। जिस दिन उन्हें JDU में शामिल होना था, उसी दिन पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने उनके नाम पर आपत्ति कर दी। दूसरे नेता भी खिलाफ हो गए। नतीजा यह हुआ कि कार्यक्रम ही रद्द कर दिया गया। नेताजी अब निराश होकर दूसरे विकल्प की तलाश में हैं।

उम्मीदवारों के साथ सीट समझौता

बिहार में I.N.D.I.A. ब्लॉक में सीटों को लेकर बातचीत जारी है। कांग्रेस पिछली बार के मुकाबले कम सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है, लेकिन वह कुछ नई सीटें चाहती है, जो अभी RJD के पास हैं। कांग्रेस का तर्क है कि पिछली बार वह भले अधिक जगहों से चुनाव लड़ी, लेकिन उसके हिस्से में मुश्किल सीटें आई थीं। इस बार पार्टी संतुलन चाहती है। वहीं, दोनों दल एक-दूसरे पर दबाव बना रहे हैं कि सीट समझौता के समय उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा कर ली जाए, ताकि जनता के बीच एक जैसा सामाजिक-राजनीतिक संदेश जाए। इससे टिकट की उम्मीद में बैठे नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है। उन्हें लग रहा है कि कहीं पार्टी सीट शेयरिंग के साथ ही उम्मीदवारों का ऐलान न कर दे!

बगावत का डर

दिल्ली से सटे एक राज्य पर BJP की चिंता भरी नजर है। वहां मौजूदा सीएम के खिलाफ उनके ही सरकार के मंत्री और दूसरे नेता छुप-छुप कर लगातार मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग का अजेंडा क्या है, यह किसी को नहीं पता। साथ ही, अक्सर सीएम के खिलाफ बयान भी दिए जा रहे हैं। सरकार मामूली बहुमत से सत्ता में है। पार्टी इन नेताओं को नजरअंदाज भी नहीं कर सकती। अब इस संभावित बगावत को कैसे दबाया जाए, इस पर नेतृत्व सिर खपा रहा है।

इगो का टकराव या कुछ और

कांग्रेस के अंदर NSUI प्रमुख वरुण चौधरी और प्रभारी कन्हैया कुमार के बीच किस बात को लेकर टकराव हुआ, इसे लेकर तरह-तरह की चर्चा है। कहा गया कि चूंकि दोनों छात्र राजनीति से आए हैं, तो इगो टकरा गया। लेकिन, कन्हैया कुमार ने आपाधापी में उनकी जगह नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू की, जिसे लेकर कुछ सीनियर नेताओं ने चिंता भी जताई। एक नेता ने सवाल किया कि जब इतने बड़े-बड़े फैसले लंबित हैं और महीनों लग जाते हैं उनको निपटाने में, तो यहां ऐसी क्या वजह हुई, बताने की जरूरत है।

THE SPEAKING TREE
और पढ़ने के लिए देखें
www.speakingtree.nbt.in

धैर्य सिखाता है अंदर की ताक़त परखने का सलीका

दादा श्री

जीवन में अक्सर ऐसी गलतफहमियां होती हैं, जो दुख देती हैं। कई बार लोग हमारे बारे में कहते हैं कि हम घमंडी, अहंकारी, झूठे या स्वार्थी हैं। वे हमें गलत समझते हैं, हमारे काम और भावनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसी बातें सुनकर मन भीतर से आहत होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया। फिर भी जब बार-बार ये बातें सुनाई दें, तो इसका सामना कैसे करें?

सबसे पहले, जब आपको लगता है कि आपकी गलती नहीं है, तो अपने मन की सच्चाई को विनम्रता और धैर्य से व्यक्त करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि आप दूसरों को समझाने या उनका दृष्टिकोण बदलने में लगे रहें। केवल अपने भीतर जो सच है, उसे स्पष्ट कर दें। जब आपने अपनी बात कह दी, तो उस विषय से दूर हो जाएं और अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करें। यह आपको मानसिक शांति देगा और आप अनावश्यक तनाव से बच पाएंगे।

AI Image

दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जब बार-बार लोग आपको दोषी बताते रहें, तब आपको उस स्थिति को स्वीकार करना होगा। स्वीकार्यता का अर्थ यह नहीं कि आप दोषी या गलत हैं, बल्कि यह एक आध्यात्मिक गुण है। उससे सीखने की कोशिश करते हैं। जब हम यह स्वीकार करते हैं कि जीवन में आलोचना और गलतफहमियां भी हमारे कर्मों का हिस्सा हैं, तो हम मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं।

तीसरी बात, अपनी ऊर्जा और ध्यान को अपने जीवन के उद्देश्य पर केंद्रित करना। दूसरों की नकारात्मक बातों में फंसने के बजाय, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें और उसे पाने के लिए मेहनत करते रहें। ऐसा करने से आपकी ऊर्जा को बल मिलेगा और वह आपको सफलता की ओर ले जाएगी।

इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण गुण है धैर्य। यह वो शक्ति है, जो हमें जीवन की चुनौतियों में स्थिर रखती है। धैर्य ही वह रास्ता है, जो कठिनाइयों के बीच भी शक्तिशाली और संतुलित बनाता है। धैर्य के साथ अपने कर्मों को स्वीकार करना और अपने उद्देश्य पर ध्यान देना ही सच्ची आध्यात्मिकता है।

मीम बहार

ऑपरेशन सिंदूर में हार के बाद झूठ। एशिया कप में हार के बाद मैच रेफरी पर निशाना

मत-सम्मत
www.edit.nbt.in

इस बार का विषय: जीएसटी दरों में कटौती पर आपका क्या कहना है?

GST कटौती: देर से लिया फैसला
केंद्र सरकार ने लंबे समय तक भारी कर बोझ लादने के बाद हाल ही में GST दरों में कटौती की है। साबुन, शैंपू, टूथपेस्ट, दूध, पनीर जैसी रोज़मर्रा की चीजों और छोटे वाहनों, मोटरसाइकिलों तथा कृषि उपकरणों पर टैक्स कम होना जनता और किसानों के लिए राहतभरा कदम है। इससे उपभोग बढ़ेगा, महंगाई से राहत और बाज़ार को गति मिलेगी। एफएमसीजी कंपनियां भी कीमतें घटाकर ग्राहकों तक लाभ पहुंचाने की तैयारी में हैं। फिर भी इतने वर्षों बाद यह कदम देर से लिया गया लगता है।
– लाडो तिवारी, ईमेल से

अगली बार भी यही विषय

mat.nbt@gmail.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

आर.एन.आई. पंजीयन नंबर 1613/1957 स्वत्वाधिकारी बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के लिए आर. कृष्णमूर्ति द्वारा टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग, डॉ. डी. एन. रोड, फोर्ट, मुंबई 400001 से प्रकाशित और उनके द्वारा (1) टाइम्स ऑफ इंडिया सबर्बन प्रेस, आकुर्ली रोड, निकट वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, कांदिवली (पू.) मुंबई 400101 एवं (2) टाइम्स ऑफ इंडिया प्रिंट सिटी, प्लॉट नं. 4, टी.टी.सी. इंडस्ट्रियल एरिया, ठाणे बेलापुर रोड, ऐरोली, नवी मुंबई-400708. फोन नं. (022) 2760 9999 ; फैक्सः (022) 2760 5275। फोन मुंबईः (022) 66353535, 22733535 रेस्पांसः (022) 66353636, 22733636 फैक्सः (022) 22731889, 22731144, कांदिवली (022) 28872324 से मुद्रित। **स्थानीय संपादक (मुंबई) : सुंदर चंद ठाकुर** (पी. आर. बी. अधिनियम के अंतर्गत समाचारों के चयन के लिए उत्तरदायी) सर्वाधिकार सुरक्षित। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। सड़क व रेल परिवहन सेवा शुल्कः मुंबई, ठाणे व रायगड जिलों के बाहर 1.00 रुपया। विमान सेवा शुल्कः रायपुर, नागपुर, गोवा एवं वाया 2.00 रुपये, इंदौर, चेन्नै एवं वाया 3.00 रुपये, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोचीन, कोयम्बतूर, एरनाकुलम, हैदराबाद, कोझीकोड, मंगलूर, त्रिवेंद्रम, उदयपुर, वाइजग एवं वाया 4.00 रुपये, दिल्ली, कोलकाता, एवं वाया 5.00 रुपये।

Machine Translated by Google

THE HINDU

नेपाल में अंतरिम सरकार में अशांत परिवर्तन , 74 लोगों की जान लेने वाले हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद, नाजायज मांगों का विरोध करना चाहिए । नेपाल की निर्वाचित सरकार गिर

एगई है, इसकी संसद भंग हो गई है और पूर्व न्यायविद सुशीला कार्की 2026 के चुनावों तक अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर रही हैं। जबकि जेनरेशन जेड के प्रदर्शनकारियों की खराब शासन व्यवस्था, जड़ जमाए भ्रष्टाचार और आलोचनात्मक विचारों के प्रति असहिष्णुता सहित जायज शिकायतें थीं, जो अपदस्थ सीपीएन-यूएमएल के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा 23 सोशल मीडिया वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाने के रूप में देखी गई थीं - परिवर्तन स्वयं स्पष्ट रूप से असंवैधानिक था, जो नेपाल के 2015 के संविधान के अनुच्छेद 76 का उल्लंघन करता है, जो केवल प्रधानमंत्री की असफल नियुक्तियों के बाद ही विघटन की अनुमति देता है। फिर भी, अत्यावश्यक परिस्थितियों को देखते हुए, पिछले सप्ताह उठाए गए कदमों की न्यायिक समीक्षा की कोई गुंजाइश नहीं है। उल्लेखनीय रूप से, राष्ट्रपति ने उच्च सदन, नेशनल असेंबली को भंग नहीं किया। नेपाल को संपत्ति और दस्तावेज़ों के विनाश के कारण प्रशासनिक समस्याओं के अलावा गंभीर आर्थिक नुकसान होने की आशंका है। लोकतांत्रिक संस्थाओं को निशाना बनाना नेपाल की संविधान-पश्चात व्यवस्था पर हमले का संकेत देता है—ये संस्थाएँ 2006 में एक दशक लंबे गृहयुद्ध के बहुप्रतीक्षित अंत के बाद श्रमसाध्य संविधान-लेखन प्रक्रिया के बाद स्थापित हुईं, एक कालबाह्य और बदनाम राजशाही पर विजय प्राप्त की और जिसमें काठमांडू घाटी की सत्ता संरचनाओं से परे हाशिए पर पड़े वर्ग शामिल थे—भले ही संविधान की भावना और शब्दों का आधे-अधूरे मन से या अप्रभावी कार्यान्वयन हुआ हो।

अंतरिम सरकार को अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाना होगा क्योंकि किसी भी तरह की निष्क्रियता हिंसा को सामान्य बना देगी और उन सभी संस्थाओं के लिए ख़तरा पैदा कर देगी जिनकी स्थापना गहन लोकतंत्रीकरण और नेपाल को एक गणराज्य में बदलने के वादों को पूरा करने के लिए की गई थी। भले ही जेनरेशन ज़ेड के प्रदर्शनकारी यह दावा करें कि हिंसा धोखेबाज़ों ने की, लेकिन निर्णय लेने के लिए डिस्कॉर्ड जैसे ऑनलाइन मंचों पर उनकी निरंतर निर्भरता अपरिपक्वता और गैर-प्रतिनिधित्ववादी स्वभाव को दर्शाती है। ऑनलाइन मंचों पर निर्भरता, जिनमें गुमनामी, तुच्छता और छद्मवेश शामिल हैं, और यह तथ्य कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये विचार कई हाशिए पर पड़े समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यह दर्शाता है कि इन गैर-ज़िम्मेदार समूहों की मांगों को बिना किसी आलोचना के मान लेना ख़तरनाक हो सकता है। मुख्यधारा के नेताओं—केपी शर्मा ओली-शेर बहादुर देउबा-पुष्प कमल दहल की तिकड़ी और उनके साथियों—की नाकामी लोकतंत्र या राजनीति को बदनाम करने को उचित नहीं ठहरा सकती, जैसा कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने असामाजिक और विनाशकारी राजशाही समर्थक तत्वों की प्रतिध्वनि करते हुए इसे प्रचारित किया है। इसका एक परिणाम यह हो सकता है कि मुख्यधारा की पार्टियों के स्थापित नेतृत्व को पार्टी के सदस्य नए लोगों को रास्ता देने के लिए मजबूर कर सकते हैं। इस बीच, अंतरिम सरकार को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए मंच तैयार करते हुए नेपाल की संस्थाओं और संवैधानिक उपलब्धियों की रक्षा करनी चाहिए—यह एक लोकतांत्रिक, बहुलवादी और गणतांत्रिक "नया नेपाल" के वादे की रक्षा का सबसे सुरक्षित रास्ता है।

समग्र दृष्टिकोण

भारत को पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए एक बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता है । सर्वोच्च न्यायालय ने सर्दियों की बुवाई या रबी

टी की फसल की तैयारी के लिए अपने खेतों में आग लगाते पकड़े गए किसानों पर मुकदमा चलाने की संभावना पर विचार किया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में वायु प्रदूषण में पराली जलाना एक प्रमुख कारक है, खासकर अक्टूबर और नवंबर में, जब दक्षिण-पश्चिम मानसून पीछे हट जाता है और प्रतिकूल मौसम संबंधी परिस्थितियाँ वाहनों, उद्योगों, कचरा जलाने और कृषि अपशिष्टों से निकलने वाले जहरीले कण उत्सर्जन को रोक लेती हैं। कृषि से होने वाले कण प्रदूषण के कारण और उसे कम करने के तरीके तो ज्ञात हैं, लेकिन केंद्र द्वारा इस लंबे समय से चली आ रही समस्या से निपटने के प्रयास आधे-अधूरे रहे हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) का गठन, जो एक केंद्रीय निकाय है और जिसके पास पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमाओं तक पहुँचने की शक्ति है, एक सकारात्मक कदम था और यह इस बात की स्वीकृति थी कि एक राज्य में वायु प्रदूषण को दूसरे राज्यों के सहयोग के बिना नहीं रोका जा सकता। हालाँकि, चार साल पुराना यह वैधानिक निकाय अपनी शक्तियों का प्रयोग राजनीतिक दबाव से स्वतंत्र रूप से करने में विफल रहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 1 जुलाई से 'जीवन-अंत' वाहनों को पेट्रोल और डीज़ल की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के इसके हालिया आदेश का ही उदाहरण लीजिए। दिल्ली और उसके राजनीतिक नेताओं में जनाक्रोश - मुख्यतः तकनीकी आधार पर - और न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण इसे इस साल नवंबर तक लागू करना पड़ा, वह भी एनसीआर के उन हिस्सों से जो दिल्ली नगर निगमों का हिस्सा नहीं हैं। पराली जलाने के मामले में भी, सीएक्यूएम न्यायपालिका पर यह दबाव नहीं डाल पाया है कि पराली जलाने की समस्या अड़ियल किसानों, पंजाब और हरियाणा द्वारा सीमित प्रवर्तन और कृषि अर्थशास्त्र की संरचना के कारण है, जिसने औसत, कर्ज में डूबे किसान के पास बहुत कम विकल्प छोड़े हैं। हाल के वर्षों में, यह सामने आया है कि पंजाब कृषि ऋण में कमी का दावा करता रहा है, जबकि वास्तव में यह बढ़ रहा था। सीएक्यूएम ने इसका खुलासा नहीं करना चुना।

किसी मुद्दे का मूल्यांकन और समाधान करने के लिए पारदर्शी तंत्र के अभाव और काल्पनिक राजनीतिक नतीजों के दबाव में, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि दूसरों को रोकने के लिए "किसानों को जेल में डालने" जैसे सुझाव दिए जा रहे हैं। हालाँकि नागरिकों का कोई भी वर्ग - चाहे किसान हो या उद्योगपति - कानून से ऊपर नहीं माना जा सकता, लेकिन बेहतर प्रोत्साहन देना, मौजूदा कानूनों को लागू करना और वास्तविक रूप से प्राप्त करने योग्य चीज़ों के बारे में पारदर्शी होना, 'आकर्षक और दंडात्मक' तरीकों से ज़्यादा उचित कदम हैं।

भारत में प्राथमिक खाद्य उपभोग को समान बनाना

पुलाप्रे बालाकृष्णन

मानद अतिथि हैं प्रोफेसर, सेंटर फॉर विकास अध्ययन, Thiruvananthapuram

Aman Raj

में स्थित एक स्वतंत्र अर्थशास्त्री हैं।

Patna, Bihar

टी फरवरी 2024 में, द्वारा एक घरेलू उपभोग सर्वेक्षण का प्रकाशन

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) ने एक दशक से अधिक के अंतराल के बाद एक बार फिर से यह उपलब्धि हासिल की है। भारत में गरीबी दर का अनुमान लगाना संभव है।

विश्व बैंक द्वारा अप्रैल 2025 में जारी किए गए ऐसे ही एक अनुमान ने सबसे ज़्यादा ध्यान आकर्षित किया है। यह अनुमान बताता है कि अब तक गरीबी दर बहुत कम हो चुकी होगी।

विश्व बैंक के अनुसार, "पिछले एक दशक में, भारत में गरीबी में उल्लेखनीय कमी आई है। अत्यधिक गरीबी (प्रतिदिन 2.15 डॉलर से कम पर जीवनयापन) 2011-12 के 16.2 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 2.3 प्रतिशत हो गई..." ('गरीबी और समता संक्षिप्त विवरण: भारत', 2025)। यदि यह वास्तव में एक सटीक विवरण है, तो यह संतोष की बात होगी, क्योंकि यह दर्शाता है कि देश से अत्यधिक गरीबी लगभग गायब हो गई है।

उपभोग के एक मीट्रिक के रूप में 'थाली भोजन' गरीबी मापने का पारंपरिक तरीका, जिसकी शुरुआत भारत सरकार ने आधी सदी से भी पहले की थी, सबसे पहले उस आय का निर्धारण करता है जो एक निश्चित कैलोरी मान के भोजन को ग्रहण करने में सक्षम बनाएगी, और फिर उससे कम कैलोरी वाले लोगों को गरीब के रूप में वर्गीकृत करता है। यह एक शारीरिक दृष्टिकोण है, और इसमें कुछ गुण हैं। लेकिन उदाहरण के लिए, वस्तुओं के उपभोग के आधार पर अन्य दृष्टिकोण भी हो सकते हैं। ऐसा एक दृष्टिकोण यह मानता है कि मनुष्य भोजन को केवल कैलोरी सामग्री से कहीं अधिक व्यापक दृष्टिकोण से देखते हैं, जिसमें वह ऊर्जा जो वह प्रदान करता है, जिसे कैलोरी मापती है, पोषण, और वह संतुष्टि जो वह देता है, को ध्यान में रखते हैं। हमारा मानना है कि थाली भोजन इसी सोच को दर्शाता है, जो इसे वास्तविक रूप में भोजन की खपत को मापने के लिए एक स्वाभाविक विकल्प बनाता है।

कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के संयोजन के रूप में और विटामिनों के मामले में, थाली दक्षिण एशिया में भोजन की खपत की एक संतुलित और आत्मनिर्भर इकाई है, भले ही इसका नामकरण अलग-अलग हो।

इसे ध्यान में रखते हुए, हमने अनुमान लगाया है कि 2024 के घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण में बताए गए मासिक व्यय के अनुसार थालियों की संख्या कितनी होगी। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने चावल, दाल, सब्ज़ी, रोटी, दही और सलाद से बनी घर में बनी थाली की कीमत ₹30 आंकी है। इस मूल्य को मानते हुए, हमने पाया कि 2023-24 में, दर्ज किए गए भोजन व्यय के हिसाब से 50% ग्रामीण आबादी और 20% शहरी आबादी प्रतिदिन दो थाली भी नहीं खा पाएगी। अगर प्रतिदिन दो थाली को भोजन की खपत का न्यूनतम स्वीकार्य मानक मान लिया जाए, तो हमारे अनुमान विश्व बैंक के गरीबी के आंकड़ों की तुलना में भारत में भोजन की कमी को कहीं ज़्यादा दर्शाते हैं।

हमारे निष्कर्षों में अंतर का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि

विस्तार जनता वितरण

जिन लोगों का खाद्य उपभोग एक उचित मानक से अधिक है, उनके लिए सब्सिडी समाप्त करके दालों की खपत के वांछनीय स्तर को सुनिश्चित करने की प्रणाली एक आदर्श कदम होगा।

हम यह नहीं मानते कि किसी परिवार की सारी आय भोजन पर खर्च करने के लिए उपलब्ध है। एक परिवार को केवल कार्यबल में बने रहने के लिए किराए, परिवहन, टेलीफोनी, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा पर खर्च करना पड़ता है।

अब, भोजन पर होने वाला खर्च ही अवशिष्ट राशि बन जाता है। इसलिए, हमने अपने अनुमान भोजन पर होने वाले वास्तविक खर्च के आधार पर लगाए हैं।

यह मान लिया जाता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) खाद्यान्न अभाव से प्रभावी रूप से निपटती है। इसका आकलन करने के लिए, हमने पीडीएस के माध्यम से प्राप्त आपूर्ति - चाहे वह खरीदी गई हो या मुफ़्त - के अनुमानित मूल्य सहित खाद्य उपभोग के मूल्य की गणना की है।

उपभोग के मूल्य को इस प्रकार समायोजित करने पर, दो थाली न जुटा पाने वाली आबादी का अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों में घटकर 40% और शहरी क्षेत्रों में 10% रह जाता है। उल्लेखनीय है कि सब्सिडी वाले भोजन के बावजूद, शहरी क्षेत्रों में भोजन से वंचित लोगों की संख्या अभी भी बहुत अधिक है।

पीडीएस की भूमिका यह समझने के लिए कि खाद्यान्न अभाव को दूर करने के लिए पीडीएस का किस प्रकार लाभ उठाया जा सकता है, हमने व्यय वर्गों में प्रति व्यक्ति सब्सिडी का अनुमान लगाया।

दिलचस्प बात यह है कि पीडीएस से होने वाली खरीदारी और आबादी के उन वर्गों द्वारा प्राप्त मुफ़्त भोजन, जो दिन में दो से ज़्यादा थाली खरीद सकते हैं, दोनों ही ज़्यादा हैं। उदाहरण के लिए, ग्रामीण भारत में, 90%-95% वर्ग के व्यक्ति को मिलने वाली सब्सिडी, 0%-5% वर्ग के व्यक्ति को मिलने वाली सब्सिडी का 88% है, जबकि पहले वर्ग का उपभोग व्यय तीन गुना से भी ज़्यादा है, और हमारे अपने थाली सूचकांक के अनुसार, उसे और सहायता की ज़रूरत नहीं है। इसके विपरीत, शहरी भारत में, सब्सिडी व्यवस्था काफ़ी प्रगतिशील है।

लेकिन यहां भी लगभग 80% लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सब्सिडीयुक्त बिक्री के साथ-साथ मुफ्त भोजन भी मिलता है, जबकि वे भी प्रतिदिन दो से अधिक थाली खरीद सकते हैं।

खाद्य वंचना और खाद्य सब्सिडी व्यवस्था की संरचना से संबंधित आँकड़ों के आधार पर, हम नीति निर्माण के तरीके पर एक प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। ये आँकड़े बताते हैं कि क्या किया जाना चाहिए और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। सबसे पहले, खाद्य सब्सिडी के पुनर्गठन की गुंजाइश है, वितरण के निचले स्तर पर इसे बढ़ाया जा सकता है और ऊपरी स्तर पर इसे पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है। हालाँकि, हालिया उपभोग सर्वेक्षण से हमें पता चलता है कि एक बाधा का सामना करना होगा: 0%-5% फ्रैक्टाइल और 95%-100% फ्रैक्टाइल वाले व्यक्तियों के लिए अनाज की खपत लगभग समान है।

इससे पता चलता है कि चावल और गेहूँ, दोनों ही अनाजों की खपत का वांछित स्तर प्राप्त हो चुका है, क्योंकि सबसे अमीर लोग अपनी इच्छानुसार सभी अनाज खरीद सकते हैं। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की सफलता की ओर इशारा करता है, क्योंकि इसने

एक ओर जहाँ एक ओर मुख्य भोजन की खपत को समान कर दिया गया है, वहीं दूसरी ओर, यह खाद्यान्न अभाव को समाप्त करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के वर्तमान स्वरूप के उपयोग की सीमाओं की ओर भी इशारा करता है। अनाज की खपत न केवल पूरी आबादी में अपने वांछित स्तर पर पहुँच गई है, बल्कि यह औसत घरेलू खर्च का केवल 10% ही है।

रसद और व्यय, दोनों ही दृष्टियों से, यह अपेक्षा करना अनुचित है कि सरकार किसी भी वर्ग को संपूर्ण खाद्यान्न वितरित कर सकती है। हालाँकि, एक मध्य मार्ग है, और वह है सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से दालों के वितरण का विस्तार करना। वितरण के दोनों छोरों पर उपभोग के पैटर्न की आगे की तुलना में, हम पाते हैं कि अनाज के विपरीत, 0%-5% वर्ग में दालों की प्रति व्यक्ति खपत 95%-100% वर्ग की तुलना में ठीक आधी है।

दालों की खपत: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का उपयोग जनसंख्या की प्राथमिक खाद्य खपत को समान बनाने के लिए किया जा सकता है। दालों की खपत के वांछनीय स्तर को सुनिश्चित करने के लिए पीडीएस का विस्तार वांछनीय और व्यवहार्य दोनों है – कई भारतीयों के लिए, प्रोटीन का एकमात्र स्रोत और एक बहुत महंगा खाद्य पदार्थ – वित्तीय पहलू को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के पुनर्गठन द्वारा संबोधित किया जा सकता है। 0%-5% के अनुपात में चावल और गेहूँ की प्रति व्यक्ति खपत का अर्थ है कि चावल और गेहूँ की पीडीएस पात्रता एक महत्वपूर्ण संख्या के लिए आवश्यक सीमा से कहीं अधिक है।

अनाज की आपूर्ति के लिए सब्सिडी व्यवस्था का विस्तार 80 करोड़ लोगों को चावल देने का लक्ष्य, जैसा कि केंद्र सरकार ने जनवरी 2024 में किया था, तथा कुछ राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को चावल देने का विशेष रूप से बड़ा अधिकार, आवश्यकता को प्रतिबिंबित नहीं करता है।

इसके अलावा, सार्वजनिक धन के वैकल्पिक उपयोगों को देखते हुए, इनकी अर्थव्यवस्था पर भी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। वितरण के निचले स्तर पर अनाज की वर्तमान पात्रता को हालिया उपभोग सर्वेक्षण द्वारा बताए गए आवश्यक स्तर तक कम करने और ऊपरी स्तर पर इसे पूरी तरह से समाप्त करने से भारतीय खाद्य निगम के लिए भंडारण की आवश्यकता भी कम होगी, जिससे पर्याप्त लाभ होगा।

हमने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का विस्तार वंचित वर्ग की सबसे ज़रूरी खाद्यान्न, यानी दालों की ओर करने का प्रस्ताव रखा है, साथ ही उन लोगों के लिए सब्सिडी समाप्त करने का भी प्रस्ताव रखा है जिनका भोजन उपभोग एक उचित मानक, जैसे कि दिन में दो थाली , से अधिक है । अभी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली बोझिल और अप्रभावी दोनों है, क्योंकि यह संसाधनों को सीमित करती है। हमारा प्रस्ताव इसे संक्षिप्त बनाएगा, जिससे भारत में प्राथमिक खाद्य उपभोग को समान बनाने में मदद मिलेगी और सबसे गरीब परिवारों के उपभोग को अर्थव्यवस्था में देखे गए उच्चतम स्तर तक बढ़ाया जा सकेगा, जो एक वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण परिणाम है।

भारत को महत्वपूर्ण लक्ष्य एसडीजी 3 तक पहुंचने के लिए अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है

राहुल मेहरा

राष्ट्रीय है इसका प्रतिनिधि भारत, वैश्विक स्वास्थ्य और शिक्षा और कार्यकारी अध्यक्ष, तनावग्रस्त स्वास्थ्य गठबंधन

इस वर्ष जून में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) सूचकांक में भारत का स्थान 167 देशों में से 99वां होगा, एसडीजी रिपोर्ट के 2025 संस्करण में भारत को 167 देशों में से 99वां स्थान मिलेगा।

यह 2024 में 109वें स्थान से उल्लेखनीय सुधार दर्शाता है, जो 2021 से लगातार प्रगति को दर्शाता है। भारत ने बुनियादी सेवाओं और बुनियादी ढाँचे तक पहुँच जैसे क्षेत्रों में प्रगति प्रदर्शित की है। फिर भी, रिपोर्ट में प्रमुख क्षेत्रों, विशेष रूप से स्वास्थ्य और पोषण, में गंभीर चुनौतियों का भी ज़िक्र किया गया है, जहाँ प्रगति असमान रही है, खासकर ग्रामीण और आदिवासी समुदायों में।

अभी भी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। इस पृष्ठभूमि में, सतत विकास लक्ष्य 3 पर विचार करना महत्वपूर्ण है। इसका लक्ष्य "सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और कल्याण को बढ़ावा देना" है, और यह भारत की सतत विकास लक्ष्य यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण, फिर भी चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों में से एक है। इसमें वे विशिष्ट लक्ष्य शामिल हैं जिन्हें भारत ने 2030 तक हासिल करने का संकल्प लिया है। कुछ क्षेत्रों में प्रगति के बावजूद, समग्र प्रगति दर्शाती है कि भारत अधिकांश लक्ष्यों को प्राप्त करने की राह पर नहीं है। उदाहरण के लिए, मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) - प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर प्रसव के बाद मरने वाली माताओं की संख्या - प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 97 मृत्यु दर पर है, जो 2030 के 70 के लक्ष्य से अधिक है।

यहाँ तक कि अंडर-वेव मृत्यु दर भी प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 32 मौतों पर बनी हुई है, जबकि लक्ष्य 25 का है। विकसित देशों में, यह दो से छह मौतों के बीच है। जीवन प्रत्याशा अभी केवल 70 वर्ष है, जो 73.63 वर्ष के लक्ष्य से कम है।

स्वास्थ्य देखभाल पर जेब से होने वाला खर्च कुल खपत का 13% है, जो परिवारों पर बोझ बना हुआ है, जो लक्षित 7.83% से लगभग दोगुना है। यहाँ तक कि टीकाकरण कवरेज भी, जो 93.23% के सराहनीय उच्च स्तर पर है, अभी तक 100% के सार्वभौमिक लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाया है।

इन अंतरालों के कई कारण हैं। इनमें शामिल हैं, पहला, खराब बुनियादी ढांचे और आर्थिक कारकों के कारण आंशिक रूप से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की कमी; दूसरा, गैर-आर्थिक कारक जैसे खराब पोषण, स्वच्छता और अन्य जीवन शैली विकल्प और तीसरा, सांस्कृतिक कारक

स्कूलों में अनिवार्य स्वास्थ्य शिक्षा एक ऐसा उपाय है जो इस अंतर को पाटने में मदद कर सकता है

शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी प्रथाओं और कलंक के कारण अक्सर समुदाय उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं तक भी पहुँच नहीं पाते। ये सांस्कृतिक प्रथाएँ और सीमित जागरूकता अक्सर समुदायों को उनके लिए उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँचने से रोकती हैं।

यदि भारत को सतत विकास लक्ष्य 3 पर प्रगति में तेजी लानी है, एक त्रि-आयामी दृष्टिकोण आवश्यक है और वह भी रोगों के उपचार और रोकथाम पर केंद्रित। पहला है जनता को सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना। विश्व बैंक के अध्ययनों से पता चलता है कि मज़बूत बीमा प्रणालियों वाले देशों ने स्वास्थ्य सेवा पर होने वाले विनाशकारी खर्च को कम किया है और साथ ही पहुँच में अधिक समानता सुनिश्चित की है। दूसरा है देश भर में उच्च-गुणवत्ता वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करना और प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं का समन्वय करना।

देखभाल.

विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी 2022 विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वास्थ्य संगठन इस बात पर ज़ोर देता है कि मज़बूत प्राथमिक प्रणालियाँ बीमारियों का जल्द पता लगाने, अस्पताल में भर्ती होने की लागत कम करने और बेहतर दीर्घकालिक परिणाम प्राप्त करने में मदद करती हैं। इसके लिए डिजिटल स्वास्थ्य उपकरणों की परिवर्तनकारी क्षमता का भी दोहन करना होगा। टेलीमेडिसिन और एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड, विशेष रूप से ग्रामीण और कम सुविधा वाले क्षेत्रों में, पहुँच की कमी को पाट सकते हैं। लैंसेट डिजिटल स्वास्थ्य आयोग के साक्ष्य दर्शाते हैं कि कैसे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म ने कई निम्न और मध्यम आय वाले देशों में मातृ स्वास्थ्य देखभाल और टीकाकरण ट्रैकिंग में सुधार किया है, जिससे भारत को कुछ सबक सीखने को मिल सकते हैं।

स्कूल स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा: बीमारियों की रोकथाम, उनके इलाज से ज़्यादा किफ़ायती है। बीमारियों की रोकथाम के लिए, हमें सभी स्कूली बच्चों को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है।

बच्चों को स्वस्थ पोषण, अच्छी स्वच्छता, प्रजनन स्वास्थ्य, सड़क सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य विषयों पर शिक्षित करने की आवश्यकता है।

इस छोटी सी उम्र में उन्हें न केवल अपने ज्ञान में बल्कि अपने स्वास्थ्य व्यवहार में भी सुधार करने की आवश्यकता है।
इस उम्र में विकसित की गई स्वास्थ्य संबंधी आदतें वयस्क होने पर भी बनी रहेंगी। जब लड़कियाँ माँ बनने पर, वे अपने स्वास्थ्य के बारे में अधिक शिक्षित होंगी और अपने और अपने परिवार के लिए इसकी वकालत करेंगी। दीर्घावधि में, स्कूल स्वास्थ्य शिक्षा पहल में मातृ मृत्यु दर (MMR) अनुपात, शिशु मृत्यु दर और सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को कम करने की क्षमता है। साथ ही, यह जीवन प्रत्याशा और टीकाकरण दर को भी बढ़ा सकती है।

1970 के दशक में फ़िनलैंड के स्कूल-आधारित स्वास्थ्य सुधारों, जिनमें पोषण, स्वच्छता और जीवनशैली पर आधारित पाठ्यचर्या को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था, ने बाद के दशकों में हृदय रोग की दर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जापान में, अनिवार्य स्वास्थ्य शिक्षा को बेहतर स्वच्छता प्रथाओं और लंबी जीवन प्रत्याशा से जोड़ा गया है। भारत में एक संरचित और प्रगतिशील पाठ्यक्रम समान परिणाम प्राप्त कर सकता है।

ठोस कार्रवाई की आवश्यकता इसलिए, सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के अंतर को पाटने के लिए नीति निर्माताओं द्वारा व्यक्तिगत कार्रवाई की आवश्यकता है। नीति निर्माताओं को स्कूली पाठ्यक्रमों में स्वास्थ्य शिक्षा को शामिल करने के साथ-साथ सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज और प्राथमिक स्वास्थ्य में भी निवेश करना होगा।

देखभाल.

युवाओं की स्वास्थ्य शिक्षा में सभी अभिभावकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वे अपने बच्चे के स्कूली पाठ्यक्रम की समीक्षा कर सकते हैं और यह निर्धारित कर सकते हैं कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य से संबंधित विषयों को शामिल किया जा रहा है या नहीं। यदि नहीं, तो उन्हें शिक्षा विभाग को सूचित करके इसके लिए प्रयास करना चाहिए।

भारत की बेहतर सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग उत्साहजनक है। लेकिन इससे इस वास्तविकता को छिपाया नहीं जाना चाहिए कि वर्तमान में वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का केवल 17% ही 2030 तक प्राप्त होने की राह पर है। युवाओं को स्वस्थ व्यवहार के बारे में शिक्षित करना, और मज़बूत स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों द्वारा समर्थित, सतत प्रगति की नींव का काम कर सकता है। और हालाँकि 2030 एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, लेकिन असली लक्ष्य तो अभी और दूर है - एक स्वस्थ और मज़बूत भारत का निर्माण। एक सरकार जो स्कूली पाठ्यक्रमों में स्वास्थ्य शिक्षा को शामिल करने पर अपना ध्यान केंद्रित करती है, वह विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकती है।

द टटर्सटूदएडिटर

आज यहूदी और इज़राइल

यहूदी रहे हैं सबसे अधिक सताई गई जाति - प्रलय सबसे अंधकारमय है मानव इतिहास का एक अध्याय. इसलिए, यह उम्मीद की जा सकती है कि यहूदियों में अतीत में हुए अत्याचारों को देखते हुए, सहानुभूति और सहिष्णुता के गुण स्वाभाविक रूप से विकसित होंगे। हालाँकि, ऐसा लगता है कि उत्पीड़ित लोग नए सिरे से उत्पीड़क बन गए हैं। गाजा में इज़राइल द्वारा किए जा रहे अत्याचारों को और कैसे समझाया जा सकता है? आज भी, जर्मन बच्चों को इसके बारे में पढ़ाया जाता है। विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों के विनाश में जर्मनों की शर्मनाक भूमिका को भूल जाना चाहिए। इसी तरह, इज़राइल के लोगों को भी एक पल रुककर सोचना चाहिए कि गाज़ा में हुए नरसंहार के लिए इतिहास उन्हें कैसे आंकेगा।

उन्हें जल्द ही इस संभावना से जूझना पड़ सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनके द्वारा किए गए उत्पीड़न को उनके कार्यों के बाद इतिहास के अंतिम पृष्ठों में डाल दिया जाएगा।

शारदा शिवराम, कोच्चि, केरल

इस मुद्दे पर भारत की अस्पष्ट और निरंतर चुप्पी गाजा में नरसंहार उसकी संकीर्ण मानसिकता तथा विदेश नीति पर कार्यकारी निर्णयों को चुनौती देने की उसकी अजीब अनिच्छा को दर्शाता है।

जैसे-जैसे दुनिया गाजा संघर्ष के बढ़ते नुकसान से जूझ रही है, भारत की मूकदर्शक की भूमिका लगातार असहनीय होती जा रही है। भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री अपनी कूटनीति को व्यावहारिक बता सकते हैं, लेकिन इतिहास उन्हें नैतिक ही मानेगा। विफलताएँ। फिलिस्तीन और भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा, दोनों के लिए, मिलीभगत की कीमत इतनी ज़्यादा है कि उसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। अब सवाल यह है कि क्या भारत रणनीतिक लाभ के इस रास्ते पर चलता रहेगा या गाज़ा में नरसंहार की निंदा करने का साहस फिर से हासिल करेगा—जो उसे करना भी चाहिए।

इसलिए।

इसका उत्तर न केवल फिलिस्तीन के भाग्य को आकार देगा, बल्कि वैश्विक व्यवस्था में भारत की विरासत को भी आकार देगा।

आर. शिवकुमार, चेन्नई

एक वफ़ादार बीएसएनएल ग्राहक: मैं लगभग 20 वर्षों से बीएसएनएल का पुराना ग्राहक रहा हूँ। मेरे और मेरे परिवार (लगभग 75 सदस्य) ने बीएसएनएल के साथ केवल इसलिए जुड़े रहे क्योंकि हम भारत सरकार के एक उद्यम का समर्थन करने और उसकी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने अपने क्षेत्र के अन्य लोगों को बीएसएनएल की ज्ञात सीमाओं के बावजूद उसका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया है।

हालाँकि बीएसएनएल ने आधिकारिक तौर पर ई-सिम लॉन्च कर दिया है, लेकिन यह अभी भी केरल में उपलब्ध नहीं है।

अधिक चिंता की बात यह है कि ग्राहक सेवा द्वारा स्पष्टीकरण

प्रतिनिधियों का कहना है कि पुराने ग्राहकों के लिए ई-सिम सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं। यह नीति वफादार ग्राहकों के प्रति उपेक्षा दर्शाती है। बीएसएनएल द्वारा ई-सिम सेवाएँ शुरू न किए जाने के कारण, मेरे पास अपना नंबर किसी अन्य ऑपरेटर के पास पोर्ट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।

अखिल एस. करुण, कोच्चि, केरल

letters@thehindu.co.in पर भेजे गए पत्रों में डाक पता अवश्य होना चाहिए।

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

राष्ट्रीय सहारा

नई दिल्ली • शुक्रवार • 19 सितम्बर • 2025

www.rashtriyasahara.com

लाठी अदालत की

सुप्रीम कोर्ट ने सर्दियां शुरू होने से पहले तीन सप्ताह के भीतर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु प्रदूषण रोकने के उपाय पेश करने को कहा है। उप्र, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब जैसे राज्यों से नाराजगी जताते हुए रिक्तियां भरने के लिए छह महाने का समय दिया। वायु गुणवत्ता आयोग केंद्र सरकार का वैधानिक निकाय है जिसका लक्ष्य दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता का प्रबंधन व सुधार करना है। दिल्ली एनसीआर में हरियाणा, उप्र, राजस्थान व पंजाब के हिस्से शामिल हैं, जो प्रति वर्ष सर्दियों में भीषण वायु प्रदूषण की चपेट में आ जाते हैं। पीठ ने दंड प्रावधानों पर भी जोर दिया। अदालत के बार-बार कहने के बावजूद राज्य

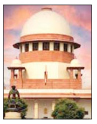

सरकारों की तरफ से वायु गुणवत्ता के सुधार के ठोस कदम नहीं उठाए जाते। आयोग के गठन के बावजूद समाधान ढूंढ़ने व राज्यों तथा एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करने को लेकर परिवर्तनकारी मानक नहीं बनाए गए हैं। सर्दियां शुरू होते ही वाहनों के धुएं, धूल-मिट्टी, कारखानों व पराली जलाने के कारण पर्यावरण पर गहरी चादर छा जाती है जो श्वसन-तंत्र के लिए घातक सिद्ध होती है। वाहन उत्सर्जन मानकों को तय करने सालों-साल से चर्चा हो रही है। किसानों या पड़ोसी राज्यों को इस प्रदूषण का दोषी ठहरा कर दिल्ली अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकती। निर्माण कार्य रोकने का सीधा असर दिहाड़ी मजदूरों को झेलना पड़ता है। पुराने वाहनों की आवाजाही पर पाबंदी से साधारण यात्री की दिक्कतों का अंदाजा वातानुकूलित लग्जरी कारों में बैठने वाले नहीं लगा सकते। फिजूल बातें, अपुष्ट दावों, नौकरशाही व जिम्मेदारी से हाथ झाड़ कर सिर्फ सालोंसाल राजनीति की जाती है। बीते साल राजधानी की वायु गुणवत्ता सूचकांक पांच सौ के पार जाने पर तहलका मच गया था। मगर नागरिकों के हितों की अनदेखी और स्वास्थ्यगत जटिलताओं के प्रति उपेक्षा बरतते हुए सरकारों ने तात्कालिक उपायों पर ही जोर लगाया। ठोस कदम उठाने या संकट से निपटने की तैयारी करने के प्रति सरकारी रैवया उदासीन बना हुआ है। अदालत से फटकार के बावजूद संस्थाओं तथा आयोगों के अविवेक, अकर्मणयता व शक्तिहीनता का खमियाजा अंततः आम नागरिक को भुगतना पड़ता है। प्रदूषण के चलते सबसे अधिक दुर्दशा गरीबों व दिहाड़ी कामगारों की होती है जिस पर विचार करने में सरकार को कोताही नहीं करनी चाहिए।

वीडियो हटाने का निर्देश

पटना हाई कोर्ट ने बुधवार को अपने नजीरी फैसले में कांग्रेस को आदेश दिया कि वह अपने सोशल मीडिया खातों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी दिवंगत मां का कृत्रिम मेधा (एआई) जनित वीडियो हटाए। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने इस वीडियो को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए देश भर में विरोध प्रदर्शन किए थे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पीबी बैजंत्री ने अधिवक्ता विवेकानंद सिंह और अन्य की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किया। याचिका में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ ही केंद्र सरकार और भारत निर्वाचन आयोग को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिका में दलील दी गई थी कि कांग्रेस के

सोशल मीडिया खातों में दर्शाया गया यह वीडियो 'आपत्तिजनक' है, और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत राजनीतिक दलों पर लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन है। सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग की ओर से वकील सिद्धार्थ प्रसाद पेश हुए। उन्होंने बताया कि 'अदालत ने सोशल मीडिया मंच फेसबुक, 'एक्स' और गूगल को नोटिस जारी किया है, और उन्हें मामले की अगली सुनवाई तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक संबंधित वीडियों को हटा लिया जाना चाहिए। गौरतलब है कि कांग्रेस की बिहार इकाई ने पिछले हफ्ते 'एक्स' पर यह वीडियो पोस्ट किया था और लिखा था 'साहब के सपनों में आईं मां। देखिए, रोचक संवाद।' वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां को अपने बेटे की राजनीति के लिए उनकी आलोचना करते दिखाया गया है। अदालत का यह फैसला नजीरी कहा जाएगा। इस लिहाज से कि इन दिनों राजनीतिक विमर्श खासा निचले स्तर पर पहुंच गया है। आलोचना का स्थान व्यक्तिगत और निजी हमलों ने ले लिया है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के बीच आचार-व्यवहार के इस तरह गिरते जाने से प्रबुद्ध जन चिंतित हैं। लोक व्यवहार में गरिमापूर्ण आचरण को सहेजे रखना जरूरी है। इस मामले में राजनीतिक दलों की महती भूमिका है, लेकिन चुनावी राजनीति के कटुतापूर्ण होते जाने से लोक व्यवहार में गरिमा बनाए रखने का तकाजा कहीं बिलाता जा रहा है। भाषा की मर्यादा का लोप हुए जा रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अदालत का रुख व्यवहारगत संयम बनाए रखने का सबब बनेगा।

समावेशी स्वास्थ्य/मुकेश सिंह

चुनौतियां हैं जटिल

किसी भी राष्ट्र की असली संपत्ति उसकी जनता होती है, और जनता की वास्तविक ताकत उसके स्वास्थ्य से आंकी जाती है। परंतु जब स्वास्थ्य सुविधाएं अमीर-गरीब, शहर-गांव, पुरुष-महिला, विकलांग-समर्थ, ग्रामीण-शहरी के बीच असमान रूप से बंटी हों तो समाज में असमानता की खाई और गहरी होती जाती है। आजादी के 75 साल बाद भी भारत सहित दुनिया के कई देशों में स्वास्थ्य सेवाओं तक समावेशी पहुंच चुनौती बनी हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बार-बार कहा है कि किसी भी राष्ट्र को न्यूनतम 6 प्रतिशत जीडीपी स्वास्थ्य पर खर्च करना चाहिए लेकिन भारत आज भी 3.3 प्रतिशत के आसपास अटका हुआ है। यह अंतर आंकड़ों का नहीं, बल्कि इंसानी जीवन-मृत्यु का है। नतीजा यह है कि लाखों परिवार हर साल इलाज के खर्च से कर्ज में डूब जाते हैं, और गरीबी की रेखा के नीचे खिसक जाते हैं। विश्व बैंक के अनुसार भारत में प्रति हजार आबादी पर केवल 0.8 डॉक्टर हैं, जबकि वैश्विक औसत 1.8 है। यह अंतर बताता है कि हमारे नागरिकों के हिस्से में बीमारी और अभाव कहीं अधिक हैं।

आज स्थिति यह है कि भारत की स्वास्थ्य चुनौतियां केवल डॉक्टरों और अस्पतालों की कमी तक सीमित नहीं हैं। यह समस्या दृष्टिकोण की भी है। जब तक स्वास्थ्य को राजनीतिक विमर्श और चुनावी मुद्दों में प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, तब तक वास्तविक सुधार संभव ही नहीं हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि चुनावों में सड़क, बिजली, पानी, जाति और धर्म पर तो चर्चा होती है, लेकिन स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दे को शायद ही कभी केंद्र में रखा जाता है। जब तक आम जनता इसे अपना अधिकार मान कर इसकी मांग नहीं करेगी, तब तक व्यवस्था में निर्णायक परिवर्तन मुश्किल ही रहेगा। स्वास्थ्य सेवा की समावेशी परिभाषा यही है कि हर नागरिक-चाहे गरीब हो या अमीर, शहर में रहता हो या गांव में, बच्चा हो या बुजुर्ग-समान सम्मान और सुविधा के साथ इलाज पा सके। यह तभी संभव है जब सरकार स्वास्थ्य अवसंरचना पर बड़े पैमाने पर निवेश करे, डॉक्टरों और नर्सों की पर्याप्त नियुक्ति सुनिश्चित करे, दवाइयों और जांच की सुविधाएं सस्ती और सुलभ बनाए और निजी क्षेत्र को सख्त नियमों के तहत नियंत्रित करे। कहना न होगा कि समावेशी स्वास्थ्य व्यवस्था ही वह आधार है, जिस पर न केवल एक मजबूत समाज, बल्कि एक सशक्त और न्यायपूर्ण भारत का निर्माण संभव है।

अनमोल वचन

नाव जल में रहे, लेकिन जल नाव में नहीं रहना चाहिए, इसी प्रकार साधक जग में रहे, लेकिन जग साधक के मन में नहीं रहना चाहिए।

-रामकृष्ण परमहंस

सामाजिक बदलाव की इबारत

बिहार में विकास

प्रवीण कुमार

देश की राजनीति और विकास यात्रा पर बारीक नजर डालें तो साफ दिखता है कि इसके केंद्र में सामाजिक बदलाव की तस्वीर फिर मजबूती से उभर रही है। हां, इसकी महत्ता को समझने से पहले एक एहतियात जरूरी है-जो लोग अब तक राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीति को अलग-अलग खांचे में बांट कर देखते रहे हैं, उन्हें सोच बदलनी होगी। यह वह दौर है जब राज्यों के साथ-साथ देश के राजनीतिक और विकासात्मक चरित्र में गहरे बदलाव हो रहे हैं। खासकर बिहार विधानसभा चुनाव की दस्तक ने इस विमर्श के कई नये रास्ते खोल दिए हैं।

पिछले दो दशकों में बिहार ने जिस तरह राजनीतिक स्थिरता के साथ विकास और सामाजिक बदलाव का रास्ता अख्तियार किया है, उसने इस सफर को ही नहीं, बल्कि देश को भी बदलाव और राजनीति का एक संतुलित मॉडल दिया है। इस सामाजिक विकास मॉडल के केंद्र में अगर कोई शख्सियत है, तो वह हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इतिहास और वर्तमान को साथ रख कर देखें तो आपातकाल और बिहार आंदोलन के 50 साल पूरे होते देखना अपने-आप में उनकी लंबी राजनीतिक-सामाजिक यात्रा का प्रमाण है। चम्पारण सत्याग्रह से लेकर संपूर्ण क्रांति और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के कठिन दौर तक बिहार ने हमेशा सामाजिक जागरूकता और राजनीति का समकोण साधे रखा है। यह समकोण है बदलाव की दृष्टि और सबको साथ लेकर चलने वाले विवेक और सद्भाव का।

हाल में केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना की अधिसूचना जारी की पर इससे पहले बिहार ने न सिर्फ जातिगत सर्वेक्षण पूरा किया, बल्कि उसी आधार पर आरक्षण के दायरे को बढ़ाने का साहसिक फैसला भी लिया। हालांकि संवैधानिक सीमाओं और अदालती अड़चनों ने इस कोशिश को रोक जरूर दिया पर इससे सामाजिक न्याय की बहस को नई ऊर्जा जरूर मिली। हाल में राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में खासी बढ़ोतरी कर साफ कर दिया कि सामाजिक सरोकार उसके एजेंडे में सर्वोपरि हैं। नीतीश कुमार ने ऐलान किया-अब वृद्धजन, दिव्यांगजन और विधवा महिलाएं हर महीने 400 की बजाय 1100 रुपये पेंशन पाएंगे। यह घोषणा करीब 1 करोड़ 10 लाख लाभार्थियों के जीवन में राहत और सम्मान का भरोसा देती है। पांच दशक पहले लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने इसी बिहार की धरती से संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, जिसकी जड़ें गांधी के 'ग्राम स्वराज' और 'सर्वोदय' में थीं। तब रामगोपाल दीक्षित ने जयप्रकाश आंदोलन का गीत लिखा था-'लाख-लाख झोपड़ियों में तो छाई हुई उदासी है,

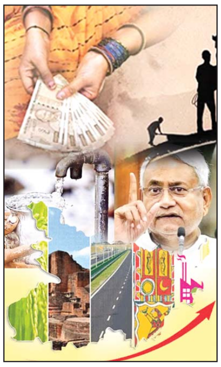

सत्ता-संपत्ति के बंगलों में हंसती पूरनमासी है।' आज भी ये पंक्तियां हमें याद दिलाती हैं कि अभी बहुत कुछ बदलना बाकी है।

पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना। साल 2006 में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आधी भागीदारी दी गई, फिर प्रारंभिक शिक्षक नियुक्तियों और नगर निकायों में भी यही सिलसिला चला। साल 2013 में पुलिस बल में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का रास्ता बना। मंडल कमीशन के बाद सामाजिक न्याय की इस गाथा ने बिहार को ऐतिहासिक बदलाव का केंद्र बना दिया। इसका नतीजा रहा कि आज राज्य में 10.81 लाख स्वयं सहायता समूह सक्रिय हैं, जिनसे 1.35 करोड़ महिलाएं आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। 2011 की जनगणना में महिलाओं की साक्षरता दर में 20 प्रतिशत की बढ़त दर्ज हुई और महिला प्रजनन दर 4.3 से घट कर 2.9 पर आ गई। इतना ही नहीं, बिहार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना के मोर्चे पर भी कई उदाहरण पेश किए हैं। प्रदेश में गांव-गांव तक पक्की सड़कें पहुंचाने की योजना 'मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ योजना' ने सैकड़ों किमी. लंबे कच्चे रास्तों को पक्की सड़कों में बदल दिया है। 'हर घर नल-का-जल' योजना के तहत करोड़ों परिवारों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा दी गई है। स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना के दायरे को और सशक्त किया गया है, जिससे बच्चों ड्रॉपआउट रेट में सुधार आया है। छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए 'मुख्यमंत्री साइकिल योजना' जैसे नवाचारों ने लड़कियों की की शिक्षा यात्रा को गति दी।

पंचायती राज से लेकर नगर निकाय, स्कूलों से लेकर पुलिस बल तक उन्होंने महिलाओं को आरक्षण देकर सत्ता के विकेंद्रीकरण को साकार किया और लाखों महिलाओं को नेतृत्व की मुख्यधारा से जोड़ा। नीतीश कुमार का एक और बड़ा साहसिक निर्णय था बिहार में शराबबंदी लागू करना। उन्होंने इसे सिर्फ नशामुक्ति तक सीमित नहीं रखा, बल्कि महिला सम्मान, पारिवारिक खुशहाली और सामाजिक सुधार से जोड़ दिया। इसी तरह वृद्धजन पेंशन, छात्रवृत्ति योजना, कन्या उत्थान योजना, हर घर नल का जल, पक्की सड़क, ग्रामीण पथ योजना और लाखों स्वयं सहायता समूहों के गठन जैसे काम बताते हैं कि उनके नेतृत्व में विकास महज आंकड़ों तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने समाज के आखिरी व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाने की ईमानदार कोशिश की और बिहार की पहचान को नई दिशा दी। आज अगर बिहार में लाखों महिलाएं आत्मनिर्भर बन चुकी हैं, गांव-गांव सड़कें और पानी की सुविधा पहुंची हैं, बच्चों में स्कूल छोड़ने की दर घटी है, युवाओं में तकनीकी कौशल बढ़ा है, तो इसके पीछे नीतीश कुमार की दूरदृष्टि और लगातार निगरानी ही है।

नीतीश कुमार ने साबित कर दिया कि इरादा मजबूत हो तो सामाजिक बदलाव महज नारा नहीं, धरातल पर उतरता सच बन सकता है। यही वजह है कि बिहार की पहचान में 'सुशासन बाबू' के रूप में उनका नाम आज भी सामाजिक बदलाव के सबसे मजबूत नायक के तौर पर लिया जाता है। कुल मिलाकर देखें तो बीते दो दशकों में बिहार ने सामाजिक बदलाव को राजनीति और विकास का आधार बना दिया है। शोर-शराबे से दूर, नीतीश कुमार के नेतृत्व में यह प्रदेश बदलाव की वह नई इबारत लिख रहा है, जिसमें सुशासन का मतलब सिर्फ सत्ता में रहना नहीं है, बल्कि समाज में भरोसा और सम्मान बहाल करना है।

(लेख में विचार निजी हैं)

> नीतीश ने साबित कर दिया कि इरादा मजबूत हो तो सामाजिक बदलाव महज नारा नहीं, धरातल पर उतरता सच बन सकता है। यही वजह है कि बिहार की पहचान में 'सुशासन बाबू' के रूप में उनका नाम सामाजिक बदलाव के मजबूत नायक के तौर पर लिया जाता है। कुल मिलाकर देखें तो बीते दो दशकों में बिहार ने सामाजिक बदलाव को राजनीति और विकास का आधार बना दिया है। शोर-शराबे से दूर नीतीश के नेतृत्व में यह प्रदेश बदलाव की नई इबारत लिख रह है

दिनोंदिन बढ़ रहा है क्यूरेटेड लिविंग स्पेस का चलन

- हाल के समय में क्यूरेटेड लिविंग स्पेस विकसित करने का चलन तेजी से बढ़ा है। क्यूरेटेड लिविंग स्पेस यानी ऐसा घर जो पसंद, आदतों, जरूरतों और कार्यशैली के मुताबिक, डिजाइन किया गया हो। यह इंटीरियर डेकोरेशन भर नहीं है, बल्कि इसका मकसद हर रंग, फर्नीचर, लाइट, खुशबू और तकनीक का मन और शरीर पर पॉजिटिव प्रभाव डालना है
- क्यूरेटेड लिविंग स्पेस के ट्रेंड से अब ऑफिस भी अछूते नहीं रहे। ऑफिसों में भी कर्मचारियों को हेल्दी माहौल देने के लिए दीवारों पर पेंटिंग्स से लेकर प्रेरक कोट्स तक लिखे जाने लगे हैं। पेड़-पौधों से ऑफिस को ग्रीन रखा जाता है। खुशबू के लिए लैवेंडर या सैंडलवुड जैसे नैचुरल अरोमा का उपयोग भी अब खूब होने लगा है

(मीडिया इनपुट्स)

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने घुसपैठियों को लेकर तल्खी भरी नाराजगी जताई है। घुसपैठिये आखिर, हमारे देश में घुस कैसे आते हैं? हमारी सीमाओं की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इस बात को बिहार में चुनावी मुद्दा बनाया जाना समझदारी की बात नहीं है?

तवलीन सिंह, पत्रकार
@tavleen_singh

व्यवस्था की पोल खोलते हादसे

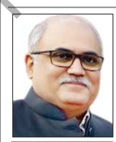

सड़क सुरक्षा **रजनीश कपूर**

दिल्ली-भारत की राजधानी-जो तेजी से विकसित हो रही है, में सड़कें न केवल प्रगति का प्रतीक हैं, बल्कि मौत का भी सैलाब बन चुकी हैं। 14 सितम्बर, 2025 को दिल्ली में फिर दिल दहला देने वाली घटना घटी, जब एक बीएमडब्ल्यू कार ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में वित्त मंत्रालय के अधिकारी नवजोत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गईं। आए दिन देश के अलग-अलग जगहों से ऐसी घटनाओं की खबर मिलती हैं, जो देश की सड़क सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख देती हैं।

सड़क हादसों के मुख्य कारण हैं-आपातकालीन सेवाओं की कमी, यातायात नियमों की अवहेलना और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सुस्ती। सबसे पहले, हालिया दुर्घटना को समझें। नवजोत सिंह की मौत के मामले में पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी की कार की गति निर्धारित गति सीमा से काफी अधिक थी। लेकिन हादसे के बाद जो सबसे बड़ी लापरवाही सामने आई, वह थी प्राथमिक चिकित्सा सहायता की अनुपस्थिति। यदि 'गोल्डन ऑवर'-यानी हादसे के पहले घंटे में उचित उपचार मिल जाता तो शायद नवजोत सिंह बच जाते। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, भारत में सड़क दुर्घटनाओं में 50 प्रतिशत मौतें प्री-हॉस्पिटल चरण में हो जाती हैं क्योंकि आपातकालीन सेवाएं अपर्याप्त हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक, देश में 1,55,622 सड़क मौतें हुईं जिनमें से 69,240 दोपहिया वाहनों से जुड़ी थीं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, 2022 में 4,64,910 दुर्घटनाओं में 1,47,913 मौतें हुईं। समस्या यह है कि भारत में एंबुलेंस सेवाएं जैसे 108 या 102, अक्सर ओवरलोडेड होती हैं। ग्रामीण और राजमार्गीय इलाकों में तो स्थिति और भी खराब है। यहां एंबुलेंस पहुंचने में औसतन 45 मिनट से एक घंटा लग जाता है।

एक अध्ययन के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना स्थल से ट्रॉमा सेंटर तक पहुंचने में देरी से 40 प्रतिशत मौतें बढ़ जाती हैं। दिल्ली में, जहां वाहनों की संख्या 1 करोड़ से अधिक है, ट्रैफिक जाम एंबुलेंस को रोक देता है। फोरेंसिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि प्री-हॉस्पिटल इमरजेंसी केयर मजबूत होती तो 30-50 प्रतिशत जानें बच

सकतीं। लेकिन सरकार की '5ई' रणनीति-इंजीनियरिंग, एजुकेशन, एनफोर्समेंट, इमरजेंसी केयर, में इमरजेंसी केयर पर निवेश न्यूनतम है। नतीजा? हर दिन 405 मौतें और 1,290 घायल। यह राष्ट्रीय संकट है।

यातायात नियमों की अवहेलना की बात करें। इसका बड़ा कारण 'चलता है' वाली मानसिकता है। इंटरनेट पर कई प्लेटफॉर्म्स पर चर्चाओं से साफ है कि लोग नियमों को 'सजावटी' मानते हैं। ओवरस्पीडिंग, बिना हेलमेट या सीटबेल्ट ड्राइविंग, लेन तोड़ना, आम हैं। क्यों? पहला, जागरूकता की कमी। स्कूलों में ट्रैफिक नियमों की शिक्षा पर्याप्त नहीं दी जाती। नतीजा, बच्चे बड़े होकर भी नियमों को महत्त्व नहीं देते। दूसरा, जनसंख्या घनत्व। 1.3 अरब आबादी वाले देश में सड़कें ओवरलोड हैं, लोग सोचते हैं, 'एक-दो नियम तोड़ लूंगा, क्या फर्क पड़ेगा?' तीसरा, सामाजिक दबाव। यदि कोई रेड लाइट पर रुकता है, तो पीछे से हॉर्न बजते हैं, गालियां पड़ती हैं, ट्रैफिक में समय की कमी से तनाव बढ़ता है, और नियम तोड़ना 'स्मार्ट' लगता है। चौथा, सांस्कृतिक पक्ष। भारत में 'जुगाड़' संस्कृति प्रचलित है। नियम तोड़ना 'चालाकी' माना जाता है।

एक सर्वे के अनुसार, अधिकांश ड्राइवरों को नियमों की पूरी जानकारी ही नहीं है। परिणामस्वरूप, 2023 में 35,000 पैदल यात्री और 10,000 बच्चे दुर्घटनाओं का शिकार बने। जनता जागरूक होती, तो ये आंकड़े कम होते। इस अवहेलना का एक प्रमुख कारण है कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सुस्ती भी है। ट्रैफिक पुलिस की कमी भयानक है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डवलपमेंट के अनुसार, 85,144 ट्रैफिक पुलिस पदों में 30 प्रतिशत और 58,509 कांस्टेबल पदों में 39 प्रतिशत रिक्त हैं। बिना सख्ती के, लोग नियम तोड़ते हैं। क्यों आलसी हैं एजेंसियां? पहला, संसाधनों की कमी। कैमरे, स्पीड गन्स, बॉडी कैमरे आदि जैसे उपकरण अपर्याप्त हैं। मोटर व्हीकल एक्ट, 2019 में सख्त जुर्माने जोड़े गए लेकिन ये लागू नहीं होते। दूसरा, भ्रष्टाचार, छोटे-मोटे उल्लंघनों पर 50-100 रुपये में सेटलमेंट हो जाता है, जिससे डर समाप्त हो जाता है। तीसरा, प्राथमिकताएं, पुलिस अन्य अपराधों पर फोकस करती है, ट्रैफिक को सेकेंडरी मानती है। चौथा, प्रशिक्षण की कमी, अधिकारी सड़क डिजाइन या व्यवहार समझ नहीं पाते। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, खराब सड़क डिजाइन और साइनेज भी दुर्घटनाएं बढ़ाते हैं, लेकिन प्रवर्तन कमजोर है। विदेशों की तरह यदि भारत में भी सख्ती हो, तो सुधार संभव है। नवजोत सिंह जैसी मौतें हमें झकझोरती हैं, यदि हम नहीं चेते, तो और कितने परिवार बिखरेंगे?

(लेख में विचार निजी हैं)

आशा **श्री राम शर्मा आचार्य**

मेघ मंडल जब घटाटोप बन कर उमड़ते-गरजते हैं, तो कृषि कर्मियों के मन आशा-उत्साह से भर कर बल्लियों उछलने लगते हैं, इंद्र वज्र सौ-सौ बार झुक कर उनकी सलामी देता है। अंधेरा आकाश प्रकाश से भर जाता है, और मोर नाचते एवं पपीहे कूकते हैं। हरीतिमा उनकी प्रतीक्षा में मखमली चादर ओढ़े मुस्कराती पड़ी रहती है। यह मनुहार मेघों की ही क्यों होती है? खोजने पर पता चलता है कि वे संचित जलराशि समेट, अपने आपको अति विनम्र बना कर उसे धरती पर बिखेर देते हैं। प्रतिभा परिवर्धन के उद्दंड उपाय तो अनेक हैं। उन्हें आतंकवादी-अनाचारी तक अपनाते और प्रेत-पिशाचों की तरह अनेक को भयभीत कर देते हैं, किंतु स्थिरता और सराहना उन्हीं प्रतिभावानों के साथ जुड़ी रहती है, जो शालीनता अपनाते हैं, और आदर्शों के प्रति अपने वैभव को उत्सर्ग करने में नहीं चूकते। ऐसे लोग शबरी, गिलहरी, केवट स्तर के ही क्यों न हों, अपने को अजर-अमर बना लेते हैं, और अनुकरण करने के लिए अनेकों को आकर्षित करते हैं। उनकी चुंबकीय विलक्षणता न जाने क्या-क्या, कहां-कहां से बटोर लाती है, और बीज को वृक्ष बना कर खड़ा कर देती है। प्रतिभा परिष्कार का अजस लाभ उठाने के लिए इन दिनों स्वर्ण सुयोग आया है। युगसंधि की वेला में, जीवट वाले प्राणवानों की आवश्यकता अनुभव की गई है। अवांछनीयताओं से ऐसे ही पराक्रमी जूझते हैं, और हनुमान, अंगद जैसे अनगढ़ होते हुए भी लंका को धराशायी बनाने के एवं राम राज्य का सतयुगी वातावरण बनाने के दोनों मोरचों पर अपनी समर्थ क्षमता का परिचय देते हैं। ऐसी परीक्षा की घड़ियां सदा नहीं आतीं। जो समय को पहचानते और बिना अवसर चूके अपने साहस का परिचय देते हैं, उन्हें प्रतिभा का धनी बनने में किसी अतिरिक्त अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। संयम और साहस का मिलन ही वरिष्ठता तक पहुंचा देता है। पुण्य और परमार्थ का राजमार्ग ऐसा है, जिसे अपनाने पर वरिष्ठता का लक्ष्य हर किसी को मिल सकता है। आत्म साधना और लोक साधना, दोनों एक ही लक्ष्य के दो पहलू हैं। जहां एक को सही रीति से अपनाया जाएगा, वहां दूसरा उसके साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ जाएगा।

रीडर्स मेल

यात्रा के जरिए संभावनाओं की तलाश

बिहार के चुनावी घमासान में यात्राओं से किस राजनीतिक दल को कितना फायदा देगा यह तो वक्त ही बताया। इतना जरूर है कि 17 अगस्त से इंडिया ब्लॉक द्वारा मतदाता अधिकार यात्रा चुनावी माहौल बना था। राजद ने बिहार अधिकार यात्रा के माध्यम से बाकी जिलों का दौरा किया ताकि इंडिया ब्लॉक का आधार मजबूत किया जा सके। इसी क्रम में भाजपा द्वारा 'चलो जीते हैं' यात्रा का शुभारंभ सम्राट चौधरी द्वारा किया गया। जन सुराज पार्टी द्वारा लगातार जन संपर्क यात्राओं को दौर जारी है। इसी कड़ी में बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद द्वारा 10 सितम्बर से 'सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाए' के माध्यम से बहुजन समाज के लोगों से संपर्क कर बिहार की जनता को बसपा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, और चुनावी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं।

वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

भारत की महती जिम्मेदारी

भारत के पड़ोसी देशों की वर्तमान स्थिति चिंता का विषय बन चुकी है। श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों में हिंसा, लूटपाट और राजनीतिक अस्थिरता के समाचार आते रहते हैं। जब पड़ोसी देशों में शांति नहीं रहती तो उसका प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष असर भारत पर भी पड़ता है। यह अस्थिरता सीमा पार आतंकवाद, अवैध शरणार्थियों की समस्या, आर्थिक असंतुलन और सामाजिक तनाव के रूप में हमारे सामने आती है। भारत के लिए समझना आवश्यक है कि पड़ोसी देशों की समस्याएं केवल उनके आंतरिक मसले नहीं हैं। वैश्विक मंच पर दक्षिण एशिया को एक इकाई की तरह देखा जाता है। यदि किसी देश में संकट गहराता है, तो उसका असर पूरे क्षेत्र की साख और संभावनाओं पर पड़ता है। भारत के पड़ोस में शांति और स्थिरता का वातावरण बनाना भारत की विदेश नीति का अहम उद्देश्य होना चाहिए। भारत के पास यह क्षमता है कि वह अपने पड़ोस में स्थिरता का मार्गदर्शक बने और पूरे क्षेत्र को प्रगति व शांति की ओर अग्रसर करे।

अंकित सोनी निशांत, धार, मप्र

कर-संग्रहण एक रणनीति भी है

जीएसटी सुधार कर-संग्रहण की प्रक्रिया भर नहीं है, बल्कि आर्थिक ढांचे को दीर्घकालीन मजबूती देने वाली रणनीति भी है। यह सवाल कराधान की जटिलता या पारदर्शिता भर का नहीं, बल्कि इस बात से भी जुड़ा है कि भारत अपने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में किस तरह स्थापित करता है। वास्तविक समस्या यह रही है कि अब तक भारत एमएसएमई क्षेत्र कर ढांचे की जटिलता, अनुपालन की ऊंची लागत और सीमित बाजार पहुंच से जूझता रहा है। नतीजतन, रोजगार सृजन और निर्यात की क्षमता घटती गई। स्थिति यही बनी रही तो भारत का 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य खटाई में पड़ सकता है। समाधान यही है कि सुधार को राजस्व उगाही की दृष्टि से ही न देखा जाए, बल्कि रोजगार, उद्यमिता और नवाचार का आधार भी बनाया जाए। ऐसी नीति बनानी होगी जहां एमएसएमई को सस्ता ऋण, आसान बाजार पहुंच और कौशल विकास की वास्तविक सुविधा मिले। तभी जीएसटी सुधार भारत को कराधान की जटिलताओं से मुक्त कर प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था की दिशा में सार्थक योगदान दे सकेंगे।

अवनीश कुमार गुप्ता, आजमगढ़

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा • राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण

सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 1209-1210, बारहवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 011-23352369, 011- 23352372, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750

वर्ष-35, अंक 36

आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026

*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्

भगवान इस जग के कण-कण में विद्यमान हैं।

संस्थापक: शहीद शिरोमणि लाला जगतनारायण जी, अमर शहीद रमेश चन्द्र जी एवं कलम के योद्धा अश्विनी कुमार जी

असभ्य होती राजनीति

चुनावों के समय तीखी बयानबाजी अक्सर होती रहती है। आरोपों-प्रत्यारोपों का दौर भी सियासत का हिस्सा है लेकिन आज के दौर में राजनीति से शालीनता गायब हो चुकी है। ऐसे लगता है कि गटर का कूड़ा चारों ओर फैल चुका है। पहली नजर में ऐसा लगता है कि अब सभ्य राजनेता बहुत कम रह गए हैं। जिस तरह से राजनेताओं के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल आम होता जा रहा है उससे साफ है कि सियासत का स्तर निम्न स्तर को छू रहा है। शब्द अपनी मर्यादाएं तोड़ते नजर आ रहे हैं। विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार सबको है लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि प्रधानमंत्री या किसी अन्य नेता की मां को गाली दी जाए। शिष्टता राजनीति से गहराई से जुड़ी है। यह एक राजनीतिक गुण है जो इस राजनीतिक आदर्श को कायम रखता है कि हमारे मतभेदों और बहुलता के बावजूद हम नागरिकों के रूप में एक-दूसरे से जुड़ सकते हैं। राजनीति का असभ्य होना इस बात का प्रमाण है कि हमारे राजनेता भी एक-दूसरे से जुड़ नहीं पाते। सिर्फ इसलिए कि हम महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमत नहीं हो पाते। राजनीति का वह दौर भी लोगों ने देखा है जब राजनीतिज्ञों में तीव्र वैचारिक मतभेद होते थे लेकिन वह एक-दूसरे का विनम्रता से अभिवादन करते थे। संसद या सार्वजनिक समारोहों में सद्भावनापूर्ण भेंट करते थे। यहां तक कि एक साथ भोजन भी करते थे। ऐसे कई उदाहरण भारत की राजनीति में मिलते रहे हैं लेकिन अब ऐसा विनम्र व्यवहार राजनीति से गायब हो चुका है।

> **राजनीतिज्ञों की भाषा और सार्वजनिक विमर्श में जिस तरह की गिरावट आ रही है उससे लोकतंत्र की वह भावना आहत हो चुकी है जिसमें परस्पर विरोधी विचारों के स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की सम्भावना हमेशा सम्माहित रहती है। हम इसका मूल कारण ढूंढें तो हम पाएंगे कि राजनीति में जिस तरह सत्ता के लिए सिद्धांतों की बलि चढ़ाई जा रही है, यह सब इसी का परिणाम है। गठबंधन सरकारों के दौर में राजनीति का सुविधापरक सामने आता गया। स्वार्थ और धन का लोभ बढ़ता गया। वैचारिक पक्ष कहीं पीछे रह गया और सामने आती गई अभद्र भाषा।**

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपशब्द कहा जाना पहले ही एक मुद्दा बन चुका है। बिहार में कांग्रेस और राजद के मंच से एक व्यक्ति ने प्रधानमंत्री मोदी की मां के लिए अपशब्द कहे थे। इस मामले को लेकर स्वयं प्रधानमंत्री ने तीखा हमला बोला था और कहा था कि मैं भले ही इन लोगों को माफ कर दूं लेकिन बिहार की जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। इस मामले पर विवाद बढ़ा तो बिहार कांग्रेस ने एआई से बनाया गया एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो के जरिये कांग्रेस पीएम मोदी पर मां के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाना चाहती थी। इस मामले पर भाजपा समर्थकों की ओर से कांग्रेस के विरुद्ध एफआईआर भी कराई गई थी। भाजपा ने इसे प्रधानमंत्री मोदी की मां का अपमान बताया। इस पर कांग्रेस का कहना था कि वीडियो में हमने कहीं भी प्रधानमंत्री की मां का अपमान नहीं किया। सभ्य राजनीति की चाह रखने वाले लोगों को इस वीडियो से काफी हताशा भी हुई। मामला पटना हाईकोर्ट में पहुंचा। अदालत ने इस पर कड़ा रुख अपनाया और कांग्रेस के इस वीडियो को सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से हटाने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री मोदी की मां अब इस दुनिया में नहीं है। उन्हें लेकर कांग्रेस को ऐसा वीडियो बनाना ही नहीं चाहिए था। पीएम मोदी और उनकी मां का एआई वीडियो बनाने के मामले को लेकर पद्मश्री मथुरभाई सवानी ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने ऐसे वीडियो पर आपत्ति जताते हुए टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि इस तरह की तकनीक के इस्तेमाल को लेकर कोई नियम कानून जरूर बनाए जाने चाहिए। ऐसे वीडियो में जिस तरह का संवाद इस्तेमाल किया जा रहा है वो हमारे भारत में कभी नहीं होता है। हम लोग इस वीडियो में दिखाए गए संवाद से पीड़ित हैं, इसलिए हमने ये पत्र लिखा है।

राजनीतिज्ञों की भाषा और सार्वजनिक विमर्श में जिस तरह की गिरावट आ रही है उससे लोकतंत्र की वह भावना आहत हो चुकी है जिसमें परस्पर विरोधी विचारों के स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की सम्भावना हमेशा सम्माहित रहती है। हम इसका मूल कारण ढूंढें तो हम पाएंगे कि राजनीति में जिस तरह सत्ता के लिए सिद्धांतों की बलि चढ़ाई जा रही है, यह सब इसी का परिणाम है। गठबंधन सरकारों के दौर में राजनीति का सुविधापरक सामने आता गया। स्वार्थ और धन का लोभ बढ़ता गया। वैचारिक पक्ष कहीं पीछे रह गया और सामने आती गई अभद्र भाषा। भारतीय राजनीति उस अंधेरी गुफा में फंसती गई जहां कोई यह नहीं जानता कि कौन सच बोल रहा है और कौन सही मार्ग का अनुसरण कर रहा है। अगर हम संसद की बात करें तो वहां भी कई सदस्यों का व्यवहार निर्लजता की श्रेणी में आता है। स्वस्थ बहस की जगह आरोप-प्रत्यारोप और व्यक्तिगत कटाक्ष देखने को मिलते हैं। सोशल मीडिया ने इस गिरावट को और भी तेज कर दिया है। यदि राजनीतिक बहस का स्तर इसी तरह गिरता रहा तो आम नागरिक नीतिगत उद्देश्यों से दूर होते जाएंगे और लोकतंत्र केवल चुनाव की जंग तक सीमित हो जाएगा।

अब सवाल यह है कि राजनीतिक दल इस गिरावट पर आत्म मंथन करेंगे? सवाल यह भी है कि राजनीति में शिष्टता वापिस आए तो कैसे? समाधान यह है कि बहस को व्यक्तिगत कटाक्षों और अभद्र भाषा से बचाया जाए और जनता को सार्थक विकल्प दिया जाए। राजनीतिक संवाद के स्तर पर ही लोकतंत्र की वास्तविकताएं सामने आएंगी। हम सब लोगों को भी यह मांग करनी चाहिए कि चुनाव प्रचार के दौरान शालीनता और विनम्रता बरती जाए ताकि युवा पीढ़ी के लिए राजनीतिज्ञ एक आदर्श बन सकें।

अनाज से भरपूर थाली का सम्मान...

कुपोषण के खिलाफ एक विश्वव्यापी जंग का ऐलान करो,
और पोषण माह में बढ़चढ़ कर बच्चों की सेहत पर ध्यान धरो,
फल, सब्जियां, अनाज से भरपूर थाली का सम्मान करो,
प्रत्येक बच्चे को कुपोषण रहित बनाने के लिए दुनिया को आह्वान करो !

गीता पाढा

हिमाचल में भारी वर्षा को लेकर 'येलो' चेतावनी

शिमला, (भाषा): हिमाचल प्रदेश के चार जिलों में भारी बारिश की 'येलो' चेतावनी के बीच राज्य के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हुई और दो राष्ट्रीय राजमार्ग समेत कुल 566 सड़कें बंद कर दी गई हैं। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा की सांसद कंगना रनौत ने गुरुवार को कुल्लू जिले के मनाली उपमंडल में सोलंग और पलचान के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, प्रभावित लोगों से बातचीत की और स्थिति का जायजा लिया।

566 सड़कें बंद

अभिनय से राजनीति में आयीं रनौत को मनाली के भाजपा नेता और पूर्व विधायक गोविंद सिंह ठाकुर ने स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर बुनियादी ढांचे को हुई क्षति और अन्य नुकसानों के बारे में बताया। सिंह ने सांसद को बताया कि खतरे में पड़े 15-16 घरों के परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। स्थानीय लोगों ने सांसद को बताया कि पूरा सोलंग गांव पर भूस्खलन का खतरा है, क्योंकि व्यास नदी उस पहाड़ को काट रही है जिस पर यह गांव बसा है।

बिहार चुनाव : अंत तक यात्री

कलम-दवात

कुमकुम चड्ढा

बिहार विधानसभा चुनाव निकट हैं। शुरुआती सर्वेक्षण एनडीए को मजबूत स्थिति में बताते हैं, किंतु राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वामदलों के महागठबंधन को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। यह प्रारंभिक चरण है और राजनीतिक समीकरण कभी भी बदल सकते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी की 20 ज़िलों में फैली 1300 किलोमीटर लंबी पदयात्रा के प्रभाव को समझा जा सकता है। एक तरह से यह उनके लिए कोई नई बात नहीं है मानो वे शाश्वत यात्री हों।

गांधी की यात्रा राजनीति, यदि यह शब्द प्रयोग किया जाए की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी, जब उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली। लगभग चार हज़ार किलोमीटर की इस पदयात्रा ने 12 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों को छुआ। यह यात्रा सितंबर में शुरू होकर 30 जनवरी 2023 को समाप्त हुई। इसका उद्देश्य था जनता से सीधे जुड़ना, राजनीतिक रूप से केंद्र में आना और अपनी प्रासंगिकता स्थापित करना। इसे सहज ही एक जन-आंदोलन और युवाओं के दुख-दर्द को समझने का प्रयास कहा जा सकता है।

राहुल गांधी ने उस समय कहा था -मैं सुबह छह बजे यात्रा शुरू करता हूं और रोज़ 25 किलोमीटर चलता हूं। इस अभियान में उनके साथ अनेक लोग जुड़े, जो उनके यूनाइट इंडिया संदेश के समर्थक बने। आलोचकों ने भले ही उनका उपहास उड़ाया लेकिन इस यात्रा ने उनकी छवि 'पप्पू' से बदलकर एक परिपक्व नेता की बनाई। उनका कथन 'नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं' सांप्रदायिक विभाजन से जूझ रहे लोगों के दिलों तक पहुंचा। राहुल गांधी की दूसरी यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा लगभग दो वर्ष बाद आरंभ हुई। यह मणिपुर से शुरू होकर मुंबई में समाप्त हुई। तीन महीने की इस यात्रा में गांधी ने 15 राज्यों की पदयात्रा की। इस बार उन्होंने भारत जोड़ो में एक नया शब्द जोड़ा, न्याय। इसका उद्देश्य था किसानों की परेशानी, बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार और असमानता जैसे मुद्दों को रेखांकित करना।

तीसरी यात्रा, जो वोट अधिकार यात्रा है। इसमें गांधी ने जनता के मौलिक मतदान अधिकार पर बल दिया। उन्होंने वोट चोरी का मुद्दा उठाया, यह आरोप लगाते हुए कि सत्तारूढ़ दल ने भारत निर्वाचन आयोग की मिलीभगत से मतों की चोरी की है। विपक्ष का दावा है कि बिहार में हुए स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू (एसआईआर) के कारण लाखों लोग मतदान से वंचित कर दिए गए। मतदाता सूची में जीवित लोगों के नाम मृतक के रूप में अंकित कर दिए गए और इस प्रकार की कई अनियमितताएं सामने आईं। तकनीकी पहलुओं और आंकड़ों से इतर जो बात असरदार साबित हुई वह थी वोट चोरी की यह राजनीति। यह केवल गांधी या यात्रा की नहीं, बल्कि उस वर्ग की कहानी है जिसे सत्ता में बैठे लोग लगातार हाशिए पर धकेलते रहे हैं। यही जनसंपर्क उनकी सबसे बड़ी ताकत साबित हुआ। इसमें जोड़ा गया नारा 'वोट चोर गद्दी छोड़' भी लोगों को खूब भाया। हाल ही में पटना की सभा में राहुल गांधी ने युवाओं से कहा 'वोट चोरी का मतलब है अधिकार की चोरी' रोजगार की चोरी, शिक्षा की चोरी, लोकतंत्र की चोरी और युवाओं के भविष्य की चोरी। वे आपकी ज़मीन और राशन छीनकर अडानी और अंबानी को देंगे। सभा में मौजूद भीड़ ने इसे ज़ोरदार समर्थन दिया।

रिपोर्टों के अनुसार वोट चोरी और अंबानी-अडानी का दोहरा मुद्दा बिहार

के मतदाताओं के बीच गहरी पकड़ बना रहा है। इस विवाद का एक जातीय पहलू भी है। विपक्ष का आरोप है कि मतदाता सूचियों में किए गए विलोपन का उद्देश्य यादवों, मुसलमानों, दलितों और पिछड़ी जातियों की ताक़त को कमज़ोर करना है। तथ्य यह है कि यही जातियां आरजेडी, वामदलों और कांग्रेस का मज़बूत सामाजिक आधार मानी जाती हैं। 2024 की ओर लौटें तो उस समय इंडिया गठबंधन ने भी जाति को चुनावी मुद्दा बनाया था और कहा था कि बीजेपी सत्ता में आई तो संविधान को 'टुकड़े-टुकड़े' कर फेंक देगी। वही संविधान जिसने दलितों और पिछड़ों सहित अनेक वर्गों को अधिकार प्रदान किए।

उतनी ही ताक़तवर है वोट चोरी की राजनीति। यदि इसे सोच-समझकर इस्तेमाल किया जाए तो यह सत्तारूढ़ दल की संभावनाओं को गंभीर क्षति पहुंचा सकती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे 2024 में संविधान बचाओ का नारा असरदार साबित हुआ था। उस समय राहुल गांधी पूरे देश में संविधान की पॉकेट कॉपी लेकर निकले थे और चुनावी सभाओं में उसे लहराकर भाषण देते थे। इसके बाद आए नतीजों में बीजेपी बहुमत से बाहर हो गई, जबकि इंडिया गठबंधन ने अप्रत्याशित प्रदर्शन करते हुए 234 सीटें जीतीं, बीजेपी को 240 सीटों पर रोक दिया।

अब यह देखना शेष है कि वोट चोरी अभियान विपक्ष को चुनावी लाभ दिला पाएगा या नहीं। फिलहाल यह अनिश्चित है परंतु इतना तय है कि बीजेपी में बेचैनी है। इसी कारण उसने हमले तेज कर दिए हैं। एक केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस की तुलना महाभारत के दुष्ट राजा कंस से की, जबकि बीजेपी के एक सांसद ने गांधी की पूरी कथा को झूठ पर आधारित बताया। इसमें प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अपनी माता के नाम पर सहानुभूति जगाने की कोशिश भी जोड़ दीजिए।

फिर भी, इस राहुल यात्रा से कुछ महत्वपूर्ण संदेश निकले हैं, 2024 के चुनाव जैसी विपक्षी एकजुटता की झलक, ज़मीनी स्तर पर नई ऊर्जा, कांग्रेस संगठन का पुनरुत्थान और सबसे अहम गांधी का बीजेपी और उसकी शासन शैली के लिए एक बड़े चुनौतीकर्ता के रूप में उभरना।

दृश्य भी उल्लेखनीय रहे, राहुल गांधी के विशाल कटआउट, फूलों की वर्षा, भारी संख्या में उमड़े स्त्री-पुरुष, बदलाव की उम्मीद से भरे किसान और वह कांग्रेस जो लगभग 35 वर्ष पहले बिहार की राजनीति में हाशिए पर चली गई थी, अब फिर से दिखने लगी है। इन तमाम बिंदुओं पर राहुल यात्रा को सफल कहा जा सकता है। हालांकि असली परीक्षा तो आने वाले बिहार चुनावों के नतीजों के बाद होगी। भारतीय चुनावों ने बार-बार दिखाया है कि भीड़ का जुटना हमेशा वोट में तब्दील नहीं होता।

विचारों को मूर्त रूप प्रदान करना मोदी का अंदाज

हसमुख अधिया

आईएएस

नरेन्द्र मोदी की की यात्रा के मूल में एक विशेष आदत अनवरत अवलोकन निहित है। वह प्रत्येक मुलाकात को विचारों के स्रोत के रूप में देखते हैं, चाहे वह सामान्य बातचीत हो या विदेश यात्रा लेकिन इन्हें नवीनता या अकादमिक विचार मानने वाले अनेक लोगों के विपरीत, मोदी इनमें से प्रत्येक विचार को संभावित समस्या के मूल कारण के आधार के तौर पर परखते हैं और फिर उसे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल समाधान में ढालते हैं। जिज्ञासा, विश्लेषण और प्रभावी क्रियान्वयन के इसी मिश्रण ने उन्हें जमीनी स्तर के आयोजक से एक वैश्विक राजनेता के रूप में स्थापित किया है। वास्तव में मोदी के लिए सीखना कभी उम्र का मोहताज नहीं रहा। बचपन से ही उनमें सहज जिज्ञासा थी और वे विविध कहानियों और अनुभवों को आत्मसात करते और तलाशते थे।

किशोरावस्था में ज्ञान की इसी ललक ने उनकी यात्रा का आगाज़ किया। पहले-पहल आध्यात्मिक साधक के रूप में और बाद में एक समर्पित संघ प्रचारक के रूप में उन्होंने समूचे भारत की यात्रा की और ऐसे अनुभव बटोरे जिन्होंने दुनिया को देखने-समझने की उनकी दृष्टि को आकार दिया। हर बातचीत उनके लिए कुछ नया सीखने का अवसर थी लेकिन जो बात उन्हें दूसरों से जुदा करती है, वह यह है कि यह सूझबूझ केवल सैद्धांतिक नहीं रही, अवसर पाते ही उन्होंने इसे क्रियान्वित किया। हालांकि, समस्या-समाधान की यह कला अक्सर अप्रत्याशित तरीकों से सामने आती रही। उदाहरण के लिए, काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के दौरान उन्होंने देखा कि कर्मचारी संगमरमर के ठंडे फर्श पर नंगे पांव काम कर रहे थे और उन्होंने तुरंत उन कर्मचारियों के लिए जूट की चप्पलों का प्रबंध कर दिया, यह एक आसान उपाय था जो सर्दी और आने वाली गर्मी, दोनों के लिए कारगर रहा। एक अन्य घटना में, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जापान की अपनी यात्रा के बाद उन्होंने स्पर्शनीय मार्गचिन्ह (उभरी हुई सतह) की अवधारणा शुरू की। दृष्टि बाधित लोगों के लाभ के लिए उन्होंने इसे अहमदाबाद में लागू करने पर ज़ोर दिया। ये संकेत उनकी एक अनवरत आदत को जाहिर करते हैं, अनदेखा कर दी गई बारीकियों को दैनिक जीवन को आसान बनाने वाले व्यावहारिक सुधारों में बदलना।

उनके कुछ विचार बीते दशकों की याद दिलाते हैं। 1993 में लॉस एंजिल्स की अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने फाइनेंशियल हाई-राइजिज के समूहों का अध्ययन किया, वर्षों बाद उन्हीं विचारों ने गुजरात में गिफ्ट सिटी को भारत की आर्थिक महत्वाकांक्षाओं को केंद्रीकृत करने के केंद्र के रूप में प्रेरित किया। इसी जिज्ञासा ने अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट को आकार दिया, जहां उन्होंने अधिकारियों से दुनियाभर की सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन करवाया लेकिन यह भी सुनिश्चित किया कि अंतिम डिज़ाइन स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित रहे। उनके अनुसार, ग्लोबल मॉडल तभी मायने रखते हैं, जब उन्हें पहले स्थानीय समुदायों की सेवा के लिए अनुकूलित किया जा सके।

2002 में, कच्छ में आए विनाशकारी भूकंप के बाद मोदी ने आपदा से निपटने में इस पद्धति को अपनाया। उन्होंने नियमित नौकरशाही मॉडलों को नकारते हुए अपनी टीम को जापान के कोबे भूकंप प्रबंधन का अध्ययन करने और उसके योजनाकारों से संपर्क करने का निर्देश दिया लेकिन उनका विचार स्पष्ट था, मॉडलों को पूरी तरह से आयातित नहीं किया जाएगा। इसके बजाय, इन जानकारियों को गुजरात के लिए तत्काल आवश्यकता वाले समाधानों जैसे भूकंपरोधी आवास, सुरक्षित निर्माण पद्धतियां और सामुदायिक भागीदारी में ढाला गया। भारत में यह पुनर्वास के लिए एक मानक बन गया, जिसने दिखाया कि कैसे एक संकट अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान को भारतीय पहल के साथ मिलाने का परीक्षण स्थल बन सकता है। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने इसी क्रम को जारी रखा, दक्षिण कोरिया में नदी-सफाई परियोजनाओं का दौरा इसी इरादे से किया, कि उनसे प्राप्त सबक को नमामि गंगे में लागू किया जा सके।

भारत के भीतर से उभरने वाले विचारों के प्रति भी उन्होंने उतना ही उत्साह दिखाया है। इसका उल्लेखनीय उदाहरण नैनो यूरिया है जो एक युवा वैज्ञानिक द्वारा प्रधानमंत्री को दिए गए सुझाव से उपजा नवाचार है। मोदी ने तुरंत इसकी क्षमता को पहचाना और इसके विकास पर ज़ोर दिया। आज इसकी एक छोटी बोतल पारंपरिक उर्वरक की एक बोरी की जगह ले सकती है जिससे लागत में कमी आती है और किसानों का बोझ कम होता है। यही खुलापन सरकारी कार्यक्रमों को भी आकार देता है, जब वित्तीय समावेशन योजना के नामकरण के लिए जनता की प्रतिक्रिया मांगी गई, तो नागरिकों ने ही 'जन धन' शब्द गढ़ा। वैज्ञानिकों और आम लोगों, दोनों के नवाचारों को प्रोत्साहित करते हुए मोदी ने दिखाया कि कैसे घरेलू विचारों को राष्ट्रीय समाधानों में बदला जा सकता है।

ये कहानियां मिलकर मोदी के जीवन के एक अनवरत सूत्र को उजागर करती हैं। मंदिर में मामूली प्रतीत होने वाली असुविधा को दूर करने से लेकर, एक आधुनिक शहर की रूपरेखा तैयार करने, किसी तबाह क्षेत्र के पुनर्निर्माण या किसी क्रांतिकारी उर्वरक को अपनाने तक उनकी प्रक्रिया एक समान ही रही है, स्थिति का ध्यानपूर्वक अवलोकन करना, लोगों की वास्तविक आवश्यकताओं की पहचान करना और उसे पूरा करने के लिए निर्णायक रूप से कार्य करना। "आ नो भद्रा: क्रतवो यन्तु विश्वत:" (प्रत्येक दिशा से कल्याणकारी विचार हमारी ओर आएं) के भारतीय दर्शन का पालन करते हुए मोदी हर यात्रा और संवाद से सक्रिय रूप से अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं और भारत को आगे बढ़ाने के लिए उनका उपयोग करने का दृढ़तापूर्वक प्रयास करते हैं। अंतत:, उनका हर विचार लोगों के लिए होता है, उनके जीवन और विकसित भारत की उनकी आकांक्षाओं में निहित होता है।

-(लेखक वित्त एवं राजस्व सचिव के पद से सेवानिवृत्त)

अब दिल्ली से आइजोल दूर नहीं

आकाश चोपड़ा

पूर्वोत्तर राज्यों का लगातार विकास हो रहा है। सरकार की योजनाओं को भी जमीन पर उतारा जा रहा है। उसी के तहत भारतीय रेलवे लगातार रेल नेटवर्क का जाल पूर्वी राज्यों में बिछा रही है। इससे ना सिर्फ कनेक्टिविटी आसान होगी बल्कि पर्यटन, व्यापार और आर्थिक विकास को भी रफ्तार मिलेगी। इससे क्षेत्रीय जीडीपी सालाना 2-3 प्रतिशत की दर से बढ़ने की संभावना है।" प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बीते दिन सैरांग-आनंद विहार राजधानी एक्सप्रेस की शुरुआत किए जाने के बाद भागलपुर भी मिजोरम से जुड़ गया। शनिवार को चली सैरांग-आनंद विहार राजधानी एक्सप्रेस रविवार को भागलपुर पहुंची। ट्रेन 19 सितंबर से हर शुक्रवार को सैरांग से नियमित चलेगी और प्रत्येक शनिवार को भागलपुर पहुंचेगी।यह ऐतिहासिक क्षण मिज़ोरम की कनेक्टिविटी यात्रा में मील का पत्थर है और देश की "एक्ट ईस्ट नीति" को ज़मीन पर उतारने का एक सशक्त उदाहरण बनकर सामने आया है। 8,070 करोड़ की लागत से बनी यह 51.38 किलोमीटर लंबी रेल लाइन तकनीकी और भूगर्भीय दृष्टि से भारतीय रेल के इतिहास की सबसे जटिल परियोजनाओं में मानी जा रही है।"बैराबी-सैरांग रेल लाइन मिजोरम की नई जीवनरेखा है। इस परियोजना में 48 सुरंगें, 55 बड़े पुल और 87 छोटे पुल शामिल हैं। इनमें से एक पुल 114 मीटर ऊंचा है जो कुतुबमीनार से भी ऊंचा है। यह तकनीकी चमत्कार न केवल आधुनिक इंजीनियरिंग का उदाहरण है, बल्कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में भी विकास की राह बनाने का प्रतीक है। राजधानी एक्सप्रेस के शुरू होने से आइजोल देश की राजधानी दिल्ली से सीधे रेल नेटवर्क से जुड़ा, इससे ना सिर्फ यात्रा सुविधाजनक और सुगम होगी, बल्कि व्यापारिक दृष्टि से भी लाभ होगा।"

गौरतलब है कि अभी तक सिर्फ सिलचर तक रेल कनेक्टिविटी थी लेकिन ऐसा पहली बार होगा जब बैराबी-सैरांग रेलवे लाइन बनने से राजधानी आइजोल आजादी के बाद पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ा. वहीं, अरुणाचल, त्रिपुरा, असम के बाद मिजोरम पूर्वोत्तर का चौथा राज्य है जो रेल नेटवर्क से सीधे जुड़ेगा मिजोरम की अर्थव्यवस्था अब तक सड़क परिवहन पर निर्भर थी। सीमित मार्ग और पहाड़ी इलाका हमेशा चुनौती बने रहे। नई रेल लाइन से यह समस्या खत्म होगी और खाद्यान्न, उर्वरक एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुचारु होगी। इससे परिवहन लागत घटेगी और शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार तथा पर्यटन में नई

गति आएगी। इस रेल लाइन का विस्तार म्यांमार सीमा तक करने की योजना है। इस रेलवे लाइन की वजह से साल के बारहों महीने माल की ढुलाई हो सकेगी और सड़कों पर निर्भरता काफी कम हो जाएगी। बरसात के सीजन में पहाड़ की मिट्टी धंसने के कारण अक्सर सड़क संपर्क कट जाता है। इससे लागत में तो कमी आएगी ही, कृषि उत्पादों के लिए नए बाजार खुलेंगे और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

पर्यटन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस रेलवे लाइन की वजह से राज्य में पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से आईआरसीटीसी ने बीते महीने मिजोरम सरकार के साथ दो साल के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत असम की राजधानी गुवाहाटी से एक विशेष पर्यटक ट्रेन का आइजोल तक संचालन किया जाएगा। इससे देशी-विदेशी पर्यटकों को राज्य की संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य से रूबरू कराया जा सकेगा। राज्य में धीरे-धीरे पर्यटकों की आवाजाही बढ़ रही है। पर्यटन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2023-24 के दौरान जहां 2.19 लाख पर्यटक यहां पहुंचे थे वहीं बीते वित्त वर्ष के दौरान यह तादाद 4.70 लाख तक पहुंच गई। अब ट्रेनों का संचालन शुरू होने के बाद इसमें और तेजी की उम्मीद है।

ऐसा होने पर पूर्वोत्तर न केवल देश के अन्य हिस्सों से बल्कि दक्षिण-पूर्व एशिया से भी मजबूत रूप से जुड़ जाएगा। इससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार और सीमा पार सहयोग के नए अवसर पैदा होंगे। इस लाइन से स्थानीय उद्योगों, खासकर बांस आधारित उत्पाद, बागवानी और हैंडीक्राफ्ट को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि अब उत्पाद आसानी से देश के बड़े बाजारों तक पहुंच सकेंगे। भारत सरकार पूर्वोत्तर में चीन की सीमा के पास रेलवे लाइनें बनाने की योजना बना रही है। इसका उद्देश्य रणनीतिक रूप से इन इलाकों में लॉजिस्टिक्स सुविधाओं को बेहतर करना है। इस प्रोजेक्ट पर 300 अरब रुपये (लगभग 3.4 अरब डॉलर) की लागत आएगी और इसे चार साल में पूरा करने का लक्ष्य है। हालांकि भारत और चीन के बीच हाल के साल में संबंधों में सुधार हुआ है लेकिन भारत यह रेलवे विकास दीर्घकालिक रणनीतिक योजना के तहत कर रहा है। पांच साल पहले सीमा विवाद के बाद दोनों देश अब आर्थिक अवसरों और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के तहत बदलते व्यापारिक रुझानों के कारण बेहतर संबंधों की दिशा में बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रोजेक्ट में 500 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बनाए जाएंगे, जिसमें पुल और सुरंगें शामिल होंगी। यह रेल नेटवर्क चीन, बंगलादेश, म्यांमार और भूटान से सटे अलग-थलग पड़े क्षेत्रों को जोड़ेगा। इसका लक्ष्य नागरिकों के लिए बेहतर पहुंच, लॉजिस्टिक्स क्षमता में सुधार और सैन्य तैयारियों को मजबूत करना है। पिछले दस सालों में भारत ने पूर्वोत्तर में 9,984 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया है, जिसमें 1.07 लाख करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। इसके अलावा, 5,055 किलोमीटर सड़कें अभी बन रही हैं। साथ ही, 1,700 किलोमीटर रेलवे ट्रैक भी बनाए गए हैं। यह बुनियादी ढांचा प्राकृतिक आपदाओं या सैन्य अभियानों के दौरान तेजी से जवाब देने की क्षमता को बढ़ाएगा। भारत ने उत्तर-पूर्व के इलाके में उन हवाई पट्टियों को फिर से खोल दिया है जो 1962 के युद्ध के बाद से बंद पड़ी थीं। इन्हें एडवांस लैंडिंग ग्राउंड कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल सैन्य हैलीकॉप्टरों और विमानों के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा लद्दाख में भी एलएसी के पास तक रेल लाइन पहुंचाने पर चर्चा चल रही है। अभी भारतीय रेलवे की पहुंच कश्मीर में बारामूला तक हुई है।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83

पंजाब केसरी

दिल्ली कार्यालय :

फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रैस, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

मतदान लोकतंत्र का आधार स्तंभ है।
-मार्टिन लूथर किंग, जूनियर

ऐतिहासिक कदम

कोलकाता में तीनों सेनाओं के संयुक्त कमांडर सम्मेलन में देश में पहली बार लिया गया तीन साझा सैन्य स्टेशन बनाने का फैसला सशस्त्र सेनाओं के बीच अभूतपूर्व एकीकरण और समन्वय के लिहाज से निस्संदेह ऐतिहासिक है, इसके साथ ही यह भविष्य की सामरिक चुनौतियों से निपटने की देश की तैयारियों की एक झलक भी पेश करता है। दरअसल, तीनों ही सेनाएं पिछले कुछ वर्षों से आपस में बेहतर एकीकरण के लिए क्रॉस-पोस्टिंग, लॉजिस्टिक्स की संयुक्त व्यवस्था और खरीद, प्रशिक्षण व स्टाफिंग की संयुक्त योजना इत्यादि को अपना रही हैं। तीन साझा स्टेशनों का निर्णय इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। दरअसल, इन्हें बदलते वैश्विक माहौल की जटिल चुनौतियों से निपटने के लिए थिएटराइजेशन सुधार लागू करने की प्रक्रिया का अंग माना जा सकता है। गौरतलब है कि रक्षा मंत्रालय तीनों सेनाओं के एकीकरण के लिए पहले ही अंतर-सेवा कानून बना चुका है, जो किसी सेना अधिकारी को दूसरी सेनाओं के ऊपर कार्रवाई एवं कमान का अधिकार देता है। थिएटराइजेशन का उद्देश्य सेना की तीनों सेवाओं और उनके संसाधनों को एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में एकीकृत कमान संरचना के तहत परिचालन तैनाती के लिए विशिष्ट 'थिएटर' कमानों में समन्वित करना है। हालांकि, तीनों सेनाएं अब तक थिएटर कमान पर एकमत नहीं हुई हैं। वायुसेना ने थिएटर कमान को लेकर इस बात पर आपत्ति जताई है कि इससे उसकी सीमित लड़ाकू परिसंपत्तियों का और अधिक विभाजन हो जाएगा। बहरहाल, तीन संयुक्त सैन्य स्टेशन बनाने से संसाधनों के बेहतर उपयोग से आर्थिक बचत तो होगी ही, आधुनिक युद्ध और आपदा राहत जैसे साझा अभियानों को पूरा करने में भी भारतीय सेना की क्षमता बढ़ेगी और सीमाओं की बेहतर ढंग से सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। इसके अलावा, सम्मेलन में तीनों सेनाओं की शिक्षा शाखा के विलय की भी घोषणा की गई है, जिससे प्रशिक्षण की गुणवत्ता तो बढ़ेगी ही, सभी सेनाओं के अधिकारियों व जवानों के बीच एक साझा रणनीतिक

दृष्टिकोण और मूल्यों को स्थापित करने में भी मदद मिलेगी। हालांकि, विभिन्न सेनाओं की पृथक परंपराओं, कार्यप्रणालियों और संस्कृति के चलते उनमें समन्वय आसान नहीं होगा, लेकिन आधुनिक युद्ध की बदलती प्रकृति और क्षेत्रीय सुरक्षा की चुनौतियों के बीच संयुक्त सैन्य स्टेशनों और त्रि-सेवा शिक्षा कोर की स्थापना देश को यकीनन एक अधिक समन्वित और शक्तिशाली रक्षा शक्ति के रूप में स्थापित करेगी।

तमिलनाडु में किसकी लहर

राज्य में अगले साल अप्रैल में चुनाव होने हैं, लेकिन विपक्षी और सत्ताधारी दल आपसी कलह में उलझे हुए हैं। अब तक कोई भी पार्टी मजबूत गठबंधन नहीं बना सकी है। राज्य के छह करोड़ मतदाताओं को समझना होगा कि यदि स्थायी सरकार नहीं बनी, तो यह राज्य की प्रगति के साथ ही देश की सुरक्षा के लिए भी जोखिम भरा होगा।

तमिलनाडु की राजनीति गरमा रही है। अगले साल अप्रैल में संभावित विधानसभा चुनाव राजनीतिक पार्टियों को डरा रहे हैं। चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक गर्मी तो दिखने लगी है, लेकिन न तो सत्ता पक्ष और न ही विपक्ष के पक्ष में कोई तेज लहर दिख रही है। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (अन्नाद्रमुक) और अन्य छोटी विपक्षी पार्टियां अब तक मजबूत विपक्षी गठबंधन नहीं बना सकी हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने निश्चित ही अन्नाद्रमुक के साथ गठबंधन कर अपनी कुछ पैठ बनाई है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि को बढ़ावा मिलने की वजह से सत्ताधारी दल द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्रमुक) में आपसी कलह मची हुई है। राज्य के विवादास्पद मुद्दों में बिगड़ी कानून व्यवस्था, नशीले पदार्थों का खतरा, शराब घोटाला और रेत माफिया का बोलबाला प्रमुख हैं। संक्षेप में, विपक्ष या सत्ताधारी दल की ओर से अब तक कोई चुनावी माहौल नहीं बनाया गया है।

आर राजगोपालन
वरिष्ठ पत्रकार

राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में अभिनेता से नेता बने तमिल वेत्री कड़गम के विजय जोसेफ जैसे नए खिलाड़ी हैं, तो पट्टाली मक्कल काची में फूट पड़ी है। तमिल राष्ट्रवाद की राजनीति करने वाली पार्टियों, जैसे विजयकांत की द्रविड़ मुर्पोक्कू मुनेत्र कड़गम और सीमान के नेतृत्व वाली नाम तमिलार काची, टीटीवी दिनाकरन की अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम (एएमएमके), इनमें से किसी ने भी अब तक कोई ठोस गठबंधन नहीं किया है। हालांकि, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसी साल अप्रैल में अन्नाद्रमुक के साथ भाजपा के गठबंधन की घोषणा कर दी थी। आगामी चुनाव में कई कारक असर डालेंगे।

प्रमुख मुद्दे : राज्य में आर्थिक, राजकोषीय, औद्योगिक और कृषि जैसे कारक महत्वपूर्ण हैं। राज्य के पास धन का अभाव है। वित्तीय व्यवस्था बाहरी कर्जे पर निर्भर है। बैंकों का ओवरड्राफ्ट बढ़ गया है। नीति निर्माण के उच्च स्तर पर कटौती और कमीशनखोरी की वजह से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) बहुत न्यूनतम स्तर पर है।

राहुल गांधी फैक्टर : कांग्रेस के पास अपना खुद का अच्छा-खासा वोट बैंक था, लेकिन राहुल गांधी पूरी तरह द्रमुक पर निर्भर थे। नतीजतन, कांग्रेस युवाओं को अपने साथ नहीं जोड़ पाई। कांग्रेस के जनाधार को बरकरार रखने में पार्टी का राज्य नेतृत्व विफल रहा। पी चिदंबरम जैसे कद्दावर नेताओं के बावजूद द्रमुक ने बड़ी ही चतुरता से कांग्रेस को अपने प्रभाव के नीचे रखा।

राज्य की अन्य पार्टियां : अगले साल तमिलनाडु में छह करोड़ से अधिक मतदाता 234 विधानसभा सदस्यों को चुनेंगे। राज्य में 12 लोकप्रिय पार्टियां हैं, जो चुनाव में अपना भाग्य आजमाएंगी। कुछ नए दल भी बन रहे हैं। ऐसे में द्रविड़ विचारधारा का परीक्षण लाजिमी है। कहने की जरूरत नहीं है कि अध्यात्मवाद के चलते एक सौम्य हिंदुत्व की भावना पहले से ही राज्य में विद्यमान थी, जो अब उभरकर सामने आ रही है। इसके अलावा, तमिलनाडु के चुनाव में जातियां भी अहम भूमिका निभाती रही हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने वाली भाजपा ने तमिल के युवाओं में राष्ट्रवाद की भावना भर दी है। जबकि राज्य के राजनीतिक दलों में अंदरूनी कलह जारी है। इनके नेता वरिष्ठ-कनिष्ठ, निष्कासन, दल-बदल, साझा न्यूनतम मसौदा तैयार करने में उलझे हुए हैं।

अन्नाद्रमुक में बगावत : मुख्य विपक्षी दल अन्नाद्रमुक में बगावत और गुटबंदी गठबंधन के विस्तार के लिए अहम समस्या है। एडापडी के पलानीस्वामी (ईपीएस) ने कानूनी लड़ाई के जरिये नीति निर्माण के लिए संगठन के महासचिव का पद, और सबसे बड़ी बात, पार्टी का दो पत्ती का चुनाव चिह्न अपने पास रखा है।

दो वरिष्ठ नेताओं का टकराव : अन्नाद्रमुक के असंतुष्ट नेता सेंगोट्टायन, जो एमजीआर-जयललिता के कट्टर समर्थक माने जाते रहे हैं, बीते कुछ दिनों से सुर्खियां बटोर रहे हैं। उन्होंने पार्टी से अलग हुए धड़ों को मिलाने को लेकर अन्नाद्रमुक के शीर्ष नेता ईपीएस को दस दिन का अल्टीमेटम दे दिया। ईपीएस ने इसे मानने के बजाय अनुशासनहीनता बताते हुए सेंगोट्टायन को तत्काल पार्टी के सभी दायित्वों से मुक्त कर दिया। इस कठोर कार्रवाई ने निश्चित रूप से एमजीआर और जयललिता के अनुयायियों को विचलित किया होगा। ईपीएस द्वारा सेंगोट्टायन पर की गई कार्रवाई का अन्नाद्रमुक के पूर्व संयोजक ओ पन्नीरसेल्वम (ओपीएस), एएमएमके के महासचिव टीटीवी दिनाकरन और दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता की सहयोगी रहीं वीके शशिकला ने निंदा कर उन्हें सांत्वना दी है। सेंगोट्टायन की बर्खास्तगी को 'तानाशाही की पराकाष्ठा' बताते हुए ओपीएस ने कहा, 'वह पार्टी के सबसे वरिष्ठ पदाधिकारियों में से एक हैं। उनका मकसद सिर्फ पार्टी को एकजुट करना है। उन्हें इतनी बड़ी सजा इसलिए दी गई, क्योंकि उन्होंने एकता की आवाज को बुलंद किया।' टीटीवी दिनाकरन ने सेंगोट्टायन के एकता के आह्वान का समर्थन किया और चेतावनी दी कि सभी पार्टी नेताओं को एकजुट करने में विफलता अन्नाद्रमुक की हार का कारण बनेगी।

पार्टियों के तूफानी दौरे : द्रमुक एवं अन्नाद्रमुक के नेताओं ने रोड शो करने शुरू कर दिए हैं। एमके स्टालिन का ध्यान द्रमुक सरकार की समाज कल्याण योजनाओं पर है। विपक्षी अन्नाद्रमुक नेता एडापडी पलानीस्वामी 125 विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो कर चुके हैं और शेष बचे 109 क्षेत्रों में आने वाले महीनों में रोड शो करेंगे।

स्टालिन की विदेश यात्रा : मुख्यमंत्री के रूप में अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) हासिल करने के लिए एमके स्टालिन विदेश दौरे पर गए थे। विपक्ष के कई नेताओं ने इसे ढकोसला बताते हुए आलोचना की कि बीते चार साल तक एफडीआई के सिर्फ झूठे दावे किए गए थे। अब भी सिर्फ दिखावे के लिए मुख्यमंत्री विदेश दौरों पर जा रहे हैं, जिसका उन्हें कोई लाभ नहीं मिलने वाला।

तमिलनाडु का भविष्य और जोखिम : आप चाहे इसे जिस तरह से देखें, तमिलनाडु का भविष्य सकारात्मक और नकारात्मक भावनाओं से भरा है। यदि मतदाता स्थायी सरकार नहीं चुनते हैं, तो राज्य की प्रगति नहीं होगी। अगले छह माह में राज्य के छह करोड़ मतदाताओं को इसे लेकर अपना मन बना लेना चाहिए कि श्रीलंका और मालदीव से सटे तटवर्ती राज्य तमिलनाडु को गठबंधन की सरकार नहीं चाहिए। यह देश की सुरक्षा के लिए भी जोखिम भरा होगा।

edit@amarujala.com

तकनीक

खतरा, जो वाशिंगटन और बीजिंग को जोड़ेगा

एआई सब कुछ बदलने वाला है। अगर मानवता की खातिर दो एआई महाशक्तियां नजदीक नहीं आईं, तो नतीजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा।

चीन और अमेरिका को अभी यह एहसास तक नहीं है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) उन्हें दूर करने के बजाय नजदीक लाने जा रही है। एआई का उदय दोनों देशों के बीच प्रभुत्व के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा का, तो इसके साथ ही इतनी ही ऊर्जा और गहराई से परस्पर सहयोग का अभूतपूर्व दबाव भी बनाएगा। दरअसल, एआई पिछली तकनीकों से बिल्कुल अलग है। यह आपकी घड़ी, टोस्टर, कार, चश्मे, कंप्यूटर और पेसमेकर इत्यादि सभी में मौजूद होगा और खुद में सुधार के लिए लगातार डाटा एकत्रित करता रहेगा। जाहिर है कि ऐसा होने पर यह सबकुछ बदल देगा, जिसमें दुनिया की दो एआई महाशक्तियों के बीच भू-राजनीति और व्यापार शामिल है। हर बीतते महीने दोनों देशों के बीच सहयोग की जरूरत अधिक तीव्रता से महसूस की जाएगी।

उदाहरण के लिए, अगर आपका कूल्हा टूट जाता है, और आपको पता चलता है कि दुनिया में सबसे स्मार्ट प्रत्यर्पण योग्य कूल्हा चीन द्वारा तैयार एआई से जुड़ा है, तो क्या आप इसे अपने शरीर में लगवाएंगे? नहीं, मैं ऐसा तब तक नहीं करूंगा, जब तक दोनों देशों के बीच सामान्य नैतिक आधारों पर इससे संबंधित कोई समझौता न हो गया हो, क्योंकि इससे यह सुनिश्चित होगा कि एआई का उपयोग हर स्थिति में मानवता के हित में होगा। अगर ऐसा नहीं हो सका, तो घोटालेबाजों, ड्रग डीलरों और आतंकियों के हाथों एआई क्रांति के दुरुपयोग का डर पैदा होगा। यह स्थिति दोनों ही महाशक्तियों को अस्थिर करेगी।

थॉमस फ्रीडमैन
द न्यूयॉर्क टाइम्स

हेनरी किसिंजर और एरिक श्मिट के साथ एआई पर आधारित *जेनेसिस* नामक पुस्तक लिखने वाले तकनीकी विशेषज्ञ क्रेग मुंडी, जो कि 20 वर्षों से मेरे दोस्त हैं, के साथ हुए संवाद के आधार पर वाशिंगटन में बैठे चीन विरोधी और बीजिंग में अमेरिका विरोधी कट्टरपंथियों तक संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि आप लोग भ्रम में हैं कि एआई की दोनों महाशक्तियां आपस में लड़ने का जोखिम उठाएंगी। एआई इतना अलग, इतना महत्वपूर्ण और इतना प्रभावी है कि-दोनों एआई महाशक्तियां अलग-अलग रास्ते पर चलने का साहस शायद ही जुटाएं। इसी वजह से मेरा मानना है कि अमेरिका और चीन एआई को लेकर मानवीय हितों को देखते हुए प्रतिस्पर्धा के बीच सहयोगी रवैया बनाए रख सकते हैं। साथ ही ऐसे देशों तक एआई की पहुंच सीमित कर सकते हैं, जो नियमों का पालन करने को तैयार नहीं हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, तो दुनिया ऐसी खंडित डिजिटल स्वायत्तता की ओर बढ़ जाएगी, जहां हर देश अपना अलग एआई पारिस्थितिकी तंत्र बनाएगा, जिसकी सुरक्षा असंगत मानकों और आपसी संदेह से होगी।

2000 के दशक को याद करें, जब मार्क जुकरबर्ग ने कहा था कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल नेटवर्क लोगों को नुकसान पहुंचाने के बजाय उनके सहयोगी होंगे। आज इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक तरह से जहर परोसा जा रहा है। ऐसे ही एआई को लेकर यदि चीन और अमेरिका जैसी महाशक्तियां नहीं चेतीं, तो मानवीय विनाश के लिए तैयार रहें, क्योंकि एआई को कोई सरकार, उनका रक्षा मंत्रालय या प्रवर्तन एजेंसियां संचालित नहीं कर रही हैं, इनका संचालन पूरी तरह निजी कंपनियों के हाथ में है। धीरे यह हर जगह अपनी पहुंच बना लेगा, तब इसको नियंत्रित करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। कुल मिलाकर, बात यह है कि यदि वाशिंगटन और बीजिंग इस चुनौती का सामना करने में विफल होते हैं, तो शेष दुनिया के पास बचाव का कोई मौका नहीं होगा। पहले ही काफी देर हो चुकी है।

©The New York Times 2025

जिन खोजा, तिन पाइयां

अगर दूरदर्शिता और आत्मबोध को आप शारीरिक सुखों के ऊपर रखते हैं, तो वृद्धावस्था में भी अवसर मिलेंगे। जहां नदी की गति कम होती है, वहीं वह सबसे अधिक गहरी होती है। वृद्धावस्था में जब जीवन की गति कुछ धीमी हो जाती है, तभी उसमें गहरे अर्थ आते हैं।

जब आप बुजुर्ग होने लगते हैं, तो भविष्य की चिंता सबसे पहले होने लगती है। अगर जीवन के मूल्य केवल शरीर और इंद्रियों के सुख हैं, तो हमें यह मान लेना चाहिए कि युवावस्था के बाद जीवन ढलान की ओर जाता है। अगर सांसारिक सफलता और शक्ति का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ है, तो मध्य आयु, यानी गृहस्थ जीवन, जिंदगी का शिखर होगी। लेकिन यदि दूरदर्शिता और आत्मबोध इनसे भी अधिक महत्वपूर्ण माने जाएं, तो वृद्धावस्था के अपने अवसर होते हैं।

रेब जालमान

ध्यान रहे, जहां नदी की गति कम होती है, वहीं वह सबसे अधिक गहरी होती है। इसी तरह वृद्धावस्था में जब जीवन की गति कुछ धीमी हो जाती है, तभी उसमें गहरे अर्थ आते हैं। लेकिन इसके लिए अज्ञानता का पर्दा हटना जरूरी है। अगर वास्तविकता एक नीरस और उदास मरुस्थल है, और आत्मा केवल जटिल यांत्रिक प्रणाली है, तो आत्मज्ञान और दृष्टि के पुरस्कार इंद्रियों के सुख या सामाजिक सफलता की तृप्ति से मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं माना जाता। उपनिषद कहते हैं, सब छोड़कर उसका अनुसरण करो! उसकी अनिर्वचनीय समृद्धि का आनंद लो। हिंदू धर्म में जीवन के तीसरे चरण की बात की जाती है, जो संन्यास या सेवानिवृत्ति का चरण है। जब पहला पौत्र या पौत्री जन्म लेती है, तब व्यक्ति समाज के दायित्वों से मुक्त हो सकता है, जिन्हें उसने अब तक इच्छा के साथ निभाया। बीस-तीस साल तक समाज के लिए काम किया, अब राहत का समय है, ताकि जीवन का अंत होने से पहले उसे समझा जा सके। अब समय है सच्ची शिक्षा शुरू करने का, यह जानने का कि मैं कौन हूं और जीवन का अर्थ क्या है। उस 'मैं' का रहस्य क्या है, जिसके साथ हम इतने करीब रहे, जिसमें अजीब विचित्रताएं, समझ से परे समस्याएं और तर्कहीन आवेग हैं?

मुड़-मुड़ के देख

हम जन्म क्यों लेते हैं, मेहनत और संघर्ष क्यों करते हैं, सुख-दुख का हिस्सा लेकर, और अंत में मृत्यु के किनारे पर टूटकर, गुमनाम मृत्यु के समुदाय में विलीन क्यों हो जाते हैं? अस्तित्व के रहस्य में अर्थ खोजना जीवन की अंतिम और आकर्षक चुनौती है।

दूसरी पारी

फिर से बच्चे बन जाएं

आजकल **किडल्टिंग** खूब प्रचलित हो रहा है यानी बुढ़ापे में बच्चा बनना। वरिष्ठ पत्रकार **क्षमा शर्मा** बता रही हैं इसके फायदे...

95 साल के हो चुके मशहूर उद्योगपति वारेन बफे अब भी छह साल के बच्चों जैसी अपनी दिनचर्या जीते हैं। हम बुजुर्ग भी जीवन के जो वर्ष बचे हैं, उन्हें फिर से जी लें। उनका आनंद मनाएं, क्योंकि जीवन भर जिम्मेदारियों के पीछे ही तो भागते रहे हैं।

किडल्टिंग, दो शब्दों से मिलकर बना है। किड यानी कि बच्चा और एडल्ट माने वयस्क। यह जीवनशैली आजकल वयस्कों में बहुत लोकप्रिय होती जा रही है। इस बात का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि जब बच्चे होते हैं, तो सब जल्दी से जल्दी बड़े बनना चाहते हैं। और अब बड़े बच्चे बनना चाहते हैं। अपने यहां कहा भी जाता है कि जब आप उम्रदराज हो जाते हैं, तो बच्चों जैसे हो जाते हैं। फिर से बच्चे बन जाएं, यह बड़ों का एक सुंदर सपना होता है। यही सपना देखा जा रहा है। न केवल देखा जा रहा है, बल्कि उसे भरपूर जीने की कोशिश की जा रही है। अतीत में लौटने की हर कोशिश खुशी-खुशी हो रही है।

इन दिनों किडल्टिंग में लोग उन खिलौनों को खरीद रहे हैं, उनसे खेल रहे हैं, जिनसे बच्चे खेलते हैं। लंबे समय तक कार्टून देख रहे हैं। वैसे ही कपड़े पहनना चाहते हैं। उन आदतों और शौक की तरफ वापस जा रहे हैं, जो बचपन में थीं। कहा जा रहा है कि यह बीते दिनों में वापस जाने और उन्हें फिर से जीने का एक तरीका है। किडल्टिंग से वयस्कों के तरह-तरह के तनाव दूर हो रहे हैं। तनाव से दूर हटकर वे आनंद की तरफ लौट रहे हैं। बचपन से दोबारा जुड़ रहे हैं। बहुत से लोग जो ऐसा करते हैं, उनका कहना है कि इस तरह वे आज की दुनिया में पड़ने वाले अनेक प्रकार के दबाव और चिंताओं से वैसे ही मुक्त हो रहे हैं, जैसे बच्चे होते हैं।

अतीत में लौटने और बच्चा बन जाने की चाह सिर्फ पश्चिमी देशों में ही नहीं, अपने यहां भी दिखाई

दे रही है। अपने समाज में जिस तरह से बुजुर्ग विवाह की पच्चीसवीं, पचासवीं वर्षगांठ धूमधाम से मना रहे हैं, इन पार्टियों का आयोजन वैसे ही हो रहा है, जैसे कि तब हुआ होगा। बुजुर्गों के डेस्टिनेशन वेडिंग भी किए जा रहे हैं। इनमें भाग लेने वाले कई बुजुर्गों ने कहा कि वे इन आयोजनों में, वह सब कुछ करना चाहते हैं, जो उस समय नहीं कर पाए। वे फिर से हनीमून पर जा रहे हैं। बहुत से लोग दुनिया घूम रहे हैं। क्लबों में जा रहे हैं। अपनी पसंद के खेलों की टीमें बनाई जा रही हैं। उनके बाकायदा मैच हो रहे हैं। नाच-गा रहे हैं। बहुत से अपने जन्मदिन किशोरावस्था की तरह मना रहे हैं। पुराने दोस्तों को ढूंढकर आमंत्रण भेजे जा रहे हैं। बुजुर्गों में बच्चों की तरह ही रंग-बिरंगे कपड़ों का चलन बढ़ रहा है। यह किडल्टिंग का ही एक उदाहरण है।

इसका एक कारण यह भी है कि जीवन भर जिन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए दौड़ते रहे, अब वे लगभग पूरी हो चुकी हैं। इसलिए जीवन के जो वर्ष बचे हैं, उन्हें फिर से जी लिया जाए। आनंद मना लिया जाए। बच्चा बन जाने का सुख फिर से प्राप्त किया जाए। जो तब नहीं कर पाए, वह अब कर लें।

*जिंदगी की **दूसरी पारी** बहुत महत्वपूर्ण होती है। हर शुक्रवार इस पर आपको नया पढ़ने को मिलेगा। आप अपने विचार, अनुभव या समस्याएं **edit@amarujala.com** पर भेज सकते हैं, विशेषज्ञों की मदद से हम कोशिश करेंगे कि संवाद का पुल बन सके।*

जब छह साल के बच्चे बन जाते हैं वारेन बफे

हाल ही में 95 वर्षीय मशहूर उद्योगपति वारेन बफे ने कहा कि वह अपने खाने में कैलोरी काउंट नहीं करते हैं। वह वैसे ही खाते हैं, जैसे कि छह साल के बच्चे खाते हैं। वह मानते हैं कि छह साल में बच्चे कैलोरी काउंट के बोझ से मुक्त होते हैं। उन्हें आइसक्रीम और शीतल पेय बहुत पसंद हैं। बाजार में मिलने वाले हर तरह के हेल्थ पेयों और खाद्य पदार्थों से दूर रहते हैं। उनका कहना है कि स्वस्थ रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि छह साल के बच्चे की तरह जो मन हो, वह खाओ। वारेन ने एक बार एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि मैंने सही आंकड़ों पर गौर किया है। इनसे पता चला कि छह साल के बच्चों में मृत्यु दर सबसे कम है। इसीलिए मैं वही करता हूं, जो इस उम्र के बच्चे करते हैं। बफे का कहना है कि बढ़ती उम्र के साथ लोग अपने अंदर के बच्चे को मार देते हैं, लेकिन हमारे अंदर के बच्चे को हमेशा जीवित रहना चाहिए। वह बच्चों की तरह ही लंबी नींद लेते हैं। रात के आठ बजते ही सोने चले जाते हैं। उनका कहना है कि यदि दिल और दिमाग को मजबूती देनी है, तो लंबी नींद आवश्यक है। दुनिया के डॉक्टर भी यह मानते हैं। बफे की जीवनशैली किडल्टिंग का सबसे अच्छा उदाहरण है। वह अरबपति हैं और आज भी बहुत काम करते हैं। उम्र ने उनकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं की है।

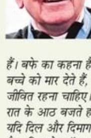

वरिष्ठ नागरिकों के काम के संगठन

अकेलेपन का सहारा

डिग्निटी फाउंडेशन बुजुर्गों को मनोवैज्ञानिक-सामाजिक चुनौतियों, 'अकेलेपन और असुरक्षाओं' से निपटने में मदद करता है। इसका मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान और सुरक्षा के साथ जीवन जीने में सक्षम बनाना तथा पूर्ण और आनंदपूर्ण तरीके से जीवन का आनंद लेने में सक्षम बनाना है। फाउंडेशन की आधिकारिक वेबसाइट www.dignityfoundation.com पर जाएं या आप सीधे सहायता और जानकारी के लिए उनकी सामान्य हेल्पलाइन 1800 267 8780 पर संपर्क कर इसका लाभ ले सकते हैं।

बुजुर्गों के मुद्दे उठाने वाला संगठन

ऑल इंडिया सीनियर सिटिजन्स कॉन्फेडरेशन देश के 25 से अधिक राज्यों के विभिन्न वरिष्ठ नागरिक संगठनों की मदद से बुजुर्गों के मुद्दों को सरकार और समाज के सामने रखता है। इसका उद्देश्य बुजुर्गों को स्वतंत्र, सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन प्रदान करना है। इसकी आधिकारिक वेबसाइट : www.aisccon.org पर उपलब्ध जानकारियों के आधार पर आप लाभ ले सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

दैनिक जागरण

विनम्रता का भाव व्यक्तित्व की आभा बढ़ाता है

आरोप उछालने की राजनीति

राहुल गांधी एक बार फिर वोट चोरी के आरोप के साथ सामने आए। इस बार उन्होंने कर्नाटक के अलंद से वोट काटे जाने का आरोप लगाया और अपनी ओर से कुछ कथित प्रमाण भी पेश किए। उनकी मानें तो यहां से कांग्रेस के 6018 वोटरों के वोट काटे गए। उन्होंने यह भी समझाया कि कर्नाटक के बाहर के लोगों ने मोबाइल फोन के जरिये कांग्रेसी वोटरों के नाम हटा दिए। उन्होंने अपने जिन आरोपों को सौ प्रतिशत पुख्ता बताया, उन्हें चुनाव आयोग ने निराधार करार देते हुए कहा कि इस तरह मोबाइल से वोट नहीं हटाए जा सकते। आयोग ने यह तो माना कि अलंद में कुछ लोगों के वोट हटाने की कोशिश हुई थी, पर यह भी साफ किया कि इसके खिलाफ एक रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी और इस मामले की जांच अभी जारी है। स्पष्ट है जब तक यह जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक राहुल के आरोपों को सच मान लेने का कोई कारण नहीं। निःसंदेह इस नतीजे पर भी नहीं पहुंचा जा सकता कि यदि कहीं किसी के नाम वोटर लिस्ट से अनुचित तरीके से हटा या जोड़ दिए गए तो ऐसा मुख्य चुनाव आयुक्त के इशारे पर किया गया।

देश में शायद ही कोई ऐसा चुनाव क्षेत्र हो, जहां मतदाता सूची में किसी तरह की गड़बड़ी न होती हो, लेकिन कम से कम राहुल को इतनी जानकारी होनी चाहिए कि इसके लिए स्थानीय नेताओं के साथ चुनाव कर्मचारी जिम्मेदार होते हैं, जो राज्य सरकारों के तहत काम करते हैं। राहुल गांधी कुछ समय पहले भी वोट चोरी के ऐसे ही एक और मामले को सामने लाए थे। उसे उन्होंने एटम बम की संज्ञा दी थी। उनका दावा है कि वे वोट चोरी का ऐसा मामला रखेंगे, जो हाइड्रोजन बम सरीखा होगा और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अपना मुंह नहीं दिखा पाएंगे। साफ है वे यह सिद्ध करने की कोशिश में हैं कि भाजपा छल-कपट से चुनाव जीत रही है। वे यह समझाने की जल्दबाजी में भी हैं कि इस छल-कपट में चुनाव आयोग भी भाजपा का साथ दे रहा है। अच्छा हो कि वे यह समझें कि कोई सनसनीखेज बात कहने मात्र से वह गंभीर आरोप की शक्ल नहीं ले लेती। वोट चोरी को तूल दे रहे राहुल को ऐसी किसी सीट का उदाहरण देना चाहिए था, जहां भाजपा विधायक जीता होता। वे जिस अलंद सीट का हवाला दे रहे हैं, वहां तो 2023 में कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी। वह वोट चोरी के मामले को उछालकर सुर्खियां भले बटोर ले रहे हों, पर उनके इस दावे में दम नहीं दिखता कि वे लोकतंत्र बचाने का काम कर रहे हैं। यदि उन्हें सच में लोकतंत्र की परवाह है तो वे वोट चोरी के अपने कथित प्रमाणों के साथ अदालत क्यों नहीं जाते? वे नेता विपक्ष हैं। उन्हें सनसनी और भ्रम फैलाने वाली नहीं, बल्कि परिपक्व और जिम्मेदार राजनीति का परिचय देना चाहिए।

सड़कों का सर्वे

पंजाब के सभी जिलों में सड़कों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। शायद ही कोई जिला ऐसा हो, जहां सड़कें बदहाल न हों। वर्षा ने पहले से ही खस्ताहाल सड़कों की स्थिति और भयावह कर दी है। कई शहरों की स्थिति तो यह है कि पता ही नहीं चल रहा कि सड़कों पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। इन सड़कों पर आरामदायक सफर तो दूर की बात है, सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचना भी अत्यंत कठिन है। खराब सड़कों के कारण प्रदेश भर में हादसे हो रहे हैं और लोगों की जान भी जा रही है। ऐसे में यह राहत की बात है कि लुधियाना, जालंधर, अमृतसर और मोहाली में सड़कों का सर्वे होने जा रहा है। पंजाब रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक रिसर्च सेंटर को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, ताकि सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को लेकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा सके। इस सर्वे में यह भी देखा जाएगा कि सबसे व्यस्त समय में सड़क से कितने वाहन गुजरते हैं। इसके बाद सड़क को उसी के अनुरूप डिजाइन किया जाएगा। सरकार का यह दावा है कि इससे लोगों को सुरक्षित और सुविधाजनक यातायात की सुविधा मिलेगी। निस्संदेह सड़कों की हालत न सिर्फ सुधारने की आवश्यकता है, अपितु इनका निर्माण आधुनिक तकनीक और तरीके से किया जाना चाहिए, ताकि सड़कें लंबे समय तक चलें और लोगों को खराब सड़क से होने वाली परेशानियों से मुक्ति मिल सके।

> सड़कों की हालत न सिर्फ सुधारने की आवश्यकता है, अपितु निर्माण भी आधुनिक तकनीक से होना चाहिए, ताकि लोगों की यात्रा सुखद हो सके

तकनीक बनी शासन की भाषा

अश्विनी वैष्णव

तकनीक को अपनाकर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने वह कर दिखाया, जो असंभव सा लगता था

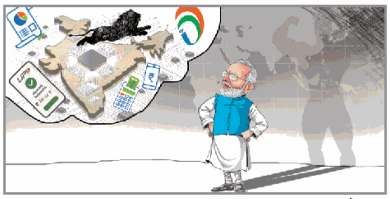

अवधेश राजपूत

प्रधानमंत्री मोदी ने तकनीक को भारत का सबसे बड़ा समान अवसर देने वाला साधन बना दिया है। मुंबई का एक रेहड़ी-पटरी वाला भी वही यूपीआइ पेमेंट सिस्टम इस्तेमाल करता है और बड़ी कंपनी का अधिकारी भी। यह बदलाव प्रधानमंत्री के मूल सोच अंत्योदय को दर्शाता है यानी कतार में खड़े सबसे आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना। हर डिजिटल पहल का मकसद है तकनीक को सबके लिए समान रूप से उपलब्ध कराना। गुजरात में शुरू हुए ये प्रयोग ही भारत की डिजिटल क्रांति की नींव बने। मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी जी ने तकनीक और नवाचार के जरिये गुजरात को बदला। 2003 में शुरू की गई ज्योतिग्राम योजना में फीडर सेपरेशन तकनीक से ग्रामीण उद्योगों को लगातार बिजली मिली। इससे महिलाएं रात में पढ़ाई कर सकीं और छोटे व्यवसाय फले-फूले, जिससे गांव से शहर की ओर पलायन घटा। इस योजना पर किए गए 1,115 करोड़ रुपये के निवेश की भरपाई सिर्फ ढाई साल में हो गई। 2012 में उन्होंने नर्मदा नहर पर सोलर पैनल लगाने का निर्णय लिया। इस परियोजना से हर साल 1.6 करोड़ यूनिट बिजली बनी, जो लगभग 16,000 घरों के लिए काफी थी। इससे नहर के पानी का वाष्पीकरण कम हुआ और पानी की उपलब्धता बढ़ी। इस नवाचार को अमेरिका और स्पेन द्वारा अपनाया जाना इसकी प्रभावशीलता को और मजबूत करता है। ई-धरा प्रणाली से जमीन के कागजात डिजिटल हुए। स्वागत पहल से नागरिक वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा मुख्यमंत्री से सीधे जुड़ सके। आनलाइन टेंडरिंग से भ्रष्टाचार पर रोक लगी।

2014 में मोदी जी ने गुजरात का अनुभव और सीख दिल्ली तक पहुंचाया, लेकिन पैमाना कहीं बड़ा था। उनके नेतृत्व में इंडिया स्टैक बना, जो दुनिया का सबसे समावेशी डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर है। इसकी बुनियाद जैम ट्रिनिटी (जन धन, आधार, मोबाइल) पर रखी गई। जन धन खातों ने 53 करोड़ से अधिक लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा। इससे उन्हें सुरक्षित बचत करने, सीधे सरकारी लाभ पाने और आसानी से कर्ज तक पहुंचने का अवसर मिला। आधार ने नागरिकों को डिजिटल पहचान दी। अब तक 142 करोड़ से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं। इससे सरकारी सेवाओं तक पहुंचना आसान हो गया। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ने बिचौलियों को हटा दिया और गड़बड़ी कम की। अब तक डीबीटी से 4.3 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बचत हुई है। यही पैसा स्कूल, अस्पताल और अन्य बुनियादी ढांचे बनाने में लगाया जा रहा है। पहले ग्राहक की पहचान (केवाईसी) की प्रक्रिया कठिन और भाग-दौड़ भरी थी। आधार-आधारित ई-केवाईसी से छोटे से छोटे लेन-देन भी आर्थिक रूप से संभव हो गए हैं। यूपीआइ ने भारत के भुगतान करने का तरीका बदल दिया। सिर्फ अगस्त में ही 20 अरब से अधिक लेन-देन हुए, जिनकी कुल राशि 24.85 लाख करोड़ रुपये रही। सिंगापुर से लेकर फ्रांस तक कई देश यूपीआइ से जुड़े हैं। जी-20 ने डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को समावेशी विकास के लिए जरूरी माना है। जापान ने इसके लिए पेटेंट भी दिया है। जो शुरुआत में भारत का समाधान था, वही अब विश्व के लिए डिजिटल लोकतंत्र का माडल बन गया। आज भारत दुनिया के कुल रियल-टाइम डिजिटल पेमेंट्स का आधा हिस्सा अकेले संभालता है। पीएम मोदी के सोच ने जैम ट्रिनिटी और यूपीआइ ढांचे को अंतिम रूप दिया। आज यूपीआइ, वैश्विक स्तर पर वीजा से भी अधिक लेन-देन करता है। एक मोबाइल फोन अब बैंक, पेमेंट गेटवे और सर्विस सेंटर सब कुछ बन गया है।

'प्रगति' ने शासन में जवाबदेही लाने का काम किया। जब अधिकारियों को पता होता है कि प्रधानमंत्री लाइव वीडियो में उनका काम देखेंगे, तो जवाबदेही अपने आप बढ़ जाती है। तकनीक ने खेती और स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह बदल दिया है। किसानों को अब मौसम की जानकारी और मिट्टी की सेहत का डाटा सीधे मोबाइल पर मिल जाता है। डिजीलाकर में 57 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ताओं के 967 करोड़ दस्तावेज डिजिटल रूप से सुरक्षित रखे गए हैं। आधार आथेंटिकेशन से आयकर रिटर्न भरना भी बेहद आसान हो गया है। मंगल तक पहली कोशिश में पहुंचना और वह भी इतने कम खर्चे में जितना एक हालीवुड फिल्म पर भी नहीं लगता। चंद्रयान-3 ने भारत को चांद पर साफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बनाया। गगनयान मिशन भारत को चौथा ऐसा देश बनाएगा जो अपनी स्वदेशी तकनीक से इंसानों को अंतरिक्ष में भेजेगा। जब कोविड-19 आया तब कोविन प्लेटफार्म रिकार्ड समय में बनाया गया। यह दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का डिजिटल समाधान था।

प्रधानमंत्री की दृष्टि के तहत आज हमारी मजबूत इलेक्ट्रानिक्स उत्पादन क्षमता हमें उन्नत सेमीकंडक्टर मैन्यूफैक्चरिंग की ओर छलांग लगाने में मदद कर रही है। दुनिया के 20 प्रतिशत से ज्यादा चिप डिजाइनर यहीं हैं। सेमीकंडक्टर उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स, गैस और विशेष सामग्री को भी समर्थन दिया जा रहा है। पीएम गति शक्ति पोर्टल जीआइएस तकनीक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करता है। इंडिया एआई मिशन के तहत 38,000 से अधिक जीपीयू उपलब्ध कराए गए हैं, वह भी वैश्विक लागत के एक-तिहाई दाम पर। इससे स्टार्टअप, शोधकर्ताओं और छात्रों को सिर्फ 67 रुपये प्रति घंटे की दर पर सिलिकान वैली जैसी सुविधाएं मिली हैं। तकनीक के प्रति पीएम मोदी की समझ भारत की अनूठी एआइ रेगुलेशन नीति में भी झलकती है।

केवड़िया में 182 मीटर की स्टैच्यू आफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। चिनाब पुल 359 मीटर ऊंचा है, जो कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है। आइजोल रेल लाइन कठिन पहाड़ी इलाकों से गुजरती है, जिसमें हिमालयन टनलिंग मेथड का प्रयोग किया गया है, जिसमें कई सुरंगें और पुल शामिल हैं। नया पंबन पुल सौ साल पुराने ढांचे की जगह आधुनिक इंजीनियरिंग से बनाया गया है। इंजीनियरिंग की ये अद्भुत कृतियां प्रधानमंत्री के उस सोच को दर्शाती हैं जिसमें तकनीक और दृढ़ संकल्प के सहारे भारत को जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी तकनीक को तो समझते ही हैं, लेकिन इंसानों को उससे भी बेहतर ढंग से समझते हैं। अंत्योदय का उनका सोच ही हर डिजिटल पहल को आगे बढ़ाती है। मोदी जी ने तकनीक को शासन की भाषा बना दिया है। उन्होंने साबित किया है कि जब नेता तकनीक को इंसानियत के साथ अपनाते हैं तो पूरा देश भविष्य की ओर बड़ी छलांग लगाता है।

(लेखक भारत सरकार के रेल,आइटी और सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं)

response@jagran.com

भटका हुआ स्मार्ट सिटी अभियान

अनुरोध ललित जैन

शहरों के आकर्षण को केवल ऊंची इमारतों और राजमार्गों से नहीं, बल्कि बुनियादी सुविधाओं की सुगमता से मापा जाना चाहिए

थोड़ी सी बारिश भी बढ़ा देती है बड़ी मुश्किलें। फाइल

वर्ष 2015 में मोदी सरकार ने स्मार्ट सिटी अभियान (एससीए) की शुरुआत की थी, जिसमें भारत के शहरी भविष्य को बदलने का वादा किया गया था। यह उद्देश्य प्रौद्योगिकी, नवाचार और बेहतर नियोजन का उपयोग करके सौ ऐसे शहर बनाना था, जो स्थिरता और दक्षता के माडल बन सकें। आज लगभग एक दशक बाद 1.5 लाख करोड़ रुपये निवेश के बावजूद भारतीय शहर एक अलग कहानी कहते हैं। जब गुरुग्राम, बेंगलुरु और मुंबई में भारी बारिश ने सड़कों को जलमग्न कर दिया, तो पानी भरे मार्गों पर फंसे यात्रियों को वह 'स्मार्टनेस' कहीं नजर नहीं आई, जिसका वादा किया गया था। भविष्य का खाका बनने वाला यह अभियान चुनिंदा सुंदरीकरण और भटकी हुई प्राथमिकताओं का प्रदर्शन बनकर रह गया है। विश्व बैंक के अनुसार भारत की शहरी आबादी 2050 तक करीब 95.1 करोड़ हो जाएगी। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे महानगरों का विस्तार जारी है, वहीं भुवनेश्वर, कोयंबटूर, इंदौर, जयपुर सरीखे शहर विकास के नए केंद्र बन रहे हैं। परिवर्तन की यह गति शहरी ढांचों पर भारी दबाव पैदा कर रही है। अनियोजित निर्माण से जल निकासी व्यवस्था चरमरा रही है, आवास की कमी लोगों को अनौपचारिक बस्तियों में धकेल रही है और परिवहन नेटवर्क बढ़ते यातायात के दबाव में ढह रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए स्मार्ट सिटी अभियान इन शहरों के पास नए ग्रीनफील्ड उपनगरीय शहरों के निर्माण पर ध्यान दे सकता था। बजाय इसके इसने मौजूदा शहरों के छोटे-छोटे हिस्सों के सुंदरीकरण, ओवरब्रिज नवीनीकरण, स्ट्रीट लाइटों के डिजिटलीकरण और नियंत्रण केंद्र स्थापित करने पर ही अधिक ध्यान केंद्रित किया। जल निकासी और आवास जैसी गहरी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। इसके दुष्परिणाम मानसून में देखने को मिले।

अटल मिशन फार रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफार्मेशन यानी अमृत भारत सरकार की एक और महत्वाकांक्षी योजना है। इसका उद्देश्य 500 शहरों में बुनियादी सुविधाओं का विकास करना है। इस अभियान में पेयजल, मल जल प्रणाली, वर्षा जल निकासी और हरे-भरे स्थान जैसी बुनियादी सुविधाओं को ठीक करने का वादा किया गया। इसके पहले चरण में पांच साल के लिए 50,000 करोड़ रुपये का बजट था। दूसरे चरण में लगभग 2.9 लाख करोड़ रुपये। इसका लक्ष्य शहरी भारत में पानी और मल जल प्रणाली को बेहतर करना था, लेकिन इस बरसात में देश ने देखा कि शहरों की कैसी दुर्दशा हुई। हमारे छोटे-बड़े शहर हर बारिश के दौरान टापुओं में तब्दील हो जाते हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित होता है।

लगता है कि भारत के शहरी विकास के कार्यक्रम अभी भी अलग-अलग खांचों में डिजाइन किए जाते हैं। नई दिल्ली में तैयार की गई योजनाएं शायद भारतीय शहरों की विविधता से भरी वास्तविकताओं से कटी हुई हैं। शहरों के बेहतर भविष्य के लिए इन खांचों को तोड़ना होगा और स्थानीय सरकारों को सशक्त बनाने के साथ दीर्घकालिक नियोजन को शहरी नीति का केंद्र बनाना होगा।

हालांकि सरकार ने गुजरात में धोलेरा, गिफ्ट सिटी, औरंगाबाद औद्योगिक शहर और ग्रेटर नोएडा जैसे कुछ ग्रीनफील्ड पहलों को आगे बढ़ाया है। 2024 में राष्ट्रीय औद्योगिक कारिडोर विकास कार्यक्रम (एनआइसीडीपी) के तहत एक दर्जन नए औद्योगिक केंद्रों को भी मंजूरी दी गई। अच्छा हो कि इनमें समावेशी शहरी विकास की व्यापक चुनौतियों को भी ध्यान में रखा जाए।

भारत के शहरी विकास को सुंदरीकरण से हटकर नए ग्रीनफील्ड निर्माण की ओर बढ़ना होगा। जिस तरह चीन ने शेंजेन को एक मछली पकड़ने वाले गांव से प्रौद्योगिकी और वित्त के वैश्विक केंद्र में बदल दिया, उसी तरह भारत को भी नए शहरी केंद्र बनाने की इच्छाशक्ति दिखानी होगी, जो लोगों और निवेश, दोनों को आकर्षित कर सकें। शहरों के आकर्षण को केवल ऊंची इमारतों और राजमार्गों से नहीं, बल्कि बुनियादी सुविधाओं की सुगमता से मापा जाना चाहिए। वित्तीय प्रोत्साहनों के माध्यम से ग्रीनफील्ड परियोजनाओं को धरातल पर लाया जा सकता है। भारत में संपत्ति कर अनुपालन बहुत कम है, जबकि स्टैंप शुल्क दुनिया में सबसे अधिक है, जो औपचारिक लेनदेन को हतोत्साहित करता है। नई स्मार्ट सिटीज को इन करों से बोझिल करने के बजाय सरकार पहले दशक के लिए कम संपत्ति कर, कम स्टैंप शुल्क और सुव्यवस्थित मंजूरी की पेशकश कर सकती है। सही प्रोत्साहन और नियोजन के साथ बड़े शहरों के पास उपनगरीय शहर नए अवसरों के केंद्रों के रूप में विकसित हो सकते हैं। हाल के वर्षों में भारत के चमकदार महानगरों को डुबोने वाली बाढ़ को केवल मौसम की घटना के रूप में नहीं, बल्कि शहरों के त्रुटिपूर्ण विकास की देन के रूप में देखा जाना चाहिए। भारत के शहरीकरण की रफ्तार अपेक्षा से तेज है। हमारे सामने विकल्प स्पष्ट है। या तो हम तनावग्रस्त महानगरों में ऊपरी सतह पर कार्य करें या फिर साहस के साथ नए, अच्छी तरह से वित्तपोषित और वास्तव में रहने योग्य शहरों का निर्माण करें।

(लेखक कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के उपाध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

शपथ

जब कभी दो पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद की स्थिति बनती है और यह साबित नहीं हो पाता कि कौन सही और कौन गलत है तो फिर 'शपथ' ली जाती है, जिसे कसम और सौगंध भी कहा जाता है। शपथ लेने के कई तरीके हैं। पहला तो दोनों पक्षों से कहा जाता है कि वे अपने सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति का नाम लेकर शपथ लें। सरकारी स्तर पर जब कोई पद प्राप्त होता है, तो पदासीन होने वाला शख्स संविधान की शपथ लेता है। इसमें मंत्री, सांसद, विधायक और अधिकारीगण भी शामिल हैं।

सनातन संस्कृति में शपथ का बहुत महत्व है। माना जाता है कि झूठी शपथ लेने वाले का अनिष्ट होता है। इसलिए शपथ तभी लेनी चाहिए, जब अंदर से यह लगे कि जो सही है, वही कहा जा रहा है। सत्य शपथ में बड़ी शक्ति बताई जाती है। जबकि झूठी शपथ साम्राज्यों से लेकर कुल के पतन का कारण भी बन सकती है।

स्मरण रहे कि महाभारत युद्ध तो पांडवों की पत्नी द्रौपदी की शपथ का परिणाम रहा। युधिष्ठिर द्वारा द्रौपदी को जुए में हारने के बाद जब दुर्योधन के भाई दुशासन ने द्रौपदी के बाल खींचते हुए भरी सभा में निर्वस्त्र करना चाहा तो उन्होंने शपथ ली कि जब तक दुर्योधन का विनाश नहीं हो जाएगा, तब तक वह बाल नहीं बांधेंगी। द्रौपदी की शपथ को पांडवों ने सच साबित किया। इसके बाद ही द्रौपदी ने बाल बांधे। इसी तरह की शपथ आचार्य चाणक्य ने भी ली थी। नंद वंश के राजा घनानंद ने चाणक्य का अपमान किया। अपमानित होने पर चाणक्य ने अपनी शिखा खोल दी और तय किया कि वह नंद वंश के विनाश के बाद ही पुनः शिखा बांधेंगे। अपनी शपथ को पूरा करने के लिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का सहयोग लिया। इसलिए शपथ बहुत सोच-समझ कर लेनी चाहिए। झूठी शपथ से पुण्य नष्ट होता है।

सलिल पांडेय

इंटरनेट ट्रेंड से रहें सावधान

सुनीता मिश्रा

> लोगों को यह बात ध्यान रखनी होगी कि इंटरनेट पर जो चीज एक बार चली गई वह कभी खत्म नहीं होती

इन दिनों से इंटरनेट मीडिया पर गूगल का जेमिनी नैनो बनाना एआइ फीचर युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हो रहा है। वे अपनी तस्वीर को इस फीचर का इस्तेमाल करके थ्रीडी माडल, रेट्रो साड़ी लुक एवं एनिमेटेड कैरेक्टर्स में बदल रहे हैं और इंटरनेट मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। हालांकि जैसे-जैसे लाखों लोग विभिन्न एआइ प्लेटफार्म पर अपनी निजी तस्वीरें अपलोड करते हैं, गोपनीयता, डाटा सुरक्षा और हमारी व्यक्तिगत जानकारी के संभावित दुरुपयोग को लेकर गंभीर सवाल उठते हैं। इसको लेकर गूगल ने स्पष्ट किया है कि जेमिनी पर अपलोड की गई फोटो सुरक्षित है और डाटा बिना अनुमति के इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि लोकेशन लीक होने का असली खतरा फोटो से नहीं, बल्कि मेटाडाटा से होता है। यानी जब आप किसी मोबाइल या कैमरे से फोटो क्लिक करते हैं, तो उसके साथ कई जानकारियां सेव हो जाती हैं जैसे किस डिवाइस से फोटो ली गई है, किस दिन और समय फोटो क्लिक किया गया है। इसमें सबसे अहम लोकेशन होती है।

इससे पहले इंटरनेट पर घिब्ली आर्ट ट्रेंड में आया था। दरअसल ये ट्रेंड्स मार्केटिंग रणनीति के तहत बनाए जाते हैं, जिससे विदेश में बैठे बहुत सारे सर्वर हमारा डाटा चुरा सकें। जैसे ही कोई व्यक्ति अपनी तस्वीर एआइ टूल में कन्वर्ट करता है, वह विदेशी सर्वर में हमेशा के लिए सेव हो जाता है, जिसका दुरुपयोग कभी भी किया जा सकता है। इसी तरह और भी आर्ट टूल आपकी फोटो गैलरी का एक्सेस ले लेते हैं, जिससे निजी तस्वीरें, वीडियो की एक कापी उनके सर्वर में चली जाती है, जिससे आसानी से डीपफेक फोटो-वीडियो बनाए जा सकते हैं। ट्रेंडिंग में बने रहने के लिए लोग एआइ टूल्स को खुद अपनी फोटो देते हैं, जिसमें उनकी कई व्यक्तिगत जानकारियां होती हैं। यहीं से उनके डाटा और फोटो का इस्तेमाल कुछ साइबर ठग करते हैं और व्यक्तिगत जानकारी को अपने पास स्टोर कर लेते हैं। ऐसे में उनके साथ किसी भी तरह की ठगी हो सकती है, जिसमें उनके सारे पैसे जा सकते हैं और व्यक्तिगत जानकारियां भी लीक हो सकती हैं।

आज बीमारी का पता लगाना हो या फिर फसल से संबंधित जानकारी लेनी हो, एआइ ने इसे काफी आसान बना दिया है। कुछ ऐसे क्षेत्रों में जिनमें मनुष्य के काम करने में जोखिम हो सकता है, उनमें एआइ का इस्तेमाल वरदान सिद्ध हुआ है, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां इसके अनेक लाभ हैं, वहीं इसके कुछ नकारात्मक पक्ष भी हैं। ठग फोटो का इस्तेमाल आपको ब्लैकमेल करने के लिए भी कर सकते हैं। बिना सोचे समझे एआइ का उपयोग करने से बचें। यह बात ध्यान रखें कि इंटरनेट पर जो चीज एक बार चली गई वह कभी खत्म नहीं होती।

(लेखिका सामाजिक मामलों की जानकार हैं)

अदालतों पर बोझ बढ़ाते झूठे मामले

'कानूनों का दुरुपयोग' शीर्षक से प्रकाशित अग्रलेख में दुष्कर्म और दहेज प्रताड़ना के बढ़ते झूठे मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए इसे रोकने के लिए कारगर उपाय अपनाए जाने का आह्वान किया गया है। इनसे संबंधित कानूनों का दुरुपयोग लोगों को ब्लैकमेल करने, डराने-धमकाने, पैसा ऐंठने में बड़े पैमाने पर हो रहा है। यह एक सामान्य प्रचलन की तरह बन गया है। ये कानून महिला सशक्तीकरण और उन पर होने वाले जुल्म के त्वरित न्याय के लिए अस्तित्व में आए थे। झूठे आरोपों से घिरने के कारण संबंधित पीड़ित पक्ष की सामाजिक प्रतिष्ठा तो प्रभावित और धूमिल होती ही है, लेकिन इसके साथ ही वे मानसिक और आर्थिक रूप से भी बुरी तरह प्रताड़ित होते हैं। ऐसी विकट परिस्थिति के परिणामस्वरूप वे तनाव और दबाव में आकर गलत कदम तक उठाने को मजबूर हो जाते हैं। समाज-कानून के समक्ष यह समस्या एक गंभीर चुनौती बनकर उभर रही है। ऐसे कानूनों में अनिवार्य रूप से ऐसे संशोधन किए जाने चाहिए, जिससे कोई भी इनका गलत उपयोग नहीं कर सके। लगातार बढ़ते झूठे मामलों के कारण सही मामलों को भी शक की नजर से देखा जाने लगा है। ऐसा होना कानून के वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति में बाधक बन रहा है। अतः न्यायालय, शासन-प्रशासन स्वतःसंज्ञान लेकर झूठे मामलों के निराकरण में विवेक और तत्परता दिखाएं। दायर मामले के झूठा साबित होने पर सख्त प्रविधानों के तहत उचित कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि लोग झूठे मामले दायर करने से पहले सोचने को विवश हों। झूठे मामलों की संख्या बढ़ने से न्यायालय में सही

मेलबाक्स

और सच्चे मामलों की सुनवाई में अनावश्यक विलंब हो जाता है। उम्मीद है कि न्यायपालिका और कानून के संरक्षक इस दिशा में सार्थक प्रयत्न करेंगे, ताकि न्याय का बोलबाला और अन्याय का प्रतिकार हो।

sonimohit895@gmail.com

त्योहारों की रौनक

केंद्र सरकार द्वारा हाल में कुछ उत्पादों की जीएसटी दरों में कटौती और कुछ पर से टैक्स हटाने का निर्णय 22 सितंबर से लागू होने जा रहा है। जीएसटी 2.0 के आगमन से रोजमर्रा की उपयोग में आने वाली वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ होगा। 22 सितंबर से नवरात्र भी प्रारंभ हो रहे हैं, और इस दौरान लोग वाहनों की खरीदारी को शुभ मानते हैं। सरकार के जीएसटी स्लैब में कमी से वाहनों की कीमतें घटेंगी, जिससे इस बार वाहनों की बिक्री में वृद्धि की उम्मीद है। त्योहारों का सीजन शुरू होने के साथ वस्तुओं की कीमतों में कमी के चलते लोगों से अच्छी खरीदारी की उम्मीद की जा रही है। इलेक्ट्रानिक उपकरण और एसी जैसे महंगे उत्पादों की घटती कीमतों के कारण भी बाजार में गर्मी बनी रहने की संभावना है। जीएसटी 2.0 न केवल लोगों को अधिक खरीदारी के लिए प्रेरित करेगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगा। जो धन जनता टैक्स में लगा रही थी, वह अब उनके पास रहेगा, जिससे वे त्योहारों का भरपूर आनंद ले सकेंगे।

अभिलाषा गुप्ता, मोहाली

किसानों की समृद्धि

''विकास को गति देने का मंत्र'' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में लेखक विकास सारस्वत ने विनिर्माण क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि युवाओं को मेज-कुर्सी के मोह को त्यागकर उद्यमशीलता की ओर अग्रसर होना होगा, तभी देश में विकास की गति बढ़ेगी। विनिर्माण उद्योग कृषि उत्पादों पर निर्भर है, और यह किसानों तथा उनके श्रमिकों के प्रयासों पर आधारित है। विनिर्माण उद्योग में कृषि उत्पादों को तकनीकी मशीनों के माध्यम से संसाधित कर अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं। यदि देश में विकास की गति को बढ़ाना है, तो यह किसानों की समृद्धि और खुशहाली, विशेषकर छोटे और मझोले किसानों तथा मजदूरों के माध्यम से ही संभव है। हाल ही में पंजाब, राजस्थान, बिहार और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ की विकराल स्थिति ने किसानों की स्थिति को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। किसानों की स्थिति में सुधार लाने के लिए युद्धस्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है।

pawanujinwal123@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।
****

https://t.me/AllNewsPaperPaid

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

फिर बढ़ता प्रदूषण

पंजाब में पानी अभी ठीक से सूखा भी नहीं है, पर खेतों में फसल अवशेष या पराली जलाने की शुरुआत हो गई है। ऐसे में, वायु प्रदूषण का दौर इस बार समय से पहले ही शुरू हो गया है और उसे लेकर चिंता भी बहुत बढ़ गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को पराली जलाने के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए कहा था कि कुछ जिम्मेदार लोगों को जेल भेजने से सही संदेश जाएगा। हां, किसानों का बड़ा योगदान है, वे लोगों को भोजन उपलब्ध कराते हैं, पर इसका अर्थ यह नहीं कि पर्यावरण की रक्षा न की जा सके। भारत के प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई ने सरकार से पूछा है कि आप दोषी लोगों के लिए किसी दंड के प्रावधान के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? प्रधान न्यायाधीश ने यहां तक पूछा कि अगर पर्यावरण की रक्षा करने का आपका सचमुच इरादा है, तो फिर क्यों कतरा रहे हैं? सर्वोच्च न्यायालय में यह खास बात भी हुई है कि अगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नागरिक प्रदूषण मुक्त हवा के हकदार हैं, तो दूसरे शहरों के लोग क्यों नहीं? ये सवाल वाकई स्वागतयोग्य हैं और हमें पूरी गंभीरता से इनके जवाब खोजने चाहिए।

कयास लगाए जा रहे हैं कि जब प्रदूषण के लिए कुख्यात मौसम की शुरुआत में ही सर्वोच्च न्यायालय का रुख इतना कड़ा है, तो आगे बड़े कड़े कदमों की संभावना साफ दिखती है। कोई संदेह नहीं कि कड़े कदमों के बिना पराली जलाने की कुप्रथा समाप्त नहीं होगी। पराली से निपटने के और भी उपाय हैं, पर कुछ किसानों को पराली जलाना ज्यादा आसान लगता है। जाहिर है, ऐसे किसानों को न अपनी सेहत की चिंता है और न दूसरों के जीवन की। तमाम किसान जानते हैं, शीतकाल में एक समय ऐसा आता है, जब अनेक गांवों-शहरों में हवा जहर हो जाती है। इसके बावजूद अपने देश में किसानों को नाराज करने का जोखिम शायद ही कोई राजनीतिक पार्टी उठाएगी। किसानों के संगठन मजबूत हैं और कुछ दोषी किसानों को गिरफ्तार करने से मकसद पूरा होने की उम्मीद कम है। क्या समझाइश का रास्ता ही सबसे बेहतर रहेगा? क्या हमारे राजनीतिक दलों ने किसानों को समझाने के लिए गंभीरता से प्रयास किए हैं? उदार कदमों को अगर पूरी ईमानदारी से आगे बढ़ाया जाए, तो कड़े कदमों की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां किसानों को समझाने का काम सरकारी महकमे की तुलना में राजनीतिक दलों का ज्यादा है। वैसे, देश में जब नकारात्मकता की राजनीति हावी हो, तब किसानों को भड़काना छोड़कर, समझाने का प्रयास कितने राजनेता करना चाहेंगे? खैर, अच्छी बात है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए चल रहे उपायों की समीक्षा की है। केंद्रीय मंत्री की बैठक में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सरकार और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। मतलब, इस बार सुधार की उम्मीद हम कर सकते हैं।

पराली जलाने वाले कुछ दोषियों को गिरफ्तार करने से मकसद पूरा होने की उम्मीद कम है। सबसे बेहतर है समझाइश का रास्ता, यहां नेताओं को पहल करनी चाहिए।

प्रदूषण निवारण के लिए भारतीयों को अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सोचना होगा। हाल ही में दो शोध पत्र सामने आए हैं। एक शोध से पता चलता है, प्रदूषण चुपचाप भारत में कैंसर की एक नई लहर को बढ़ावा दे रहा है। वायु प्रदूषण के कारण फेफड़ों के कैंसर के रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है। भारत में हर साल 14 लाख से ज्यादा कैंसर के नए मामले दर्ज किए जाते हैं। एक अन्य ताजा अध्ययन में पाया गया है कि वायु प्रदूषण के चलते लाल किले की दीवारों पर काली पपड़ी जम गई है। संदेश साफ है, अगर हमने वर्तमान में प्रदूषण को न रोका, तो हमारा भविष्य ही नहीं, बल्कि अतीत भी बदरंग हो जाएगा।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले

19 सितंबर, 1950

विदेश नीति का समर्थन

कांग्रेस कार्य समिति ने वैदेशिक नीति के बारे में एक प्रस्ताव स्वीकार किया है, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस के खुले अधिवेशन के सामने पेश किया जायेगा। जहां तक भारत की वैदेशिक नीति का संबंध है, कांग्रेसजनों में कोई खास मतभेद नहीं है, अतः कांग्रेस द्वारा उसकी पुष्टि होने में कोई कठिनाई नहीं होगी। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव में कहा गया है कि कांग्रेस भारत सरकार द्वारा अमल में लाई जा रही नीति का समर्थन करती है। इस प्रस्ताव से नेहरू जी की मांग का एक हिस्सा पूरा हो जाता है कि कांग्रेस को उनकी विदेश नीति का समर्थन करना चाहिए। प्रस्ताव में कांग्रेस ने अपनी यह हार्दिक आशा प्रकट की है कि दुनिया के बड़े राष्ट्र भय अथवा आवेगवश शांति के ध्येय को खतरे में नहीं डालेंगे और ऐसी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन नहीं देंगे, जो कटुता और घृणा को बढ़ाने वाली हों। विश्व के इस संकट काल में कांग्रेस चाहती है कि प्रत्येक देश सहिष्णुता और संयम से काम ले, भय को हटाये और शांति की खोज में निरन्तर प्रयत्नशील रहे।

भारतीय जनता परंपरा से शांतिप्रिय है और इसलिए दुनिया के देशों से वह शांति के पक्ष में ही अपील कर सकती है। कांग्रेस ने इस विषय में भारतीय जनमानस का सही प्रतिनिधित्व किया है। दुनिया में आज जो बड़े राष्ट्र समझे जाते हैं, उसका मुख्य कारण यही है कि उन्होंने अपने भौतिक साधनों का बहुत विकास किया है। उन्होंने जो शक्ति हासिल की है, वह निर्माण और संहार दोनों ही कामों में लाई जा सकती है। उसका उपयोग संहार के लिए होगा, इसकी अधिक संभावना नजर आती है। भारत भौतिक उन्नति में इन देशों से पीछे हो सकता है। किन्तु उसे जो आध्यात्मिक पूंजी विरासत में मिली है, उसके बल पर वह संसार को विनाश की ओर जाने से रोकने का प्रयास कर सकता है।

आज के अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष की पृष्ठभूमि का यदि अध्ययन किया जाये, तो पता चलेगा कि दुनिया के बड़े राष्ट्रों में भय और संदेहों ने घर कर लिया है। रूस यह समझता है कि अमरीका उसे चारों ओर से घेर रहा है और उस पर हमले की तैयारियां कर रहा, तो अमरीका यह मान बैठा है कि रूस धीरे-धीरे चारों ओर अपने पांव फैला रहा है और सारी दुनिया पर छा जायेगा। इस भय और अविश्वास का अन्त होने पर ही मौजूदा अन्तर्राष्ट्रीय तनाव दूर हो सकता है।

चुनाव की साख को सवालों से बचाएं

राजकुमार सिंह | वरिष्ठ पत्रकार

यहां स्कैन करें

चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष हो, यह सुनिश्चित करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। यह काम पारदर्शिता से न सिर्फ किया जाना चाहिए, बल्कि वैसा होते हुए दिखना भी चाहिए।

शायद ही कोई मुख्य चुनाव आयुक्त कभी सभी राजनीतिक दलों-नेताओं का प्रिय रहा हो, लेकिन अगर बात उस पर 'वोट चोरों' को संरक्षण देने के आरोप तक पहुंच जाए, तो मामले की गंभीरता को समझने में विलंब नहीं किया जाना चाहिए। यहां दांव पर व्यक्ति नहीं, बल्कि एक सांविधानिक संस्था चुनाव आयोग की विश्वसनीयता लगी है, जिसकी एक अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा रही है।

बेशक, यह पहला मौका नहीं है, जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं, मगर पावर प्रेजेंटेशन के जरिये कथित साक्ष्यों के साथ लगाए जा रहे आरोपों को भी निराधार करार देकर चुनाव आयोग जिस तरह अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेना चाहता है, उससे उसकी साख का संकट गहरा रहा है। लगभग एक दशक तक ईवीएम पर संदेह के बाद पिछले एक साल से मतदान और मतगणना की निष्पक्षता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में सभी चुनावी पंडित कांग्रेस की जीत पर दांव लगा रहे थे, पर भाजपा को बहुमत मिला। राजस्थान व छत्तीसगढ़ के चुनावी मुकाबले ने भी सबको चौंकाया। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन 'इंडिया', सत्तारूढ़ राजग पर भारी पड़ा, तो हरियाणा में मुकाबला बराबरी पर छूटा, पर चंद महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में दोनों राज्यों में बाजी पलट गई।

भाजपा कहती रही है कि हार की हताशा में कांग्रेस पहले ईवीएम और अब चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ रही है, लेकिन संदेह और सवाल शायद इससे ज्यादा तथ्यात्मक ठोस जवाब की मांग करते हैं। मसलन, लोकसभा चुनाव में भी कुछ राज्यों में शाम पांच बजे के बाद अचानक मत प्रतिशत बहुत ज्यादा कैसे बढ़ गया? महाराष्ट्र में इस लोकसभा चुनाव से पहले साढ़े चार साल में जितने मतदाता बढ़े, उससे भी ज्यादा लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच छह महीने में कैसे बढ़ गए? यदि वैसा होने के कुछ अपरिहार्य या व्यावहारिक कारण रहे, तो वे चुनाव आयोग को तथ्यों के साथ सार्वजनिक करने चाहिए।

यही बात बिहार में एसआईआर से शुरू विवाद और अब राहुल गांधी द्वारा लगाए जा रहे 'वोट चोरी' के आरोपों पर लागू होती है। दो राय नहीं कि चुनाव प्रक्रिया से जुड़ा हर काम आयोग का विशेषाधिकार है, पर हर अधिकार के साथ कुछ दायित्व भी होते हैं। चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष हो, यह सुनिश्चित करना चुनाव आयोग की ही जिम्मेदारी और जवाबदेही है। यह काम पूरी पारदर्शिता से न सिर्फ किया जाना चाहिए, बल्कि वैसा होते हुए जन साधारण को दिखना भी चाहिए।

चुनाव आयोग क्यों बिहार में एसआईआर में आधार कार्ड स्वीकार करने और नाम काटे गए मतदाताओं के विवरण सार्वजनिक करने पर, सर्वोच्च न्यायालय की सख्ती तक टालमटोल करता रहा? एक सांविधानिक संस्था के रूप में चुनाव आयोग की अपनी साख के लिए जरूरी है कि वह संदेह से परे रहे। यह तभी संभव है, जब उसकी कार्यप्रणाली पारदर्शी हो तथा जनता के मन में उठने वाले सवालों का वह तथ्यों के साथ संतोषजनक जवाब देने की पहल स्वयं करे, मगर हो यह रहा है कि खुद पर लगने वाले हर आरोप को निराधार बताकर चुनाव आयोग अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेता है, और फिर सत्तारूढ़ दल की ओर से विपक्ष पर तीखा हमला बोला जाता है।

अगर बिहार में मृत बताकर नाम काटे गए कुछ मतदाता अपने जीवित होने के प्रमाणस्वरूप सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गए, तो यह एसआईआर की प्रक्रिया पर ही सवालिया निशान है। एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के रूप में भाजपा को इस पर चिंता जतानी चाहिए थी, तो आयोग को गलती स्वीकार करते हुए अपनी कार्यप्रणाली को चाक-चौबंद करने का वायदा न्यायालय और जनता से करना चाहिए था।

18 सितंबर को जब राहुल गांधी ने कर्नाटक के आलंद और महाराष्ट्र के राजुरा चुनाव क्षेत्र में क्रमशः वोट काटने और वोट जोड़ने के आरोप पावर प्रेजेंटेशन के जरिये कुछ गवाह पेश करके लगाए, तब भी आयोग और भाजपा की ओर से ऐसी ही प्रतिक्रिया आई। आयोग ने आरोपों को निराधार बता दिया, तो सत्तारूढ़ दल ने याद दिलाया कि अतीत में मुख्य चुनाव आयुक्त रहे मनोहर सिंह गिल को कांग्रेस ने केंद्र में मंत्री बनाया था, तो टी एन शेषन कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे। इससे क्या यही ध्वनि नहीं निकलती कि तब मुख्य चुनाव आयुक्त आपके थे, तो अब हमारे हैं?

अगर मुख्य चुनाव आयुक्त सत्तारूढ़ दल के प्रति ही निष्ठावान होते हैं, तब चुनाव आयोग के सांविधानिक संस्था होने और उसकी साख का क्या अर्थ रह जाएगा? अगस्त में राहुल गांधी ने कर्नाटक के महादेवपुरा चुनाव क्षेत्र के आंकड़े देकर चुनाव आयोग और भाजपा पर मिलीभगत के आरोप लगाए, तो सत्तारूढ़ दल ने रायबरेली और वायनाड समेत कुछ चुनाव क्षेत्रों में फर्जी वोटर होने के जवाबी आरोप लगाए। आयोग ने राहुल गांधी को एक सप्ताह में हलफनामा देने या माफी मांगने का अल्टीमेटम दे दिया, पर सत्ता पक्ष से कुछ नहीं कहा। ऐसा क्यों? वैसे अल्टीमेटम की अवधि बीत जाने के बावजूद चुनाव आयोग द्वारा राहुल गांधी के विरुद्ध कोई कार्रवाई न करना भी सवाल खड़े करता है।

उसी अंदाज में अब राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को अल्टीमेटम दे दिया है कि वह आलंद चुनाव क्षेत्र में वोट काटने के सुनियोजित खेल में इस्तेमाल किए गए कर्नाटक से बाहर के फोन और डिवाइस के आईपी एड्रेस आदि की जानकारी राज्य की सीआईडी को एक सप्ताह में दे। बकौल राहुल, इस बाबत सीआईडी एफआईआर दर्ज कर 18 महीने में आयोग को 18 पत्र लिख चुकी है, पर कोई सूचना नहीं दी गई। अब आयोग कह रहा है कि वोट काटने की वैसी कोशिश की गई थी, जिसमें उसने एफआईआर भी दर्ज की, पर 2023 के मामले में अब स्वीकारोक्ति सवाल खड़े करती है।

अब बिना प्रामाणिक जानकारी के कह पाना संभव नहीं कि कौन सच बोल रहा है, लेकिन आज दलगत राजनीतिक हितों से ज्यादा दांव पर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रतिष्ठित चुनाव आयोग की साख लगी है। सरकारें आती-जाती रही हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त भी। यह सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन एक बार अगर चुनाव आयोग की साख चली गई, तो उसकी बहाली आसान नहीं होगी। यह बात मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष, को भी समय रहते समझ लेनी चाहिए।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मधुमेह की उलझती पहेली को मिलकर सुलझाएं विशेषज्ञ

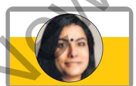

यहां स्कैन करें

रिद्मा कौल | हेल्थ एडिटर, एचटी

दुनिया भर में मधुमेह (डायबिटीज) के एक नए रूप की काफी चर्चा हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों (एलएमआईसी) के कम वजन वाले लाखों नौजवान इस डायबिटीज के शिकार हैं और इसे 'टाइप 5' डायबिटीज की औपचारिक मान्यता दी जानी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय मधुमेह महासंघ, यानी आईडीएफ ने इसी साल अप्रैल की विश्व मधुमेह कांग्रेस की 'वेल्लोर घोषणा' में इस नाम का प्रस्ताव पारित किया था और अब द *लैंसेट ग्लोबल हेल्थ* में इसे प्रकाशित किया गया है। इससे पहले तमिलनाडु के वेल्लोर में जनवरी में हुई एक बैठक में आम सहमति से इस नाम को स्वीकार किया गया था।

डायबिटीज की बीमारी कई तरह की होती है। सबसे चर्चित टाइप1 (स्व-प्रतिरक्षी, इंसुलिन-निर्भर) और टाइप2 (वजन-संबंधी) हैं। इनके अलावा, टाइप3 मधुमेह तब होता है, जब मस्तिष्क में न्यूरॉन्स इंसुलिन के प्रति प्रतिक्रिया नहीं करते, जबकि टाइप3सी में अग्न्याशय की इंसुलिन उत्पादन क्षमता प्रभावित होती है। इसी तरह, टाइप4 में बुजुर्गों, दुबले-पतले वयस्कों में आयु के कारण इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। *लैंसेट* के लेखकों का कहना है, 'हम मधुमेह पर काम करने वाले अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इस विशिष्ट बीमारी को 'टाइप5' के रूप में मान्यता देने का आह्वान करते हैं।' इन लेखकों का कहना है कि निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों में इस बीमारी से ग्रस्त लोगों की संख्या में काफी वृद्धि होने की आशंका है, क्योंकि ये देश कुपोषण व अति-पोषण की दोहरी मार झेल रहे हैं। *लैंसेट* के अनुसार, टाइप5 मधुमेह की पहचान 1955 में हुई थी, जो कम वजन वालों व बचपन में कुपोषित रहे लोगों में देखी जा रही है।

निम्न व मध्यम आय वाले देशों में टाइप5 मधुमेह के रोगियों की संख्या काफी बढ़ने की आशंका है। ये देश कुपोषण व अति-पोषण की दोहरी मार झेल रहे हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सन् 1985 में इसे 'कुपोषण-जनित मधुमेह' के रूप में वर्गीकृत किया था, मगर 1999 में इसे मधुमेह की सूची से हटा दिया गया, क्योंकि इस बात पर सहमति नहीं थी कि इस मधुमेह के लिए कुपोषण मुख्य वजह है। हालांकि, *लैंसेट* में प्रकाशित लेख में कहा गया है कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से दशकों के शोध के बाद अब पता चला है कि इन रोगियों में टाइप1 और टाइप2 से अलग लक्षण होते हैं। उदाहरण के लिए, टाइप5 मधुमेह वाले लोगों में पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनते, फिर भी उनका शरीर इंसुलिन को सामान्य रूप से प्रसंस्कृत करता रहता है। उन्हें कीटोएसिडोसिस (टाइप1 मधुमेह में रोग के अचानक शुरू होने) का अनुभव नहीं होता है और उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली अग्न्याशय पर हमला नहीं करती है। हालांकि, अनुमान है कि कम से कम 2.5 करोड़ लोग टाइप5 मधुमेह से ग्रस्त हैं। इसे लेकर अभी जागरूकता की कमी है और इस पर कम ही शोध हुआ है। ऐसे में, गलत उपचार और साक्ष्य आधारित उपचार दिशा-निर्देशों के अभाव से रोगियों को नुकसान पहुंच रहा है।

इन लेखकों के मुताबिक, 'डायबिटीज के इस रूप के अपर्याप्त साक्ष्य अलग-अलग तरह के समुदायों के लिए उपचार के मानदंडों व जोखिम संबंधी कारकों को परिभाषित करना चुनौतीपूर्ण बना देते हैं।' इसीलिए, आईडीएफ का लक्ष्य मानदंड विकसित कर इसके लक्षणों, इतिहास और उपचार पर अनुसंधान के लिए एक नए कार्य समूह का गठन करना है। लेखकों ने कहा है कि अब जो इसके प्रमाण सामने आ रहे हैं, वे इसके विशिष्ट प्रकार के मधुमेह होने की पुष्टि करते हैं। इस मधुमेह की विशेषता यह है कि इसमें अग्नाशयी इंसुलिन स्राव में भारी कमी हो जाती है। इसमें सामान्य यकृत और परिधीय इंसुलिन संवेदनशीलता, कीटोएसिडोसिस का अभाव देखने को मिलता है।

हालांकि, विशेषज्ञों का एक वर्ग टाइप5 को एक अलग श्रेणी के रूप में वर्गीकृत करने के पक्ष में नहीं है। मैक्स हेल्थकेयर के एंडोक्रिनोलॉजी एवं मधुमेह विभाग के अध्यक्ष और प्रमुख डॉ. अंबरीश मित्तल की मानें, तो 'इस समय हमारे पास जिस तरह के प्रमाण उपलब्ध हैं, उसे देखते हुए और टाइप3 व टाइप4 के ही अभी पूरी तरह से समझ में न आने के कारण, इसको एक अलग श्रेणी के रूप में वर्गीकृत करना जल्दबाजी होगी।

जो भी हो, स्वास्थ्य विशेषज्ञों का दायित्व बनता है कि वे जल्द इसका गहन अध्ययन करें और इस नई बला को टालने के लिए सक्षम मंचों को आवश्यक व उपयोगी सुझावों से अवगत कराएं।

मनसा वाचा कर्मणा

सुनना एक अच्छा काम

हम सब अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों से मिल चुके हैं, जो इतने चिड़चिड़े, अभिमानी और जटिल हैं कि कोई उनसे उलझना नहीं चाहता। मगर इस कोलाहल भरे समय ने इसे आम बना दिया है। विभाजकता के कारण अब सामान्य बातचीत भी उत्तेजक बहस में बदल जाती है, एक-दूसरे के प्रति खामोश शत्रुता पलने लगी है और लोगों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। यहां तक कि ऐसे लोगों से भी, जिनकी हमारी जिंदगी में निजी भूमिका है।

इसलिए यह जानना बहुत उपयोगी है कि अपनी आंतरिक शांति और संतुलन को कैसे बनाए रखा जाए? कुछ परिस्थितियां अपरिहार्य होती हैं। इनसे आप बच नहीं सकते। उस मुश्किल शख्स के दूर जाने तक आप बस प्रतीक्षा कर सकते हैं। हालांकि, इंतजार करने के बजाय व्यावहारिक मनोविज्ञान में कुशल बनना कहीं बेहतर विकल्प है। अध्यात्म और मनोविज्ञान के बीच की रेखा बहुत ठोस नहीं है। आंतरिक शांति मानसिक परिपक्वता और आध्यात्मिक विकास का प्रतीक है।

इसलिए किसी भी बातचीत में आप अपनी तरफ से जिम्मेदार बर्ताव करें। दुश्मनी आपके ही दिल में पैदा होती है। अगर आप अपनी प्रतिक्रिया से निपट सकते हैं और उसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं, तो इससे अधिक कारगर कोई और रास्ता नहीं। विलगाव हमेशा सबसे अच्छी प्रतिक्रिया है, क्योंकि अगर आप बिना कोई प्रतिक्रिया दिए बातचीत कर सके, तो मुश्किल इंसान के साथ संबंध बनाने में प्रगति कर पाएंगे।

इसके बाद, समस्या के खास कारणों को चिह्नित करें। क्या वह व्यक्ति चिपकू है, वर्चस्ववादी है, या प्रतिस्पर्द्धी है? हम इन शब्दों का प्रयोग प्रायः लापरवाही से करते हैं, लेकिन इनको जानना यह समझने में मददगार होता है कि वास्तव में हो क्या रहा है? चिपकने वाले लोग चाहते हैं कि उनका ध्यान रखा जाए। वे खुद को कमजोर महसूस करते हैं और मजबूत लोगों की ओर आकर्षित होते हैं। वहीं वर्चस्ववादी व्यक्ति के पास दूसरों को दोषी ठहराने का एक न एक कारण होता ही है। परनिंदा की उनकी क्षमता अनंत होती है और प्रतिस्पर्द्धी लोगों को बस जीतना होता है। वे हरेक मुठभेड़ को, चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों न हो, एक प्रतियोगिता की तरह देखते हैं। जब तक वे जीत नहीं जाते, हार नहीं मानते।

अहंकारी लोग चाहते हैं कि कोई उनकी बात सुने और उन्हें जज न करे। अगर आप बिना तनाव के ऐसा कर सकते हैं, तो कुछ देर के लिए उनकी बात सुनना एक अच्छा काम है।

मुश्किल लोग बस यही चाहते हैं कि कोई उनकी बात सुने और उन्हें 'जज' न करे। अगर आप बिना तनाव के ऐसा कर सकते हैं, तो कुछ देर के लिए उनकी बात सुनना एक अच्छा काम है। एक अच्छा श्रोता होने का मतलब है- बहस न करना, आलोचना न करना, अपनी राय न देना या बीच में न बोलना। अगर दूसरे व्यक्ति को आपमें सच्ची दिलचस्पी है, तो वे आपको सिर्फ सुनने के बजाय बात करने के लिए आमंत्रित करेंगे।

दीपक चोपड़ा

बराक ओबामा | पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति

हमारा लोकतंत्र अपने आप खड़ा नहीं हो गया है। यह हम सबके प्रयास का परिणाम है। हमें अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठकर उन बुनियादी मूल्यों के साथ खड़े रहना चाहिए, जिनके कारण दुनिया हमारे देश से ईर्ष्या करती है।

अनुलोम-विलोम
भारत-पाकिस्तान मैच

जन-भावना के खिलाफ हो रहे मैच

एशिया कप के इस टूर्नामेंट में फॉर्मेट ही कुछ ऐसा बनाया गया है कि महज दो हफ्ते के भीतर भारत और पाकिस्तान की टीमें तीन बार आमने-सामने आ सकें। दो हफ्ते के अंदर तीन मैच कराना; योजना बनाकर रविवार को मैच रखना, यह बताने के लिए काफी है कि इन खेलों का उद्देश्य जन-भावनाओं, देशभक्ति को परे रखकर सिर्फ पैसा कमाना है। इस टूर्नामेंट में ओमान, यूएई, हांगकांग जैसी टीमों को सिर्फ खानापूर्ति के लिए रखा गया है।

जो लोग यह तर्क दे रहे हैं कि क्या भारत किसी टूर्नामेंट का सिर्फ इसलिए बहिष्कार कर दे कि उसमें पाकिस्तान खेल रहा है, तो उन्हें बता दूं कि केंद्र सरकार खुद मानती है, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। तो, युद्ध के दौरान मैच खेलने और युद्ध समाप्त होने के बाद मैच खेलने में अंतर है। और, यह भी नहीं है कि टीमों ने इससे पहले बहिष्कार नहीं किया है। खुद भारत ने 1986 में श्रीलंका में गृह युद्ध के हालात को देखते हुए एशिया कप में हिस्सा नहीं लिया था। पाकिस्तान ने भी 1990-91 में राजनीतिक तनाव और कश्मीर मसले को लेकर भारत में हुए एशिया कप का बहिष्कार किया था। 1993 में तो भारत-पाकिस्तान तनाव के कारण पूरा एशिया कप टूर्नामेंट ही रद्द कर दिया गया था। रही बात ओलंपिक की दुहाई देने वालों की, तो इसमें भी बहिष्कार के ढेरों उदाहरण हैं। 1936 बर्लिन ओलंपिक में हिटलर के शासन और उसके यहूदी विरोध के चलते कई देशों ने खेलों का बहिष्कार किया था। 1956 मेलबर्न ओलंपिक में हंगरी संकट, स्वेज युद्ध, और चीन-ताइवान विवाद के कारण आठ देशों ने भाग नहीं लिया था। 1976 मॉन्ट्रियल ओलंपिक में 20 से अधिक अफ्रीकी देशों ने न्यूजीलैंड के बहिष्कार की मांग न माने जाने पर हिस्सा नहीं लिया था। सोवियत संघ द्वारा अफगानिस्तान पर हमले के विरोध में 1980 के मॉस्को ओलंपिक का अमेरिका के नेतृत्व में 65 देशों ने बहिष्कार किया था। 1984 के लॉस एंजेलिस ओलंपिक का सोवियत संघ और पूर्वी ब्लॉक के 13 देशों ने अमेरिकी कार्रवाइयों के विरोध में बहिष्कार किया था। कुछ वर्ष पूर्व 2022 बीजिंग विंटर ओलंपिक में अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत समेत कई देशों ने चीन की नीति के विरोध में 'कूटनीतिक बहिष्कार' किया था।

वैसे भी, जब दो देशों के बीच जंग चल रही होती है, तो उसमें सिर्फ सैनिक नहीं लड़ते। खिलाड़ी, कलाकार, राजनेता, संस्थाएं और देश की पूरी जनता उसमें भाग ले रही होती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता, तो वह जन-भावनाओं के खिलाफ काम करता है। इसलिए, अगले भारत-पाकिस्तान मैच का भी पुरजोर विरोध होना चाहिए।

विनय सिंह बैस, टिप्पणीकार

क्रिकेट हमारी साझा धार्मिक भावना

भारत और पाकिस्तान एशिया कप में एक बार फिर टकराने वाले हैं। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, वे मेरी नजर में देशभक्त नहीं हैं। हमारी लड़ाई आतंकियों से है; पाकिस्तान की फौज और उसके हुक्मरान से है। अवाम से थोड़े है। कलाकारों, खिलाड़ियों, लेखकों और फकीरों से काहे की लड़ाई। हम सबको एकजुट होना है। एकजुट होकर नफरत के सौदागरों से लड़ना है। जहां तक क्रिकेट का सवाल है, तो वह भारत और पाकिस्तान, दोनों देशों का सबसे बड़ा धर्म है। इस महाद्वीप में जितने पुजारी, मुरीद, भक्त और मजहबी लोग क्रिकेट के हैं, वैसे और उतने और किस धर्म के हैं? क्रिकेट हमारी साझा धार्मिक भावना है। जब तक क्रिकेट है; गजल है; हिंदी, उर्दू, हिन्दुस्तानी, पंजाबी, सिंधी सरीखी जबानें हैं; दाल-रोटी है; हमारी पोशाकें हैं; संगीत है, सिनेमा है, तब तक भारत और पाकिस्तान को कोई अलग नहीं कर सकता। खुलकर खेलो इंडिया और जीतकर आओ।

आशुतोष कुमार, टिप्पणीकार

भारत और पाकिस्तान की आपसी राजनीति में क्रिकेट को बेमतलब घसीटा जा रहा है। यह एक खेल है और इसे खेल के रूप में ही लेना चाहिए। क्रिकेट को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। आखिर किस पड़ोसी में विवाद नहीं होता। लड़ाई-झगड़े चलते ही रहते हैं। उसका असर खेल पर नहीं पड़ता। यहां तक कि कला-संस्कृति और व्यापार को भी उससे बाहर रखा जाता है। मगर भारत और पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं हो रहा। पहले तो भारतीय खिलाड़ियों के पाकिस्तान के साथ खेलने पर जमकर आपत्ति जताई गई। यहां तक कि कई खिलाड़ियों को ट्रोल तक किया गया। मगर जब भारतीय टीम को जीत मिली और टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ नहीं मिलाया, तो उनको खूब शाबाशी दी गई। उनकी देशभक्ति के कसीदे पढ़े गए। इन सब भौंड़े प्रदर्शनों से हमें ऊपर उठना चाहिए। भारत कोई ऐसा देश नहीं है, जहां खेल को लेकर इस तरह की राजनीति की जाए। कल्पना कीजिए कि जीत के बाद यदि पाकिस्तान के कप्तान ने भी हमारे खिलाड़ियों के साथ ऐसा व्यवहार किया होता, तो फिर क्या होता? तब तो शायद हमारे खिलाड़ियों को यहां जमकर लानत मलामत की जाती कि आखिर वे गए ही क्यों? हमें खेल भावना का परिचय देना चाहिए और खुले दिन से मैच खेलना चाहिए। इन्हीं सबसे तनाव खत्म होगा। यही कारण है कि मैं रविवार के मैच का भी जमकर लुत्फ लेना चाहता हूं। खेल को खेल की नजर से देखना ही उचित है। उसे राजनीतिक औजार नहीं बनने देना चाहिए।

दीपक शर्मा, टिप्पणीकार

https://t.me/AllNewsPaperPaid

विनम्रता का भाव व्यक्तित्व की आभा बढ़ाता है

आरोप उछालने की राजनीति

राहुल गांधी एक बार फिर वोट चोरी के आरोप के साथ सामने आए। इस बार उन्होंने कर्नाटक के अलंद से वोट काटे जाने का आरोप लगाया और अपनी ओर से कुछ कथित प्रमाण भी पेश किए। उनकी मानें तो यहां से कांग्रेस के 6018 वोटरों के वोट काटे गए। उन्होंने यह भी समझाया कि कर्नाटक के बाहर के लोगों ने मोबाइल फोन के जरिये कांग्रेसी वोटरों के नाम हटा दिए। उन्होंने अपने जिन आरोपों को सौ प्रतिशत पुख्ता बताया, उन्हें चुनाव आयोग ने निराधार करार देते हुए कहा कि इस तरह मोबाइल से वोट नहीं हटाए जा सकते। आयोग ने यह तो माना कि अलंद में कुछ लोगों के वोट हटाने की कोशिश हुई थी, पर यह भी साफ किया कि इसके खिलाफ एक रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी और इस मामले की जांच अभी जारी है। स्पष्ट है जब तक यह जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक राहुल के आरोपों को सच मान लेने का कोई कारण नहीं। निःसंदेह इस नतीजे पर भी नहीं पहुंचा जा सकता कि यदि कहीं किसी के नाम वोटर लिस्ट से अनुचित तरीके से हटा या जोड़ दिए गए तो ऐसा मुख्य चुनाव आयुक्त के इशारे पर किया गया।

देश में शायद ही कोई ऐसा चुनाव क्षेत्र हो, जहां मतदाता सूची में किसी तरह की गड़बड़ी न होती हो, लेकिन कम से कम राहुल को इतनी जानकारी होनी चाहिए कि इसके लिए स्थानीय नेताओं के साथ चुनाव कर्मचारी जिम्मेदार होते हैं, जो राज्य सरकारों के तहत काम करते हैं। राहुल गांधी कुछ समय पहले भी वोट चोरी के ऐसे ही एक और मामले को सामने लाए थे। उसे उन्होंने एटम बम की संज्ञा दी थी। उनका दावा है कि वे वोट चोरी का ऐसा मामला रखेंगे, जो हाइड्रोजन बम सरीखा होगा और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अपना मुंह नहीं दिखा पाएंगे। साफ है वे यह सिद्ध करने की कोशिश में हैं कि भाजपा छल-कपट से चुनाव जीत रही है। वे यह समझाने की जल्दबाजी में भी हैं कि इस छल-कपट में चुनाव आयोग भी भाजपा का साथ दे रहा है। अच्छा हो कि वे यह समझें कि कोई सनसनीखेज बात कहने मात्र से वह गंभीर आरोप की शक्ल नहीं ले लेती। वोट चोरी को तूल दे रहे राहुल को ऐसी किसी सीट का उदाहरण देना चाहिए था, जहां भाजपा विधायक जीता होता। वे जिस अलंद सीट का हवाला दे रहे हैं, वहां तो 2023 में कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी। वह वोट चोरी के मामले को उछालकर सुर्खियां भले बटोर ले रहे हों, पर उनके इस दावे में दम नहीं दिखता कि वे लोकतंत्र बचाने का काम कर रहे हैं। यदि उन्हें सच में लोकतंत्र की परवाह है तो वे वोट चोरी के अपने कथित प्रमाणों के साथ अदालत क्यों नहीं जाते? वे नेता विपक्ष हैं। उन्हें सनसनी और भ्रम फैलाने वाली नहीं, बल्कि परिपक्व और जिम्मेदार राजनीति का परिचय देना चाहिए।

अनियंत्रित रफ्तार

राज्य के विभिन्न हिस्सों में आए दिन सड़क दुर्घटना की खबरें आती रहती हैं। इसके कारणों में सबसे प्रमुख है तेज रफ्तार। गुरुवार की सुबह भी सारण जिले में अमनौर- सोनहो स्टेट हाईवे पर ऐसा ही हादसा हुआ। स्कूल बस और पेट्रोल टैंकर आमने-सामने टकरा गए। आधा दर्जन बच्चे चोटिल हो गए। कल्पना की जा सकती है कि यदि पेट्रोल टैंकर की टंकी फटी होती तो क्या हालात पैदा होते। वाहन चालन के लिए सबसे जरूरी है धैर्य। ज्यादातर वाहन चालक जल्दीबाजी के चक्कर में धैर्य खो देते हैं। सारण की घटना की जांच हो रही है। कारण जो भी निकलकर सामने आए, दोनों वाहनों के चालकों की मनोदशा को भी समझने की जरूरत है। समय पर स्कूल पहुंचने की जल्दी में प्रायः चालक मानसिक दबाव में रहते हैं। बसों की फिटनेस पर भी कई बार सवाल खड़े होते रहे हैं। पिछले डेढ़ वर्ष में राज्य में निर्धारित गति सीमा का उल्लंघन करने वाले 3552 वाहनों को पकड़ा गया है। गौर करें तो इनमें ज्यादातर कैब, बस और कारें हैं। गति सीमा के उल्लंघन में सर्वाधिक वाहन राजधानी में पकड़े गए। यदि राज्य के हर हिस्से में गति की जांच की व्यवस्था हो तो नियमों के उल्लंघन करने वाले वाहनों की संख्या काफी बढ़ जाएगी। अतः जरूरी है कि नवाचार के साथ वाहनों की गति मापने और उसपर नियंत्रण के सख्त उपाय किए जाएं।

> दुर्घटनाग्रस्त वाहनों की जांच में वाहन की फिटनेस के साथ चालकों की मनोदशा के अध्ययन की भी व्यवस्था होनी चाहिए।

कह के रहेंगे — माधव जोशी

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की बाधाएं दूर होती दिख रही हैं?

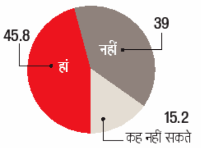

आज का सवाल
क्या वोट चोरी के राहुल गांधी के ताजा आरोप विश्वसनीय लग रहे हैं?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

तकनीक बनी शासन की भाषा

अश्विनी वैष्णव

तकनीक को अपनाकर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने वह कर दिखाया, जो असंभव सा लगता था

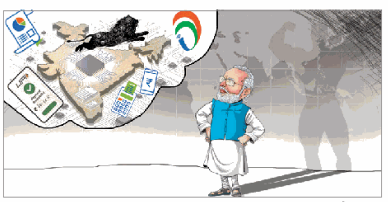
अवधेश राजपूत

प्रधानमंत्री मोदी ने तकनीक को भारत का सबसे बड़ा समान अवसर देने वाला साधन बना दिया है। मुंबई का एक रेहड़ी-पटरी वाला भी वही यूपीआइ पेमेंट सिस्टम इस्तेमाल करता है और बड़ी कंपनी का अधिकारी भी। यह बदलाव प्रधानमंत्री के मूल सोच अंत्योदय को दर्शाता है यानी कतार में खड़े सबसे आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना। हर डिजिटल पहल का मकसद है तकनीक को सबके लिए समान रूप से उपलब्ध कराना। गुजरात में शुरू हुए ये प्रयोग ही भारत की डिजिटल क्रांति की नींव बने। मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी जी ने तकनीक और नवाचार के जरिये गुजरात को बदला। 2003 में शुरू की गई ज्योतिग्राम योजना में फीडर सेपरेशन तकनीक से ग्रामीण उद्योगों को लगातार बिजली मिली। इससे महिलाएं रात में पढ़ाई कर सकीं और छोटे व्यवसाय फले-फूले, जिससे गांव से शहर की ओर पलायन घटा। इस योजना पर किए गए 1,115 करोड़ रुपये के निवेश की भरपाई सिर्फ ढाई साल में हो गई। 2012 में उन्होंने नर्मदा नहर पर सोलर पैनल लगाने का निर्णय लिया। इस परियोजना से हर साल 1.6 करोड़ यूनिट बिजली बनी, जो लगभग 16,000 घरों के लिए काफी थी। इससे नहर के पानी का वाष्पीकरण कम हुआ और पानी की उपलब्धता बढ़ी। इस नवाचार को अमेरिका और स्पेन द्वारा अपनाया जाना इसकी प्रभावशीलता को और मजबूत करता है। ई-धरा प्रणाली से जमीन के कागजात डिजिटल हुए। स्वागत पहल से नागरिक वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा मुख्यमंत्री से सीधे जुड़ सके। आनलाइन टेंडरिंग से भ्रष्टाचार पर रोक लगी।

2014 में मोदी जी ने गुजरात का अनुभव और सीख दिल्ली तक पहुंचाया, लेकिन पैमाना कहीं बड़ा था। उनके नेतृत्व में इंडिया स्टैक बना, जो दुनिया का सबसे समावेशी डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर है। इसकी बुनियाद जैम ट्रिनिटी (जन धन, आधार, मोबाइल) पर रखी गई। जन धन खातों ने 53 करोड़ से अधिक लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा। इससे उन्हें सुरक्षित बचत करने, सीधे सरकारी लाभ पाने और आसानी से कर्ज तक पहुंचने का अवसर मिला। आधार ने नागरिकों को डिजिटल पहचान दी। अब तक 142 करोड़ से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं। इससे सरकारी सेवाओं तक पहुंचना आसान हो गया। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ने बिचौलियों को हटा दिया और गड़बड़ी कम की। अब तक डीबीटी से 4.3 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बचत हुई है। यही पैसा स्कूल, अस्पताल और अन्य बुनियादी ढांचे बनाने में लगाया जा रहा है। पहले ग्राहक की पहचान (केवाईसी) की प्रक्रिया कठिन और भाग-दौड़ भरी थी। आधार-आधारित ई-केवाईसी से छोटे से छोटे लेन-देन भी आर्थिक रूप से संभव हो गए हैं। यूपीआइ ने भारत के भुगतान करने का तरीका बदल दिया। सिर्फ अगस्त में ही 20 अरब से अधिक लेन-देन हुए, जिनकी कुल राशि 24.85 लाख करोड़ रुपये रही। सिंगापुर से लेकर फ्रांस तक कई देश यूपीआइ से जुड़े हैं। जी-20 ने डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को समावेशी विकास के लिए जरूरी माना है। जापान ने इसके लिए पेटेंट भी दिया है। जो शुरुआत में भारत का समाधान था, वही अब विश्व के लिए डिजिटल लोकतंत्र का माडल बन गया। आज भारत दुनिया के कुल रियल-टाइम डिजिटल पेमेंट्स का आधा हिस्सा अकेले संभालता है। पीएम मोदी के सोच ने जैम ट्रिनिटी और यूपीआइ ढांचे को अंतिम रूप दिया। आज यूपीआइ, वैश्विक स्तर पर वीजा से भी अधिक लेन-देन करता है। एक साधारण मोबाइल फोन अब बैंक, पेमेंट गेटवे और सर्विस सेंटर सब कुछ बन गया है।

'प्रगति' ने शासन में जवाबदेही लाने का काम किया। जब अधिकारियों को पता होता है कि प्रधानमंत्री लाइव वीडियो में उनका काम देखेंगे, तो जवाबदेही अपने आप बढ़ जाती है। तकनीक ने खेती और स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह बदल दिया है। किसानों को अब मौसम की जानकारी और मिट्टी की सेहत का डाटा सीधे मोबाइल पर मिल जाता है। डिजीलाकर में 57 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ताओं के 967 करोड़ दस्तावेज डिजिटल रूप से सुरक्षित रखे गए हैं। आधार आथेंटिकेशन से आयकर रिटर्न भरना भी बेहद आसान हो गया है।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने वह कर दिखाया जो असंभव सा लगता था। मंगल तक पहली कोशिश में पहुंचना और वह भी इतने कम खर्चे में जितना एक हालीवुड फिल्म पर भी नहीं लगता। चंद्रयान-3 ने भारत को चांद पर साफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बनाया। गगनयान मिशन भारत को चौथा ऐसा देश बनाएगा जो अपनी स्वदेशी तकनीक से इंसानों को अंतरिक्ष में भेजेगा। जब कोविड-19 आया तो पूरी दुनिया वैक्सीन बांटने की अफरा-तफरी से जूझ रही थी। तब कोविन प्लेटफार्म रिकार्ड समय में बनाया गया। यह दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का एक संपूर्ण डिजिटल समाधान था।

प्रधानमंत्री की दृष्टि के तहत आज हमारी मजबूत इलेक्ट्रानिक्स उत्पादन क्षमता हमें उन्नत सेमीकंडक्टर मैन्यूफैक्चरिंग की ओर छलांग लगाने में मदद कर रही है। दुनिया के 20 प्रतिशत से ज्यादा चिप डिजाइनर यहीं हैं। सेमीकंडक्टर उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स, गैस और विशेष सामग्री को भी समर्थन दिया जा रहा है। पीएम गति शक्ति पोर्टल जीआइएस तकनीक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करता है। इंडिया एआई मिशन के तहत 38,000 से अधिक जीपीयू उपलब्ध कराए गए हैं, वह भी वैश्विक लागत के एक-तिहाई दाम पर। इससे स्टार्टअप, शोधकर्ताओं और छात्रों को सिर्फ 67 रुपये प्रति घंटे की दर पर सिलिकान वैली जैसी सुविधाएं मिली हैं। तकनीक के प्रति पीएम मोदी की समझ भारत की अनूठी एआइ रेगुलेशन नीति में भी झलकती है।

केवड़िया में 182 मीटर की स्टैच्यू आफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। चिनाब पुल 359 मीटर ऊंचा है, जो कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है। आइजोल रेल लाइन कठिन पहाड़ी इलाकों से गुजरती है, जिसमें हिमालयन टनलिंग मेथड का प्रयोग किया गया है, जिसमें कई सुरंगें और पुल शामिल हैं। नया पंबन पुल सौ साल पुराने ढांचे की जगह आधुनिक इंजीनियरिंग से बनाया गया है। इंजीनियरिंग की ये अद्भुत कृतियां प्रधानमंत्री के उस सोच को दर्शाती हैं जिसमें तकनीक और दृढ़ संकल्प के सहारे भारत को जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी तकनीक को तो समझते ही हैं, लेकिन इंसानों को उससे भी बेहतर ढंग से समझते हैं। अंत्योदय का उनका सोच ही हर डिजिटल पहल को आगे बढ़ाती है। मोदी जी ने तकनीक को शासन की भाषा बना दिया है। उन्होंने साबित किया है कि जब नेता तकनीक को इंसानियत के साथ अपनाते हैं तो पूरा देश भविष्य की ओर बड़ी छलांग लगाता है।

(लेखक भारत सरकार के रेल, आइटी और सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं)
response@jagran.com

भटका हुआ स्मार्ट सिटी अभियान

अनुरोध ललित जैन

शहरों के आकर्षण को केवल ऊंची इमारतों और राजमार्गों से नहीं, बल्कि बुनियादी सुविधाओं की सुगमता से मापा जाना चाहिए

वर्ष 2015 में मोदी सरकार ने स्मार्ट सिटी अभियान (एससीए) की शुरुआत की थी, जिसमें भारत के शहरी भविष्य को बदलने का वादा किया गया था। यह उद्देश्य प्रौद्योगिकी, नवाचार और बेहतर नियोजन का उपयोग करके सौ ऐसे शहर बनाना था, जो स्थिरता और दक्षता के माडल बन सकें। आज लगभग एक दशक बाद 1.5 लाख करोड़ रुपये निवेश के बावजूद भारतीय शहर एक अलग कहानी कहते हैं। जब गुरुग्राम, बेंगलुरु और मुंबई में भारी बारिश ने सड़कों को जलमग्न कर दिया, तो पानी भरे मार्गों पर फंसे यात्रियों को वह 'स्मार्टनेस' कहीं नजर नहीं आई, जिसका वादा किया गया था। भविष्य का खाका बनने वाला यह अभियान चुनिंदा सुंदरीकरण और भटकी हुई प्राथमिकताओं का प्रदर्शन बनकर रह गया है।

विश्व बैंक के अनुसार भारत की शहरी आबादी 2050 तक करीब 95.1 करोड़ हो जाएगी। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे महानगरों का विस्तार जारी है, वहीं भुवनेश्वर, कोयंबटूर, इंदौर, जयपुर सरीखे शहर विकास के नए केंद्र बन रहे हैं। परिवर्तन की यह गति शहरी ढांचों पर भारी दबाव पैदा कर रही है। अनियोजित निर्माण से जल निकासी व्यवस्था चरमरा रही है, आवास की कमी लोगों को अनौपचारिक बस्तियों में धकेल रही है और परिवहन नेटवर्क बढ़ते यातायात के दबाव में ढह रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए स्मार्ट सिटी अभियान इन शहरों के पास नए ग्रीनफील्ड उपनगरीय शहरों के निर्माण पर ध्यान दे सकता था। बजाय इसके इसने मौजूदा शहरों के छोटे-छोटे हिस्सों के सुंदरीकरण, ओवरब्रिज नवीनीकरण, स्ट्रीट लाइटों के डिजिटलीकरण और नियंत्रण केंद्र स्थापित करने पर ही अधिक ध्यान केंद्रित किया। जल निकासी और आवास जैसी गहरी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। इसके दुष्परिणाम मानसून में देखने को मिले।

अटल मिशन फार रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफार्मेशन यानी अमृत भारत सरकार की एक और महत्वाकांक्षी योजना है। इसका उद्देश्य 500 शहरों में बुनियादी सुविधाओं का विकास करना है। इस अभियान में पेयजल, मल जल प्रणाली, वर्षा जल निकासी और हरे-भरे स्थान जैसी बुनियादी सुविधाओं को ठीक करने का वादा किया गया। इसके पहले चरण में पांच साल के लिए 50,000 करोड़ रुपये का बजट था। दूसरे चरण में लगभग 2.9 लाख करोड़ रुपये। इसका लक्ष्य शहरी भारत में पानी और मल जल प्रणाली को बेहतर करना था, लेकिन इस बरसात में देश ने देखा कि शहरों की कैसी दुर्दशा हुई। हमारे छोटे-बड़े शहर हर बारिश के दौरान टापुओं में तब्दील हो जाते हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित होता है।

थोड़ी सी बारिश भी बढ़ा देती है बड़ी मुश्किलें ● फाइल

लगता है कि भारत के शहरी विकास के कार्यक्रम अभी भी अलग-अलग खांचों में डिजाइन किए जाते हैं। नई दिल्ली में तैयार की गई योजनाएं शायद भारतीय शहरों की विविधता से भरी वास्तविकताओं से कटी हुई हैं। शहरों के बेहतर भविष्य के लिए इन खांचों को तोड़ना होगा और स्थानीय सरकारों को सशक्त बनाने के साथ दीर्घकालिक नियोजन को शहरी नीति का केंद्र बनाना होगा।

हालांकि सरकार ने गुजरात में धोलेरा, गिफ्ट सिटी, औरंगाबाद औद्योगिक शहर और ग्रेटर नोएडा जैसे कुछ ग्रीनफील्ड पहलों को आगे बढ़ाया है। 2024 में राष्ट्रीय औद्योगिक कारिडोर विकास कार्यक्रम (एनआइसीडीपी) के तहत एक दर्जन नए औद्योगिक केंद्रों को भी मंजूरी दी गई। अच्छा हो कि इनमें समावेशी शहरी विकास की व्यापक चुनौतियों को भी ध्यान में रखा जाए।

भारत के शहरी विकास को सुंदरीकरण से हटकर नए ग्रीनफील्ड निर्माण की ओर बढ़ना होगा। जिस तरह चीन ने शेंजेन को एक मछली पकड़ने वाले गांव से प्रौद्योगिकी और वित्त के वैश्विक केंद्र में बदल दिया, उसी तरह भारत को भी नए शहरी केंद्र बनाने की इच्छाशक्ति दिखानी होगी, जो लोगों और निवेश, दोनों को आकर्षित कर सकें। शहरों के आकर्षण को केवल ऊंची इमारतों और राजमार्गों से नहीं, बल्कि बुनियादी सुविधाओं की सुगमता से मापा जाना चाहिए। वित्तीय प्रोत्साहनों के माध्यम से ग्रीनफील्ड परियोजनाओं को धरातल पर लाया जा सकता है। भारत में संपत्ति कर अनुपालन बहुत कम है, जबकि स्टैंप शुल्क दुनिया में सबसे अधिक है, जो औपचारिक लेनदेन को हतोत्साहित करता है। नई स्मार्ट सिटीज को इन करों से बोझिल करने के बजाय सरकार पहले दशक के लिए कम संपत्ति कर, कम स्टैंप शुल्क और सुव्यवस्थित मंजूरी की पेशकश कर सकती है। सही प्रोत्साहन और नियोजन के साथ बड़े शहरों के पास उपनगरीय शहर नए अवसरों के केंद्रों के रूप में विकसित हो सकते हैं। हाल के वर्षों में भारत के चमकदार महानगरों को डुबोने वाली बाढ़ को केवल मौसम की घटना के रूप में नहीं, बल्कि शहरों के त्रुटिपूर्ण विकास की देन के रूप में देखा जाना चाहिए। भारत के शहरीकरण की रफ्तार अपेक्षा से तेज है। हमारे सामने विकल्प स्पष्ट है। या तो हम तनावग्रस्त महानगरों में ऊपरी सतह पर कार्य करें या फिर साहस के साथ नए, अच्छी तरह से वित्तपोषित और वास्तव में रहने योग्य शहरों का निर्माण करें।

(लेखक कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के उपाध्यक्ष हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

शपथ

जब कभी दो पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद की स्थिति बनती है और यह साबित नहीं हो पाता कि कौन सही और कौन गलत है तो फिर 'शपथ' ली जाती है, जिसे कसम और सौगंध भी कहा जाता है। शपथ लेने के कई तरीके हैं। पहला तो दोनों पक्षों से कहा जाता है कि वे अपने सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति का नाम लेकर शपथ लें। सरकारी स्तर पर जब कोई पद प्राप्त होता है, तो पदासीन होने वाला शख्स संविधान की शपथ लेता है। इसमें मंत्री, सांसद, विधायक और अधिकारीगण भी शामिल हैं।

सनातन संस्कृति में शपथ का बहुत महत्व है। माना जाता है कि झूठी शपथ लेने वाले का अनिष्ट होता है। इसलिए शपथ तभी लेनी चाहिए, जब अंदर से यह लगे कि जो सही है, वही कहा जा रहा है। सत्य शपथ में बड़ी शक्ति बताई जाती है। जबकि झूठी शपथ साम्राज्यों से लेकर कुल के पतन का कारण भी बन सकती है।

स्मरण रहे कि महाभारत युद्ध तो पांडवों की पत्नी द्रौपदी की शपथ का परिणाम रहा। युधिष्ठिर द्वारा द्रौपदी को जुए में हारने के बाद जब दुर्योधन के भाई दुशासन ने द्रौपदी के बाल खींचते हुए भरी सभा में निर्वस्त्र करना चाहा तो उन्होंने शपथ ली कि जब तक दुर्योधन का विनाश नहीं हो जाएगा, तब तक वह बाल नहीं बांधेंगी। द्रौपदी की शपथ को पांडवों ने सच साबित किया। इसके बाद ही द्रौपदी ने बाल बांधे। इसी तरह की शपथ आचार्य चाणक्य ने भी ली थी। नंद वंश के राजा घनानंद ने चाणक्य का अपमान किया। अपमानित होने पर चाणक्य ने अपनी शिखा खोल दी और तय किया कि वह नंद वंश के विनाश के बाद ही पुनः शिखा बांधेंगे। अपनी शपथ को पूरा करने के लिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का सहयोग लिया। इसलिए शपथ बहुत सोच-समझ कर लेनी चाहिए। झूठी शपथ से पुण्य नष्ट होता है।

सलिल पांडेय

पाठकनामा

pathaknama@pat.jagran.com

अदालतों पर बोझ बढ़ाते झूठे मामले

'कानूनों का दुरुपयोग' शीर्षक से प्रकाशित अग्रलेख में दुष्कर्म और दहेज प्रताड़ना के बढ़ते झूठे मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए इसे रोकने के लिए कारगर उपाय अपनाए जाने का आह्वान किया गया है। इनसे संबंधित कानूनों का दुरुपयोग लोगों को ब्लैकमेल करने, डराने-धमकाने, पैसा ऐंठने में बड़े पैमाने पर हो रहा है। यह एक सामान्य प्रचलन की तरह बन गया है। ये कानून महिला सशक्तीकरण और उन पर होने वाले जुल्म के त्वरित न्याय के लिए अस्तित्व में आए थे। झूठे आरोपों से घिरने के कारण संबंधित पीड़ित पक्ष की सामाजिक प्रतिष्ठा तो प्रभावित और धूमिल होती ही है, लेकिन इसके साथ ही वे मानसिक और आर्थिक रूप से भी बुरी तरह प्रताड़ित होते हैं। ऐसी विकट परिस्थिति के परिणामस्वरूप वे तनाव और दबाव में आकर गलत कदम तक उठाने को मजबूर हो जाते हैं। समाज-कानून के समक्ष यह समस्या एक गंभीर चुनौती बनकर उभर रही है। ऐसे कानूनों में अनिवार्य रूप से ऐसे संशोधन किए जाने चाहिए, जिससे कोई भी इनका गलत उपयोग नहीं कर सके। लगातार बढ़ते झूठे मामलों के कारण सही मामलों को भी शक की नजर से देखा जाने लगा है। ऐसा होना कानून के वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति में बाधक बन रहा है। अतः न्यायालय, शासन-प्रशासन स्वतःसंज्ञान लेकर झूठे मामलों के निराकरण में विवेक और तत्परता दिखाएं। दायर मामले के झूठा साबित होने पर सख्त प्रविधानों के तहत उचित कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि लोग झूठे मामले दायर करने से पहले सोचने को विवश हों। झूठे मामलों की संख्या बढ़ने से न्यायालय में सही और सच्चे मामलों की सुनवाई में अनावश्यक विलंब हो जाता है। उम्मीद है कि न्यायपालिका और कानून के संरक्षक इस दिशा में सार्थक प्रयत्न करेंगे, ताकि न्याय का बोलबाला और अन्याय का प्रतिकार हो।

sonimohit895@gmail.com

कर्तव्य का स्मरण कराता पितृपक्ष

भारत की संस्कृति और परंपराएं बहुत ही गहरी और महान हैं। इन्हीं परंपराओं में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। यह परंपरा हर वर्ष बिहार के गया जी में निभाई जाती है। इस वर्ष पितृपक्ष छह से 21 सितंबर तक है। यहां देश-विदेश से लाखों लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और पिंडदान करने आते हैं। सनातन धर्म में पितृपक्ष का समय अत्यंत पवित्र माना गया है। मान्यता है कि गया जी में पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है और परिवार की सुख-समृद्धि बनी रहती है। यह अनुष्ठान हमें अपने पितरों और पूर्वजों के प्रति कर्तव्य का स्मरण कराता है। गया जी का विष्णुपद मंदिर और फल्गु नदी इस अनुष्ठान के प्रमुख केंद्र हैं। इस अवसर पर साधु-संत भी आते हैं और संस्कृति व धर्म का संदेश देते हैं। स्थानीय लोग श्रद्धालुओं की सेवा में लगे रहते हैं। जिससे सामाजिक सहयोग और भाईचारे की भावना बढ़ती है। पितृपक्ष मेला भारतीय संस्कृति और परंपरा का जीवंत उदाहरण है।

प्रभात कुमार भारती, झंझारपुर, मधुबनी

कर नीति बने विकास नीति

जीएसटी सुधार केवल कर संग्रहण की प्रक्रिया नहीं, बल्कि आर्थिक ढांचे को दीर्घकालीन मजबूती देने वाली रणनीति है। यह सवाल कराधान की जटिलता या पारदर्शिता भर का नहीं, बल्कि इस बात से जुड़ा है कि भारत अपने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में किस तरह स्थापित करता है। यहीं से यह सुधार कर नीति से आगे बढ़कर विकास नीति का रूप लेते हैं। वास्तविक समस्या यह रही है कि अब तक एमएसएमई क्षेत्र कर ढांचे की जटिलता, अनुपालन की ऊंची लागत और सीमित बाजार पहुंच से जूझता रहा। नतीजतन रोजगार सृजन और निर्यात की क्षमता घटती गई। यदि यही स्थिति बनी रही तो भारत का 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य चुनौती में पड़ सकता है। नए सुधारों का लक्ष्य कर आधार को विस्तारित करना, दरों को सरल बनाना और राजस्व के रिसाव को रोकना है। किंतु जब तक इन प्रविधानों को व्यवहारिक स्तर पर लागू नहीं किया जाएगा, परिणाम सीमित रहेंगे। कर भुगतान की पूर्ण डिजिटल व्यवस्था, छोटे उद्यमों को प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग ही इस सुधार की सफलता तय करेंगे। समाधान यही है कि सुधार को केवल राजस्व उगाही की दृष्टि से न देखा जाए, बल्कि इसे रोजगार, उद्यमिता और नवाचार का आधार बनाया जाए। एमएसएमई को सस्ता ऋण व आसान बाजार पहुंच मिले।

अवनीश कुमार गुप्ता, पटना

X पोस्ट

पाकिस्तान ने आइसीसी के समक्ष अपनी मांगें रखकर अल्टीमेटम दिया कि उन्हें नहीं माना गया तो वह एशिया कप का बहिष्कार करेगा। उसकी मांगों पर तो कोई विचार नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने मैच जरूर खेला। लगता है शर्मिंदगी उठाए बिना पाकिस्तान का कोई दिन नहीं बीतता। शिवानी शुक्ला@iShivani_Shukla

इसमें सभी के लिए सबक छिपा है कि कभी भी ऐसा अल्टीमेटम नहीं देना चाहिए, जिसे आप लागू न कर सकें। इससे आप और कमजोर दिखते हैं। हर्षा भोगले@bhogleharsha

जिन्हें भी आपरेशन सिंदूर की सफलता पर संदेह रहा हो तो वे जैश के आतंकी और अजहर मसूद के खास चेले इलियास के बयान को सुन लें। उसे सुनकर धुंध छंट जानी चाहिए। अमिताभ अग्निहोत्री@Aamitabh2

कांग्रेस चुनाव से पहले माहौल बनाने के प्रयास में है। यह नैरेटिव की लड़ाई है। हर पक्ष खुद को सही साबित करने की कोशिश में है, लेकिन तटस्थ होकर सोचा जाए तो चुनाव में अनियमितता के मामले को अदालत में ले जाने में आपत्ति क्या है? मीनाक्षी जोशी@IMinakshiJoshi

जनपथ

खाए पाकिस्तान ने सौ जूते, सौ प्याज,
बेइज्जती करा रहा वह अपनी मय ब्याज।
वह अपनी मय ब्याज हर जगह करता हुज्जत,
तो कैसे यह देश भला पाएगा इज्जत!
ये पिटकर हर बार कहानी अपनी गाए,
होय जंग या खेल हर जगह मुंह की खाए।

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त
जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प. बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073
E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 26 अंक 158

****

कल्पमेधा

हिम्मत और दृढ़ता के पास जादुई तावीज होता है, जिसके सामने मुश्किलें लुप्त हो जाती हैं और बाधाएं हवा में नष्ट हो जाती हैं।

– जान क्विंसी एडम्स

हथियारों की होड़

हर दौर में हुए युद्ध और उनके नतीजों ने यह साबित किया है कि यह किसी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि खुद ही एक समस्या है। शायद ही कोई सिद्धांत रूप में युद्ध का समर्थन करता दिखे, लेकिन बहाने अलग-अलग भले हों, उनकी आड़ में ज्यादातर देश अपने रक्षा खर्च को ऊंचा रखते हैं, दूसरे देशों की ओर से खतरा बता कर उसमें भारी बढ़ोतरी को जरूरी बताते हैं। उसके बाद शुरू होता है हथियारों की खरीद का सिलसिला, जो देशहित के अन्य बेहद जरूरी मसलों की कीमत पर होता है। इसमें कोई दोराय नहीं कि देश की रक्षा सबसे जरूरी मसला होना चाहिए, मगर यह हैरानी बात है कि ज्यादा सभ्य, शांत और विकसित होने का दावा करते ऐसे कई देश हैं, जो शांति के लिए ठोस पहलकदमी करने के बजाय युद्ध में इस्तेमाल होने वाले घातक हथियारों के खरीद-फरोख्त में लगे रहते हैं। सवाल है कि अगर बड़े पैमाने पर व्यापक जनसंहार के हथियार खरीदे या निर्मित किए जाते हैं, तो आखिर उनका इस्तेमाल क्या होगा और उसके नतीजे क्या सामने आएंगे।

दरअसल, हाल के वर्षों में दुनिया कहीं ज्यादा हिंसाग्रस्त और खतरनाक बन चुकी है। एक रपट के मुताबिक, सन 2024 में वैश्विक स्तर पर राज्य आधारित संघर्षों की संख्या 1946 के बाद अपने सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गई है। जब भी विश्व के किसी कोने में राज्य आधारित टकराव होते हैं, तब खासतौर पर युद्ध में शामिल देशों के अलावा आसपास के अन्य देश भी अपना रक्षा खर्च बढ़ा देते हैं और पहले से ज्यादा आधुनिक और घातक हथियार खरीदने लगते हैं। इस क्रम में देशों के बीच होड़ लग जाती है कि सबसे खतरनाक हथियार खरीदने में कौन सबसे आगे रहता है। कई बार युद्ध की महज आशंका को ही आधार बना कर व्यापक जनसंहार के हथियारों की खरीद शुरू हो जाती है। पिछले वर्ष सभी यूरोपीय देशों ने अपने सैन्य बजट बढ़ाए। रूस ने भी ऐसा ही किया। चीन ने पिछले तीस वर्षों में लगातार सैन्य खर्च बढ़ाया है, जबकि अमेरिका को रक्षा पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाले देश के तौर पर देखा जाता है।

करीब एक वर्ष पहले संयुक्त राष्ट्र ने 'समिट फार द फ्यूचर' यानी भविष्य के खातिर सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसका मकसद शीत युद्ध के बाद बहुपक्षीय प्रणाली के पतन, संघर्ष की बढ़ती स्थितियों और मानवीय आपदाओं से निपटने पर चर्चा करना था। विडंबना यह है कि ऐसे सम्मेलनों में युद्ध पर रोक को लेकर जितनी संजीदगी दिखाई जाती है, उसका अमल में कोई खास असर नहीं दिखता। मसलन, संयुक्त राष्ट्र में इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष के औचित्य और उसमें मारे गए पचास हजार से ज्यादा लोगों को लेकर काफी चिंता जताई जा चुकी है, लेकिन इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ा। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि पिछले कुछ दशकों में हुए शांति समझौते टूट रहे हैं और नए सिरे से संघर्ष के हालात खड़े हो रहे हैं। मौजूदा दौर में अलग-अलग जगहों पर जारी सशस्त्र संघर्षों में पीड़ित बच्चों की संख्या रेकार्ड स्तर तक पहुंच चुकी है और महिलाओं के अधिकारों पर वैश्विक स्तर पर खतरा मंडरा रहा है। किसी भी युद्ध में सबसे ज्यादा घातक और बहुस्तरीय मार बच्चों और महिलाओं पर ही पड़ती है। सवाल है कि जब बहुत सारे देश विनाशक हथियारों से लैस होंगे, तब युद्ध की आशंकाओं को कहां तक टाला जा सकेगा। क्या आज की सभ्य कही जाने वाली दुनिया हथियारों की होड़ में शामिल होने के बजाय मानवता के हक में शांति का रास्ता नहीं चुन सकती?

दावे के बरक्स

उत्तर प्रदेश सरकार बार-बार यह दावा करती रही है कि राज्य में अपराधों पर काबू पा लिया गया है। मगर सच यह है कि आए दिन राज्य में सरेआम गंभीर आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं। सख्ती के बावजूद अपराधी अगर काबू में नहीं आ रहे, तो समझा जा सकता है कि अपराध नियंत्रण में कहीं न कहीं कोई कमजोर कड़ी बाकी है, जिसकी या तो शिनाख्त नहीं हो पाई है या जानबूझ कर उसकी अनदेखी की जाती है। महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देने के दावे के बरक्स सच यह है कि राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। पुलिस उनमें अभी तक यह भरोसा नहीं जगा सकी है कि वे सड़कों पर कहीं बेखौफ आ-जा सकें। बल्कि अक्सर होने वाली आपराधिक घटनाएं यही बताती हैं कि वे घरों में भी सुरक्षित नहीं। एक हफ्ते पहले अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर के बाहर गोलियां चला कर कुछ अपराधियों ने दहशत फैलाने की कोशिश की थी। अब उनमें से दो आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है, लेकिन इस दौरान बड़ी संख्या में मिले कारतूसों से यह सवाल उठा है कि अपराधियों तक घातक हथियार कैसे पहुंच रहे हैं। वे बिना किसी रोक-टोक के सड़कों पर घूमते हैं और तब तक नहीं पकड़े जाते, जब तक कोई घटना तूल नहीं पकड़ लेती।

किसी वारदात के बाद मुठभेड़ में अपराधियों के मार गिराए या पकड़े जाने की खबर आती है, लेकिन आखिर क्या वजह है कि इसके बावजूद अपराध को रोकने में कामयाबी नहीं मिल पा रही और आपराधिक तत्त्वों को पुलिस का खौफ नहीं सताता है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए करीब आठ साल पहले 'मिशन शक्ति' अभियान शुरू किया गया था। यह उम्मीद की गई थी कि इससे महिलाओं में सुरक्षा की भावना बढ़ेगी। मगर इस अभियान के पांचवें चरण से पहले ही एक अभिनेत्री के परिवार को धमकाने के लिए सरेआम गोलियां चलाई गईं। अपराध कम होने के सरकार के दावे के उलट महिलाओं के खिलाफ जिस तरह आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, उससे 'मिशन शक्ति' पर भी सवाल उठना स्वाभाविक है।

पैदल यात्रियों की सुरक्षा का सवाल

पैदल चलने का अधिकार एक बुनियादी मानवीय जरूरत है और इसे हमारे संविधान के तहत जीने के मौलिक अधिकार का एक हिस्सा माना गया है। अफसोस की बात है कि देश में पैदल यात्रियों के हक में कोई ठोस समर्थन नहीं दिखता है।

जयवीर सिंह

देश में सड़कों पर पैदल चलने वाले लोगों की सुरक्षा एक गंभीर विषय है। इस पर गौर करना बेहद जरूरी है कि सड़कें क्या केवल वाहनों के लिए है या उन पर चलने का समान अधिकार पैदल यात्रियों का भी है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की एक रपट भयावह तस्वीर पेश करती है। इसके मुताबिक, सड़क दुर्घटनाओं में पैदल यात्रियों की मौत की संख्या लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2022 में देश भर में सड़क दुर्घटनाओं में 32,825 पैदल यात्रियों की जान चली गई, जो हादसों में हुई कुल मौतों का लगभग पांचवां हिस्सा है। यह आंकड़ा केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि एक गहरी प्रणालीगत विफलता को दर्शाता है। वर्ष 2014 से 2018 के बीच सड़क पर पैदल चलने वाले लोगों की मौत में 84 फीसद की भारी वृद्धि हुई है। यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि पैदल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर विभिन्न स्तरों पर सतर्कता और गंभीरता का अभाव है। जागरूकता की कमी के साथ-साथ यातायात नियमों का भी सुचारु रूप से पालन सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है।

भारत में सड़कें मुख्य रूप से वाहनों को ध्यान में रख कर बनाई गई हैं, जिससे पैदल यात्रियों को अपनी सुरक्षा के लिए जद्दोजहद करना पड़ता है। अधिकांश शहरों में फुटपाथ या तो हैं ही नहीं या वे टूटे हुए हैं या फिर अतिक्रमण की जद में आ गए हैं। इस वजह से पैदल यात्रियों को मुख्य सड़कों पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जहां तेज रफ्तार वाहनों से हमेशा दुर्घटना का खतरा बना रहता है। दूसरी ओर, सड़कों पर अतिक्रमण भी एक बड़ी समस्या बन गई है। शहरों में तो सड़कों किनारे ही वाहन खड़े कर दिए जाते हैं, जिससे यातायात में बाधा उत्पन्न होती है और पैदल यात्रियों के लिए भी परेशानियों के साथ जान का जोखिम बना रहता है। स्थानीय प्रशासन की ओर से भी फुटपाथ और सड़कों पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई नाममात्र ही होती है।

देश के कई शहरों में पैदल यात्रियों के लिए नीतियां तो बनाई गई हैं, लेकिन उनके कमजोर कार्यान्वयन के कारण जमीनी स्तर पर उनका प्रभावी असर नजर नहीं आता है। बंगलुरु इसका एक उदाहरण है। वहां वर्ष 2008 में पैदल यात्री नीति प्रस्तावित की गई थी, लेकिन पंद्रह वर्ष बाद भी जमीनी स्तर पर कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला है और सड़क हादसों में पैदल चलने वालों की मौत लगातार बढ़ रही हैं। इसी तरह चेन्नई और मुंबई में भी पैदल यात्री-केंद्रित नीतियों के बावजूद इनके खराब कार्यान्वयन के कारण मृत्यु दर अधिक बनी हुई है। ये नीतियां केवल कागजों की ही शोभा बढ़ा रही हैं। आम सड़कों पर पैदल चलने का अधिकार एक बुनियादी मानवीय जरूरत है और इसे हमारे संविधान के तहत जीने के मौलिक अधिकार का एक हिस्सा माना गया है। अफसोस की बात है कि देश में सड़क पर पैदल यात्रियों के लिए कोई ठोस समर्थन नहीं दिखता है। हालांकि, कुछ मौजूदा कानून जैसे मोटर वाहन अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता में ऐसे नियम हैं, जिनमें लापरवाही से वाहन चलाने पर सजा का प्रावधान किया है। ये नियम अप्रत्यक्ष रूप से पैदल चलने वालों की मदद करते हैं, लेकिन इनमें 'चलने के अधिकार' को स्पष्ट तौर से परिभाषित नहीं किया गया है।

न्यायपालिका ने हमेशा पैदल यात्रियों के अधिकारों को मान्यता दी है। इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ वर्ष 1985 का ओल्गा टेलिस बनाम बंबई नगर निगम मामला था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि फुटपाथों का मुख्य उद्देश्य पैदल चलने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। शीर्ष अदालत ने कहा कि फुटपाथों पर अतिक्रमण करके इस महत्त्वपूर्ण सुविधा को खत्म नहीं किया जा सकता है। इस सिद्धांत को वर्ष 2018 में ओमप्रकाश गुप्ता बनाम मुंबई नगर निगम मामले में बंबई उच्च न्यायालय ने फिर से दोहराया। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में एक और ऐतिहासिक फैसला दिया, जिसमें सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को दो महीने के भीतर व्यापक दिशानिर्देश बनाने का निर्देश दिया गया है। इन दिशानिर्देशों का मुख्य उद्देश्य सड़क किनारे फुटपाथों को बाधा-मुक्त और दिव्यांग-अनुकूल बनाना है। इसके अलावा, न्यायालय ने केंद्र सरकार को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड स्थापित करने का भी निर्देश दिया है, जो इस दिशा में एक बड़ा कदम होगा।

> **विश्व स्वास्थ्य संगठन सुरक्षित पैदल यात्री बुनियादी ढांचा बनाने और निजी वाहनों को हतोत्साहित करने की सलाह देता है। फिनलैंड ने वर्ष 2030 तक पैदल चलने और साइकिल चलाने के लिए जगह तीस फीसद तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। मेक्सिको सिटी में सुलभ फुटपाथ बनाने से यात्रा के समय में चालीस फीसद की कमी आई है। जापान और स्वीडन जैसे देशों में दिव्यांगों की मदद के लिए खास सुविधाएं हैं, जैसे पीले रंग के फर्श और श्रव्य संकेत। भारत को भी अब पैदल चलने के अधिकार को सिर्फ सुरक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि सम्मान, समानता और स्वास्थ्य का मुद्दा मानना चाहिए।**

आम सड़कों पर पैदल यात्रियों के अधिकारों को मान्यता दिए जाने के बावजूद जमीनी स्तर पर अभी भी बहुत सुधार की जरूरत है। भारतीय सड़क कांग्रेस ने वर्ष 2012 में ही फुटपाथों को लेकर बहुत ही स्पष्ट दिशानिर्देशों के साथ सिफारिशें की थीं। इनमें पैदल चलने के लिए कम से कम 1.8 मीटर चौड़ा और बाधा-मुक्त क्षेत्र बनाने का सुझाव दिया गया था। इसके साथ ही रेहड़ी-पटरी वालों और अन्य सुविधाओं के लिए एक अलग 'फर्नीचर जोन' बनाने, बस ठहराव के लिए सही जगह तय करने और 'जेब्रा क्रासिंग' पर पैदल चलने वालों को प्राथमिकता देने जैसे सुझाव भी शामिल थे। मगर हकीकत यह है कि सड़क बनाने और रखरखाव का काम करने वाली एजंसियां अक्सर इन दिशानिर्देशों को नजरअंदाज कर देती हैं। जहां 'जेब्रा क्रासिंग' बनाई गई होती है, वहां वाहन चालक दिशानिर्देशों का पालन नहीं करते हैं। नियमों को सख्ती से लागू करने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन और यातायात पुलिस की होती है, मगर इस ओर उनका ध्यान कम ही जाता है।

दिल्ली जैसे महानगर में सड़कों के निर्माण एवं विकास और रखरखाव के लिए कई सरकारी एजंसियां-जैसे नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जिम्मेदार हैं। इस बहु-एजंसी प्रणाली के कारण यह तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि मुख्य जवाबदेही किसकी है और इससे अक्सर भ्रम की स्थिति पैदा होती है। इसके अलावा, राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी भी एक बड़ी बाधा है। अक्सर सरकार और प्रशासन सुधारों पर तभी ध्यान देते हैं, जब कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है। यह सिर्फ एक प्रतिक्रियागत रवैया है। कुछ दिनों की मुस्तैदी के बाद हालात फिर से पुराने ढर्रे पर लौट आते हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन सुरक्षित पैदल यात्री बुनियादी ढांचा बनाने और निजी वाहनों को हतोत्साहित करने की सलाह देता है। फिनलैंड ने वर्ष 2030 तक पैदल चलने और साइकिल चलाने के लिए जगह तीस फीसद तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। मेक्सिको सिटी में सुलभ फुटपाथ बनाने से यात्रा के समय में चालीस फीसद की कमी आई है। जापान और स्वीडन जैसे देशों में दिव्यांगों की मदद के लिए खास सुविधाएं हैं, जैसे पीले रंग के फर्श और श्रव्य संकेत। भारत को भी अब पैदल चलने के अधिकार को सिर्फ सुरक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि सम्मान, समानता और स्वास्थ्य का मुद्दा मानना चाहिए। इस समस्या के समाधान के लिए लिए सरकार को एक स्पष्ट कानून बनाने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, जो पैदल चलने वालों के अधिकारों की रक्षा करे। इसके साथ ही कुछ और भी जरूरी कदम उठाने होंगे। सबसे पहले वाहन चालकों और आम लोगों को जागरूक करना होगा, ताकि वे पैदल चलने वालों के अधिकारों का सम्मान करें। दूसरा, फुटपाथों को पूरी तरह अतिक्रमण से मुक्त कराना होगा। इसके अलावा सड़कों को 'पैदल यात्री-पहले' के दृष्टिकोण से तैयार करना होगा, ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

सुख के समांतर दुख

तनुजा चौबे

जिस तरह हर रोज सुबह की कोमल किरणें अंधकार को चीरकर नवजीवन का संकेत देती हैं, उसी तरह मनुष्य जीवन की यात्रा आरंभ करता है। दुनिया में आने के बाद धीरे-धीरे डग भरते हुए वह बचपन की भोर से आगे बढ़ता है और यौवन की दोपहरी तक पहुंचता है, जहां तपती धूप के समान संघर्षों की तपन और अनुभवों की आंच उसे परिपक्व बनाती है। उसके बाद ही संध्या की मद्धम आभा दिनभर की आपाधापी को विश्रांति प्रदान करती है। उसी तरह जीवन भी अनवरत गति से अपने रंगों और रागों के साथ बहता चला जाता है।

यह जीवन, जो बाहरी रूप में निरंतर गतिशील प्रतीत होता है, भीतर से कहीं ठहर-सा गया लगता है। गुजरते समय ने अपने-पराए का अंतर स्पष्ट कर दिया है। रिश्तों के बंधनों में बंधकर वह अक्सर अपने लिए नहीं, अपनों की खुशी के लिए जीने को विवश होता है। जीवन की गाड़ी को चलाए रखने के लिए उसे ऊंचे-नीचे पथरीले रास्तों का लंबा सफर तय करना पड़ता है और इसी निरंतर भागमभाग में उसका अस्तित्व परिपक्व होता जाता है। उसके भीतर निस्वार्थ सुख के वे क्षण खोते चले जाते हैं, जिन्हें बार-बार चुराना पड़ता है।

मनुष्य की दिनचर्या में शांति के पल सहज नहीं आते, उन्हें क्षण-क्षण की आपाधापी में खोजकर ही पाया जा सकता है। पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को संघर्षों से गुजरना पड़ता है। यह साधना तभी सार्थक होती है, जब हम अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरकर उसे अर्जित करने का प्रयत्न करें। मगर कभी-कभी यह वचन और उपलब्धि हमारे अपने ही या पराए जनों द्वारा हमसे छीन ली जाती है। ऐसे क्षणों में इसे अवसाद का कारण न बनाकर अगर हम त्याग की भावना में स्थित होकर देखें, तो वहीं से एक नई खुशी का स्रोत भी खोजा जा सकता है। इसी खोज में अक्सर दिन के सारे क्षण दुविधाओं, द्वंद्वों और उत्तरदायित्वों के बोझ तले दब जाते हैं। रह जाती है केवल एक मूक इच्छा- स्वयं के लिए जी लेने की।

कभी-कभी यह भी होता है कि जीवन की इस व्यस्त धारा में वे लोग हमसे दूर होते चले जाते हैं, जो हमारे हृदय के सबसे निकट थे, जिनके साथ हमने कभी जीवन के सुनहरे स्वप्न बुने थे। वे रिश्ते, वे क्षण, जिनमें कभी हृदय लयबद्ध हुआ करता था, अब स्मृतियों की परछाइयों में विलीन हो जाते हैं। जब हृदय पर एकाकीपन की छाया पड़ती है, तब मन अनायास ही अतीत की ओर भागने लगता है। बीते हुए क्षणों को फिर जीने की लालसा भीतर उमड़ती है, मानो समय को रोककर उसे फिर से पकड़ लेना चाहता हो। यही ठहराव दुख का कारण बनता है। सत्य को स्वीकार न कर पाने की जिद हमें वर्तमान की मधुर संभावनाओं और आने वाली खुशियों से वंचित कर देती है। और मन, उसी बीते हुए समय को 'सर्वश्रेष्ठ' मानकर बारंबार उसकी ओर लौट जाना चाहता है।

हम आत्मचिंतन करें, तो अनुभव करेंगे कि यह केवल मस्तिष्क का एक मोह-जाल है, एक मानसिक कोहरा, जो वर्तमान की स्पष्टता को ढक देता है। वास्तविकता यह है कि जीवन स्वयं में एक चक्र है- सुख और दुख का, संयोग और वियोग का, गति और विश्रांति का। कभी इसकी गति तीव्र होती है, तो कभी मंद। और मंद गति में दुख की छाया अधिक सघन प्रतीत होती है। ऐसे क्षणों में मन को विषादग्रस्त नहीं होने देना चाहिए, बल्कि इन्हीं पलों में भीतर संचित उन सौंदर्यपूर्ण स्मृतियों को फिर जीवंत करना चाहिए, जो हमें आत्मिक विश्रांति प्रदान करती हैं। उन रिश्तों को, उन लम्हों को फिर से स्मरण में लाना चाहिए, जिन्होंने हमें संपूर्णता का बोध कराया था। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है सुख को थामे रखने की और दुख को नकारने की। वह हर उस भाव, वस्तु या व्यक्ति को रोक लेना चाहता है, जिसने उसे सुख प्रदान किया हो। मगर यही आग्रह और मोह उसे पीड़ा की ओर ले जाता है, क्योंकि जीवन का स्वभाव परिवर्तनशील है। कोई भी क्षण, परिस्थिति या अनुभूति स्थायी नहीं।

अगर प्रतिदिन आनंद में डूबे रहना संभव होता, तो 'आनंद' शब्द अपनी विशिष्टता खो बैठता। वह केवल एक सामान्य अनुभव बनकर रह जाता। उसी प्रकार अगर दुख भी स्थायी होता, तो उसकी पीड़ा निष्क्रिय हो जाती। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने भावों में संतुलन स्थापित करें, सुख और दुख, दोनों को समान भाव से स्वीकार करें। तभी हम जीवन की विविधता को उसकी संपूर्णता में अनुभूत कर सकते हैं।

दुनिया मेरे आगे

> **जीवन स्वयं में एक चक्र है- सुख और दुख का, संयोग और वियोग का, गति और विश्रांति का। मंद गति में दुख की छाया अधिक सघन प्रतीत होती है। ऐसे क्षणों में मन को विषादग्रस्त नहीं होने देना चाहिए, बल्कि इन्हीं पलों में भीतर संचित उन सौंदर्यपूर्ण स्मृतियों को फिर जीवंत करना चाहिए, जो हमें आत्मिक विश्रांति प्रदान करती हैं।**

यह भी संभव है कि हम अपने जीवन के उन सुकुमार क्षणों को स्मृति में सहेजकर रखें और जब मनुष्य स्वयं से मिलना चाहे, जीवन से क्षण भर का विराम चाहे, तब वे स्मृतियां उसका मार्गदर्शन करें। सुखद अनुभूतियां, दुख की उष्णता को शीतलता प्रदान करती हैं। वे आश्वासन देती हैं कि 'यह समय भी व्यतीत हो जाएगा।' मगर जब जीवन सुख के उजास से भरा हो, तब भी यह न भूलें कि कहीं न कहीं, दुख की कोई मद्धम छाया हमारी प्रतीक्षा कर रही है। यही चेतना हमें विनम्र बनाती है, और यही अनुभूति हमें संपूर्णता की ओर ले जाती है।

जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम उसकी निरंतर बदलती लयों को स्वीकार कर सकें। सुख और दुख, उतार-चढ़ाव, हानि और लाभ- ये सब केवल अनुभवों की सीढ़ियां हैं, जो हमें आत्मिक ऊंचाई प्रदान करती हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति को समभाव से देखना सीख लेता है, वह बाहरी अशांति के बीच भी भीतर की शांति को संजो पाता है। संध्या का सौंदर्य इसी में निहित है कि वह दिन की थकान के बाद विश्राम देती है और आने वाले प्रभात का संकेत भी बनती है। जीवन भी ऐसा ही है अनश्वर, गतिशील और अनुभवों की ज्योति से आलोकित होता है।

सार्थक प्रयास

जीवन की सफलता किसी चमत्कार का परिणाम नहीं होती, बल्कि यह निरंतर किए गए प्रयासों का प्रतिफल होती है। जो व्यक्ति एक लक्ष्य निर्धारित कर दृढ़ता से उसकी ओर बढ़ता है, उसके मार्ग में चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों न आएं, वह अंततः सफलता का स्वाद अवश्य चखता है। इतिहास साक्षी है कि साधारण से दिखने वाले लोगों ने भी सतत प्रयास से असाधारण उपलब्धियां अर्जित की हैं। निरंतर प्रयास व्यक्ति के आत्मविश्वास को मजबूत करता है और उसे असफलताओं से उबरने का साहस देता है। असफलता जहां आलसी को निराश करती है, वहीं कर्मशील के लिए यह और अधिक मेहनत करने की प्रेरणा बन जाती है। जैसे नदी का बहाव कठोर चट्टानों को भी काट देता है, वैसे ही निरंतर अभ्यास और परिश्रम असंभव प्रतीत होने वाले कार्यों को संभव बना देते हैं। अवसरों की प्रतीक्षा करना निष्क्रियता है। अवसर भी उसी के पास आते हैं जो निरंतर स्वयं को तैयार रखता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने सपनों को पूरा करने के लिए धैर्य, लगन और सही दिशा में प्रयास करना चाहिए। यही सफलता का विश्वसनीय मार्ग है।

– अमन सिंह गौर, वाराणसी

एकाधिकार की प्रवृत्ति

भारतीय राजनीति में एकाधिकारवाद की प्रवृत्ति चिंता का विषय है। इसका आभास किसी भी राज्य के विधानसभा या लोकसभा चुनाव के समय आसानी से हो जाता है। दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रवृत्ति का संज्ञान आमतौर पर नहीं लिया जाता है। दूसरी ओर प्रत्याशी बनने की चाहत या यों कहें जीत की संभावना में एक राजनीतिक वर्ग द्वारा विभिन्न दलों का दामन थामने का सिलसिला देखा जा सकता है। पिछले कुछ दशकों से इसके बदस्तूर जारी रहने से पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता मुंह ताकते रह जाते हैं या वे भी नए ठौर-ठिकाने की तलाश में लग जाते हैं। अब सवाल यह है कि इसका संसदीय लोकतंत्र पर क्या और कैसा प्रभाव पड़ता होगा। इसकी पड़ताल जरूरी है। कुछ लोगों का मानना है कि इस अपसंस्कृति के चक्कर में एक खास राजनीतिक वर्ग हमेशा सत्ता में बना रहता है। नतीजतन यह वर्ग समावेशी नहीं हो पाता है। कुछेक वर्गों और जातियों का प्रभुत्व लोकतंत्र के लिए घातक है।

– मुकेश कुमार मनन, पटना

रफ्तार पर लगाम

'हादसे की रफ्तार' (संपादकीय, 17 सितंबर) पढ़ा। अपने देश में गाड़ियों की रफ्तार पर निगरानी के लिए कुछ जगहों पर कैमरे लगे दिखते तो हैं, लेकिन सख्ती से निगरानी की कोई व्यवस्था नहीं है। नतीजा यह कि लोग बेतहाशा गाड़ियां चलाते हैं और दूसरों की जान संकट में डाल देते हैं। उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सड़क हादसों के आंकड़े डराते हैं। वर्ष 2022 में 1.68 लाख, तो 2023 में 1.72 लाख व्यक्तियों की दुर्घटनाओं में जान गई। उल्लेखनीय है कि इनमें 68 फीसद लोगों की मौत तेज रफ्तार के कारण ही हुई है। हाल ही में दिल्ली छावनी मेट्रो स्टेशन के पास तेज रफ्तार से आ रही कार ने एक सरकारी अधिकारी की जान ले ली। इसी तरह इंदौर में भी तेज रफ्तार ट्रक ने पंद्रह लोगों को कुचल दिया। जिससे तीन लोगों की मौत हो गई, वहीं बारह लोग घायल हो गए। निस्संदेह तेज रफ्तार पर लगाम लगाने की जरूरत है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर किसी को भी न बख्शा जाए।

– बीएल शर्मा 'अकिंचन' उज्जैन

नापसंदगी का आधार

आतंकी हमले के बाद से भारत पाकिस्तान संबंधों में काफी खटास आ गई है। आज हर भारतीय यही चाहता है कि पाकिस्तान जब तक हमारे देश में आतंकवादी गतिविधियां चलाता रहेगा, तब तक उसके साथ कोई भी व्यापार नहीं हो और न ही किसी भी तरह का कोई संबंध रखा जाए। इसलिए कोई नहीं चाहता है कि भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेले। फिर भी हमारी टीम को पाकिस्तान के साथ दुबई में क्रिकेट खेलना पड़ा। चूंकि ज्यादातर लोग इस बात के खिलाफ थे, इसलिए दर्शकों की संख्या कम रही। वैसे आमतौर पर देखा जाता है कि भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच के दौरान बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचते हैं। पिछली चैम्पियन ट्राफी में इन दोनों के मैच को रेकार्ड संख्या में दर्शकों ने देखा था। मगर पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान का विरोध अब भी जारी है। दर्शक पाकिस्तान को पसंद नहीं करते।

– मनमोहन राजावतराज, शाजापुर

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

{ संपादकीय }

नई दिल्ली, शुक्रवार 19 सितम्बर 2025
संस्थापक-सम्पादक : स्व. मायाराम सुरजन

राहुल गांधी की दूसरी प्रेस कांफ्रेस, कुछ नए सवाल

कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को एक प्रेस कांफ्रेस में फिर से वोट चोरी और चुनावी धांधली के नए सबूत पेश किए हैं। बुधवार शाम को जब सूचना आई कि श्री गांधी 18 सितंबर की सुबह प्रेस कांफ्रेस करने वाले हैं, तो कयास लगने की लगे कि 1 सितंबर को जिस हाईड्रोजन बम का डर उन्होंने भाजपा को दिखाया था, वो फूटने वाला है। लेकिन प्रेस कांफ्रेंस शुरु होते ही राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि यह हाइड्रोजन बम नहीं है, हाइड्रोजन बम आने वाला है। यह इस देश के युवाओं को यह दिखाने और स्थापित करने में एक और मील का पत्थर है कि चुनावों में किस तरह धांधली की जा रही है।

गौर करने की बात है कि राहुल गांधी ने इस बार प्रेस कांफ्रेस में युवाओं को संबोधित किया है, क्योंकि इस देश का लोकतंत्र अब युवाओं को ही संभालना है। इसलिए उन्हें न केवल चुनावी प्रक्रिया की जानकारी होनी चाहिए, बल्कि ये भी पता होना चाहिए कि इसमें किस किस्म की गड़बड़ी की जा सकती है। अभी यह कहना मुश्किल है कि कितने युवाओं ने इस प्रेस कांफ्रेस को देखा और राहुल गांधी की बात को समझा है। लेकिन देश का युवा राहुल गांधी के दिखाए सबूतों के आधार पर अगर मोदी सरकार से और चुनाव आयोग से सवाल करने लग जाए तो फिर ऐसी धांधलियों पर काफी हद तक रोक लग जाएगी।

गुरुवार की प्रेस कांफ्रेस में राहुल गांधी ने एक बार फिर मुख्य चुनाव आयुक्त को भी कड़ी चेतावनी दी है कि आप को पद संभालते वक्त ली जाने वाली शपथ याद रखनी चाहिए। राहुल गांधी ने दावा किया कि उनकी पार्टी के समर्थक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने के प्रयास हुए और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 'लोकतंत्र की हत्या करने वालों' तथा 'वोट चोरों' की रक्षा कर रहे हैं। 'वोट चोरी' का काम मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार में संरक्षण हो रहा है।

बता दें कि 7 अगस्त की प्रेस कांफ्रेस में राहुल गांधी ने कर्नाटक की महादेवपुरा सीट पर कई नाम जोड़े जाने के सबूत पेश किए थे। लेकिन गुरुवार की प्रेस कांफ्रेस में राहुल गांधी ने बताया है कि कैसे मतदाता सूची से नाम काटे गए हैं और इसके लिए अलग-अलग राज्यों से फोन नंबर का इस्तेमाल हुआ है। राहुल गांधी प्रेस कांफ्रेस में ऐसे लोगों को लेकर भी आए जिनके नाम से वोट काटे गए। इन्हीं में से एक शख्स ने बताया कि उनके नाम से 12 वोट काटे गए, जबकि उन्होंने कभी ऐसा किया ही नहीं। दो शख्स और आए, जिनमें एक का नाम सूची से काटा गया था और दूसरे ने नाम काटने की अर्जी दी थी। लेकिन असल में दोनों ही इस बात से अनजान थे कि उनके नाम पर ऐसा कुछ हुआ है। एक दिलचस्प उदाहरण भी राहुल गांधी ने दिया कि एक शख्स ने सुबह चार बजे उठकर दो अर्जियां दाखिल कीं और दोनों ही महज 36 सेकंड में दाखिल की गईं। यानी आधे मिनट में दो-दो आवेदन दिए गए वो भी सुबह 4 बजे, जिस पर एकबारगी यकीन नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसा हुआ है और इस सबके पीछे बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है।

राहुल गांधी के मुताबिक योजना बनाकर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है। जिस बूथ पर कांग्रेस वोटर ज्यादा हैं, वहीं वोट काटा जा रहा है। कर्नाटक की ही आलंद विधानसभा का प्रमाण देते हुए चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि आलंद में किसी ने 6,018 वोट हटाने की कोशिश की। हमें यह नहीं पता कि 2023 के चुनाव में कुल कितने वोट हटाए गए हैं, लेकिन इतना तय है कि यह संख्या 6,018 से कहीं ज़्यादा थी। राहुल ने बताया कि यह मामला तब सामने आया जब गलती से एक वोट डिलीट करने के दौरान गड़बड़ी पकड़ में आ गई। दरअसल, एक बूथ-लेवल अधिकारी ने देखा कि उसके चाचा का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। जब उसने जांच की कि यह वोट किसने डिलीट किया, तो पता चला कि उसका ही पड़ोसी जिम्मेदार दिखाया गया है। लेकिन जब उसने अपने पड़ोसी से बात की, तो उसने साफ कहा कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। यानी जिसने वोट हटाया और जिसका वोट हटा- दोनों ही इस बात से अनजान थे।

राहुल गांधी ने कहा कि इस मामले में जांच चल रही है। सीआईडी ने 18 महीने में 18 पत्र चुनाव आयोग को भेजे हैं और पूछा कि हमें डेस्टिनेशन आईपी दीजिए, डिवाईस डेस्टिनेशन के बारे में जानकारी दीजिए, इसके अलावा ओटीपी ट्रेल को भी देने के लिए कहा। कर्नाटक की सीआईडी ने कई बार इसकी मांग चुनाव आयोग से की। लेकिन उस पर चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। लेकिन गुरुवार की प्रेस कांफ्रेस के कुछ देर बाद ही चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के दावों के स्क्रीन शॉट पर गलत का ठप्पा लगा दिया और कहा कि आरोप गलत और निराधार हैं। आयोग ने अपने बचाव में कहा कि किसी भी वोट को ऑनलाइन किसी के भी द्वारा नहीं हटाया जा सकता, जैसा कि राहुल गांधी ने गलत धारणा बनाई है। प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना कोई भी वोट नहीं हटाया जा सकता।

लेकिन आयोग के इन दावों की व्यावहारिक हकीकत देश जानता है। कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जब किसी को जानकारी दिए बिना, या उसकी सुनवाई के बिना ही वोटर लिस्ट से नाम काटा गया है। बहरहाल चुनाव आयोग ने ये भी कहा कि 2023 में अलंद विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं के नाम हटाने के कुछ असफल प्रयास किए गए थे और मामले की जाँच के लिए चुनाव आयोग के प्राधिकारी द्वारा स्वयं एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। लेकिन चुनाव आयोग ने अब भी ये नहीं बताया कि सीआईडी कर्नाटक के 18 अलग-अलग मौकों पर जो जानकारी मांगी, वो क्यों नहीं दी गई। इसी तरह प्रेस कांफ्रेस में कुछ खास लोगों ने यह दावा कैसे किया कि उनके नाम का दुरुपयोग करके नाम हटाए गए, और उन्हें पता ही नहीं चला। क्या चुनाव आयोग यह मानता है कि राहुल गांधी के साथ-साथ उन लोगों ने भी गलत जानकारी दी। अगर ऐसा है तो क्या कोई कार्रवाई की जाएगी। और सबसे आखिरी सवाल जब बार-बार चुनाव आयोग पर उंगली उठ रही है, तो क्या यह बेहतर नहीं होगा कि ज्ञानेश कुमार इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए खुद आगे आएं। बार-बार भाजपा उनके बचाव में क्यों खड़ी हो रही है।

संघ का नया चुनावी युद्धघोष-घुसपैठियों का खतरा!

आने वाले चुनावी सीजन के लिए, भाजपा-आरएसएस ने विपक्ष के खिलाफ अपना मुख्य नैरेटिव तय कर लिया लगता है। पहले, असम में दारांग जिले के मंगलडोई में और उसके अगले ही दिन, बिहार में पूर्णिया में प्रधानमंत्री मोदी ने ''विकास'' के अपने दावों के अलावा, जो राजनीतिक संदेश दिया, वह इसी का संकेत करता है। असम में प्रधानमंत्री ने दावा किया कि देश के सीमावर्ती इलाकों में, आबादी का गठन बदलने का षडयंत्र रचा जा रहा है। और प्रधानमंत्री के अनुसार इस षडयंत्र को ''घुसपैठियों'' के जरिए अंजाम दिया जा रहा है। अगले ही दिन, पूर्णिया में अपनी सभा में प्रधानमंत्री ने ''घुसपैठियों'' के खतरे का अपना आख्यान दोहराया। यही नहीं यहां प्रधानमंत्री ने असम तथा बिहार के साथ, बंगाल के लिए भी इसे गंभीर खतरा बता दिया। और इस खतरे में भावनात्मक छोंक लगाते हुए, उन्होंने ''बहन-बेटियों की सुरक्षा'' के लिए खतरे की दुहाई दे डाली। याद दिला दें कि कथित घुसपैठियों से बहन-बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरे की ठीक इसी दुहाई का, प्रधानमंत्री मोदी ने ही बिहार की तरह ही बंगाल से ही लगती हुई सीमा वाले एक और राज्य, झारखंड में विधानसभाई चुनाव में पूरा जोर लगाकर इस्तेमाल किया था। यह दूसरी बात है कि उसके बावजूद जनता ने एक बार फिर भाजपा को राज्य में सत्ता से बाहर ही रखने का जनादेश दिया था।

जाहिर है कि संघ-भाजपा का यह चुनावी नैरेटिव उतना कथित ''घुसपैठियों'' के खिलाफ नहीं है, जितना कि भाजपा के राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ है। इसलिए, अपने असली निशाने के संबंध में किसी संदेह या दुविधा की गुंजाइश न छोड़ते हुए, प्रधानमंत्री ने असम में अपने भाषण में कहा कि वास्तव में सीमावर्ती इलाकों में यह षड्यंत्र वे लोग चला रहे थे, जो घुसपैठियों को शरण देने पर आमादा थे। यहां से एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने असम में अपनी मुख्य राजनीतिक विरोधी, कांग्रेस पर और पहले की कांग्रेसी सरकारों पर, इन घुसपैठियों को बचाने तथा उनकी हिमायत करने का आरोप जड़ दिया। प्रधानमंत्री ने आगे यह भी कहा कि, ''कांग्रेस चाहती है कि घुसपैठिए हमेशा के लिए भारत में बने रहें और उसका भविष्य तय करें।'' यानी खतरा इतना बड़ा है कि देश भविष्य ही घुसपैठिये तय करने लग जाएंगे।

''राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे'' के लबादे में, वास्तव में चुनावी द्वंद्व की अपनी इस प्रस्तुति में, प्रधानमंत्री मोदी अति-नाटकीयता का छोंक लगाना भी नहीं भूले। उन्होंने कहा, ''मैं (विरोधी) राजनीतिज्ञों से कहना चाहता हूं कि मैंने उनकी चुनौती स्वीकार कर ली है...लिखकर रख लीजिए। मैं देखूंगा कि कैसे तुम घुसपैठियों को बचाने के लिए अपनी ताकत लगाते हो और कैसे हम उन्हें निकालने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाते हैं। हो जाए मुकाबला। घुसपैठियों को बचाने वाले हार जाएंगे और मेरी बात लिखकर रख लीजिए, देश उन्हें माफ नहीं करेगा!'' इसके बाद तो सिर्फ भाजपा के लिए वोट मांगना ही बाकी रह जाता था।

उधर बिहार में पूर्णिया में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने स्वाभाविक रूप से घुसपैठियों की हिफाजत करने के दोषियों का अपना दायरा बढ़ा दिया और कांग्रेस के साथ ही राष्ट्रीय जनता दल को घुसपैठियों को ''लंबे समय से'' संरक्षण दे रहे होने का दोषी ठहरा दिया। उन्होंने चुनौती की मुद्रा में कहा, ''लेकिन, उन्हें बाहर निकालना एनडीए की जिम्मेदारी है'' और यह भी जोड़ा कि ''घुसपैठियों को संरक्षण देने वाले नेता कान खोलकर सुन लें, हम उन्हें बाहर भेजना जारी रखेंगे। हमने जनसांख्यिकीय आयोग के गठन का एलान कर दिया है।'' इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी यह कहकर इस खतरे को अखिल भारतीय खतरा बनाने की कोशिश करना नहीं भूले कि, ''बिहार, बंगाल, असम के लोग अपनी बहन-बेटियों की सलामती और सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं।''

राजेंद्र शर्मा

> ''राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे'' के लबादे में, वास्तव में चुनावी द्वंद्व की अपनी इस प्रस्तुति में, प्रधानमंत्री मोदी अति-नाटकीयता का छोंक लगाना भी नहीं भूले। उन्होंने कहा, ''मैं (विरोधी) राजनीतिज्ञों से कहना चाहता हूं कि मैंने उनकी चुनौती स्वीकार कर ली है...लिखकर रख लीजिए। मैं देखूंगा कि कैसे तुम घुसपैठियों को बचाने के लिए अपनी ताकत लगाते हो और कैसे हम उन्हें निकालने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाते हैं।

जाहिर है कि आने वाले दिनों में हमें प. बंगाल में भी घुसपैठियों के खतरे की यह कहानी बार-बार सुनने को मिलेगी। हां! प. बंगाल में इसे कुछ अलग ढंग से जरूर पेश किया जा रहा होगा। आखिरकार, प. बंगाल में बांग्लादेश से समय-समय पर आए ऐसे हिंदू प्रवासियों की भी बहुत बड़ी संख्या है, जिनकी नागरिकता का मुद्दा, आम राजनीतिक सर्वानुमति होने के बावजूद, तरह-तरह के तकनीकी कारणों से लटका रहा है। प. बंगाल में घुसपैठियों के खतरे का शोर मचाने में, उन्हें इन हिंदू प्रवासियों को बचाने का खास ध्यान रखना होगा। वर्ना ''बांग्लादेशी घुसपैठियों'' के खतरे के नाम पर गोलबंदी, तो संघ-भाजपा के लिए राजनीतिक रूप से उल्टी ही पड़ जाएगी। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और एनआरसी के बीच, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कुख्यात रूप से जिस ''क्रोनोलॉजी'' पर जोर दिया था, वह इसी पैंतरे को साधने की कोशिश का हिस्सा था।

ऐसा लगता है कि संघ-भाजपा को अपनी मुस्लिम विरोधी गोलबंदी और उसके आधार पर ध्रुवीकरण की मुहिम के लिए एक और नारा मिल गया है। जाहिर है कि इस सिलसिले में तो वे कभी किसी भ्रम की गुंजाइश नहीं छोड़ते हैं कि जब वे घुसपैठ की बात करते हैं, घुसपैठ के जरिए आबादी का गठन बदले जाने की बात करते हैं और इस तरह घुसपैठ से सामाजिक ताने-बाने से लेकर, राष्ट्र की सुरक्षा तक खतरे में पड़ जाने की बात करते हैं, तो वे सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों की और उसमें भी खासतौर पर मुसलमानों की आबादी बढ़ने की ही बात कर रहे होते हैं। इस संबंध में अगर कोई अस्पष्टता रही भी होगी तो नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) बनाए तथा लागू किए जाने के बाद दूर हो चुकी है, जो कानूनी तौर पर बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आदि, पड़ौसी देशों से अवैध रूप से आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को छांटकर उनके लिए नागरिकता का रास्ता खोलता है। इस कानून से संबंधित नियमों में ताजातरीन संशोधनों के जरिए, अब 2024 के अंत में आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों तक के लिए नागरिकता का यह रास्ता खोल दिया गया है। यह ''घुसपैठिया'' शब्द को मुस्लिम प्रवासी का समानार्थी ही बना देता है। आबादी के गठन में ठीक ऐसी ही घुसपैठ से होने वाले बदलाव को वे हिंदुओं के लिए ही नहीं, राष्ट्र के लिए भी खतरे की तरह पेश करते हैं। जनसांख्यिकीय आयोग के गठन का मोदी सरकार का एलान, खतरे के ठीक इसी दावे को देश की सरकार की नीति और कदमों के स्तर तक पहुंचा देता है।

उक्त आयोग चूंकि सबसे बढ़कर, बदले हुए नाम से मुस्लिम खतरे के प्रोपेगंडा का ही औजार है, इसलिए हैरानी की बात नहीं है कि 15 अगस्त के लालकिले से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी के इस आयोग का गठन की घोषणा करने के बाद गुजरे महीने भर में, इस संबंध में आगे कुछ किए जाने की कोई खबर नहीं आयी है। न इस आयोग की संरचना के बारे में, न उसकी कार्यप्रणाली या कार्य क्षेत्र के बारे में, देश को कुछ भी बताया गया है। बस प्रधानमंत्री की औपचारिक-अनौपचारिक चुनावी सभाओं में, इस आयोग के गठन की बात को दोहराया जा रहा है। फिलहाल इस आयोग के नाम का इस्तेमाल इस धारणा की पुष्टि के लिए किया जा रहा है कि राष्ट्र के लिए, यह कोई वास्तविक खतरा खड़ा हो गया है। दूसरे, इसके नाम का इस्तेमाल इस धारणा से प्रभावितों यानी हिंदुत्व समर्थकों को इसका भरोसा दिलाने के लिए किया जा रहा है कि मोदी सरकार, इस खतरे से निपटने के लिए सक्रिय तरीके से काम कर रही है।

इस पूरे मामले का सबसे बेढ़ब पहलू यह है कि यह सब कोरे प्रोपेगंडा से बनी और लगातार बनायी जा रही धारणाओं का मामला है। बेशक, यह प्रोपेगंडा इतना ज्यादा सघन और तीव्र है कि बढ़ती संख्या में लोग इन धारणाओं के शिकार होते गए हैं। लेकिन, यह प्रोपेगंडा तथ्यों के मामले में करीब पूरी तरह से अंधेरे में ही संचालित किया जाता रहा है। वास्तव में इसके कोई तथ्यात्मक साक्ष्य हैं ही नहीं कि सीमावर्ती इलाकों में, आबादी के सामुदायिक अनुपात में कोई असामान्य बदलाव आए हैं। लेकिन, यह प्रचार बदस्तूर जारी है और जैसा कि हमने पीछे कहा, अब देश की सरकार की नीति और कदमों के स्तर पर भी पहुंच गया है।

''घुसपैठियों के खतरे'' के नारे के इस तरह सरकार की नीति के स्तर तक पहुंचने की यह यात्रा भी काफी शिक्षाप्रद है। हमारे देश में बहुसंख्यकवादी सांप्रदायिक प्रचार में यह धारणा तो बहुत पहले से चली आ रही थी कि मुसलमान बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। शिक्षित, सवर्ण, संपन्न हिंदू, यह तुलना करते हुए, इस मामले अन्य गैर-मुस्लिम अशिक्षित, गरीबों की स्थिति की ओर से आसानी से आंखें मूंद लेते थे और इस तरह ज्यादा संतानें पैदा करने का संबंध, अशिक्षा और गरीबी से काटकर, आधे-अधूरे तरीके से धर्म से जोड़ देते थे। यह इसके बावजूद था कि जनगणना के आंकड़े, आबादी के बारे में कुछ और कहानी कह रहे थे। इस कहानी का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि भारत में शिक्षा के प्रसार के साथ आबादी में वृद्धि की रफ्तार सभी समुदायों के लिए तेजी से घटती जा रही है और मुसलमानों के मामले में हिंदुओं से भी तेजी से घट रही है। इसके अकाट्य साक्ष्यों के सामने, सांप्रदायिक प्रोपेगंडा में थोड़ा बदलाव कर अब इसे आम तौर पर आबादी बढ़ने से खतरे के बजाए, खासतौर पर ''घुसपैठ से मुस्लिम आबादी बढ़ने के खतरे'' में तब्दील कर दिया गया है। यह दिखाता है कि सांप्रदायिक प्रोपेगंडा, सिर्फ प्रचार और पूर्वाग्रहों के बल पर, अपने लक्ष्य समुदाय के लिए हवा में से खतरे का भूत खड़ा कर सकता है।

हाल के दौर में संघ-भाजपा के इस प्रोपेगंडा को नये चरण में पहुंचाते हुए, देश के विभिन्न हिस्सों में खासतौर बंगाली मुस्लिम मजदूरों पर हमलों से लेकर उनकी पकड़-धकड़ तथा जबरन बांग्लादेश में धकेले जाने तक की कार्रवाइयां शुरू कर दी गयीं। उसके बाद, प्रधानमंत्री ने लाल किले से अपने भाषण में आबादी के गठन में बदलाव के खतरे का मुद्दा उठा दिया और डेमोग्राफी आयोग के गठन का एलान कर दिया। उसके बाद आरएसएस ने जोधपुर में हुई अपने आनुषांगिक संगठनों की सालाना बैठक में, घुसपैठ के खतरे को सांप्रदायिक प्रचार का मुख्य नारा बनाने की पुष्टि कर दी। अब प्रधानमंत्री ने इसे युद्धघोष के रूप में चला दिया है।

(लेखक साप्ताहिक पत्रिका लोक लहर के संपादक हैं।)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लुभाने के लिए ब्रिटिश शाही तामझाम

■ अंजन रॉय

ब्रिटेन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत और उन्हें लुभाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। ट्रंप वर्तमान में राजा चार्ल्स के निमंत्रण पर राजकीय अतिथि के रूप में ब्रिटेन के दौरे पर हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का स्वागत विंडसर किले स्थित 900 साल पुराने शाही घर में किया जा रहा है, जहां वह रात्रि विश्राम करेंगे।

शुरू से ही, ब्रिटिश सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति को प्रभावित करने के लिए अपने रविवार के सर्वश्रेष्ठ परिधान पहनने की कोशिश कर रही थी। प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर ने ओवल ऑफिस में प्रेस की मौजूदगी में निमंत्रण पत्र सौंपा, जिसमें कहा गया था कि यह ब्रिटिश राजा का पत्र है।

राजा के निमंत्रण से लेकर अतिथि गणमान्य अतिथि के स्वागत तक, ब्रिटेन ट्रंप को प्रभावित करने, उन्हें अपने साथ कुछ व्यापारिक समझौते करने के लिए राजी करने और उस बात को मज़बूत करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है जिस पर ब्रिटेन ज़ोर देते हुए कभी नहीं थकता -वह है इंग्लैंड और अमेरिका के बीच 'विशेष संबंध'।

युद्धकालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र देशों की सेना के एक प्रमुख सदस्य के रूप में अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूज़वेल्ट को शामिल करने के लिए इसका भरपूर इस्तेमाल किया था। रूज़वेल्ट थोड़े उदासीन थे और चर्चिल की विभिन्न हरकतों के प्रति ज़्यादा उदार नहीं थे।

अब, जब यूरोप में स्थिति गंभीर होती जा रही है और पूरा पश्चिमी यूरोप रूसी सैन्य बल की तपिश महसूस कर रहा है, ब्रिटेन डोनाल्ड ट्रंप को रूस के साथ अपने रिश्ते को और भी सक्रिय बनाने के प्रयासों का नेतृत्व कर रहा है। इसके अलावा, ब्रिटेन अब वह आर्थिक शक्ति नहीं रहा जो वह पहले हुआ करता था और अब अपने आर्थिक कायाकल्प के लिए अमेरिका के साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है।

हालांकि, ये बातें बाद में होंगी जब अमेरिकी राष्ट्रपति ब्रिटिश प्रधानमंत्री के कंट्री हाउस, द चेकर्स का दौरा करेंगे, जहां दोनों देशों के बीच कुछ व्यापारिक समझौतों और तकनीकी सहयोग पर चर्चा होनी है। इस अमेरिकी उदारता का आधार विंडसर पैलेस और उसके प्रांगण में ब्रिटिशों द्वारा की जाने वाली कुछ भव्यता और दिखावटी शान-शौकत की पेशकश करके तैयार किया जा रहा है।

लेकिन जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति महल के प्रांगण में उतरेंगे, डोनाल्ड ट्रम्प एक घोड़े से खींची जाने वाली राजकीय गाड़ी में सवार होंगे और तोपों की सलामी होगी और एक घुड़सवार उन्हें महल के प्रवेश द्वार तक ले जाएगा जहां वेल्स के राजकुमार और राजकुमारी उनका स्वागत करेंगे। उनकी इस संक्षिप्त यात्रा के दौरान, शाही बैंड स्कॉटिशहाइलैंड लेडी और अन्य धुनें बजाते रहेंगे।

यह पूरा तामझाम ट्रम्प के स्कॉटिश वंश को ध्यान में रखकर आयोजित किया गया है। जहां तक उनकी स्मृतियों का सवाल है, ट्रम्प ने याद किया था कि कैसे उनकी मां महारानी एलिजाबेथ के राज्याभिषेक को मंत्रमुग्ध होकर देख रही थीं और उनके पिता ने उनसे बार-बार उनके लिए यह उबाऊ शो बंद करने के लिए कहा था। हालांकि, जब से डोनाल्ड ने अपनी मां से प्रेरणा ली है, तब से वह ब्रिटिश शाही परिवार और उनके तौर-तरीकों से हमेशा मोहित रहे हैं।

राजपरिवार अपने कला संग्रह की कुछ वस्तुओं का प्रदर्शन करेगा, और संभवत: औपनिवेशिक लूटपाट के दौरान भारत और अन्य देशों से चुराई गई कई वस्तुओं का भी। गौरतलब है कि जब रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड लौटे थे, तो उनके धन के प्रदर्शन ने ब्रिटिश लॉर्ड्स को निराश कर दिया था।

दुर्व्यवहार के लिए बाद में उन पर महाभियोग लगाया गया जिस दौरान क्लाइव ने कथित तौर पर कहा था कि बंगाल के खजाने में देखे गए अपार खजाने को देखते हुए, वह चोरी में 'अपनी संयमशीलता पर आश्चर्यचकित' थे। उच्च सदन के लॉर्ड्स इस उत्तर से इतने प्रभावित हुए कि क्लाइव को लॉर्डशिप का पद दिया गया और बाद में उन्हें 'भारत का लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव' कहा गया।

उन खजानों में से कई विंडसर कैसल और अन्य जगहों के शाही संग्रहालयों में रखे गए होंगे, जहां उसे अक्सर आने वाले गणमान्य व्यक्तियों को दिखाया जाता था।

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समय में, वेल्स के राजकुमार रहते हुए, वर्षों पहले अपने स्वर्णिम रिसॉर्ट मार-ए-लागो में वर्तमान राजा और वेल्स की प्रिंसेज का स्वागत किया था। हालांकि, उस समय राजकुमार चार्ल्स ने शाही परिवार के घोड़ों के प्रति प्रेम को देखते हुए, गोल्ड क्लब की बजाय पास के एक घुड़दौड़ फार्म में रात बिताना पसंद किया था।

बेशक, ट्रंप को महल के प्रांगण में घुड़सवारी का वह आनंद नहीं मिलेगा जैसा कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति (रोनाल्डरीगन) को ब्रिटेन की अपनी यात्रा के दौरान महारानी एलिजाबेथ के साथ मिला था।

फिर भी, राष्ट्रपति का वर्तमान दौरा भी भटक सकता है। बाल यौन शोषण मामले में, बेहद चर्चित एपस्टीन के साथ घनिष्ठ संबंधों के कारण, अमेरिका में ब्रिटिश राजदूत लॉर्ड पीटर मैंडेलसन को अचानक बर्खास्त किए जाने से पहले ही माहौल खराब हो चुका था। लॉर्ड मैंडेलसन ने ही सबसे पहले ट्रंप की दूसरी राजकीय यात्रा का प्रस्ताव रखा था ताकि उन्हें ब्रिटेन का समर्थन करने के लिए राजी किया जा सके।

यह निश्चित रूप से शर्मनाक होगा कि एक राजदूत को उस संबंध के लिए बेरहमी से अपमानित किया गया और वापस बुलाया गया, जिसके बारे में यह साबित हो चुका है कि राष्ट्रपति भी उससे जुड़े थे। यात्रा के अंत में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में एपस्टीन प्रकरण पर कुछ सवाल शाही स्वागत के पूरे आकर्षण को बिगाड़ सकते हैं और इसे और भी उलझा सकते हैं। चंचल ट्रम्प बिल्कुल अलग मूड में हैं।

ब्रिटिश लोग ट्रम्प के दिखावे और ब्रिटिश शाही परिवार के शौक़ को जानते हैं। वे उसी का फ़ायदा उठा रहे हैं। इसका सबसे सटीक उदाहरण होगा उड़ाया गया गुब्बारा जब वह पिछली बार वह ब्रिटेन आए थे,जिसमें ट्रम्प को डायपर पहने दिखाया गया था।

> यह निश्चित रूप से शर्मनाक होगा कि एक राजदूत को उस संबंध के लिए बेरहमी से अपमानित किया गया और वापस बुलाया गया, जिसके बारे में यह साबित हो चुका है कि राष्ट्रपति भी उससे जुड़े थे। यात्रा के अंत में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में एपस्टीन प्रकरण पर कुछ सवाल शाही स्वागत के पूरे आकर्षण को बिगाड़ सकते हैं और इसे और भी उलझा सकते हैं। चंचल ट्रम्प बिल्कुल अलग मूड में हैं।

आपके पत्र

टिटहरी: प्रकृति की मौन चेतावनी

भारत का ग्रामीण जीवन सदियों से प्रकृति के साथ गहरे संवाद में रहा है। खेत, मौसम और जीव-जंतु मिलकर किसान की दिनचर्या और भविष्य दोनों को प्रभावित करते हैं। इन सबके बीच टिटहरी एक ऐसा छोटा-सा पक्षी है, जो सामान्य आंखों से मामूली दिखता है, लेकिन किसानों और लोकजीवन की स्मृतियों में यह मौसम की सटीक भविष्यवाणी करने वाला प्रहरी माना जाता है। यह केवल एक पक्षी नहीं, बल्कि धरती और आकाश के बीच संवाद का माध्यम है, एक मौन दूत है जो संकट और समृद्धि दोनों की आहट पहले ही दे देता है।

ग्रामीण अनुभव बताते हैं कि टिटहरी का व्यवहार मौसम और कृषि की दिशा तय करने में अहम संकेत देता है। यदि वह चार अंडे देती है तो चार महीने अच्छी वर्षा होने का विश्वास किया जाता है। जब वह ऊंचाई पर अंडे देती है, तो लोग मानते हैं कि सामान्य से अधिक वर्षा होगी। यदि कभी वह मजबूरी में छत या पेड़ पर अंडे दे, तो यह भीषण बाढ़ का संकेत माना जाता है। वहीं, यदि वह अंडे न दे तो यह सबसे डरावनी स्थिति होती है, क्योंकि लोग इसे अकाल का दूत मानते हैं। किसान कहते हैं कि जिस खेत में टिटहरी अंडे देती है, वह खेत खाली नहीं रहता। वहां फसल जरूर होती है। इस तरह यह पक्षी न केवल वर्षा और मौसम से जुड़े संकेत देता है बल्कि उपजाऊपन और अकाल जैसी चरम स्थितियों की चेतावनी भी बन जाता है।

लोकजीवन में एक और मान्यता है कि टिटहरी का मृत शरीर कुरुक्षेत्र के अलावा कहीं दिखाई नहीं देता। चाहे यह तथ्य हो या प्रतीकात्मक कल्पना, लेकिन यह विश्वास उसे जीवन और अस्तित्व की रक्षा का प्रतीक बना देता है। टिटहरी को देखने वाला किसान समझ जाता है कि यह पक्षी उसकी मिट्टी, फसल और भविष्य का पहरेदार है। यही कारण है कि ग्रामीण लोकगीतों और कहावतों में भी टिटहरी का उल्लेख मिलता है। यह उन जीवों में से है जिनकी गतिविधियों पर पीढ़ियां भरोसा करती रही हैं।

अब सवाल उठता है कि जब विज्ञान मौसम की भविष्यवाणी के लिए उपग्रह, राडार और कंप्यूटर मॉडल जैसे अत्याधुनिक साधन लेकर आया है, तब टिटहरी जैसे पक्षियों की भूमिका क्या रह जाती है। वास्तव में इसका उत्तर यही है कि विज्ञान और लोकअनुभव एक-दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो टिटहरी जैसे पक्षी पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। हवा की नमी, तापमान का उतार-चढ़ाव, भूमि की नमी, जल स्तर का बढ़ना या घटना - इन सबका असर उनके व्यवहार पर पड़ता है। यही कारण है कि वैज्ञानिक भाषा में इन्हें 'इकोसिस्टम इंडिकेटर' कहा जाता है। यानी ऐसे जीव जो अपने आचरण के माध्यम से हमें पर्यावरणीय बदलावों की समय रहते जानकारी दे देते हैं।

टिटहरी के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह पक्षी खेत को कभी खाली नहीं छोड़ता। उसका वहां अंडे देना किसानों के लिए आश्वासन का प्रतीक है। यह विश्वास अपने आप में गहरा संदेश है कि प्रकृति मनुष्य को निराश नहीं करती, बशर्ते हम उसका सम्मान करें। लेकिन जब हम प्रकृति के नियम तोड़ते हैं, उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं, तब उसके प्रहरी पक्षी भी अपने संकेत बदलने को मजबूर हो जाते हैं। यही वजह है कि कई बार बाढ़ या अकाल जैसी स्थिति का पूर्वाभास हमें टिटहरी के व्यवहार से पहले ही मिल जाता है।

निष्कर्ष यही है कि जहां विज्ञान आंकड़ों और मशीनों पर भरोसा करता है, वहीं टिटहरी जैसे पक्षी सहज चेतावनी देते हैं। विज्ञान देर से अलर्ट करता है, लेकिन टिटहरी पहले से सावधान कर देती है। हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हम इस मौन संवाद को सुनें और उसके अनुसार कदम उठाएं। यदि हमने इस आवाज़ को नज़रअंदाज़ किया, तो आने वाले समय में न केवल टिटहरी गायब हो जाएगी, बल्कि उसका दिया हुआ संदेश भी हमारे जीवन से खो जाएगा।

- डॉ. सत्यवान सौरभ

ललित सुरजन की कलम से

भगवत रावत की कवितायें

एक बड़ी मंचसिद्ध कलाकार महाभारत की पुनर्रचना कर रही है, लेकिन कवि धीरे से कहता है कि इसके बाद भी कुछ नहीं बदला और अदृश्य चौपड़ पर खेल अभी भी जारी है। यहीं भगवत रावत के व्यक्तित्व का एक और पहलू स्पष्ट होता है। एक तरफ कवि है, एक तरफ गायिका। वे दो कलाकारों के बीच एक आत्मीय संबंध जोड़ते हैं और उस अधिकार से तीजन बाई को इन पंक्तियों में सलाह देते हैं-

तुम दुनिया-जहान में घूम आना
गुंजा आना जगह-जगह अपना छत्तीसगढ़ी गाना
लेकिन उनके बीच जाना मत छोड़ना
जो तुम्हारा एक-एक बोल सच मानते हैं
जो न्याय और अन्याय
तुम्हारी ही बोली में
पहचानते हैं।

(अक्षर पर्व सितम्बर 2015 अंक की प्रस्तावना)

https://lalitsurjan.blogspot.com/2015/09/blog-post.html

पावन प्रसंग

व्यवहार की उत्प्रेरक हैं भावनाएं

भावना के अनुरूप ही दृष्टिकोण उपजता है और जैसा दृष्टिकोण बन जाता है, कालांतर में वैसी ही भावनाएं जन्मने लगती हैं। भावनाएं और दृष्टिकोण एक दूसरे के कारक भी हैं और परिणाम भी। दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। एक ही वस्तु के प्रति लोगों के भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण हो सकते हैं। भावनात्मक अस्थिरता से ही मनोविकृति पनपती है।

आजकल भावनाओं का उतार-चढ़ाव सुर्खियों में है। खासतौर पर घृणा, द्वेष, कुंठा जैसी भावनाएं और उनसे उपजती हिंसा चारों ओर उथल-पुथल मचाती नजर आ रही है। बच्चे से लेकर प्रौढ़ व्यक्ति तक अपने लिए हिंसा को संतुष्टि पाने का एक पक्का, सीधा और सरल तरीका मानकर अपनाते जा रहे हैं।

पहले अनैतिक घटनाएं कम घटती थीं, पर अब इनकी भरमार है और तो और धर्म का नाम लांछित करते हुए सारी शरम-हया छोड़ अनेक चतुर-चालाक लोग धर्म के संस्थागत रूप की आड़ में भावनाओं से खेलते हुए दु:खी, कठिनाई में पड़े व सुख की चाह रखने वाले लोगों का गिरोह बनाकर शोषण करते रहते हैं।

इन सब घटनाओं से जुड़े आंकड़ों पर विचार करें तो स्पष्ट हो जाता है कि इन सबमें अपने सुख के लिए 'दूसरों' को शारीरिक-मानसिक रूप से पीड़ा और हानि पहुंचाई जाती है। कोशिश यही रहती है कि किसी तरह अपने को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट किया जाए। इच्छाओं की इस छटपटाहट के लिए हमारे आस-पास का परिवेश उत्तेजना के अवसर भी खूब दे रहा है।

मीडिया और विज्ञान नित नए आकर्षणों के साथ असंतुष्टि और अतृप्ति के मनोभावों को सतत प्रसारित एवं प्रचारित करते रहते हैं। प्रभावशाली ढंग से बतलाते रहते हैं कि अमुक चीजों के अभाव में हम कुछ कमतर मनुष्य हैं, अधूरे हैं। ऐसे में हमारी परिस्थितियां खंडित या अपर्याप्त हैं, यह भाव हममें से अधिकांश के जीवन का स्थायी भाव बनता जा रहा है। पात्र हों या अपात्र इच्छा पूरी न हो तो सबमें कुंठा पैदा होती है। तब जिम्मेदार स्रोत के पति आक्रोश की तात्कालिक प्रतिक्रिया होती है।

हिंसा, लोभ, आसक्ति और भावनाओं के जोड़-तोड़ से सामाजिक जीवन में इस तरह की प्रवृत्ति बढ़ रही है। तीव्र भावनाएं हमारे निर्णय की क्षमता या विवेक को प्रभावित करती हैं। मुख्य रूप से भावनाओं या संवेगों को सकारात्मक और नकारात्मक, दो श्रेणियों में रखा जाता है। ये हमारे दैनिक जीवन में कई तरह के रंग भरते रहते हैं। संवेग कभी तटस्थ नहीं होते हैं।

दिन-प्रतिदिन का आकलन करें तो पता चलता है कोई व्यक्ति अपेक्षाकृत अधिक सकारात्मक या नकारात्मक दशाओं का अनुभव करता है। मानवीय संवेगों की अनुभूति घटनाओं की समझ या व्याख्या पर निर्भर करती है। परिस्थिति के आकलन के आधार पर ही भिन्न-भिन्न संवेगों का अनुभव किया जाता है। सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टि से विचार करें तो आचारों से जुड़े नैतिक संवेग अधिक महत्त्व पूर्ण होते हैं।

नैतिक संवेगों को हम बचपन से सीखते हैं, और वे सहजात जैसे हो जाते हैं। अपनी संस्कृति के अनुरूप हम परिस्थितियों के नैतिक पक्षक का मूल्यांकन करते हैं। जब नैतिक आत्मचेतना विकसित होती है, तो व्यक्ति स्वयं अपने व्यवहार को दंडित या पुरस्कृत करता है।

-अखण्ड ज्योति

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

प्रकाशक, मुद्रक : राजीव रंजन श्रीवास्तव द्वारा पत्रकार प्रकाशन प्रा. लि. के लिए 506, आई.एन.एस. बिल्डिंग, 9, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित एवं बीएफएल इंफोटेक लि., सी 9, सेक्टर-3, नोएडा से मुद्रित। सम्पादक : राजीव रंजन श्रीवास्तव, (पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार)। आर.एन.आई. नं. DELHIN/2008/24216. दिल्ली कार्यालय :फोन: 011-23718195,23357784, फैक्स: 011-43581404, नोएडा कार्यालय: फोन: 0120-4114404 फैक्स: 0120-4273770
ई-मेल: deshbandhudelhi@gmail.com वेब: www.deshbandhu.co.in

चिंतन

पाकिस्तान को लेकर हमेशा सतर्क रहने की जरूरत

पाकिस्तान हर संभव प्रयास कर रहा है कि किसी भी ढंग से भारत को घेरा जा सके। ऑपरेशन सिंदूर में बुरी गत बनने के बाद उसकी सक्रियता और ज्यादा बढ़ गई है। वो कभी अमेरिका की जी हुजूरी करता है तो कभी बांग्लादेश को अपने पक्ष में करने की जुगत भिड़ाता है। महज कुछ ही दिन पहले मुस्लिम देशों को नाटो जैसा संगठन बनाने की वकालत करने वाले पाकिस्तान ने अब सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत किसी एक पर कोई भी हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच डिफेंस कॉर्पोरेशन भी डेवलप किया जाएगा। समझौते के तहत मिलिट्री सहयोग किया जाएगा। इसमें जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी शामिल है। वैसे तो सऊदी अरब और पाकिस्तान पुराने दोस्त हैं। सऊदी अरब को पाकिस्तान का एटीएम भी कहा जाता है। पाक जब भी कंगाली की हालत में होता है, सबसे पहले सऊदी अरब के सामने ही हाथ फैलाता है। यह रक्षा समझौता ऐसे समय हुआ है, जब खाड़ी के अरब देश लंबे समय के सुरक्षा गारंटर के रूप में अमेरिका की विश्वनीयता पर संदेह जता रहे हैं। पिछले हफ्ते कतर पर इजरायली हमले ने इन देशों की चिंताओं को और बढ़ा दिया है। जिस वक्त इस रक्षा समझौते पर साइन किए जा रहे थे, तब पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसीम मुनीर भी वहां मौजूद थे। आपरेशन सिंदूर के बाद मुनीर को पाकिस्तान का सबसे शक्तिशाली इंसान माना जा रहा है और वो लगातार इस समझौते को करवाने की कोशिशों में जुटे थे। क्योंकि वह जानते हैं कि भारत को उनकी सेना अकेले दम पर हराना तो बहुत दूर की बात है, मुकाबले में खड़ी भी नहीं हो सकती। आपरेशन सिंदूर के दौरान महज 48 घंटे में ही उसे युद्ध रोकने की गुहार लगानी पड़ी थी। इसीलिए वो एक ऐसे मजबूत कंधे की तलाश में थे, जिसके सहारे भारत के कोप से बचा जा सके। भारत के साथ-साथ इस समझौते को कतर में किए गए इजरायली हमले को भी कारण माना जा रहा है। 14 सितंबर को दोहा में मुस्लिम देशों के कई नेता इजरायल के खिलाफ एक खास बैठक के लिए इकट्ठा हुए थे। यहां पाकिस्तान ने सभी इस्लामी देशों को नाटो जैसी जॉइंट फोर्स बनाने का सुझाव दिया था। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री मोहम्मद इशाक डार ने एक जॉइंट डिफेंस फोर्स बनाने की संभावना का जिक्र करते हुए कहा था कि न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान इस्लामिक समुदाय के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए इस समझौते के पीछे तात्कालिक क्षेत्रीय तनाव तो हैं ही, इसके साथ ही मुख्य प्रावधान किसी एक पर हमले को दोनों पर हमला मानना, औपचारिक गठबंधन संधियों में दी जाने वाली सुरक्षा गारंटी जैसा है। सऊदी अरब के लिए, यह अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के एक कदम का संकेत है। वहीं, पाकिस्तान को डर है कि भारत आतंकवाद के पोषक पाकिस्तान को सबक सिखाने से चूकने वाला नहीं है। पाक अब सऊदी को ढाल के रूप में इस्तेमाल भी करेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि पाक परमाणु शक्ति भी है, जिसकी विदेश नीति दबाव में तुरंत पलट सकती है। क्योंकि उसकी माली हालत अच्छी नहीं है। वो आर्थिक सहायता के बदले कुछ भी कर सकता है। हालांकि, पाकिस्तान सीधे तौर पर इजरायल या भारत पर हमले की हिमाकत शायद ही करे, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है कि उसका परिणाम क्या होने वाला है। फिर भी भारत को हमेशा सतर्क रहना होगा। क्योंकि पाक एक जहरीले सांप की तरह है, जिस पर कतई भरोसा नहीं किया जा सकता।

विश्लेषण
राज कुमार सिंह

'वैश्विक गांव' का बिखरता सपना

ब्रिटेन के लाखों मूल निवासी पिछले दिनों 'यूनाइट द किंगडम' के नारों के साथ प्रवासियों के विरुद्ध रैली निकालते नजर आए तो संदेश साफ है कि विश्व को एक गांव के रूप में देखने-दिखाने के सपने बिखरने लगे हैं। पिछली शताब्दी के अंतिम दशक में आर्थिक उदारीकरण के नाम पर वैश्विक गांव का नारा दिया गया था। तमाम देशों ने अर्थव्यवस्था ही नहीं, सोच-समझ की दृष्टि से भी अपने खिड़की-दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोल दिए। सत्ता राजनीति अपनी सुविधा के लिए इस तथ्य को छिपा जाती है कि कम वेतन पर स्थानीय पेशेवर न मिलने अथवा उतने कुशल स्थानीय पेशेवर न मिलने से ही प्रवासी पेशेवरों को इन देशों की कंपनियां नौकरी देती हैं, न कि धर्मार्थ भाव से।

कहावत है कि एक समय ब्रिटिश सत्ता में सूरज कभी नहीं डूबता था, अब उसी ब्रिटेन के लाखों मूल निवासी पिछले दिनों 'यूनाइट द किंगडम' के नारों के साथ प्रवासियों के विरुद्ध रैली निकालते नजर आए तो संदेश साफ है कि विश्व को एक गांव के रूप में देखने-दिखाने के सपने बिखरने लगे हैं। पिछली शताब्दी के अंतिम दशक में आर्थिक उदारीकरण के नाम पर वैश्विक गांव का नारा दिया गया था। भारत समेत तमाम देशों ने अर्थव्यवस्था ही नहीं, सोच और समझ की दृष्टि से भी अपने खिड़की-दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोल दिए। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों के दबाव में आर्थिक उदारीकरण को गति मिली, लेकिन सभी जानते हैं कि उसके मूल में अपने उत्पादों के लिए दुनिया भर के बाजार हासिल करने की अमेरिकी रणनीति काम कर रही थी। इसलिए भी, अमेरिका के वैचारिक विरोधियों ने अर्थव्यवस्था के उस उदारीकरण और वैश्वीकरण का विरोध किया।

कुछ परंपरागत क्षेत्रों पर नकारात्मक असर के अलावा उससे लाभ भी मिला, लेकिन साढ़े तीन दशक बाद अब विश्व व्यवस्था फिर वापस अपने-अपने दायरे में लौटने को बेताब दिख रही है। विडंबना यह कि इसकी शुरुआत भी अमेरिका से ही हुई। अमेरिका को फिर महान बनाने और अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने के नारे के साथ, चार साल के अंतराल के बाद, दूसरी बार राष्ट्रपति बनने में सफल रहे डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का भले ही अब अमेरिका में भी विरोध होने लगा हो, लेकिन 'स्थानीय बनाम प्रवासी' का मोर्चा खोलने की राजनीति यूरोप समेत दूसरे देशों में भी रंग दिखाने लगी है। ये पश्चिमी देश हर तरह के उदारीकरण के लिए जाने जाते रहे हैं। इसीलिए प्रवासियों की पसंद की सूची में ऊपर रहे हैं। प्रवासियों को वहां बेहतर जीवन स्तर मिलता है तो वे भी उनके सर्वांगीण विकास में अपना योगदान देते हैं। अब अचानक इन देशों को प्रवासी अपने मूल निवासियों और अंततः राष्ट्रीय हितों के लिए खतरा नजर आने लगे हैं। स्थानीयता और राष्ट्रवाद के नाम पर नागरिकों की भावनाएं भड़काने की राजनीति जांची-परखी है। इसलिए इसे आधार बना कर सत्ता-राजनीति की बिसात भी बिछायी जाने लगी है।

अगर अमेरिका सरीखे विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र और मजबूत अर्थव्यवस्था वाले उदार समाज में राष्ट्रवाद डोनाल्ड ट्रंप को दूसरी बार राष्ट्रपति बनवाने वाला 'ट्रंप कार्ड' बन सकता है तो फिर ब्रिटेन, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया समेत अन्य देशों के राजनेता उसे क्यों नहीं आजमाना चाहेंगे? ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में चुनाव भी होने वाले हैं। बेशक फ्रांस से लेकर ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया तक जनता के सड़कों पर उतरने के मूल में वहां की सरकारों की, जन आकांक्षाओं पर खरा उतरने में नाकामी तथा महंगाई, बेरोजगारी एवं खराब कानून व्यवस्था के चलते बढ़ती जीवन की मुश्किलें ही हैं, लेकिन ट्रंप के 'ट्रंप कार्ड' के बाद तमाम समस्याओं को स्थानीय बनाम प्रवासी का मुद्दा बना कर पेश करने की राजनीति जोर पकड़ रही है।

पिछले दिनों लंदन में प्रवासी विरोधी रैली का हिंसक हो जाना बताता है कि ये भावनाएं लगातार गहरा रही हैं। बेशक आर्थिक विकास की दौड़ में किसी देश के पिछड़ जाने या आगे निकल जाने का कोई एक कारण नहीं होता

और यह अचानक भी नहीं होता, पर महंगाई- बेरोजगारी के साथ-साथ अपराधों में भी वृद्धि की तपिश झेल रहे अंग्रेजों को यह समझा पाना मुश्किल नहीं कि कभी दुनिया पर राज करने वाले ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था लगातार पिछड़ने के मूल में उस पर बढ़ता प्रवासियों का दबाव भी है। आश्चर्य नहीं कि नोजली, लॉटन और केंट के कुछ क्षेत्रों में प्रवासी विरोधी गुट सक्रिय और मुखर हो रहे हैं। कुछ दशक पहले यह कल्पना भी मुश्किल थी कि ब्रिटेन के मूल निवासी अपने ही देश में खुद को असुरक्षित महसूस करने लगेंगे, लेकिन अब राजधानी लंदन में ही कुछ 'नो-गो जोन' बन गये हैं, जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में गैर मुस्लिम जाना असुरक्षित समझते हैं। ब्रिटेन की ही बात करें तो लगातार बढ़ती मुस्लिम आबादी फिलहाल प्रवासी विरोध की बड़ी वजह है। अनुमान है कि 2035 तक ब्रिटेन की कुल आबादी में मुस्लिम आबादी 25 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी।

किसी भी देश और समाज में जब आबादी का स्वरूप और संतुलन बदलता है, तो कई तरह की चुनौतियां पैदा होना स्वाभाविक है। बेहतर जीवन की चाह में विदेश जाने वाले प्रवासी भी अपनी संस्कृति को आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेजे रखना चाहते हैं। इस प्रक्रिया में वे संगठित भी होते हैं, लेकिन राष्ट्रवाद के जरिये स्थानीयता की राजनीति करने वाले उनकी सक्रियता और मुखरता को देश की मूल संस्कृति और निवासियों के लिए खतरे के रूप में पेश करते हैं।

इस्लामी संस्कृति से ले कर गाजा पर एकजुटता के प्रदर्शन तक मुस्लिम संगठनों की सक्रियता और मुखरता अंग्रेजी समाज में भविष्य के खतरे के रूप में भी रेखांकित की जा रही है। ऐसा लग सकता है कि ब्रिटेन में प्रवासी विरोध के निशाने पर मुस्लिम ही हैं, पर वास्तव में अवैध प्रवासी हर देश में समस्या बनते जा रहे हैं। अमेरिका की तरह अन्य पश्चिमी देशों में भी अवैध प्रवासियों से सख्ती से निपटने के लिए जनता का दबाव बढ़ रहा है। एक अनुमान के मुताबिक इसी साल लगभग 28 हजार अवैध प्रवासी छोटी नावों से इंग्लिश चैनल पार कर ब्रिटेन में प्रवेश कर चुके हैं। खुद को अवैध प्रवासियों के लिए धर्मशाला नहीं बनने देना किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं माना जा सकता। बेशक जिन देशों से ये अवैध प्रवासी आते हैं, वे भी उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई का तर्कसम्मत विरोध नहीं कर सकते। जब अमेरिका ने अवैध भारतीय प्रवासी हथकड़ी-बेड़ी पहना कर भारत भेजे तो हमारे पास भी मानवीय व्यवहार का मुद्दा उठाने के अलावा कहने को ज्यादा कुछ नहीं था। इस विश्वव्यापी समस्या का चिंताजनक पहलू यह भी है कि अवैध प्रवासियों के विरुद्ध मुखर होते इस विरोध की आंच अंततः वैध प्रवासियों तक भी पहुंचेगी, क्योंकि उनके चलते मूल निवासियों के लिए रोजगार के घटते अवसरों और बढ़ती मुश्किलों की बहस शुरू हो चुकी है। बेशक पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने वाले भारतीय छात्र वहां की अर्थव्यवस्था में लगभग छह अरब डॉलर का सालाना योगदान देते हैं।

ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी भारतीय पेशेवरों की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन कोई भी प्रवासी मूलतः अपने बेहतर जीवन के लिए ही विदेश जाता है, न कि उस देश को बेहतर बनाने में योगदान देने। हां, सत्ता राजनीति अपनी सुविधा के लिए इस तथ्य को छिपा जाती है कि कम वेतन पर स्थानीय पेशेवर न मिलने अथवा उतने कुशल स्थानीय पेशेवर न मिलने से ही प्रवासी पेशेवरों को इन देशों की कंपनियां नौकरी देती हैं, न कि धर्मार्थ भाव से। जरूरत यह भी समझने-समझाने की है कि परस्पर आदान-प्रदान से ही भविष्य की बेहतर दुनिया बनेगी, संकीर्ण सोच से नहीं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

सारा संसार

लवासा में देवकुंड झरना एक छिपा हुआ रत्न है। 20 फिट की ऊंचाई से गिरते हुए पानी को देख यात्री तरोताजा महसूस करते हैं। यहां पहुंचने के बाद देवकुंड पर्यटन टीम आपको कैंपिंग, ट्रेकिंग जैसी एडवेंचर एक्टिविटी के बारे में पूरी जानकारी देती है।

मन की कड़वाहट मिटेगी तो संबंध में आएगी ताजगी

संकलित
दर्शन

हम अपने सोच व विचारों से अपना ऊर्जा क्षेत्र बनाते हैं। हमारे संकल्पों की गुणवत्ता ऊर्जा क्षेत्र की गुणवत्ता निर्धारित करती है। उस ऊर्जा क्षेत्र से हम अपने आपको अलग नहीं कर सकते। उसके सकारात्मक व नकारात्मक प्रकंपन को हम हमेशा साथ लेकर चलते हैं, चाहें घर में प्रवेश करते हुए अथवा घर से बाहर निकलते हुए। जब किसी के बारे में हम अच्छा सोचते हैं और उसके प्रति हमारे विचारों को शुद्ध, सुंदर व सकारात्मक रखते हैं, तो स्वाभाविक है कि हम उसे एक प्रकार से आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद देने का यह मतलब नहीं कि हम केवल औपचारिक रूप में शुभकामनाएं देते हैं। अगर हमारे पास किसी के लिए उपहार लेने के लिए पैसे नहीं हैं, तो हमारी ओर से उनके लिए सबसे बड़ा उपहार यही होगा कि हम उनके घर-परिवार को आशीर्वाद दें। सामान्यतः दूसरों के लिए हम अपने सोच के साथ बोल को ध्यान में रखते हैं। भले ही हम उस व्यक्ति के लिए मन में नकारात्मक भावनाएं रखते हों, पर एक पल के लिए उसे बधाई भी देते हैं। इसका मतलब है, हम उसके लिए मन में अच्छा सोच भी पैदा कर सकते हैं। संबंधों का अर्थ ही है संकल्प रूपी ऊर्जा का आदान-प्रदान करना। मैं आपके बारे में जो सोचती हूं, वह आप तक पहुंचता है। आप मेरे बारे में जो सोचते हैं, वह मुझ तक पहुंचता है-यही हमारे संबंधों का आधार बनता है। यदि मैं आपके बारे में अच्छा सोच नहीं रखती और आपके लिए अच्छे काम करती हूं, तो मैं कितनी भी कोशिश क्यों न करूं, हमारे संबंध का नींव कभी मजबूत नहीं होगी।

लक्ष्मी जी कहां निवास करतीं हैं

संकलित
प्रेरणा

एक बार की बात है, राजा बलि समय बिताने के लिए एकान्त स्थान पर गधे के रूप में छिपे हुए थे। देवराज इन्द्र उनसे मिलने के लिए उन्हें ढूंढ रहे थे। एक दिन इन्द्र ने उन्हें खोज निकाला और उनके छिपने का कारण जानकर उन्हें काल का महत्व बताया। साथ ही उन्हें तत्वज्ञान का बोध कराया। तभी राजा बलि के शरीर से एक दिव्य रूपात्मा स्त्री निकली। उसे देखकर इन्द्र ने पूछा- दैत्यराज! यह स्त्री कौन है? देवी, मानुषी अथवा आसुरी शक्ति में से कौन-सी शक्ति है? राजा बलि बोले देवराज! ये देवी तीनों शक्तियों में से कोई नहीं हैं। आप स्वयं पूछ लें। इन्द्र के पूछने पर वे शक्ति बोलीं- देवेन्द्र! मुझे न तो दैत्यराज बलि जानते हैं और न ही तुम या कोई अन्य देवगण। पृथ्वी लोक पर लोग मुझे अनेक नामों से पुकारते हैं। जैसे- श्री, लक्ष्मी आदि। इन्द्र बोले- देवी! आप इतने समय से राजा बलि के पास हैं लेकिन ऐसा क्या कारण है कि आप इन्हें छोड़कर मेरी ओर आ रही हैं? लक्ष्मी जी बोलीं- देवेन्द्र! मुझे मेरे स्थान से कोई भी हटा या डिगा नहीं सकता है। मैं सभी के पास काल के अनुसार आती-जाती रहती हूं। जैसा काल का प्रभाव होता है मैं उतने ही समय तक उसके पास रहती हूं। अर्थात मैं समयानुसार एक को छोड़कर दूसरे के पास निवास करती हूं। इन्द्र बोले- देवी! आप असुरों के यहां निवास क्यों नहीं करतीं? लक्ष्मी जी बोलीं- देवेन्द्र! मेरा निवास वहीं होता है जहां सत्य हो, धर्म के अनुसार कार्य होते हों, व्रत और दान देने के कार्य होते हों। लेकिन असुर भ्रष्ट हो रहे हैं। ये पहले इन्द्रियों को वश में कर सकते थे।

आस्था

बाल मुकुन्द ओझा

शक्ति भक्ति, मेलों-ठेलों और खुशियों के त्योहार

भारत त्योहारों का देश है। त्योहार देश की सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक बुनियाद को मजबूत बनाने और समाज को जोड़ने का काम करते हैं। त्योहार जीवन में खुशियां लेकर आते हैं। विशेषकर सितम्बर और अक्टूबर का त्योहारी महीना अपने साथ कई सौगातें लेकर आता है। इस दौरान बारिश विदाई ले चुकी होती है और मौसम में बदलाव की आहट लोग महसूस करते है। इस मौसम में प्राकृतिक सौंदर्य अपने चरम पर होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सितम्बर माह से देश में त्योहारी मौसम की शुरुआत हो जाती है। नवरात्रि से दीपावली तक दो माह इस बार कई महत्वपूर्ण धार्मिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पर्वों की सौगात लेकर आ रहा है। ये माह आस्था, परंपरा और भक्ति से जुड़ी अनेक शुभ तिथियों को अपने साथ लेकर आया है। यह एक के बाद एक व्रत और त्योहारों से सजा हुआ है। श्राद्ध पक्ष की समाप्ति के साथ ही 22 सितम्बर से विधिवत त्योहारी सीजन की शुरुआत हो जाएगी। इस दौरान शारदीय नवरात्रि, विजयदशमी, करवा चौथ, दीपावली, प्रदोष व्रत, शरद पूर्णिमा जैसे बड़े व्रत, त्योहार और मेले ठेले हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाये जायेंगे। दीपावली तक त्योहारी खरीदारी का माहौल रहेगा और उसके बाद शादियों का दौर बाजारों को नई रफ्तार देगा। बहरहाल यहां हम त्योहारी सीज़न की चर्चा कर रहे हैं। इस त्योहारी सीजन में एक दर्जन बड़े त्योहार और व्रत आते हैं जिसमें देशवासी उमंग और उत्साह के साथ शामिल होकर अपनी खुशियों का इजहार करते हैं। लोकमंगल के इस सीजन में बच्चे से बुजुर्ग तक खुशियां बांटते हैं और खुशहाली की कामना करते हैं। त्योहारी सीज़न की शुरुआत शारदीय नवरात्रि से हो रही है। 22 सितम्बर से शुरू हो रहे नवरात्रि के पावन अवसर पर मां दुर्गा के लाखों भक्त उनकी तन मन से पूजा-आराधना करते हैं ताकि उन्हें उनकी श्रद्धा का फल मां के आशीर्वाद के रूप में मिल सके। धनतेरस का पर्व शनिवार, 18 अक्टूबर 2025 को है। इस दिन भगवान धन्वंतरि और मां लक्ष्मी की पूजा होती है। इसे स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। नरक चतुर्दशी का पर्व रविवार, 19 अक्टूबर को मनाया जाएगा। मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था। इसे छोटी दिवाली भी कहते हैं। दिवाली सोमवार, 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस दिन मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान कुबेर की पूजा की जाती है। शाम को घरों में दीपक जलाकर अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा मंगलवार, 21 अक्टूबर को है। लोग तरह-तरह के व्यंजन बनाकर भगवान को भोग लगाते हैं। भाई दूज गुरुवार, 23 अक्टूबर को है। यह दिन भाई-बहन के पवित्र रिश्ते को समर्पित है। बहनें अपने भाइयों को तिलक करती हैं और लंबी उम्र की कामना करती हैं। त्योहारों में लोग अपनी सामर्थ्य के मुताबिक नए कपड़े, जमीन जायदाद सोने-चांदी के सामान सहित घरेलू जरूरत के सामान खरीदते हैं। तन-मन को प्रफुल्लित करने वाला ये पर्व हमारे जीवन में हजारों खुशियां प्रदान करते हैं। त्योहार जीवन को प्रेम, बन्धुत्व और शुद्धता से जीने की सीख देता है और बुराइयों को अन्तर्मन से बाहर निकाल कर अच्छाइयों को ग्रहण करने की ताकत प्रदान करता है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

अंतर्मन

आज की पाती

नए मीटर हटाए सरकार

इलेक्ट्रानिक स्मार्ट मीटर क्या लगे, जी का जंजाल बन गए हैं। पुराने मीटर उपभोक्ताओं के लिए उपयुक्त थे और किसी को शिकायत नहीं थी। जैसे हो बिजली के नए मीटर लगे उपभोक्ताओं के दोगुने बिल आने लगे हैं। चारों तरफ त्राहि-त्राहि है। आर्थिक तंगी में बढ़े हुए बिल जैसे गरीबी में आटा गीला हो गया है। उपभोक्ता चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीटर हटा कर पुराने मीटर ही लगाए जाएं और नए मीटर हटा कर विभाग जनहित का कार्य करे। इन नए मीटरों की न तो जनता ने मांग की थी और न इन्हें कोई चाहता है। इस कवायद से भले ही विद्युत विभाग की आय बढ़ी है, पर उपभोक्ता इस ट्रंप के से टैरिफ को नहीं सह पा रहे हैं। आशा है जनहित में विभाग और सरकार इस योजना को बंद कर अवश्य अनुगृहीत करेंगे।

- प्रदीप यदु, रायपुर

करंट अफेयर

अफगानिस्तान के कई प्रांतों में इंटरनेट सेवाएं प्रतिबंधित

अफगानिस्तान में लोगों को "अनैतिक आचरण से बचाने के लिए" तालिबान की ओर से फाइबर-ऑप्टिक इंटरनेट सेवाओं पर लगाया गया पूर्ण प्रतिबंध कई और प्रांतों में प्रभावी हो गया है। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकी बलों की पूर्ण वापसी के बाद सत्ता की कमान संभालने वाले तालिबान ने पहली बार इस तरह का प्रतिबंध लागू किया है। इससे सरकारी कार्यालय, निजी क्षेत्र के दफ्तर, सार्वजनिक प्रतिष्ठान और घर वाई-फाई इंटरनेट सेवा से वंचित हो गए हैं। हालांकि, देश में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अभी भी चालू हैं। अधिकारियों का कहना है कि "जरूरत पूरी करने के लिए" विकल्प तलाशे जा रहे हैं। उत्तरी बल्ख प्रांत ने मंगलवार को वाई-फाई इंटरनेट सेवाएं बंद होने की पुष्टि की, जबकि देश के अन्य हिस्सों में भी गंभीर व्यवधान की खबरें हैं। बृहस्पतिवार को पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों के अधिकारियों ने बताया कि बगलान, बदख्शान, कुंदुज, नंगरहार और तखर प्रांत में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई हैं। 'अफगानिस्तान मीडिया सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन' ने वाई-फाई इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध की निंदा की। संगठन ने कहा, 'तालिबान के शीर्ष नेता के आदेश पर उठाया गया यह कदम न केवल मुफ्त सूचनाओं और आवश्यक सेवाओं तक लाखों नागरिकों की पहुंच बाधित करता है।

ऑफ बीट

हमेशा जीवित रहने अमरत्व बेचने की तैयारी में विशेषज्ञ

क्या आपको मौका मिले तो हमेशा जीवित रहने के लिए भुगतान करना चाहेंगे? सिलिकॉन वैली के कुछ अरबपति अब सिर्फ प्रौद्योगिकी संबंधी उत्पाद ही नहीं बना रहे, बल्कि उनकी नजरें 'अमरत्व' हासिल करने पर हैं। सोशल मीडिया पर स्वास्थ्य संबंधी सोच को प्रभावित करने वाले (इन्फ्लुएंसर्स) बड़ी संख्या में उपयुक्त खाद्य सामग्री, मशरूम पाउडर और अन्य कई 'तरह के आहार' को बढ़ावा दे रहे हैं जो दावा करते हैं कि वे आपकी उम्र को उलट सकते हैं या जीवनकाल को बढ़ा सकते हैं। हालांकि इनमें से अधिकांश उपायों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। बर्फीले स्नान (आइस बाथ), सौना, क्रायोथेरेपी और रेड लाइट थैरेपी जैसे उपाय अब तेजी से बढ़ते एक उद्योग का हिस्सा बन चुके हैं जो लंबे जीवन और युवा दिखने की चाह पर आधारित है। वैज्ञानिक साक्ष्य की बजाय मुनाफे पर ज़ोर विशेषज्ञों का कहना है कि यह उद्योग उन लोगों को लक्षित कर रहा है जो बुढ़ापे और मृत्यु से डरते हैं। हालांकि, आज तक कोई मनुष्य अमर नहीं हुआ, और न ही जैविक रूप से यह संभव है। डार्विन के सिद्धांत पर आधारित विकास प्रक्रिया जीवों को अधिक समय तक जीवित रहने की बजाय सफल प्रजनन और अनुकूलन के लिए तैयार करती है।

ट्रेंड

एक पेड़ मां के नाम

सेवा पखवाड़े के तहत 'एक पेड़ मां के नाम 2.0' अभियान न केवल पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है बल्कि इसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। मेरी सभी भारतीयों से अपील है कि वे निश्चित रूप से अपनी मां के नाम पर एक पेड़ लगाएं।

- भूपेंद्र यादव, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री

मुश्किल पार करने की ताकत

बारिश की वजह से हुआ कीचड़ हो या इंसानों द्वारा बनाए गए बांध - मुझे मेरे लोगों से मिलने से कोई भी परिस्थिति नहीं रोक सकती। यह रिश्ता हर मुश्किल को पार करने की ताकत रखता है।

- हिमंत बिस्वा सरमा, सीएम, असम

कई कैदियों की रिहाई

हमारी सरकार ने आजीवन कारावास की सजा काट चुके कई कैदियों को कानूनी तौर पर रिहा किया है। 2011 से अब तक ऐसे 840 लोगों को रिहा किया जा चुका है। 45 और कैदियों को कानूनी तौर पर रिहा किया जा रहा है। मैं उन्हें बधाई देती हूं।

-ममता बनर्जी, सीएम, प. बंगाल

प्रभावित परिवारों से मुलाकात

आज मनाली विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गाँवों और कस्बों का दौरा कर आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। हम मिलकर पुनर्निर्माण और राहत कार्यों को पूरी ताकत से आगे बढ़ाएंगे।

-कंगना रनौत, सांसद, भाजपा

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

19 hindi nd-06_page 02.qxd 9/18/2025 6:42 PM Page 1

पायनियर
नई दिल्ली, शुक्रवार, 19 सितंबर 2025

भारत-अमेरिका वार्ता

राजनयिकों की परीक्षा

यह बात घिसी-पिटी लग सकती है, लेकिन कूटनीति वास्तव में असंभव को संभव बनाने की कला है—और राजनयिक कठिनतम वाताओं में ही सफल होते हैं। भारतीय कूटनीति अब एक कठिन परीक्षा का सामना कर रही है। अमेरिका के साथ चल रही व्यापार वार्ता के नतीजे बहुत कुछ दांव पर लगे हैंः भारत की विकास गति प्रभावित हो सकती है, जबकि वाशिंगटन एक विश्वसनीय साझेदार से अलग होने का जोखिम उठा रहा है। फिर भी, इसमें एक सकारात्मक पहलू भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हाल ही में जन्मदिन की शुभकामनाओं का आदान-प्रदान, दोस्ती और वैश्विक साझेदारी की पुष्टि के साथ, एक आशाजनक शुरूआत प्रदान करता है।

लेकिन शब्दों की गर्माहट के नीचे कठोर वास्तविकताएं छिपी हैंः चल रही भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता गहरे मतभेदों के बोझ तले दबी है, जिन्हें केवल बयानबाजी से पाटा नहीं जा सकता। वाशिंगटन द्वारा भारतीय आयातों पर भारी शुल्क लगाने के बाद यह पहली बार है—दोनों पक्षों ने व्यवस्थित वार्ता फिर से शुरू की है। 2030 तक 500 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य के साथ, दोनों के लिए दांव बहुत ऊंचे हैं। यह एक कठिन वार्ता प्रक्रिया है जिसमें अमेरिका को बढ़त हासिल है, लेकिन वह अभी भी कमजोर है क्योंकि अत्यधिक दबाव वार्ता को विफल कर सकता है, जिससे वह एक विश्वसनीय साझेदार खो सकता है जो उसके सबसे बड़े डर - चीन - का एकमात्र प्रतिकार है।

लेकिन वार्ता अभी भी कठिन है। अमेरिका की शर्तें आर्थिक और रणनीतिक, दोनों ही कारणों से भारत के लिए अस्वीकार्य साबित हो रही हैं। वाशिंगटन का यह आग्रह कि भारत रूस से तेल की खरीद कम करे, और उसकी मक्के तक बाजार पहुँच की उसकी शर्तें, भारत के अपने ऊर्जा स्त्रोतों में विविधता लाने और अपनी कृषि अर्थव्यवस्था की रक्षा करने के अधिकार पर प्रहार करती हैं। ऐसी माँगों को स्वीकार करने से न केवल भारत की खाद्य सुरक्षा और किसानों के हित कमजोर होंगे, बल्कि विदेश नीति में उसकी रणनीतिक स्वायत्तता भी खतरे में पड़ेगी। भारत पर 50 प्रतिशत का शुल्क अमेरिका द्वारा किसी भी देश पर लगाए गए सबसे ज्यादा शुल्कों में से एक है।

जबरदस्ती और शर्तों के आधार पर कोई भी गंभीर व्यापारिक साझेदारी नहीं बनाई जा सकती। साथ ही, भारत को अमेरिका की उतनी ही जरूरत है जितनी अमेरिका को भारत की। भारत का विशाल उपभोक्ता बाजार और विनिर्माण आधार इसे अमेरिकी कंपनियों के लिए अपरिहार्य बनाते हैं। इसके विपरीत, अमेरिकी तकनीक, पूँजी और बाजारों तक पहुँच भारत के आर्थिक उत्थान के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों पक्षों को अपनी-अपनी जगह अड़े रहने से पहले एक-दूसरे के महत्व को समझना होगा और लेन-देन की राजनीति से आगे बढ़कर अपनी साझेदारी के व्यापक रणनीतिक तर्क को समझना होगा। भारत के लिए, इसका अर्थ है अपने व्यापार करने के तरीके और लोगों के साथ व्यापार करने के अधिकार पर अडिग रहना, साथ ही टैरिफ और गैर-संवेदनशील व्यापार बाधाओं पर लचीलापन दिखाना। अमेरिका के लिए, इसका अर्थ है भारत को अधीनस्थ नहीं, बल्कि एक साझेदार मानना।

एक संतुलित व्यापार समझौते की राह लंबी होगी, लेकिन दिशा स्पष्ट है। भारत-अमेरिका संबंध केवल टैरिफ और बाजार पहुंच तक सीमित नहीं रह सकते; यह एक व्यापक रणनीतिक दृष्टि पर आधारित है। फिलहाल, चुनौती यह सुनिश्चित करने की है कि आर्थिक अड़चनें इस दृष्टि को पटरी से न उतारें। बातचीत कठिन हो सकती है, लेकिन टकराव से कहीं बेहतर है।

घृणा की राजनीति के घातक परिणाम

नफरत के सामान्यीकरण ने डोनाल्ड ट्रंप के लोकप्रिय समर्थक चार्ली किर्क की जान ले ली। अति-दक्षिणपंथी कार्यकर्ता और टर्निंग पॉइंट के सीईओ की यूटा वैली विश्वविद्यालय में दर्शकों को संबोधित करते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह यात्रा परिसरों में उनकी विवादास्पद अमेरिकी वापसी यात्रा का हिस्सा थी।

भूपिंदर सिंह
लेखक, सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी हैं।

ध्रुवीकरण की राजनीति और अमेरिकी सार्वजनिक जीवन में नफरत के सामान्यीकरण ने डोनाल्ड ट्रंप के लोकप्रिय समर्थक चार्ली किर्क की जान ले ली। अति-दक्षिणपंथी कार्यकर्ता और टर्निंग पॉइंट के सीईओ की यूटा वैली विश्वविद्यालय में दर्शकों को संबोधित करते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह यात्रा परिसरों में उनकी विवादास्पद अमेरिकी वापसी यात्रा का हिस्सा थी।

ट्रंप ब्रांड की राजनीति के चीयरलीडर के रूप में प्रसिद्ध या कुख्यात, किर्क ने जलवायु परिवर्तन, नागरिक अधिकार आंदोलन, अल्पसंख्यकों, बंदूक नियंत्रण, एलजीबीटीक्यू आदि जैसे मुद्दों पर विवादास्पद रूप से अपनी राय रखी थी, जिसमें इन सभी मुद्दों पर ट्रंप के प्रतिगामी रुख की सराहना की गई थी। विडंबना यह है कि परिसरों और स्कूलों में गोलीबारी की घटनाओं में वृद्धि के बावजूद, किर्क ने लापरवाही से इसे दूसरे संशोधन (हथियार रखने और धारण करने का अधिकार) के संरक्षण के साथ जोड़ दिया था। उन्होंने कहा था, ₹दुर्भाग्य से, हर साल बंदूक से होने वाली कुछ मौतों की कीमत चुकाना उचित है, ताकि हम अपने अन्य ईश्वर प्रदत्त अधिकारों की रक्षा के लिए दूसरा संशोधन प्राप्त कर सकें... यह एक विवेकपूर्ण सौदा है। यह एक कट्टर ट्रम्पी (अवैध) तर्क था जिसने शायद उनके अपने जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

हैरानी की बात यह है कि ट्रम्प भी अपने अभियान के दौरान एक बंदूक हमले से बच गए थे, लेकिन व्हाइट हाउस में अपनी सफल वापसी के बाद से, एक के बाद एक, विभिन्न प्रगतिशील कानूनों को बेरहमी से ध्वस्त कर रहे हैं। एक बार ट्रम्प ने गोलीबारी को अति-उत्तेजित बयानबाजी का अस्वीकार्य परिणाम कहकर सही किया।

लेकिन सामाजिक बयानबाजी को गर्म करने और भड़काने में अमूल्य भूमिका का श्रेय बहुत हद तक उन रुखों, राजनीति और डॉग-व्हिसलिंग को दिया जा सकता है जिन्हें स्वयं ट्रम्प ने सामान्य बना दिया है। अमेरिकी समाज के कट्टरपंथीकरण (और इसकी अविश्वासपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति) ने या तो संरक्षण (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट चुप्पी के साथ) द्वारा चरमपंथी विचारों को चुनिंदा रूप से वैध ठहराया है, या इसके विपरीत, वैचारिक गलियारे के पार से समान रूप से चरमपंथी विचारों को प्रेरित किया है।

ट्रंप का (मेक अमेरिका ग्रेट अगेन) रिपब्लिकनवाद, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जॉर्ज एचडब्ल्यू बुश या यहां तक कि रोनाल्ड रीगन जैसे पूर्व रिपब्लिकन राष्ट्रपतियों के समावेशी और अधिक उदारवादी रुख से बिल्कुल अलग है।

जबकि ट्रंप और उनके समर्थक—जैसे निक फ्यूएंट्स (अमेरिका फर्स्ट मूवमेंट के संस्थापक), लॉरा लूमर (दक्षिणपंथी टिप्पणीकार), एलेक्स जोन्स (इन्फोवॉर्स के होस्ट), या यहां तक कि खुद चार्ली किर्क—ने एक निश्चित रूप से अधिक वर्चस्ववादी, नस्लवादी, बहिष्कारवादी और जेनोफोबिक एजेंडे को आगे बढ़ाया जिसने माहौल को विस्फोटक रूप से प्रभावित किया। हालाँकि, किसी भी राजनीतिक टिप्पणीकार की विचारधारा या व्यक्त स्थिति चाहे जो भी हो, हिंसा को किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता। किर्क की गोलीबारी को कोई भी उचित नहीं ठहरा सकता, क्योंकि लोकतांत्रिक समाजों में हमेशा मतभेद होते हैं (और वे आवश्यक भी हैं)—लेकिन किसी भी तर्क में ₹दूसरे पक्ष₹ को उन असहमतियों का कभी भी हिंसा से सामना नहीं करना चाहिए।

> **हैरानी की बात यह है कि ट्रम्प भी अपने अभियान के दौरान एक बंदूक हमले से बच गए थे, लेकिन व्हाइट हाउस में अपनी सफल वापसी के बाद से, एक के बाद एक, विभिन्न प्रगतिशील कानूनों को बेरहमी से ध्वस्त कर रहे हैं। एक बार ट्रम्प ने गोलीबारी को अति-उत्तेजित बयानबाजी का अस्वीकार्य परिणाम कहकर सही किया।**

असहमति या विरोधी विचारों को परिपक्वता से संबोधित किया जाना चाहिए, जैसा कि अंग्रेजी लेखिका एवलिन बीट्राइस हॉल ने कहा था, ₹आप जो कहते हैं, मैं उससे असहमत हूँ, लेकिन मैं आपके कहने के अधिकार की मरते दम तक रक्षा करूँगी।

आज कई सहभागी लोकतंत्रों में, राष्ट्रवाद के बहाने हिंसा को एक विरोधी रुख के प्रति एक वैध प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है। अंतर्निहित मूलनिवासीवाद या बहुसंख्यकवाद (जिसे हमेशा राष्ट्रवाद के रूप में प्रचारित किया जाता है) के एक हिस्से के रूप में, किर्क की भारत और भारतीय जातीयता के बारे में अप्रिय राय थी। उन्होंने कुख्यात रूप से कहा था, अमेरिका को भारत के लोगों के लिए और अधिक वीजा की आवश्यकता नहीं है। शायद किसी भी प्रकार के कानूनी आव्रजन ने अमेरिकी श्रमिकों को भारत से आए लोगों की तरह विस्थापित नहीं किया है। अब बहुत हो गया।

हालांकि, धर्म और मूल देशों के संदर्भ में अन्य समूहों के प्रति घृणा की गलत समानता ने भारत में कई लोगों को ट्रम्प के शासन के घृणा से भरे एजेंडे को नजरअंदाज (यहाँ तक कि समर्थन) करने के लिए मजबूर किया, जिसने अंततः एक कथित मित्र को तब मारा जब उसकी अनुमानित उपयोगिता पूरी हुई।

दिल्ली ने अब ट्रंप के भारत के प्रति अस्थिर, अविश्वासी और अशिष्ट बयानों को प्रत्यक्ष रूप से देखा है, जिससे उम्मीद है कि वह समझ जाएगा कि किसी की नफरत कभी भी सिर्फ.आपके दुश्मन के दरवाजे पर नहीं निर्देशित की जा सकती, क्योंकि इसका असर आप पर भी पड़ सकता है! दुःख की बात है कि जहाँ किर्क ने हमेशा दूसरों के अपने साथ असहमत होने के अधिकार का बचाव किया और किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए सार्वजनिक बहस पर जोर दिया, वहीं उनके राजनीतिक आका (जैसा कि हर लोकतंत्र में होता है) अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल करने में कहीं ज्यादा चुनिंदा और चालाक थे।

हालांकि आज उनमें से कई लोग किर्क की गोलीबारी पर शोक व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन जब, उदाहरण के लिए, नफरत भरी गोलीबारी के शिकार वैचारिक भेद के दूसरी तरफ के लोग भी थे, तब वे चुप रहे या अशिष्ट बयान दिए।

ट्रंप जैसे विक्षिप्त और निर्मम राजनेता अपने निजी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए चयनात्मकता का सहारा लेंगे, जिससे माहौल और भी ज्यादा खराब होगा। अपने राष्ट्रपति पद की घोषणा के जरिए, ट्रंप ने राष्ट्रीय शोक का आदेश दिया है, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाकर या नीचा करके फहराया जाएगा।

यह गंभीर भाव आमतौर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश आदि जैसे प्रमुख सरकारी हस्तियों की मृत्यु, बड़ी संख्या में लोगों की जान लेने वाली राष्ट्रीय त्रासदियों, मित्र विदेशी गणमान्य व्यक्तियों की मृत्यु, या शहीद सैन्य कर्मियों या प्रथम प्रतिक्रियाकताओं के स्मारकों के लिए आरक्षित होता है। हालांकि, किर्क की गोलीबारी की स्पष्ट रूप से और बिना किसी पक्षपातपूर्ण संदर्भ के निंदा की जानी चाहिए, लेकिन बिना किसी सरकारी पद वाले एक ध्रुवीकरणकारी व्यक्ति को राष्ट्रीय शोक का श्रेय देना, पक्षपात को और हथियार बनाने की सरासर राजनीति है।

एक धार्मिक और धार्मिक प्रचारक ईसाई के लिए (जबकि वह अन्य धर्मों, जातियों, रंग या राजनीतिक विश्वासों के लोगों पर घृणित आरोप लगाता है), विडंबना तब और बढ़ जाती है जब बाइबल (विशेषकर मत्ती 26:52) को प्रतिबिंबित किया जाता है, जहाँ यीशु एक शिष्य को फटकारते हैं जिसने तलवार से उनका बचाव करने की कोशिश की थी, अपनी तलवार काठी में रख ले; क्योंकि जो तलवार उठाते हैं, वे तलवार से ही नाश किए जाएँगे। लेकिन ट्रम्प जैसे राजनीतिक लोगों ने धर्म को भी हथियार बना लिया है।

भारत में फिनटेक क्रांति पर जोर

> पिछले छह वर्षों में, फिनब्लू ने अपने शुरुआती लक्ष्यों को पार करते हुए 61 फिनटेक स्टार्ट-अप को सफलतापूर्वक इनक्यूबेट किया है। इन स्टार्ट-अप ने बाहरी निवेश में 24 करोड़ रुपये से अधिक जुटाए हैं और 73 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व उत्पन्न किया है।

अरविंद कुमार
लेखक, साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के डीजी हैं।

जैसे जैसे भारत वैश्विक फिनटेक लीडर बनने की ओर अग्रसर है, एक शांत लेकिन शक्तिशाली परिवर्तन चल रहा है। इस विकास में सबसे आगे फिनब्लू है, जो फिनटेक में एक समर्पित उद्यमिता केंद्र (सीओई) है, जिसे तमिलनाडु सरकार के सक्रिय समर्थन से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वावधान में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) द्वारा स्थापित किया गया है। 2019 में अपनी स्थापना के बाद से, फिनब्लू उन स्टार्ट-अप्स का पोषण कर रहा है जो अगली पीढ़ी की सुरक्षित, स्केलेबल और समावेशी वित्तीय तकनीकों का निर्माण कर रहे हैं।

भारत का फिनटेक उद्योग उल्कापिंड विकास का अनुभव कर रहा है। ट्रीलाइफ की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में फिनटेक उद्योग पिछले एक दशक में 31 प्रतिशत की प्रभावशाली सीएजीआर से बढ़ रहा है और 2029 तक 420 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। हालांकि, इस क्षेत्र के तेजी से विस्तार के लिए एक संरचित पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता है जो गहन तकनीकी नवाचार का समर्थन करे और स्थानीय और वैश्विक, दोनों वित्तीय चुनौतियों का समाधान करे। फिनब्लू वास्तव में ऐसा ही एक प्रवर्तक है, जो एक व्यापक इनक्यूबेशन वातावरण प्रदान करता है जो प्रौद्योगिकी, प्रतिभा और बाजार पहुंच का मिश्रण है।

पिछले कुछ वर्षों में, एसटीपीआई की भूमिका में उल्लेखनीय विकास हुआ है। हालाँकि, भारत के प्रौद्योगिकी क्षेत्र को मजबूत करने पर मुख्य ध्यान इसके स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के माध्यम से बदल गया है।

इसने देश भर में 24 उद्यमिता केंद्र (सीओई) स्थापित किए हैं। इन सीओई के माध्यम से, एसटीपीआई नवाचार और उत्कृष्टता के लिए आवश्यक प्लग-एंड-प्ले सीटें, प्रयोगशाला अवसंरचना, मार्गदर्शन, वित्त पोषण और बाजार पहुंच प्रदान करके एक 360-डिग्री सहायता प्रणाली प्रदान कर रहा है। 827 स्टार्ट-अप को सीओई द्वारा समर्थित किया गया है, जिनमें 223 स्टार्ट-अप शामिल हैं जिन्हें बाहरी वित्त पोषण प्राप्त हुआ है। फिनब्लू की ताकत इसके सहयोगात्मक आधार में निहित है। यह आईआईटी मद्रास जैसे प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों, बीएनवाई मेलॉन, इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना और ट्रांसयूनियन सिबिल जैसे प्रमुख उद्योग खिलाड़ियों और सरकारी समर्थन को एक समृद्ध, नवाचार-संचालित पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए एक साथ लाता है। फिनब्लू में स्टार्ट-अप को आधुनिक बुनियादी ढांचे, गहन तकनीक मेंटरशिप, नियामक सैंडबॉक्स, निवेशक संपर्क और बाजार में जाने के समर्थन तक पहुंच प्राप्त होती है, जिससे उन्हें अवधारणा के प्रमाण से आगे बढ़कर स्केलेबल बिजनेस मॉडल में जाने में मदद मिलती है।

पिछले छह वर्षों में, फिनब्लू ने अपने शुरुआती लक्ष्यों को पार करते हुए 61 फिनटेक स्टार्ट-अप को सफलतापूर्वक इनक्यूबेट किया है। इन स्टार्ट-अप ने बाहरी निवेश में 24 करोड़ रुपये से अधिक जुटाए हैं और 73 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व उत्पन्न किया है। इसके अलावा, स्टार्ट-अप ने 195 उत्पाद, 198 प्रोटोटाइप विकसित किए हैं और 29 आईपीआर दायर किए हैं।

कई फिनब्लू-इनक्यूबेटेड स्टार्ट-अप्स ने पहले ही अभूतपूर्व नवाचारों के साथ अपनी पहचान बना ली है। डीप-टेक साइबर सुरक्षा फर्म, नेपिड साइबरसेक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-आधारित डिजिटल प्रमाणीकरण उपकरण विकसित किए हैं और 2021 और 2024 में आरबीआई के हारबिंगर हैकथॉन जीते हैं। यह वर्तमान में प्रमुख बैंकों के साथ अपने समाधानों का परीक्षण कर रहा है। गोल्डपीई एआई ने भारत का पहला गोल्ड लोन एटीएम पेश किया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी में डिजिटल कियोस्क के माध्यम से आंशिक सोना उधार देने में अग्रणी भूमिका निभाई।

फिनारा ने ग्रामीण और शहरी भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए आधार-सक्षम एंड्रॉइड एटीएम और डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ डिजाइन कीं। अन्य सफलता की कहानियों में अजेट्टा इंसुरटेक शामिल है, जो वंचित समुदायों में बीमा पहुँच का लोकतंत्रीकरण कर रहा है; प्राइमइन्वेस्टर, खुदरा निवेशकों के लिए एक डिजिटल निवेश अनुसंधान मंच; और एक्सचेंज.पे, भारतीय एसएमबी और गिग श्रमिकों के लिए डिजाइन किया गया एक सीमा-पार विदेशी मुद्रा और प्रेषण मंच।

फैनम डिजिटल, भारत के पहले इंटरऑपरेबल क्रॉस-बॉर्डर यूपीआई प्लेटफॉर्म्स में से एक है, जो अंतरराष्ट्रीय फिनटेक और गिफ्ट सिटी पहलों के साथ जुड़ा हुआ है। वनएनडीएफ, फाइनेंसकार्ट और इनोसायक्स जैसे स्टार्ट-अप्स डिजिटल ऋण, एसएमई वित्त और नियामक तकनीक में फिनब्लू के प्रभाव की व्यापकता को और भी स्पष्ट करते हैं।

फिनब्लू एक इनक्यूबेटर से कहीं अधिक है, यह डिजिटल वित्तीय सशक्तिकरण के लिए एक रणनीतिक खाका है। यह इस बात का उदाहरण है कि कैसे दूरदर्शी नीति, शैक्षणिक उत्कृष्टता और उद्योग सहयोग सामूहिक रूप से नवाचार को बढ़ावा दे सकते हैं और सार्थक सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पैदा कर सकते हैं। यह तेजी से विकसित हो रहे वित्तीय परिदृश्य में विश्वास, समावेश और नवाचार को सक्षम करते हुए एक राष्ट्रीय उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता रहेगा।

आप की बात

महिलाओं को मोदी जी का तोहफ़ा

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने पिचोत्तर वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर देश के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रही महिलाओं के लिए दो महत्वपूर्ण उपहारों की घोषणा की है स्वास्थ्य का कवच और रोजगार का धागा।स्वास्थ्य का कवच पहल के तहत अब दो अक्टूबर तक देश भर में मेगा स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों में महिलाओं की मधुमेह(डायबिटीज), कैंसर, उच्च रक्तचाप (बी.पी.), एनीमिया और टीबी जैसी पुरानी बीमारियों का निःशुल्क इलाज किया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत उपचार, दवाइयों और अस्पताल के समस्त खर्चों का वहन आयुष्मान कार्ड के माध्यम से किया जाएगा।दूसरा उपहार रोजगार का धागा मध्य प्रदेश के धार ज़िले में निमार्णाधीन पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क से जुड़ा है, जहाँ अनेक महिलाओं को रोजगार के सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे।अक्सर महिलाएं संकोचवश अथवा आर्थिक अभाव के कारण अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा करती हैं और परिवार के दूसरे सदस्यों की चिंता में स्वयं को पीछे रख लेती हैं। इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सशक्त नारी, स्वस्थ परिवार की भावना को आगे बढ़ाते हुए सुमन सखी चैटबॉट सेवा का भी शुभारंभ किया है।

– **भगवानदास छारिया**, झाबुआ मप्र

नदी किनारे न जाएं

बाढ़ का प्रकोप बढ़ने से नदी का जलस्तर बहुत बढ़ गया है एवं कई क्षेत्र बाढ़ का भयंकर शिकार हो गई है जिससे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है लोग ऊंचे स्थान की ओर प्रवास कर रहे हैं बाढ़ आने से जनमानस को भयंकर पीड़ा का सामना करना पड़ता है खाने, रहने एवं शौचालय और मवेशियों का चारा की कमी हो जाती है जिससे महंगाई चरम पर चली जाती है इसी बाढ़ में कई लोगों का घर उजर जाता है बच्चे बाढ़ वाले क्षेत्र की ओर स्नान करने अपने संगतियों एवं टोलियो के साथ चले जाते हैं जिस कारण कई बार दुर्घटना हो जाती है और उनका पैर फिसलने से नदी के धारा के प्रवाह में चले जाते हैं कई बार देखा गया है कि स्कूली बच्चे भी, गांव, टोला और मोहल्ले के बच्चे भी शिकार हो जाते हैं इसलिए बच्चों के माता-पिता को इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है और स्कूल के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक गण बच्चों की निगरानी करें ताकि बच्चे स्कूली बच्चे नदी की ओर बढ़ वाले क्षेत्र में ना जाएं और किसी अप्रिय घटना का शिकार ना हो इसके अलावा कोई भी यदि बड़े बुजुर्ग लोग यदि बच्चे को नदी की ओर जाते हुए देखे तो उन्हें उसे तरफ जाने के लिए मना करें एवं उनके उनके माता-पिता को अवश्य सूचित करें हमारे और आपके बच्चे थोड़े से प्रयास से किसी के घर उजरने से बच सकता है इस प्रयास में हम सभी को आगे जाकर जन कल्याण के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए।

– **तारामुनि देवी**, लालगंज, वैशाली

आर्थिक शक्ति बनता भारत

भारत आज वैश्विक मंच पर एक उभरती आर्थिक शक्ति के रूप में खड़ा है। मोबाइल फोन निर्माण में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बनने से लेकर सेमीकंडक्टर उद्योग में कदम रखने तक हमारी उपलब्धियां गौरवपूर्ण हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि 140 करोड़ की आबादी वाले इस देश में क्या केवल उच्च प्रौद्योगिकी-गहन उद्योग ही पर्याप्त होंगे? हमें श्रम-आधारित उद्योगों और श्रमिकों के सम्मान पर उतना ही ध्यान देना होगा जितना उद्यमियों और निवेशकों पर दिया जा रहा है। पिछले दो दशकों से भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी 14-16 प्रतिशत पर ही ठहरी हुई है। इसके विपरीत चीन ने लंबे समय तक 30 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी बनाए रखी। यह अंतर केवल नीतियों से नहीं, बल्कि कार्यसंस्कृति से भी पैदा हुआ है। भारत में श्रम को अपेक्षित सम्मान न मिलना सबसे बड़ी बाधा है। कुर्सी-मेज वाली नौकरी को प्रतिष्ठा मिलती है, जबकि मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर जैसे कौशल-आधारित कार्यों को अक्सर हीन दृष्टि से देखा जाता है। यही कारण है कि युवा वर्ग उद्यमशीलता और श्रम-प्रधान कार्यों से विमुख होकर नौकरी या विदेश पलायन की ओर भाग रहा है। विडंबना यह है कि जिन घरेलू कार्यों को लोग तुच्छ समझते हैं, वही कार्य करने वाले श्रमिक आराम से 40-50 हजार रुपये प्रतिमाह कमा रहे हैं। असल समस्या रोजगार की कमी नहीं, बल्कि मानसिकता की जकड़न है।

– **सुभाष बुड़ावनवाला**, रतलाम

समय का फेर या कुछ और?

भारत को अपेक्षाकृत कमजोर और मजबूर समझने वाले ट्रंप की धीरे-धीरे अकल ठिकाने लगती जा रही है। व्यवहार में नरमी, नई दिल्ली में भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता के दौरान सकारात्मक बातचीत से तीन महीने बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन पर फोन करना और रूस-यूक्रेन युद्धविराम समर्थन हेतु आभार जताना रिश्तों में आई तल्खी कम करने की कोशिश माना जा रहा है। अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद यह पहली सीधी बातचीत थी जिससे विवाद के समाधान और पारस्परिक व्यापार समझौते की उम्मीद बढ़ी है। माना जा रहा है कि शंघाई सहयोग संगठन बैठक में भारत-रूस-चीन की नजदीकी से ट्रंप चिंतित हुए और अब नरमी दिखा रहे हैं। हालांकि अमेरिका चाहता है कि भारत कृषि और डेयरी क्षेत्र खोल दे, लेकिन भारत किसानों, डेयरी उत्पादकों व एमएसएमई के हितों से समझौता करने को तैयार नहीं है। इसी बीच अमेरिकी दबाव मक्का खरीद पर भी जारी है। जहां भारत-अमेरिका वार्ता में बाधा रही वहीं भारत-यूरोपीय संघ की वार्ता तेज गति से आगे बढ़ रही है और वर्षांत तक समझौते की उम्मीद है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में सक्रिय बने रहने के लिए भारत अन्य देशों से भी समझौते कर रहा है। अब गौर करने वाली बात यही होगी कि ट्रंप की नरमी स्थायी संकेत है या सिर्फ रणनीतिक कदम।

– **अमृतलाल मारू, 'रवि'**, इन्दौर